वार्षिक रिपोर्ट
2017 - 2018

NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATIONAL PLANNING AND ADMINISTRATION

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान

वार्षिक रिपोर्ट
2017-18

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान

(मानित विश्वविद्यालय)

17–बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली–110016

© राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, 2018
(भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत घोषित)

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के लिए कुलसचिव, नीपा द्वारा प्रकाशित तथा मैसर्स विबा प्रेस प्रा. लि., ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–।।, नई दिल्ली–110020, जून 2021 में 150 प्रतियां डिजाईन एवं मुद्रित

विषय सूची

अध्याय		
1.	विहंगावलोकन	01
2.	अध्यापन और व्यावसायिक विकास कार्यक्रम	23
3.	अनुसंधान	41
4.	पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं	67
5.	कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं	75
6.	प्रकाशन	79
7.	नीपा में सहायता अनुदान योजना	83
8.	प्रशासन और वित्त	89
अनुलग्नक		
I.	संकाय का अकादमिक योगदान	95
परिशिष्ट		
I.	नीपा परिषद के सदस्य	205
II.	प्रबंधन बोर्ड के सदस्य	207
III.	वित्त समिति के सदस्य	208
IV.	अकादमिक परिषद के सदस्य	209
V.	अध्ययन बोर्ड के सदस्य	211
VI.	संकाय और प्रशासनिक स्टाफ	213
VII.	वार्षिक लेखा	217
लेखापरीक्षा रिपोर्ट		259
अधिसूचना (नाम परिवर्तन–न्यूपा से नीपा)		267

1

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर अपने महत्वपूर्ण और व्यापक शैक्षणिक कार्यकलापों के साथ देश के शिक्षा संस्थानों के नेटवर्क में विशेष स्थान रखता है। यह देश में एक समावेशी और वहनीय शैक्षणिक रणनीति के उद्‌गम हेतु मार्ग प्रशस्त करने के लिए उत्तरदायी है।

नीपा की स्थापना आरंभिक रूप से फरवरी 1962 में यूनेस्को तथा भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौते के अंतर्गत शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों तथा पर्यवेक्षकों के लिये एशिया क्षेत्रीय केंद्र के रूप से हुई थी। इस केंद्र का मुख्य कार्य एशिया के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों तथा पर्यवेक्षकों के लिये शैक्षिक योजना, प्रशासन तथा विद्यालय पर्यवेक्षण से संबंधित समस्याओं पर अनुसंधान तथा अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन तथा सदस्य राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करना था।

1 अप्रैल 1965 से शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों तथा पर्यवेक्षकों के लिये एशिया क्षेत्रीय केंद्र का नाम बदलकर एशिया शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान कर दिया गया। यूनेस्को तथा भारत सरकार के बीच दस वर्ष के समझौते के समाप्त होने के बाद, एशिया संस्थान को भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया और तत्पश्चात 1970 में शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के लिये राष्ट्रीय स्टाफ कालेज की स्थापना की गई। पुनः इस कालेज का पुनर्गठन किया गया और 31 मई 1979 को इसका विस्तार करते हुये इसको राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) के रूप में पुनः पंजीकृत किया गया।

शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में नीपा द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुये संस्थान को वर्ष 2006 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत इसे 'मानित विश्वविद्यालय' का दर्जा प्राप्त हुआ जिसके अंतर्गत इसे डिग्री प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई और पुनः नाम परिवर्तन के बाद इसे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) कहा जाने लगा। इसे आगे 'राष्ट्रीय विश्वविद्यालय' के नाम से भी संबोधित किया जायेगा। अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह यह पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

दिनांक 30.11.2017 की अधिसूचना संख्या फा.सं. न्यूपा/प्रशासनिक/आरओ/परिपत्र/030/2017 के द्वारा **राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा)** का नाम परिवर्तन **राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) (मानित विश्वविद्यालय)** के रूप में कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 10 नवंबर 2017 और 29 नवंबर 2017 के संप्रेषित पत्राचार सं. एफ. 5–1/2017(सी.पी.पी.–I/डी.यू.) द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 'विश्वविद्यालय' शब्द के स्थान पर 'संस्थान' शब्द रख दिया गया है।

नीपा का विज़न और मिशन

संस्थान का उद्देश्य 'ज्ञान के उन्नयन से एक मानवीय अधिगम समाज का निर्माण करना है'। इस विज़न के अंतर्गत संस्थान शैक्षिक नीति, उच्च स्तरीय शिक्षण के साथ योजना तथा प्रबंधन, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में सेवायें प्रदान करने हेतु मिशन के रूप में कार्य कर रहा है।

संस्थान का उद्देश्य 'ज्ञान के उन्नयन से एक मानवीय अधिगम समाज का निर्माण करना है'। इस विज़न के अंतर्गत संस्थान शैक्षिक नीति, उच्च स्तरीय शिक्षण के साथ योजना तथा प्रबंधन, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में सेवायें प्रदान करने हेतु मिशन के रूप में कार्य कर रहा है।

संस्थान के मुख्य कार्यनीतिक उद्देश्य निम्नांकित हैं :

- शैक्षिक क्षेत्र के विकास लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी नीतियों, योजना तथा कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय तथा संघ क्षेत्रों के स्तर पर सांस्थानिक क्षमता का सुदृढ़ीकरण तथा स्कूल, समुदाय, जिला, राज्य/संघ प्रदेशों तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक त्वरित, सहभागिता और जवाबदेह शैक्षिक अभिशासन तथा प्रबंधन प्रणाली का सांस्थनीकरण।
- शैक्षिक सुधारों का अनुसमर्थन करने और शिक्षा क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों की प्रभावी योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुश्रवण को बढ़ावा देने के प्रयोजन से अपेक्षित ज्ञान और कौशलों से सुसज्जित शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्र में युवा पेशेवरों सहित और शिक्षाविदों सहित विशेषीकृत मानव संसाधनों के समूह का विस्तार करना;
- शैक्षिक क्षेत्र में उभरती तथा वर्तमान चुनौतियों का सामना करने हेतु तथ्य आधारित जवाबदेही एवं प्रभावी कार्यक्रम क्रियान्वयन को बढ़ावा देने हेतु शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रशासन एवं संबंधित विषयों के ज्ञान आधार में वृद्धि;
- शैक्षिक क्षेत्र विकास लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन व्यवहार तथा बेहतर शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन हेतु शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन व्यवहार, अनुसंधान परिणामों, नवाचारों तथा सर्वोत्तम व्यवहार समेत सूचना तथा ज्ञान की साझेदारी एवं पहुंच में सुधार;
- अंतरशास्त्रीय जिज्ञासाओं को प्रोत्साहन देते हुये शैक्षिक नीति निर्माण, शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन व्यवहार/तकनीक शिक्षा के सभी चरणों तथा व्यवस्था में, तथा रणनीतिक उपागम शैक्षिक योजना प्रक्रियाओं, अभिशासन तथा प्रबंधन में सुधार हेतु तथा अंतरशास्त्रीय जिज्ञासाओं में नेतृत्वकारी भूमिका जो शैक्षिक नीति–निर्माण तथा देश में शैक्षिक योजना तथा प्रशासन व्यवहार का निर्माण करती है।

मुख्य कार्य

अपने मिशन को पूरा करने के उद्देश्य से संस्थान निम्नांकित मुख्य कार्यों में संलग्न है :

- शिक्षा के सभी चरणों में शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रबंधन में नेतृत्वकारी भूमिका प्रदान करना;
- सर्वोत्तम प्रशिक्षित शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के कैडर के गठन हेतु प्री–डाक्टरल, डॉक्टरल तथा पोस्ट डॉक्टरल कार्यक्रमों और व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों सहित अध्यापन के विकसित अंतरशास्त्रीय कार्यक्रमों का विकास तथा आयोजन और साथ में शैक्षिक नीतियों योजना तथा कार्यक्रमों की रूपरेखा, क्रियान्वयन, अनुश्रवण हेतु सतत् सांस्थानिक क्षमता का निर्माण करना;
- शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनुसंधान एजेंडा तथा वचनबद्धता को स्वरूप देना, क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिये आवश्यक समर्थन हेतु नये ज्ञान का सृजन तथा तथ्य आधारित नीति निर्माण और बेहतर शैक्षिक योजना और प्रबंधन व्यवहार/तकनीक का प्रयोग करना;
- केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थानों को उनकी शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन से संबंधित क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु तकनीकी समर्थन प्रदान करना और उन्हें शैक्षिक नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों की रूपरेखा, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन में सुधार हेतु मदद करना;
- शैक्षिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा निर्माण हेतु राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों को परामर्श सेवायें प्रदान करना;
- शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान तथा नवीन ज्ञान के सृजन हेतु सूचना तथा विचारों के समाशोधन गृह के रूप में कार्य, शैक्षिक नीतियों, योजना तथा प्रशासन में विशेष रूप से, विचारों/अनुभवों के आदान–प्रदान तथा नीति–निर्माताओं, शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के बीच नीतिगत चर्चा हेतु विचार मंच प्रदान करना, प्रभावी नीतियों तथा शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन तकनीक/व्यवहार को शिक्षा क्षेत्र संबंधी चुनौतियों को सामना करने हेतु चिह्नित करना तथा शिक्षा क्षेत्र संबंधी विकास लक्ष्यों/उद्देश्यों को प्राप्त करना;
- शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन में सुधार हेतु संयुक्त प्रयासों/कार्यक्रमों तथा अनुसंधान अध्ययनों को प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अंतर्गत कार्यक्रमों, निधि एवं एजेंसियों समेत राष्ट्रीय

तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों एवं संगठनों के साथ नेटवर्किंग तथा सहयोग;

- शैक्षिक क्षेत्र के विकास में उभरती हुई प्रवृत्तियों का मूल्यांकन तथा विश्लेषण, शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन में उभरती हुई चुनौतियों की पहचान तथा शैक्षिक क्षेत्र के विकास लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त नीति निर्माण तथा कार्यक्रम हस्तक्षेप के निर्माण को सुगम बनाने के लिए शैक्षिक क्षेत्र विकास लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रगति का मूल्यांकन।

संस्थान के उपरोक्त कार्य राज्य तथा संघशासित प्रदेश एवं केंद्रीय स्तर पर सरकारों तथा संस्थानों के साथ निकटतम संपर्क तथा सहयोग द्वारा आयोजित किये जाते हैं। उच्च स्तरीय शिक्षा के साथ संस्थान कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन एवं शिक्षा व्यवस्था की योजना तथा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है। संस्थान का एक मुख्य पहलू जमीनी स्तर पर संस्थान का संबंध द्वि–रूप कार्य प्रणाली है। संस्थान अपने ज्ञान आधार में वृद्धि वास्तविकता क्षेत्र में अनुसंधान तथा क्षेत्र कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल, कालेज, राज्य तथा केंद्रीय सरकार के विभिन्न स्तरों पर विभागों के साथ संपर्क द्वारा करता रहा है। संस्थान के रूप में, संस्थान राज्यों/संघशासित प्रदेशों की शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन संबंधी क्षमता निर्माण को पूर्ण करने हेतु संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण, राज्य सरकारों तथा राज्य संस्थानों के साथ निकटवर्ती संपर्क, उनकी शैक्षिक व्यवस्था का समालोचनात्मक अध्ययन, नीतियां तथा कार्यक्रम एवं उन्हें व्यावसायिक परामर्श तथा तकनीकी समर्थन हेतु प्रयासरत है। संस्थान अपने ऐसे कार्यक्रमों की शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्र में एक थिंक टैंक (प्रसार केन्द्र) बना हुआ है। संस्थान अपने अधिकांश क्षमता निर्माण के कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी विशेषज्ञता, अनुभव और अन्तर्दृष्टि जमीनी स्तर के शैक्षिक कार्यकर्त्ताओं को हस्तान्तरित कर रहा है। इस प्रकार से संस्थान की इस दोहरी भूमिका ने अपने अध्यापन तथा अनुसंधान के अकादमिक कार्य को व्यापक प्रामाणिकता प्रदान की है।

अकादमिक ढांचा तथा समर्थन सेवाएं

संस्थान के अकादमिक ढांचे में विभाग, केंद्र, विशेष पीठ हैं जो शिक्षा के विशिष्ट पक्षों तथा तकनीकी समर्थन एकक/समूह तथा अकादमिक समर्थन प्रणाली अपने संबंधित विषयगत क्षेत्रों से जुड़ी विकास तथा क्रियान्वयनकारी गतिविधियों के प्रति उत्तरदायी हैं। संस्थान के संकाय में प्रोफेसर, सह–प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर तथा राष्ट्रीय अध्येता सम्मिलित हैं जो शिक्षा नीति, योजना तथा प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। प्रत्येक विभाग अंतरशास्त्रीय विषयों के आधार पर संयोजित है और वे ज्ञान, विद्वता तथा अन्य अध्ययन कार्यक्रमों और अनुसंधान क्षेत्रों, सामान्यतः शिक्षा, और विशेष रूप से शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रबंधन में विशेष तौर पर संसाधन प्रदान करते हैं। प्रत्येक विभाग के पास अनुसंधान/परियोजना सहायकों तथा अनुसचिवीय कर्मचारियों के अतिरिक्त विषय विशेषज्ञ के रूप में संकाय सदस्य हैं। अकादमिक विभाग का अध्यक्ष प्रोफेसर होता है। विभाग विभिन्न प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रमों के निष्पादन और विकास तथा उनको प्रदान किये गये क्षेत्रों में परामर्श तथा सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के अंतर्गत, संस्थान के अकादमिक कार्यक्रमों का आयोजन आठ अकादमिक विभागों तथा विशेष पीठ स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक, परियोजना प्रबंधक एकक, भारत–अफ्रीका शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (आई.ए.आई.ई.पी.ए.) तथा दो केंद्रों द्वारा किया गया जिन्हें अकादमिक तथा प्रशासनिक सेवा एककों द्वारा समर्थन प्रदान किया गया।

अकादमिक संगठन

विभाग

- शैक्षिक योजना
- शैक्षिक प्रशासन
- शैक्षिक वित्त
- शैक्षिक नीति
- विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा
- उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा
- शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली
- शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास

केन्द्र

- राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केन्द्र
- उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केन्द्र
- राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केन्द्र

एकक

- विद्यालय मानक एवं मूल्यांकन एकक

आईएआईईपीए

- भारत–अफ्रीका शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान

समर्थन सेवाएं

- पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र
- कंप्यूटर केन्द्र
- प्रकाशन एकक
- परियोजना प्रबंधन एकक
- डिजीटल अभिलेखागार
- प्रशिक्षण कक्ष/ हिन्दी कक्ष

पीठ तथा राष्ट्रीय अध्येता

- मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पीठ
- अध्यापक विकास और प्रबंधन पीठ
- नीपा राष्ट्रीय अध्येता

अकादमिक विभाग

शैक्षिक योजना विभागः केंद्रीकृत नियोजन से हटकर विकेंद्रीकृत योजनाओं पर बल के साथ, नीपा के प्रमुख विभागों में से एक यह विभाग, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत योजना के आगतों, प्रक्रियाओं, और उत्पादों के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। पारंपरिक अर्थों में व्यापक योजना से हटकर आज, आर्थिक उदारीकरण की पृष्ठभूमि में, ध्यान रणनीतिक योजना पर स्थानांतरित हो गया है। हाल के दिनों में, गरीबी कम करने और स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक साधन के रूप में शिक्षा पर दबाव के साथ न केवल शैक्षिक योजना का दायरा समष्टि स्तर पर रणनीतिक योजना के संस्थानीकरण को समेकित करना है बल्कि विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देने और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्कूल मैपिंग, सूक्ष्म नियोजन और स्कूल सुधार योजना के रूप में स्थानीय स्तर की योजना तकनीकों का प्रयोग करना भी है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निकायों को परामर्श उपलब्ध कराने के साथ–साथ शिक्षण और प्रशिक्षण, शैक्षिक योजनाकारों के पेशेवर विकास, अनुसंधान और क्षमता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। विभाग शैक्षिक विकास में पहल का निदान और मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ा विश्लेषण और संकेतकों के प्रयोग हेतु शिक्षा पदाधिकारियों की क्षमताओं में सुधार करने में लगा हुआ है। विभाग एम.फिल. और पीएच.डी. के विभिन्न केंद्रिक और वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के संचालन, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में राष्ट्रीय डिप्लोमा (डेपा) और अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा) शिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में योगदान देता है।

शैक्षिक प्रशासन विभाग

शैक्षिक प्रशासन विभाग मुख्य रूप से सभी शैक्षिक स्तर और शाखाओं को समाहित करते हुए प्रशासन और प्रबंधन के विविध आयामों अनुसंधान, अध्ययन, प्रशिक्षण तथा प्रचार–प्रसार में सक्रिय रूप से संलग्न है। विभाग का एक मुख्य शैक्षिक क्षेत्र सरोकार एक समृद्ध ज्ञान आधार का विकास करना और शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंधन के विविध आयामों पर शैक्षिक प्रशासकों तथा शोधार्थियों को एक मजबूत पेशेवर अनुसमर्थन का निर्माण करना है। अपने लक्ष्य के अनुसार विभाग शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन पर ठोस ज्ञान के आंकड़ा आधार का निर्माण किया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान विभाग ने कई अध्ययन किये और एक बड़े पैमाने पर शैक्षिक प्रशासन के तीसरे अखिल भारतीय सर्वेक्षण, शैक्षिक प्रशासन में नवाचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना और जिला एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन के आयोजन के साथ कई दूरगामी और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किये। कार्यशालाओं, सम्मेलनों एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से विभाग ने राज्यों और भारत के केन्द्र शासित प्रदेशों भर में करीब एक हजार तीन सौ राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर की शिक्षा अधिकारियों तक अपनी पहुंच बनाई। विभाग ने जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों के लिए नवाचार पर राष्ट्रीय पुरस्कार योजना का क्रियान्वयन किया।

शैक्षिक वित्त विभाग

इस विभाग का दोहरा उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों– राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा विश्वस्तर पर आर्थिक तथा वित्तीय पक्ष पर अनुसंधान करना तथा उसे प्रोत्साहित करना है तथा विकासशील देशों और भारत में शिक्षा क्षेत्र की वित्तीय योजना तथा प्रबंधन से जुड़े कर्मियों के क्षमता निर्माण और ज्ञान का सृजन करना है। विभाग के कार्यक्रम/गतिविधियां– अनुसंधान, अध्यापन, प्रशिक्षण तथा परामर्श हैं जो नीति, योजना तथा विकास, शिक्षा के सार्वजनिक तथा निजी वित्त पोषण, सरकारी तथा निजी संसाधनों की लामबंदी, शिक्षा के सभी स्तरों पर संसाधनों का आवंटन तथा उपयोग, प्राथमिक से उच्च, तथा संसाधन आवश्यकताओं के आकलन से

जुड़े मुद्दों के इर्द–गिर्द केंद्रित हैं। अधिकांशतः शोध के क्षेत्र शिक्षा के वित्त पोषण, कार्यक्रम और नीतिगत मुद्दों से संबंधित हैं। परामर्शकारी सेवाएँ नीतिगत मुद्दों पर केंद्रित हैं। अध्यापन के विषय में शिक्षा का अर्थशास्त्र और शैक्षिक वित्त पोषण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम के विषय योजना तकनीक और प्रबंधन प्रणाली पर आधारित हैं।

शैक्षिक नीति विभाग

शैक्षिक नीति विभाग शैक्षिक अभिशासन और प्रबंधन में वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए शैक्षिक नीति का अध्ययन, शैक्षिक समस्याओं का मूल्यांकन और विश्लेषण, नीति तथा व्यवहारों का मार्गदर्शन तथा परिणामों को समझने के लिए प्रतिबद्ध है। चूँकि अपने मिशन में यह प्रतिबद्ध है, शैक्षिक क्षेत्र में प्रासंगिता और गुणवत्ता, समता, पहुँच जैसे अवरोधकों के प्रति ज्ञान के वर्धन में, इसलिए यह विभाग समय–समय पर विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर हितधारकों, व्यवहारकर्त्ताओं तथा भारत में शैक्षिक व्यवस्था को प्रमाणित करने वाली जननीति मुद्दों पर चर्चाएं आयोजित करता है। उपरोक्त मुद्दों के साथ शैक्षिक अनुसंधान और शैक्षिक नीति के बीच शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन अधिगम और प्रदर्शन के बेहतर लिंकेज को स्थापित करने हेतु यह विभाग अनुसंधान पर बल देता है। अनुसंधान का उद्देश्य केवल शैक्षिक प्रतिभास की जटिलताओं को दर्शाना ही नहीं होता। बल्कि कार्रवाई के लिए संस्तुतियों को प्रदान करना भी होता है। समाज में वर्तमान परिवर्तनों और शिक्षा पर इसके प्रभाव को देखते हुए, विभाग समय–समय पर हितधारकों द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए गुंज–यंत्र के रूप में कार्य करता है। विभाग योजनाकारों, प्रशासकों, क्रियान्वयनकर्त्ताओं तथा विद्वानों के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करता है जिससे कि वे वर्तमान ढांचे, प्रक्रियाओं और भारत में संगठित शिक्षा के सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभावी और नैतिकता से कार्य कर सकें।

विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग

विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग व्यापक रूप से अधिकार–आधारित और समेकित ढांचे के अंतर्गत–स्कूल शिक्षा, अनौपचारिक और प्रौढ़ साक्षरता से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष बल देता है। यह गुणवत्ता, समता, सामाजिक न्याय और समेकन की सैद्धांतिक समझ विकसित करने का प्रयास करता है। यह विभाग संस्थान के रूप में स्कूलों और स्कूल तथा अनौपचारिक शिक्षा में हो रहे बदलावों पर नीतियों तथा व्यावहारिक हस्तक्षेपों हेतु अनुभवजन्य आधार प्रदान करने के उद्देश्य से शोध अध्ययन करता है। यह विभाग शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम एवं एम.फिल, पी–एच.डी. के कुछ पाठ्यक्रमों के अध्यापन सहित राज्य, जिला स्तर के अधिकारियों के लिये कार्यशालाएं और क्षमता विकास के कार्यक्रम आयोजित करता है। यह योजनाओं तथा नीतियों के अध्ययन तथा निर्माण में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। यह विभाग सह–क्रियात्मक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ अनुभव और विशेष क्षमता साझा करता है। वर्तमान में व्यावहारिक कारणों के मद्देनजर यह विभाग कमोबेस सीमित चार क्षेत्रों–अधिकार आधारित ढांचे के अंदर स्कूली शिक्षा में समता गुणवत्ता और समावेशन, अध्यापक विकास और प्रबंधन, स्कूल नेतृत्व एवं स्कूली मानकों के मूल्यांकन पर विशेष बल दे रहा है। संकाय के सदस्य राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र में भी कार्य करते हैं और विद्यालय मानक और मूल्यांकन एकक में भी संबद्ध हैं।

उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग

यह विभाग वर्षों से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को लगातार अनुसंधानात्मक अनुसमर्थन और नीतिगत सुझाव प्रदान करता रहा है। विभाग के विश्व व्यापार संगठन कक्ष ने गेट्स के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों के विश्लेषण और भारत की सहमति की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। विभाग ने उच्चतर शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के विविध आयामों पर अध्ययन किया और उन पर विमर्श हेतु संगोष्ठियां आयोजित की तथा उनके निष्कर्षों का प्रसारण किया। यह विभाग उच्चतर शिक्षा के लिये विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देने में सहयोग करता रहा है। यह विभाग विशेषज्ञों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संकायाध्यक्षों और कुलसचिवों के सम्मेलन और संगोष्ठियों के आयोजन में यू.जी.सी. का सहयोग करता रहा है। इस विभाग ने कार्य निष्पादन आधारित उच्चतर शिक्षा पर विश्व

सम्मेलन आयोजित करने हेतु यूनेस्को क्षेत्रीय सम्मेलन के आयोजन ओर भारतीय उच्चतर शिक्षा में कार्य निष्पादन आधारित वित्त पोषण पर योजना आयोग – विश्व बैंक प्रायोजित संगोष्ठी के आयोजन में भी सहयोग किया है। वार्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत यह विभाग विभिन्न श्रेणियों के कॉलेज प्राचार्यों के लिये नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। विभाग विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच के विभिन्न आयामों तथा अकादमिक सुधार पर संगोष्ठियां आयोजित करने में अकादमिक समर्थन प्रदान करता है। विभाग राष्ट्रीय संस्थान के शैक्षणिक कार्यक्रम– एम.फिल. तथा पी–एच.डी. कार्यक्रमों के केंद्रिक तथा वैकल्पिक पाठ्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और इसके शोधार्थियों का अतिरिक्त शोधनिर्देशन कर रहा है।

शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विभाग

यह विभाग शैक्षिक प्रशासकों की क्षमता में सुधार के लिये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर सहसंबंध विकसित करने पर विशेष बल देता है। शिक्षा विभाग में प्रशिक्षित दलों का वृहद सृजन हेतु विभाग स्थायी और समर्पित सांख्यानिक प्रबंधन को सृजित करने के उद्देश्य से राज्य संस्थानों को सशक्त बनाने हेतु कार्यक्रमों की संरचना तैयार करता है। चरणबद्ध तरीके से पूरे राष्ट्र में डी.ई.ओ. / बी.ई.ओ. के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सम्मेलनों के द्वारा देश में जारी शैक्षिक सुधार नीतियों और कार्यक्रमों की स्पष्टता हेतु आधारभूत स्तर पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम विषयगत और संवर्ग आधारित पाठ्यक्रम होते हैं, विशेषतौर से अधिष्ठापन और प्रोन्नत स्तर पर।

इसके अलावा यह विभाग लंबी अवधि के दो डिप्लोमा कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय और दूसरा अंतरराष्ट्रीय शिक्षा कर्मियों के लिये आयोजित करता है। शैक्षिक योजना और प्रशासन में राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित करता है तथा शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम भी वार्षिक रूप से आयोजित करता है।

यह विभाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में क्षमता निर्माण रणनीति और प्रशिक्षण में अनुसंधान करता है। स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर के प्रशासकों और क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के विभिन्न संवर्ग की शैक्षिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं के मूल्यांकन पर इसका मुख्य बल होता है।

शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग

शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग शोध और क्षमता विकास संबंधित कार्य करता है और भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों की शिक्षा का आंकड़ा आधार और प्रबंधन सूचना प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए तकनीकी परामर्श देता है। यह विभाग भारत में प्रारंभिक शिक्षा की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) और आंकड़ा आधार को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूनीसेफ के सहयोग से जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डाइस) का प्रबंधन करता है। इसके अलावा यह विभाग शैक्षिक सांख्यिकी के मुद्दों और शिक्षा के समकालीन मुद्दों पर सम्मेलन / संगोष्ठियां और शैक्षिक योजना में मात्रात्मक विधियों पर कार्यशालाएं / प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और सांख्यिकी तथा शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली पर परामर्श प्रदान करता है। विभाग के संकाय सदस्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूल शिक्षा सांख्यिकी की एकीकृत प्रणाली के निर्माण हेतु गठित विशेषज्ञ समिति में सक्रिय रूप से शामिल हैं। तद्नुसार स्कूल शिक्षा सांख्यिकी की एकीकृत प्रणाली की दिशा में वर्ष 2012–13 से देशभर में समान आंकड़ा प्रपत्र में पहले कदम के रूप में डाइस और सेमीस का समेकित आंकड़ा संगृहित किया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान स्कूल शिक्षा प्रदान कर रहे 1.5 मिलियन स्कूलों से आंकड़ा एकत्र किए गए। विभाग द्वारा आयोजित कुछ कार्यक्रमों / संगोष्ठियों / कार्यशालाओं के विषय हैं :

एजुसेट द्वारा डाइस पर संवेदनशीलता कार्यक्रम, शैक्षिक शोध में डाइस आंकड़ों का उपयोग और स्कूल शिक्षा सांख्यिकी की एकीकृत प्रणाली आदि। यह विभाग विकासशील देशों के लिए ईएमआईएस पर सुनियोजित पाठ्यक्रम के साथ–साथ पीजीडेपा के भाग के रूप में शैक्षिक योजना में मात्रात्मक विधि पर पाठ्यक्रम का अध्यापन करता है। विभाग का संकाय ईएमआईएस और स्कूली शिक्षा से संबंधित पक्षों पर भारत सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों को परामर्शकारी सेवाएं प्रदान करता है।

विशेष पीठ

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पीठ

यह पीठ स्वतंत्र भारत के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के पहले मंत्री मौलाना आज़ाद के योगदान को स्मरण करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2008 में नीपा में स्थापित किया गया है। पीठ का मुख्य अनुसंधान क्षेत्र 1950 के दशक के अंतिम वर्षों के दौरान मौलाना आजाद के योगदान की खोज करते हुए एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के विकास पर अध्ययन करना है। यह पीठ राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष, मौलाना आजाद स्मारक व्याख्यान का आयोजन करता है। यह पीठ मौलाना आज़ाद के दर्शन और वैश्विक विचारों व अन्य संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन भी करता है।

अध्यापक विकास और प्रबंधन पीठ

राजीव गांधी स्थापना पीठ, अध्यापक विकास और प्रबंधन पीठ जून 2013 से प्रारंभ हुआ। यह भारत भर में प्रबंधन प्रणालियों और अध्यापक विकास की प्रभाविकता में सुधार करने हेतु नीतियों तथा आचरण का विकास के लिए विश्लेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने की अभिव्यक्ति है।

प्रावधान, आवंटन और शिक्षा प्रणालियों की मांगों को पूरा करने के लिए अध्यापकों का उपयोग, प्रभावी ढंग से कार्य निष्पादन हेतु वर्तमान शिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा करना; और व्यवसायीकरण और स्कूल/संस्थागत नेतृत्व का क्षमता विकास अंत:संबंध है। हालांकि, यहाँ एक सुसंगत नीति और कार्यक्रम रूपरेखा की कमी है जो उन्हें एक साथ जोड़ सकें और ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर शिक्षक विकास और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित मुद्दों को संबोधित कर सकें। प्रोफेसर विमला रामचंद्रन को आर.जी.एफ. पीठ का प्रोफेसर प्रभारी नियुक्त किया गया है।

पीठ की विशेष गतिविधियों में शामिल हैं:

- विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षकों और संबंधित शैक्षिक प्रबंधन मुद्दों की कार्यशील स्थितियों पर स्वतंत्र और सहयोगात्मक अनुसंधान। यह आशा की जाती है, सूचित निर्णय लेने और नीतियों के सुसंगत ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक ज्ञान के आधार को समृद्ध करेगा।
- राज्य मंत्रालयों और अन्य राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के संस्थानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना ताकि उन्हें शिक्षक विकास और प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करने में मदद मिल सके।

- अनुमोदित कार्यक्रम हस्तक्षेप में शामिल हितधारकों और राज्य स्तरीय शिक्षा प्राधिकरणों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर नीतिगत संवाद को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना।
- प्रलेखन और ज्ञान एवं सूचना की जानकारी का प्रचार–प्रसार, शोध निष्कर्षों समेत, सर्वोत्तम प्रथाओं और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हितधारकों के बीच नवाचारों सहित सूचित निर्णय लेने की सुविधा।
- प्रभावी शिक्षक विकास और प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के लिए समर्थन।

दो परियोजनाएं चल रही हैं:

नौ राज्यों में प्रारंभिक और माध्यमिकः इन दो स्तरों पर सरकारी स्कूलों में सभी श्रेणियों के कार्यरत शिक्षकों (नियमित और अनुबंध शिक्षकों) के लिए काम की परिस्थितियों, वेतन तथा व्यवहार, तैनाती की नीतियों का दस्तावेजीकरण और विश्लेषण (स्थानान्तरण, पोस्टिंग, व्यावसायिक विकास और विकास) सरकार के अधिसूचना, आदेश और शिक्षक प्रबंधन में शामिल महत्वपूर्ण प्रशासकों के साथ राज्य–स्तरीय क्षेत्र–आधारित अध्ययनों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें सरकारी सूचनाओं, शिक्षकों के प्रबंधन में शामिल प्रमुख प्रशासकों के आदेश, साक्षात्कार शामिल हैं।

केंद्र

राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र

राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केन्द्र (एनसीएसएल) विद्यालयों के रूपांतरण की वचनबद्वता के साथ 2012 में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान में स्थापित किया गया था। एनसीएसएल के लिए प्रमुख प्राथमिकता स्कूल परिवर्तन को तैयार करना है। एनसीएसएल–नीपा देश भर में 6500 ब्लॉक, 679 जिलों तथा 35 राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में नेतृत्व आवश्यकता और संदर्भित स्कूल मुद्दों को संबोधित करता है। प्रत्येक राज्य में प्रत्येक स्कूल के लिए परिवर्तन एजेंडा को लागू करने पर केन्द्र की सारी गतिविधियां आधारित हैं। केन्द्र अंतर संबंधी और व्यावहारिक नेतृत्व मॉडल के उद्भव पर बल देता है।

केंद्र का मकसद देश के प्रत्येक विद्यालय तक पहुंचना है, जिससे हर स्कूल उत्कृष्ट हो और हर बच्चा शिक्षित हो। इस मिशन को पूर्ण करने हेतु केन्द्र ने निम्नांकित चार घटकों को सम्मिलित किया है जो केंद्र की रूपरेखा की गतिविधियों में समाहित हैं। पाठ्यक्रम और सामग्री विकास, क्षमता निर्माण, नेटवर्किंग और संस्था निर्माण, अनुसंधान और विकास।

स्कूल नेतृत्व पर पारंपरिक लघु–कालिक कार्यक्रमों के विपरीत, केन्द्र ने स्कूल नेतृत्व गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की है जो स्कूल प्रमुखों और व्यवस्थित प्रशासकों को सतत संलग्नता तथा दीर्घकालिक विकास प्रदान करती है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल नेतृत्व पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा और पाठ्यचर्या विकास की संकल्पना की गई है। संपूर्ण कार्यक्रम व्यवहारकर्त्ता केंद्रित पाठ्यचर्या पर तैयार की गई है। जो कि राज्यों में स्कूलों के संदर्भित मुद्दों और बुनियादी आवश्यकताओं और विविधता को संबोधित करती है। पाठ्यचर्या रूपरेखा के अंतर्गत, स्कूल नेतृत्व विकास पर एक हस्तपुस्तिका विकसित की गई है जो कि एक समृद्ध संग्रह है और जो भविष्य की चुनौतियों का समना करने हेतु संभावित नेतृत्व की तैयारी और स्कूलों के रूपांतरण हेतु वर्तमान नेतृत्व को समक्ष करने के लिए एक संदर्भित रूपरेखा है।

उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र (सीपीआरएचई)

उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र (सीपीआरएचई) भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नीति अनुसंधान और समर्थन नीति और नियोजन को बढ़ावा देने के लिए संस्थान द्वारा एक विशेष संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। भारत में उच्च शिक्षा की योजना और नीति बनाने में एक विचार मंच के रूप में कार्य करने के लिए सीपीआरएचई का व्यापक मिशन है। केंद्र नीति, योजना की तैयारी में मदद और भारत में उच्च शिक्षा के विकास के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा के लिए अनुसंधान साक्ष्य के सृजन में योगदान की अपेक्षा रखता है। केंद्र वर्तमान राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर अपनी गतिविधियों और अनुसंधानों को केंद्रित करता है।

केंद्र की नियमित गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं: i) विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं का आयोजन; ii) नीतिगत संवादों का आयोजन; iii) इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्ट (आईएचईआर) का वार्षिक प्रकाशन; iv) एक चयनित विषय पर प्रतिवर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का संगठन; और v) प्रत्येक वर्ष एसएचईसी के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की बैठक का आयोजन। द्वितीय 'भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2016' (आईएचईआर 2016) उच्च शिक्षा में समता पर केंद्रित है। सेज, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है। तृतीय, भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2017 (आई.एच.ई.आर. 2017) शिक्षण, अधिगम और गुणवत्ता पर केंद्रित है तथा भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2018 (आई.एच.ई.आर. 2018) शिक्षा के वित्तपोषण पर केंद्रित है और प्रकाशनाधीन है।

गुणवत्ता, आश्वासन और उत्कृष्टता के संदर्भ में अनुभव और आचरण पर चर्चा हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नीपा, नई दिल्ली और ब्रिटिश काउंसिल ने संयुक्त रूप से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर संगोष्ठी आयोजित की। केन्द्र ने 'उच्च शिक्षा में वित्तपोषण में नवाचार', द्वारा प्रो. एन.वी. वर्गीज और प्रो. जिणुसा पाणिग्रही, सीपीआरएचई/नीपा नई दिल्ली, द्वारा रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सीपीआरएचई ने दो अनुसंधान आलेखों का प्रकाशन ''अनुसंधान आलेख श्रृंखला'' के अंतर्गत किया।

केंद्र द्वारा पूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं की रिपोर्ट जारी की है। केंद्र में निम्नलिखित शोध रिपोर्ट उपलब्ध हैं: उच्च शिक्षा में अध्यापक नियुक्तिः राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की भूमिका; उच्च शिक्षा के लिए नागरिक अधिगम और लोकतांत्रिक संवादः उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और भेदभाव पर अध्ययन; पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन के क्रियान्वयन का मूल्यांकन; उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों में एकाग्रता और अधिक आपूर्ति; राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप योजना का मूल्यांकन।

एकक

स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक

स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में स्कूल मानक और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (शाला सिद्धि) में अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। एडनेक्स्ट के भाग के रूप में – शाला सिद्धि को स्कूल शिक्षा में आईसीटी पर राष्ट्रीय सम्मेलन में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा शुरु किया गया था।

शाला सिद्धि कार्यक्रम गुणवत्ता सुधार के लिए स्कूल मूल्यांकन की दिशा में एक पहल है। इसका लक्ष्य ''स्कूल

मूल्यांकन'' का साधन और ''स्कूल सुधार'' के रूप में देखता है। कार्यक्रम जवाबदेही के साथ स्कूल सुधार के प्रति आन्तरिक और बाह्य मूल्यांकन के लिए प्रत्येक स्कूल को स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है। स्कूल सुधार के साक्ष्य आधारित प्रणाली, स्कूल के मानकों और मूल्यांकन ढांचे के आधार पर, प्रयास के एक नए क्षेत्र के रूप में, स्कूलों और शिक्षार्थियों की वृद्धिशील प्रगति की दिशा में स्कूलों के आत्म संलग्नकता पर महत्वपूर्ण जोर देता है। शाला सिद्धि कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य विकसित करना है, एक तकनीकी रूप से वैचारिक ढांचे, कार्यप्रणाली, साधन; भारतीय स्कूलों की विविधता के अनुरूप स्कूल मूल्यांकन की प्रक्रिया; प्रत्येक विद्यालय की क्षकता में निरंतर सुधार के लिए स्वयं को बेहतर बनाना। यह एकक शाला सिद्धि कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और संस्थागतकरण के लिए सभी राज्यों को समर्थन प्रदान कर रहा है।

एकक ने देश में शाला सिद्धि कार्यक्रम के विकास के लिए बहुत व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन किया। वैचारिक ढांचे को स्कूल मूल्यांकन पर आधारित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध के साक्ष्य द्वारा दृढ़ता से समर्थन किया जाता है। स्कूल मानकों और मूल्यांकन ढांचे, स्कूल मूल्यांकन डैशबोर्ड और दिशानिर्देशों का एक व्यापक पैकेज विकसित किया गया है और इसका उपयोग स्कूलों के स्वः और बाह्य मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इन सभी दस्तावेजों का अनुवाद और संदर्भ सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। स्कूल मूल्यांकन के व्यापक पैकेज और एक समर्पित वेब पोर्टल (आईटी सक्षम समर्थन) के विकास की अगली कड़ी के रूप में, शाला सिद्धि कार्यक्रम एक विस्तृत रणनीतिक योजना के बाद नीपा के शैक्षणिक समर्थन के साथ राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

वर्ष 2017–18 के दौरान, 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने मुख्य हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर शाला सिद्धि कोर टीमों का गठन किया और स्कूलों और अधिकारियों को सभी सामग्रियों का अनुवाद और संदर्भीकरण का वितरण किया। लगभग 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही स्कूल स्वःमूल्यांकन प्रक्रिया को लागू कर दिया है और शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर स्कूल मूल्यांकन डैश बोर्ड अपलोड कर दिया है।

स्कूली शिक्षा और सीखने के परिणामों की गुणवत्ता में

सुधार के लिए केंद्र के रूप में व्यापक स्कूल मूल्यांकन की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, शाला सिद्धि कार्यक्रम (स्कूल मूल्यांकन) ने स्कूल सुधार के लिए समग्र स्कूल मूल्यांकन की दिशा में गति उत्पन्न की है। यह प्रत्येक स्कूल को स्वः और बाह्य मूल्यांकन के लिए एक स्पष्ट रोड–मैप प्रदान करता है, जिससे जवाबदेही के साथ स्कूल सुधार प्रगति की ओर अग्रसर होता है। शाला सिद्धि कार्यक्रम की स्थिरता के लिए समय अवधि, तैयारियों, क्षमता निर्माण, सामग्री विकास, प्रणालीगत, वित्त और मानव संसाधन समर्थन की आवश्यकता होती है।

परियोजना प्रबंधन एकक (पी.एम.यू.)

संस्थान में परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) समर्थन और गृह स्तर प्रबंधन एवं प्रायोजित अनुसंधान के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

यह एकक शिक्षा नीति और शैक्षिक योजना एवं प्रशासन (व्यक्ति शोध) के क्षेत्र में अध्ययन के लिए नीपा सहायता योजना के कार्यान्वयन हेतु नीपा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अध्ययन सेमिनार, मूल्यांकन आदि के लिये अनुदान सहायता योजना विभाग के सभी बाह्य वित्त–पोषित और आंतरिक अनुसंधान परियोजनाओं के उचित समन्वय के लिये प्रशासन की एक केन्द्रीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

यह एकक सामान्य रूप से, परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिये परियोजना कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी और संबंधित समर्थन सेवाएँ प्रदान करने सहित नीपा में किए गए विभिन्न परियोजनाओं के प्रबंधन के लिये प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। यह सभी मामलों में धन और घरेलू व्यय के लेखा सहित नीपा – परियोजना भर्ती और नियुक्तियों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है।

पीएमयू विभिन्न परियोजनाओं के लेखांकन, परियोजना स्टाफ की भर्ती, बजट के अलावा संस्थान में चल रहे और पूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं से संबंधित सभी कार्य की देखभाल करता है।

पीएमयू एकक में अध्यक्ष, कुलपति द्वारा चयनित किया जाता है। इसके अलावा पांच अन्य अकादमिक तथा समर्थन स्टाफ भी चयनित किये जाते हैं। समर्थन स्टाफ में परियोजना परामर्शदाता, परियोजना प्रबंधक तथा कनिष्ठ परामर्शदाता सम्मिलित हैं।

भारत अफ्रीका संस्थान

भारत अफ्रीका शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (आई.ए.आई.ई.पी.ए) :

भारत अफ्रीका शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान अप्रैल 2008 में आयोजित भारत–अफ्रीका मंच सम्मेलन के संकल्पों के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई कार्यवाई योजना के ढांचे के अंतर्गत स्थापित एक अखिल अफ्रीकी संस्था है। यह संस्थान बुरूण्डी गणराज्य की राजधानी बुजुम्बुरा में स्थित है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा), भारत सरकार की तरफ से आईएआईईपीए की स्थापना, संचालन तथा प्रबंधन संबंधी कार्य कर रहा है। इस संस्थान का मुख्य कार्य क्षमता विकास करना है। इसके शैक्षणिक कार्यक्रमों/गतिविधियों का प्रथम चरण भवन नवीनीकरण और परिसर विकास संबंधी अन्य गतिविधियों के पूरा होने के तीन–चार माह बाद ही शुरु करने का प्रस्ताव है।

इसके प्रथम चरण में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल होंगी– (i) अफ्रीकी संघ सदस्य देशों की शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, (ii) शैक्षिक नीति शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में अफ्रीकी संघ सदस्य देशों की शिक्षा प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर शोध और केस अध्ययन, (iii) देश और क्षेत्र/महाद्वीप स्तरों पर शिक्षा के विकास की प्रवृत्तियों का विश्लेषण और आकलन, (iv) अफ्रीका संघ देशों को क्षमता विकास और शोध से संबंधित विशिष्ट शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करने में तकनीकी सहायता प्रदान करना, (v) अफ्रीकी संघ देशों में शैक्षिक योजना और प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए परस्पर अनुभवों और कार्य व्यवहारों को साझा करना, (vi) अफ्रीका और अफ्रीका के बाहर के शिक्षा शोध से जुड़े शोधकर्त्ताओं तथा संस्थानों का नेटवर्क बनाना, (vii) सामान्यतः शैक्षिक विभाग और विशेषकर अफ्रीका संघ सदस्य देशों में शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर नीतिगत परिसंवाद।

इसके प्रथम चरण के दौरान आयोजित कार्यक्रमों/गतिविधियों के विस्तार के साथ दूसरे चरण के दौरान संस्थान शैक्षिक योजना और प्रशासन पर लम्बी अवधि का उन्नत डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित करेगा जिसमें अफ्रीका संघ सदस्य देशों के प्रशिक्षित शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों में बढ़ोतरी के लिये समिश्रित उपागम पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे।

अकादमिक अनुसमर्थन सेवा एकक

पुस्तकालय और प्रलेखन केन्द्र :

संस्थान में एक अत्याधुनिक पुस्तकालय है जिसमें शैक्षिक नीति, शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रशासन और अन्य सहायक विषयों से संबंधित पुस्तकों और अन्य सामग्री का समृद्ध संग्रह है। पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र अपने पाठकों को विभिन्न सेवाएं जैसे–सीएएस, एसडीआई, संदर्भ सेवाएं वेब ओपैक, प्रसारण और फोटोकापी की सुविधाएं प्रदान करता है। पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर संसाधनों की साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डेलनेट का सदस्य भी है। वर्तमान में पुस्तकालय में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, जैसे–यूएनओ, यूएनडीपी, यूनेस्को, आईएलओ, यूनीसेफ, विश्व बैंक, ओईसीडी आदि द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों की रिपोर्टों के अलावा 59,208 से अधिक पुस्तकों/दस्तावेज़ों तथा 7,616 जर्नलों का समृद्ध संग्रह है। पुस्तकालय में शैक्षिक नीति, योजना और प्रबंधन तथा अन्य सहायक क्षेत्रों से संबंधित 250 जर्नल मंगाए जाते हैं। इसके अलावा पुस्तकालय पाठकों के लिए ऑन लाइन जर्नल डाटाबेस, जैसे–जेएसटीओआर, एलसेवियर और सेज भी मंगाता है। नीपा के प्रलेखन केंद्र में अधिकारिक रिपोर्टों, केंद्र तथा राज्य सरकारों के प्रकाशनों, शैक्षिक सर्वेक्षणों, पंचवर्षीय योजनाओं और जनगणना रिपोर्टों आदि सहित लगभग 17,993 दस्तावेज हैं। प्रलेखन केंद्र के पास महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें और शैक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हैं जो शैक्षिक शोध अेर नीति निर्माण के लिए जरूरी हैं। राष्ट्रीय संस्थान में एक डिजीटल अभिलेखागार बनाया गया है। भारत में शिक्षा के सभी क्षेत्रों, स्तरों और पक्षों पर शोध और संदर्भ के स्रोत के रूप में एक स्थान पर सभी दस्तावेजों की साफ्टकापी सुलभ करवाई जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य प्रयोक्ता समुदाय का निर्माण करना है जो कि संस्थान के कार्यों का एक विस्तार है। नवीनतम सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के रूप में उच्च स्तरीय स्वचालित डिजीटल स्कैन का उपयोग डिजाइन, संग्रह और डिजीटल दस्तावेजों की पुनः प्राप्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस डिजीटल अभिलेखागार में प्रयोक्ता सुलभ बहुखोजी विकल्पों के साथ अंतर्निहित उपयोगों सहित साफ्टवेयर उपलब्ध है।

वर्ष 2013 में शैक्षिक प्रलेखों का एक डिजीटल अभिलेखागार स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी शैक्षिक प्रलेखों को एक स्थान पर डिजीटल रूप में संग्रहित करना है। डिजीटल अभिलेखागार में 11,000 से अधिक अभिलेख संग्रहित हैं और सतत् इनकी संख्या में वृद्धि की जा रही है। प्रलेखों को मुख्यतः 18 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और इसी क्रम में आगे भी केंद्र, राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर उप वर्ग बनाए गये हैं। डिजीटल अभिलेखागार में आज़ादी के बाद से शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों तथा क्षेत्रों से संबंधित नीतिगत तथा अन्य अभिलेख सुलभ करवाए जाते हैं ताकि नीति विश्लेषकों, योजनाकारों, शोधार्थियों एवं अभिरुचि रखने वाले अन्य विद्वानों को एक स्थान पर आवश्यक सामग्री सुलभ करवाई जा सके और उन्हें संदर्भ सामग्री और आंकड़ों के लिए कहीं और नही जाना पड़े। डिजीटल अभिलेखागार नीपा का विस्तारित कार्य है जो प्रयोक्ता समुदाय को समर्पित है।

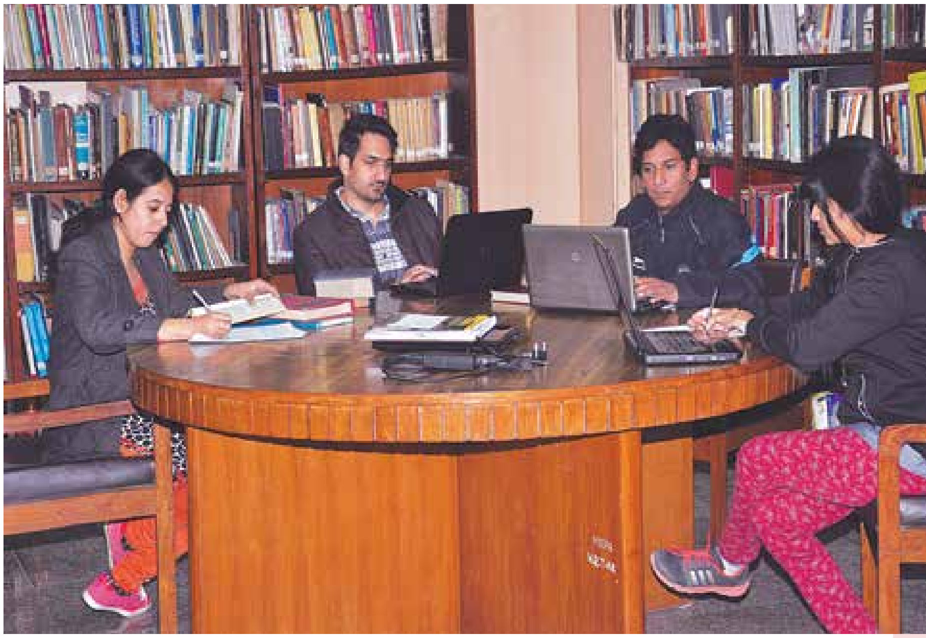

कंप्यूटर केंद्र : कंप्यूटर केंद्र संस्थान की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी जरुरतें पूरा करता है। यह केंद्र संस्थान के सभी प्रशिक्षणार्थियों और स्टाफ सदस्यों को कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान करता है। नेटवर्क संसाधन को पहुंचाने के लिए सभी संकाय और स्टाफ को नेटवर्क प्वाइंट सुलभ किए गए हैं। नीपा डोमेन से सभी संकाय और स्टाफ सदस्यों के व्यक्तिगत ई–मेल खाता खोले गए हैं। सभी संकाय सदस्यों को 1 जीबीपीएस की इंटरनेट कनेक्टिविटी दी गई है। सभी स्टाफ सदस्यों को डेस्कटॉप और संकाय सदस्यों को लैपटाप आवंटित किए गए हैं। संस्थान में समुचित नेटवर्क सुरक्षा का रखरखाव किया जा रहा है। केद्र में आधुनिकतम सुविधाएं हैं, जैसे–आईबीएम–ई सिरीज सर्वर जो तीव्र अर्थनेट से जुड़ा है। वर्तमान में निम्नलिखित आधारभूत सुविधाएं हैं–उन्नत कैट–6 केबल, केंद्रीकृत कंप्यूटिंग सुविधा, जिसमें उच्च कार्यनिष्पादन वाले सर्वर्स, क्लाइंट पी सी, इंटरनेट से अपलिंक और अन्य सेवाएं और अति सक्षम बहुकल्पिक यू पी एस के जरिए पर्याप्त रूप में अनवरत पावर आपूर्ति उपलब्ध है।

प्रकाशन एकक : संस्थान में शिक्षा के शोध और विकास के प्रसार–प्रचार हेतु प्रकाशन कार्यक्रम है। नीपा प्रकाशन एकक विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अन्य संबंधित सामग्रीरिपोर्टों, पुस्तकों, जर्नलों, न्यूज़लेटर, अनुसंधान आलेखों, तथा अन्य प्रकाशनों के माध्यम से शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रशासन से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास की सूचनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। संस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं : जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 'परिप्रेक्ष्य' हिन्दी जर्नल तथा एंट्रीप न्यूज़लेटर। संस्थान का प्रकाशन एकक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी पूर्ण करता है।

हिंदी कक्ष : यह कक्ष शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन में व्यावसायिक प्रकाशनों के अनुवाद के माध्यम से अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा प्रसार में अकादमिक सहायता प्रदान करता है। यह कक्ष राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में भी प्रशासन और संकाय को सहयोग देता है।

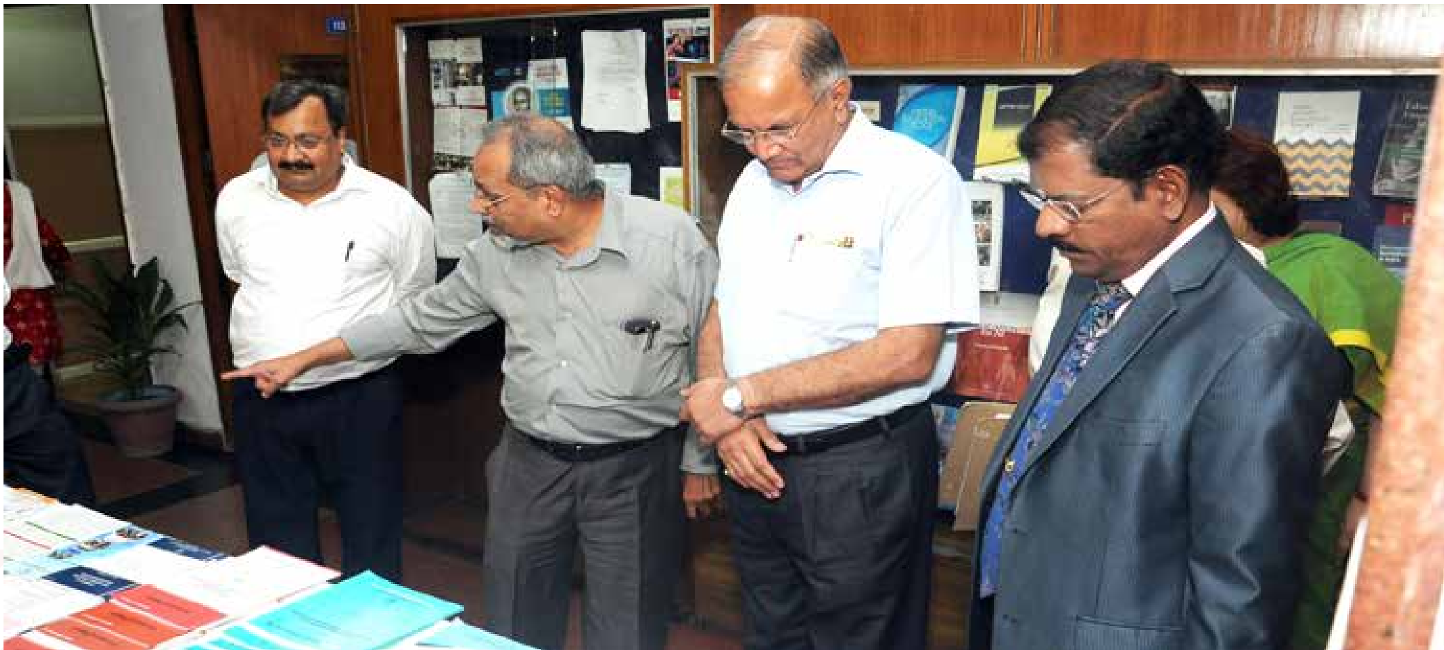

अभिशासन और प्रबंधन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत घोषित एक मानित विश्वविद्यालय है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। इस संस्थान के प्राधिकारियों में शामिल हैं : अध्यक्ष, कुलाधिपति, कुलपति, परिषद, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद, वित्त समिति और अध्ययन बोर्ड तथा विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड द्वारा घोषित ऐसे अन्य प्राधिकरण। संस्थान के कुलपति प्रधान शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी हैं।

नीपा परिषद : नीपा परिषद संस्थान का सर्वोच्च निकाय है जिसका प्रमुख अध्यक्ष होता है। परिषद का मुख्य कार्य कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित राष्ट्रीय संस्थान के लक्ष्यों को कार्यान्वित करना है। नीपा परिषद संस्थान के सभी मामलों के सामान्य पर्यवेक्षण का उत्तरदायी है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार नीपा परिषद के अध्यक्ष हैं। संस्थान के कुलपति इसके उपाध्यक्ष हैं। परिषद के पदेन सदस्य हैं : सचिव, भारत सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सचिव, भारत सरकार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, और वित्त सलाहकार, मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार। परिषद के अन्य सदस्य हैं– अध्यक्ष द्वारा नामित तीन विख्यात शिक्षाविद्, अध्यक्ष द्वारा नामित राज्य/संघ क्षेत्र प्रतिनिधि (5 प्रभागों में से प्रत्येक प्रभाग से एक–एक प्रतिनिधि) और अध्यक्ष द्वारा नामित नीपा संकाय का

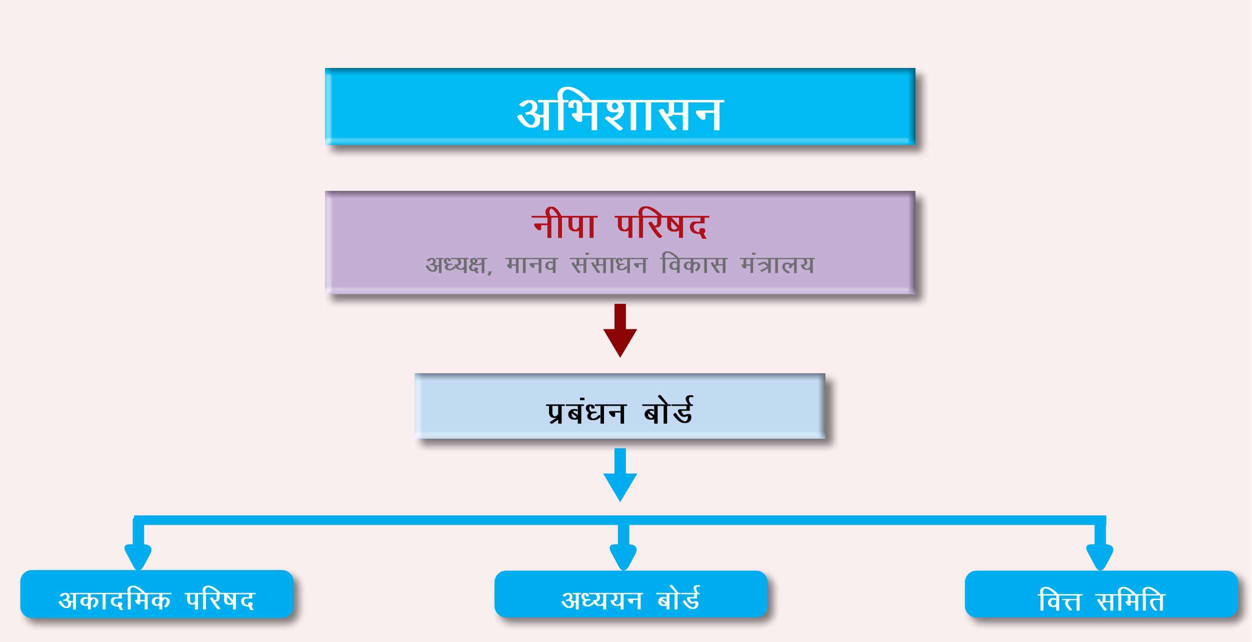

एक सदस्य। संस्थान के कुलसचिव परिषद के सचिव हैं। दिनांक 31 मार्च 2018 के अनुसार नीपा परिषद के सदस्यों की सूची परिशिष्ट–I में प्रस्तुत है।

प्रबंधन बोर्ड : प्रबंधन बोर्ड संस्थान का प्रमुख कार्यकारी निकाय है। संस्थान के कुलपति प्रबंध बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं। अन्य सदस्य हैं : संस्थान के अध्यक्ष द्वारा नामित तीन सदस्य मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार का एक नामिती, वि.अ.आ. के अध्यक्ष का एक नामिती, राष्ट्रीय संस्थान के संकाय डीन, संस्थान के दो संकाय सदस्य (एक प्रोफेसर और एक सह–प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर), कुलसचिव, नीपा, प्रबंधन बोर्ड का सचिव होता है। 31 मार्च, 2018 के अनुसार प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों की सूची परिशिष्ट–II में दी गई है।

वित्त समिति : वित्त समिति की मुख्य भूमिका संस्थान की लेखा की जांच करना और व्यय के प्रस्तावों की समीक्षा करना है। राष्ट्रीय संस्थान की वार्षिक लेखा और वित्तीय आकलनों को वित्त समिति के सम्मुख रखा जाता है और समिति की टिप्पणियों के साथ इसे अनुमोदन के लिए प्रबंधन बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है। वित्त समिति संस्थान की आय और संसाधनों के आधार पर वार्षिक आवर्ती और गैर आवर्ती व्यय की सीमाऐं तय करती है। संस्थान के कुलपति वित्त समिति के पदेन अध्यक्ष हैं; इसके अतिरिक्त नीपा परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित दो व्यक्ति, कुलपति द्वारा नामित एक व्यक्ति, वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि होता है। वित्त अधिकारी, वित्त समिति के सचिव का कार्य करता है। 31 मार्च 2018 के अनुसार वित्त समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट–III में दी गई है।

अकादमिक परिषद : नीपा अकादमिक परिषद संस्थान का शीर्षस्थ अकादमिक निकाय है। अकादमिक परिषद शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध और परामर्श के स्तर पर सतत सुधार और अंतर–विभागीय सहयोग, परीक्षा और परीक्षण आदि के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका पदेन अध्यक्ष कुलपति होता है। अकादमिक परिषद में शामिल हैं : संस्थान के संकाय डीन, अकादमिक विभागों के अध्यक्ष, और अध्यक्ष द्वारा मनोनीत तीन शिक्षाशास्त्री जो संस्थान की गतिविधियों से जुड़े हुए क्षेत्रों से संबंधित हों और संस्थान की सेवा में न हों, कुलपति द्वारा चक्रानुसार नामित एक सहायक प्रोफेसर और तीन सहयोजित सदस्य जो शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य न हों और अकादमिक परिषद द्वारा विषय विशेषज्ञ के आधार पर सहयोजित किए गए हों। नीपा का कुलसचिव परिषद का सचिव होता है। 31 मार्च 2018 के अनुसार सदस्यों की सूची–IV में दी गई है।

अध्ययन बोर्ड : नीपा के कुलपति अध्ययन बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं। इसके सदस्य हैं: संकाय–डीन, विभागाध्यक्ष, कुलपति द्वारा नामित एक सह–प्रोफेसर, और एक सहायक प्रोफेसर और कुलपति द्वारा सहयोजित अधिकतम दो विषय विशेषज्ञ। अध्ययन बोर्ड के सदस्यों की सूची 31 मार्च, 2018 के अनुसार परिशिष्ट–V में दी गई है।

कार्यबल और समितियां : कुलपति द्वारा विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए समय–समय पर विशेष कार्यबलों और समितियों का गठन किया जाता है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञों को शामिल करके परियोजना सलाहकार समितियां गठित की जाती हैं। विशेषज्ञों से गठित परियोजना सलाहकार समिति विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के निरीक्षण और सलाह देने के लिए कार्य करती है। कुलपति की अध्यक्षता में शोध अध्ययन सलाहकार बोर्ड गठित किया गया है। इसमें अन्य विशेषज्ञों के साथ–साथ सभी विभागाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। कुलसिचव इस समिति के सदस्य सचिव हैं जो सहायता योजना के अंतर्गत शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करती है।

प्रशासन और वित्त

संस्थान के प्रशासनिक ढांचे में तीन अनुभाग–अकादमिक प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, सामान्य प्रशासन और दो कक्ष–प्रशिक्षण कक्ष और एम.फिल., पीएचडी कक्ष हैं। कुलसचिव सभी अनुभागों के प्रभारी हैं। कुलसचिव नीपा परिषद, प्रबंधन बोर्ड और अकादमिक परिषद के सचिव भी हैं। कुलसचिव को प्रशासनिक कामकाज में प्रशासनिक अधिकारी, प्रशिक्षण अधिकारी और अनेक अनुभाग अधिकारी अनुसमर्थन प्रदान करते हैं।

कुलसचिव अकादमिक अनुसमर्थन सेवा एककों, जैसे– पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र, कंप्यूटर केंद्र, एवं डिजीटल अभिलेखागार, प्रकाशन एकक और हिंदी कक्ष के कार्यकलापों के प्रति उत्तरदायी हैं। वित्त अधिकारी वित्त और लेखा अनुभाग के प्रभारी है। अनुभाग अधिकारी (लेखा) वित्त अधिकारी का अनुसमर्थन करता है।

स्टाफ की संख्या (2017–18)

31 मार्च, 2018 के अनुसार संस्थान की कुल स्टाफ संख्या 162 थी।

वर्ष 2017–18 के दौरान संस्थान को कुल 2612.95 लाख रुपये का अनुदान मिला (गैर–आवर्त्ती और आवर्त्ती मद)। वर्ष के आरंभ में संस्थान के पास आवर्त्ती मद में 548.15 लाख रुपये शेष थे। वर्ष के दौरान कार्यालय और छात्रावास से 59.32 लाख रुपए की राशि प्राप्ति हुई। योजना और गैर–योजना मदों में इस वर्ष का व्यय 2956.09 लाख रुपये था।

दूसरे संगठनों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों/अध्ययनों की मद में इस वर्ष के दौरान संस्थान के पास 1247.44 लाख रुपये थे और 570.27 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्ति हुई। प्रायोजित कार्यक्रमों/अध्ययनों पर वर्ष में कुल 535.06 लाख रुपये खर्च किए गए। (परिशिष्ट–VII)

परिसर और भवन आधारभूत सुविधा

संस्थान के पास एक चार–मंजिला कार्यालय, सुसज्जित स्नानघरयुक्त 60 कमरों वाला एक सात मंजिला छात्रावास और एक आवास–क्षेत्र है। इस आवास क्षेत्र में टाइप–I के 16, टाइप–II से V तक के 8–8 क्वार्टर और एक कुलपति आवास है।

संस्थान के पास बिंदापुर, द्वारका में टाइप–III के 25 क्वार्टर हैं।

संस्थान परिसर में सुसज्जित प्रशिक्षण कक्ष, कंप्यूटर केंद्र, अंतरराष्ट्रीय डायनिंग हाल, जिम और क्लास रूम हैं।

संस्थान ने हाल ही में परिसर में अर्जित 2100 वर्ग मीटर के भूखंड में नया अकादमिक भवन के निर्माण के लिये अपेक्षित कदम उठाए हैं। इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लीज डीड जारी कर दिया है।

2

अध्यापन और व्यावसायिक विकास कार्यक्रम

अध्यापन और व्यावसायिक विकास कार्यक्रम

एम.फिल. और पी–एच.डी.

वस्तुतः संस्थान की एम.फिल और पी.एच.डी. उपाधियाँ विशेष रूप से शैक्षिक नीति, योजना, प्रशासन और वित्त पर केंद्रित हैं। इसके द्वारा संस्थान विभिन्न पृष्ठभूमि के शोधकर्ताओं को सशक्त और सक्षम बनाता है।

शैक्षिक प्रशासन के लिए विद्वान तैयार करना

संस्थान एक प्रोत्साहक संस्था है जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तरों पर शैक्षिक प्रशासन से संबंधित जरुरत के अनुसार शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन में विशेषज्ञता से युक्त मानव संसाधनों का विकास करता है ऐसे विशेषज्ञ जो अंतरशास्त्रीय कार्यक्रमों/एम.फिल. और पी–एच.डी. उपाधियों के पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा तैयार किये जाते हैं। वे व्यापक एवं गतिशील संदर्भों में समुचित योजनाओं और कार्यनीतियों के निर्माण या सांस्थानिक प्रबंधन के सीमित भूमिकाओं से जुड़े मामलों के समाधान हेतु पूर्णतः सक्षम होते हैं।

वस्तुतः संस्थान की एम.फिल. और पी–एच.डी. उपाधियाँ विशेष रूप से शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन पर केंद्रित हैं। इसके द्वारा संस्थान युवा शोधकर्त्ताओं को सशक्त और सक्षम बनाता है और शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में उनका करियर तैयार करता है। नीपा यह कार्य कर रहा है और इसके माध्यम से यह शैक्षिक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुश्रवण करने हेतु विशेषज्ञ और सक्षम मानव संसाधन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। पूर्व डाक्टोरल और डाक्टोरल कार्यक्रमों का महत्व इसमें अंतर्निहित गतिशील और लचीले उपागम के द्वारा है जिसमें यह शिक्षा और सामाजिक विकास के अन्य सहायक क्षेत्रों से जुड़कर नवाचारी बहुशास्त्रीय पाठ्यक्रमों का विस्तार करता है।

संस्थान द्वारा संचालित पूर्व डाक्टोरल और डाक्टोरल कार्यक्रम में शामिल हैं: (i) पूर्णकालिक एम.फिल. कार्यक्रम (ii) पूर्णकालिक पी–एच.डी. कार्यक्रम और (iii) अंशकालिक पी–एच.डी. कार्यक्रम। ये कार्यक्रम वर्ष 2007–08 में आरंभ किए गए थे। एम.फिल. और पी–एच.डी. कार्यक्रम विभिन्न पृष्ठभूमि के शोधकर्मियों की शोध क्षमता के निर्माण के लिए डिजाइन किए गए हैं जो शैक्षिक नीति, योजना प्रशासन तथा वित्त के संबंधित क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। एम.फिल.

और पी–एच.डी. कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरे किए गए शोध अध्ययनों से अपेक्षा की जाती है कि ये नीति निर्माण, शिक्षा सुधार कार्यक्रमों तथा क्षमता विकास संबंधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ–साथ ज्ञान आधार को समृद्ध करने में भारी योगदान करेंगे। एम.फिल. और पी–एच.डी. कार्यक्रमों के अंतर्गत शोध के व्यापक क्षेत्रों में शामिल हैं– शैक्षिक नीति, शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक वित्त, शैक्षिक प्रबंधन, सूचना प्रणाली, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षा में समता और समावेशन, शिक्षा में लैंगिक मुद्दे, अल्पसंख्यक शिक्षा, तुलनात्मक शिक्षा और शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण।

एम.फिल. डिग्री कार्यक्रम की अवधि दो वर्ष है। इस दो वर्षीय एम.फिल. डिग्री कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष का पाठ्यक्रम कार्य (30 क्रेडिट) है। इसके बाद एक वर्ष लघु शोध प्रबंध (30 क्रेडिट) के लिए है। दो वर्ष के एम.फिल. पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत और निर्धारित आर्हता (वर्तमान में 10 प्वाइंट स्केल पर) 6 एफ जी पी ए या इससे अधिक का ग्रेड पाने वाले शोधार्थी पी–एच.डी. कार्यक्रम में दाखिला प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। पी–एच.डी. कार्यक्रम में दाखिला लेने की तिथि के दो वर्ष बाद ही शोधार्थी अपने शोध प्रबंध जमा करा सकते हैं।

पी–एच.डी. में सीधे दाखिला लेने वाले शोधार्थियों को दाखिला की पुष्टि हेतु एक वर्ष का प्रारंभिक पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है। इसके बाद वे दो वर्ष के शोध कार्य के उपरांत ही वे उपाधि हेतु शोध प्रबंध संस्थान में जमा कर सकते हैं।

अंशकालिक पी–एच.डी. में सीधे दाखिला लेने वाले शोधार्थियों को पी–एच.डी. में दाखिला की पुष्टि से पहले एक वर्ष का प्रारंभिक पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है। अंशकालिक पी–एच.डी. के शोधार्थी दाखिला की पुष्टि के कम से कम चार वर्ष बाद अपना शोध प्रबंध संस्थान में जमा कर सकते हैं।

	एम.फिल.	**पी–एच.डी. पूर्णकालिक**	**पी–एच.डी. अंशकालिक**	**योग**
वर्ष 2017–18 में नामांकन	22	9	-	31
वर्ष 2017–18 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रम कर रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या	36 (वर्ष 2016–17 में नामांकित विद्यार्थियों सहित)	34 (वर्ष 2007–08 से 2017–18 तक नामांकित विद्यार्थियों सहित)	17 (वर्ष 2007–08 से 2017–18 तक नामांकित विद्यार्थी)	87
वर्ष 2017–18 के दौरान स्नातक विद्यार्थी की कुल संख्या	8	-	3	11

डिप्लोमा कार्यक्रम

पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम के छः घटक हैं: (i) पाठ्यक्रम तैयारी कार्य (ii) आमने–सामने पाठ्यक्रम कार्य (iii) परियोजना कार्य (iv) परियोजना कार्य का मूल्यांकन और अंतरिम प्रमाण पत्र विवरण और (v) उन्नत पाठ्यक्रम कार्य और (vi) अंतिम मूल्यांकन और पीजी डिप्लोमा प्रमाण–पत्र वितरण।

शैक्षिक योजना और प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडेपा)

संस्थान वर्ष 1982–83 से शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में विशेष रूप से डिजाइन, डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित कर रहा था। आरंभ में यह कार्यक्रम विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए पूर्व प्रवेश पाठ्यक्रम के रूप में डिजाइन किया गया था। यद्यपि वर्ष 2014–15 से इस कार्यक्रम में पाठ्यक्रम को संवर्धित करके इसमें परिवर्तन किया गया है और इसके डेपा मूलभूत से पीजीडेपा (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन)– शैक्षिक योजना और प्रशासन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा) में बदल दिया गया है। प्रतिभागियों के कार्य और भूमिकाओं तथा उनकी संस्थाओं जैसे एससीईआरटी/सीमेट/डाइट/डीईओ/बीईओ और राज्य सरकारों के शिक्षा निदेशालयों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को संबर्धित किया गया है।

एक वर्षीय पीजीडेपा कार्यक्रम को मौजूदा डेपा में व्यापक रूपांतरण के बाद निर्मित किया गया है जो एक सघन दीर्घकालिक कार्यक्रम है जो देश में पेशेवर रूप से शैक्षिक प्रशासकों का संवर्ग का विकास सुनिश्चित करेगा। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(i) शैक्षिक योजना और प्रबंधन की मूलभूत अवधारणाओं से प्रतिभागियों को अवगत कराना।

(ii) शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में बेहतर निर्णय कार्य के लिए प्रतिभागियों में योजना और प्रबंधन कौशल के विकास हेतु सक्षम बनाना।

(iii) प्रतिभागियों में शैक्षिक कार्यक्रमों और परियोजनाओं के पर्यवेक्षण और मूल्यांकन योग्यता का विकास करना।

पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम का निरूपण करते समय मूलतः इस बात का ध्यान दिया गया था कि प्रतिभागी को इस पाठ्यक्रम के लिए नीपा में तीन माह से अधिक अवधि के लिए प्रवास न करना पड़े और वह अपने कार्य स्थल पर पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सके। इसके अनुसार इसे 12 महीने के पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रम में रूपातंरित किया गया है। अनेक शिक्षा विभाग इस पाठ्यक्रम हेतु अपने अधिकारियों को लंबी अवधि के लिए प्रतिनियुक्त नहीं कर सकते हैं इसलिए पीजीडेपा कार्यक्रम को इस रूप में नियोजित किया गया है कि आमने–सामने पाठ्यक्रम कार्य हेतु प्रतिभागियों को नीपा में 3 महीने से अधिक अवधि के लिए प्रवास न करना पड़े। इस पाठ्यक्रम में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं: कार्यस्थल पर पाठ्यक्रम तैयारी कार्य, नीपा में आमने–सामने पाठ्यक्रम कार्य, कार्यस्थल पर परियोजना कार्य, मुक्त और दूरवर्ती अधिगम

तालिका 2.1

शैक्षिक योजना और प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (डेपा) में राज्य/संघ क्षेत्रावार भागीदारी			
राज्य/संघ क्षेत्र	**तृतीय पी.जी.– डेपा**	**चतुर्थ पी.जी.– डेपा**	**योग**
अरुणाचल प्रदेश	-	2	2
असम	1	2	3
छत्तीसगढ़	1	1	2
गुजरात	-	3	3
हिमाचल प्रदेश	1	2	3
जम्मू और कश्मीर	1	1	2
कर्नाटक	3	-	3
मध्य प्रदेश	1	-	1
महाराष्ट्र	-	1	1
मणिपुर	2	4	6
मेघालय	-	2	2
मिजोरम	2	2	4
नागालैण्ड	2	2	4
ओडिशा	-	1	1
राजस्थान	-	2	2
तमिलनाडु	3	-	3
सिक्किम	1	1	2
उत्तराखंड	3	3	6
एयर फोर्स	2	2	4
योग	**23**	**31**	**54**

प्रणाली के द्वारा उन्नत पाठ्यक्रम और नीपा में संगोष्ठी सहित कार्यशाला में परियोजना कार्य प्रस्तुति।

पीजीडेपा के पाठ्यक्रम कार्य निम्नलिखित चरणों में संपादित किए जाते हैं:

चरण 1 : पाठ्यक्रम तैयारी कार्य (कार्य स्थल)

चरण 2 : आमने–सामने पाठ्यक्रम कार्य (नीपा)

चरण 3 : परियोजना कार्य (कार्य स्थल)

चरण 4 : परियोजना कार्य का मूल्यांकन और अंतरिम प्रमाण–पत्र वितरण (नीपा)

चरण 5 : प्रारंभिक उन्नत पाठ्यक्रम कार्य (कार्य स्थल)

चरण 6 : अंतिम मूल्यांकन और पीजीडेपा प्रमाण–पत्र वितरण (नीपा)

तृतीय पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम में 13 राज्यों/संघ क्षेत्रों के 23 प्रतिभागी शामिल हुए। यह सितंबर 2016 से जुलाई 2017 के दौरान आयोजित किया गया।

डिप्लोमा कार्यक्रम का संयोजन शैक्षिक प्रशिक्षण और क्षमता विकास विभाग ने किया। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में पी.जी. डिप्लोमा में राज्यवार/संघ शासित प्रदेशों की भागीदारी का विवरण तालिका 2.1 में प्रदर्शित है :

शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा)

संस्थान 1985 से विकासशील देशों के पेशेवरों के लिए शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में 6 माह का अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम के विद्यार्थी एशिया, अफ्रीका, मध्य एशियाई गणराज्यों, दक्षिणी अमरीका और कैरिबियाई क्षेत्रों के देशों से आते हैं। इस कार्यक्रम के तीन घटक हैं– (i) सघन पाठ्यचर्चा कार्यक्रम; (ii) अनुप्रयुक्त कार्य और (iii) लघु शोध प्रबंधन। आईडेपा की अवधि छः माह है और यह दो चरणों में पूरा किया जाता है। पहले चरण में तीन माह का सघन पाठ्यचर्या है जो संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। यह चरण आवासीय है और प्रतिभागियों से

अपेक्षा की जाती है कि वे इस चरण के दौरान परिसर में निवास करें। दूसरे चरण में प्रतिभागी को स्वदेश में संस्थान के संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में क्षेत्र आधारित शोध परियोजना अध्ययन करना होता है।

आईडेपा कार्यक्रम की पाठ्यचर्या में केंद्रिक पाठ्यक्रम और वैकल्पिक पाठ्यक्रम, प्रायोगिक अभिविन्यास और अप्रयुक्त कार्य शामिल हैं। पाठ्यचर्या कार्य के विषय हैं : शिक्षा और विकास से संबंधित अध्ययन, विकासशील देशों में शैक्षिक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र, शैक्षिक योजना और प्रशासन, परियोजना नियोजन, शिक्षा में व्यष्टि स्तरीय योजना, शिक्षा में वित्तीय योजना और प्रबंधन, जनशक्ति योजना, शैक्षिक योजना में मात्रात्मक तकनीकें, शैक्षिक प्रबंधन, शोध प्रविधि और सांख्यिकी और शैक्षिक प्रबंधन और सूचना प्रणाली। अनुप्रयुक्त कार्य में शामिल हैं : विषयगत संगोष्ठियां डिप्लोमा कार्यक्रम के अभिन्न घटक हैं जो प्रत्येक प्रतिभागी या प्रतिभागियों के समूह को शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित विषयों से जुड़े वस्तुगत आंकड़ों और अनुभवों के आधार पर अपने विचार व्यक्त करने और उनका परस्पर आदान–प्रदान करने के अवसर प्रदान करती हैं। संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण के एक भाग के रूप में प्रतिभागियों को अपने देश की शिक्षा प्रणाली की विशिष्ट प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करने और परस्पर आदान–प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को स्वदेश में उनके कार्यों की प्रासंगिकता और जरुरतों के विशिष्ट क्षेत्र में शोध परियोजना की रूपरेखा बनाने में सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशलों के बीच संबंध स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में चरण–I के दौरान प्रत्येक प्रतिभागी के लिए एक शोध निर्देशक नियुक्त किया जाता है जो दूसरे चरण के कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी के परियोजना कार्य का निर्देशन करता है।

कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रतिभागी के स्वदेश में आयोजित होता है। इसमें प्रत्येक प्रतिभागी को प्रथम चरण के दौरान निर्धारित क्षेत्र कार्य आधारित शोध परियोजना पर कार्य करना पड़ता है। शोध परियोजना कार्य (तीन माह की अवधि) पूरा करने के बाद प्रतिभागी को अपना लघुशोध प्रबंध संस्थान को प्रस्तुत करना पड़ता है। लघु शोध प्रबंध की प्राप्ति और तदुपरांत संस्थान के संकाय द्वारा उसके मूल्यांकन के बाद प्रतिभागी को डिप्लोमा की उपाधि प्रदान की जाती है।

वर्ष 2017–18 के दौरान संस्थान ने 33वें अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा का दूसरा चरण पूरा किया जिसका प्रथम चरण 1 फरवरी से 30 अप्रैल 2017 को आयोजित किया गया था। उसमें 20 देशों के 26 प्रतिभागी शामिल हुए। 33वें अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम का दूसरा चरण 1 मई से 31 जुलाई 2017 के दौरान आयोजित किया गया।

34वें अंतरराष्टीय डिप्लोमा कार्यक्रम का प्रथम चरण 1 फरवरी 2018 को शुरु हुआ और इसके प्रथम घटक की अध्यापन–अधिगम गतिविधियां 30 अप्रैल 2018 तक पूरी की गईं। 34वें अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम में 12 देशों से कुल 27 प्रतिभागी शामिल हुए। इसका दूसरा चरण 1 मई से 31 जुलाई 2018 के दौरान प्रतिभागियों के स्वदेश में नियत किया गया जो परियोजना कार्य पर आधारित था।

अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम का संयोजन शैक्षिक प्रशिक्षण और क्षमता विकास विभाग करता है। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रमों की देशवार भागीदारी का विवरण तालिका 2.2 में प्रदर्शित है।

तालिका 2.2:

शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा) कार्यक्रमों में देशवार भागीदारी			
देश का नाम	33वां डिप्लोमा	34वां डिप्लोमा	योग
अफगानिस्तान	2	3	5
बांग्लादेश	1	-	1
भूटान	1	4	5
केमेरून	2	-	2
कम्बोडिया	2	-	2
कांगो	1	-	1
इथोपिया	2	3	5
घाना	1	-	1
गिनी बिसाऊ	1	-	1
जमैका	-	1	1
किरिबती	-	1	1
लाओस	-	1	1
लिबेरिया	-	3	3
लिथुआनिया	1	-	1
मेडागास्कर	1	-	1
मॉरीशस	2	2	4
मंगोलिया	1	-	1
म्यांमार	1	-	1
नेपाल	1	-	1
नाइजीरिया	1	1	2
सेनेगल	1	-	1
दक्षिणी सूडान	1	-	1
श्रीलंका	-	2	2
तंजानिया	2	4	6
ट्यूनिशिया	-	1	1
उजबेकिस्तान	1	-	1
योग	**26**	**26**	**52**

तालिका 2.3:

सभी कार्यक्रमों में देशवार भागीदारी 2017–18		
क्र. सं.	देश	भागीदारों की संख्या
1.	अफगानिस्तान	15
2.	आस्ट्रेलिया	01
3.	भूटान	05
4.	इथोपिया	03
5.	फ्रांस	02
6.	जमैका	01
7.	किरिबाती	01
8.	लाओस	01
9.	लाइबेरिया	03
10.	केन्या	01
11.	मेडागास्कर	01
12.	मलेशिया	01
13.	मॉरीशस	04
14.	नेपाल	03
15.	नाइजीरिया	03
16.	रूस	01
17.	श्रीलंका	07
18.	तजाकिस्तान	01
19.	तंजानिया	04
20.	थाइलैंड	01
21.	त्रिनिदाद एंड टोबागो	01
22.	ट्यूनिशिया	01
23.	संयुक्त अरब अमीरात	02
24.	यू.के.	04
25.	संयुक्त राज्य अमेरिका	01
26.	जिम्बाम्बवे	02
27.	यूनेस्को	02
28.	विश्व बैंक	02
	योग	**74**

तालिका 2.4:

व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार भागीदारी 2017–18

क्र. सं.	राज्य/संघीय क्षेत्र	भागीदारों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	594
2.	अरुणाचल प्रदेश	27
3.	असम	394
4.	बिहार	436
5.	छत्तीसगढ़	158
6.	गोवा	48
7.	गुजरात	384
8.	हरियाणा	557
9.	हिमाचल प्रदेश	356
10.	जम्मू और कश्मीर	81
11.	झारखण्ड	87
12.	कर्नाटक	835
13.	केरल	81
14.	मध्य प्रदेश	518
15.	महाराष्ट्र	926
16.	मणिपुर	27
17.	मेघालय	18
18.	मिजोरम	21
19.	नागालैण्ड	28
20.	ओडिशा	184
21.	पंजाब	423
22.	राजस्थान	592
23.	सिक्किम	21
24.	तेलगांना	83
25.	तमिलनाडु	230
26.	त्रिपुरा	24
27.	उत्तराखंड	86
28.	उत्तर प्रदेश	806
29.	पश्चिम बंगाल	63
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2
31.	चंडीगढ़	29
32.	दादरा और नगर हवेली	1
33.	दमन और दीव	2
34.	दिल्ली	412
35.	लक्षद्वीप	2
36.	पुडुचेरी	8
	योग	**8544**

व्यावसायिक विकास कार्यक्रम

शैक्षिक योजना और प्रशासन में सुधार हेतु सांस्थानिक क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न वर्गों के शिक्षा कर्मियों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रम विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यकलाप के रूप में सतत जारी है। वर्ष 2017–18 के दौरान संस्थान ने शिक्षा के विभिन्न विकास क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों और शिक्षा नीति योजना, प्रशासन के विविध पक्षों से जुड़े 149 अभिविन्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, सम्मेलन और बैठकें आयोजित कीं। इन कार्यक्रमों के विषय थे : स्कूलों की योजना और प्रबंधन, उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंधन, माध्यमिक स्तर पर स्कूल प्रावधानों का आकलन, शैक्षिक वित्त की योजना और प्रबंधन, और स्कूल नेतृत्व आदि। इन कार्यक्रमों के प्रतिभागी थे जिला और राज्य स्तर के शिक्षाकर्मी, शिक्षा निदेशक और राज्य स्तर के अन्य अधिकारी, केंद्र, राज्य और जिला स्तर के शैक्षिक संस्थानों के प्रमुख, विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव और अन्य प्राधिकारी, कालेज प्राचार्य और कालेजों तथा उच्च शिक्षा के वरिष्ठ प्रशासक, विश्वविद्यालय तथा समाजविज्ञान शोध संस्थानों के नवनियुक्त प्राध्यापक आदि। ये कार्यक्रम संस्थान के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान संस्थान के विभिन्न विभागों द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियां, सम्मेलन और बैठकें आयोजित की गईं :

शैक्षिक योजना विभाग

- ओडिशा के शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआइ) के प्रमुखों के लिए शिक्षक शिक्षा की योजना पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम, 17–21 जुलाई, 2017, भुवनेश्वर, ओडिशा।
- स्कूल शिक्षा कार्यक्रमों की योजना और निगरानी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए), अगस्त 21–25, 2017, नीपा, नई दिल्ली।
- पूर्वोत्तर राज्यों, 4–8 सितम्बर, 2017, गुवाहाटी, असम में स्कूल शिक्षा कार्यक्रमों की योजना और निगरानी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- एससीईआरटी के संकाय और सिक्किम के डाईट संकायों के लिए योजना और रूपरेखा अनुसंधान परियोजनाओं पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 29 जनवरी– 2 फरवरी, 2018, सिक्किम।

शैक्षिक प्रशासन विभाग

- नासिक, महाराष्ट्र में जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन, 19–20 जून, 2017।
- पुणे, महाराष्ट्र में जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन, 6–7 फरवरी, 2018 ।
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विविधता और समानता के प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 10–14 जुलाई, 2017, नीपा, नई दिल्ली।

- जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक शासन में नेतृत्व पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 31 जुलाई – 04 अगस्त, 2017, नीपा, नई दिल्ली।
- राज्य और जिला स्तर की महिला प्रशासकों के लिए शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम, अगस्त 21–25, 2017, नीपा, नई दिल्ली।
- व्यावसायिक शिक्षा के प्रबंधन और योजना पर अभिविन्यास कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण, 13–17 नवंबर, 2017, नीपा, नई दिल्ली
- चेन्नई में जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन पर राज्य स्तरीय सम्मेलन, 20–21 सितम्बर, 2017, चेन्नई।
- संस्थानिक प्रमुखों के लिए प्रबंधन और पर्यवेक्षण पर अभिविन्यास कार्यक्रम सह–कार्यशाला, 7 सितंबर, 2017, नीपा, नई दिल्ली।

शैक्षिक वित्त विभाग

- वित्तीय योजना पर उन्मुखी कार्यक्रम और राज्यों में शिक्षा का प्रबंधन, फरवरी 6–10, 2017, नीपा, नई दिल्ली

- वित्तीय योजना पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम और राज्यों में शिक्षा का प्रबंधन, 11–15 सितंबर, 2017, नीपा, नई दिल्ली।
- विश्वविद्यालय प्रशासकों के लिए उच्च शिक्षा में नेतृत्व विकास पर कार्यशाला, 26–28 फरवरी, 2018, नीपा, नई दिल्ली ।
- कॉलेज वित्त की योजना और प्रबंधन में अभिविन्यास कार्यक्रम, 19–21 मार्च, 2018।

शैक्षिक नीति विभाग

- शिक्षा में गुणात्मक अनुसंधान विधियों के तरीकों पर उन्मुखीकरण कार्यशाला, 18–28 दिसंबर, 2017, नीपा, नई दिल्ली।

- भारत में शहरी सीमान्तता, सामाजिक नीति और शिक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, 12–13 फरवरी, 2018, नीपा, नई दिल्ली।
- भारत में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ाव पर राष्ट्रीय कार्यशाला; युक्ति और इसके व्यवहार के रूप में स्वायत्तता, मार्च 8–9, 2018 नीपा, नई दिल्ली।
- प्राथमिक स्तर पर वंचित बच्चों की शिक्षा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर अभिविन्यास कार्यक्रमः नीति मुद्दे और कार्यक्रम हस्तक्षेप, 21–25 अगस्त 2017, नीपा, नई दिल्ली।
- उत्तर–पूर्वी राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन में संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत स्थानीय प्राधिकरण और स्वायत्त जिला परिषदों के कामकाज पर अभिविन्यास कार्यशाला, 11–15 सितम्बर, 2017, गुवाहाटी, असम।
- आरटीई के तहत स्कूल प्रबंधन समितियों के सुदृढ़ीकरण पर राष्ट्रीय/राज्य सम्मेलन, 20–23 मार्च, 2018 बैंगलोर, कर्नाटक।
- नीति परिप्रेक्ष्य में गांधीवादी शैक्षिक विचारों पर सह–बैठक और कार्यशालाः प्रासंगिकता, चुनौतियां और संभावनाएं पर राष्ट्रीय चर्चा , 3–5 अक्टूबर, 2017, नीपा, नई दिल्ली।
- शिक्षा अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन पर सह–कार्यशाला और चर्चाः स्थिति, मुद्दे और चुनौतियां, 26–28 मार्च, 2018, बंगलुरू, कर्नाटक।

स्कूल एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग

- चयनित राज्यों में ईसीईसी में प्रोत्साहन परिवर्जन और समन्वय पर राष्ट्रीय परामर्श (यूनिसेफ के सहयोग से), 9–10 नवंबर, 2017, नीपा, नई दिल्ली।

उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग

- दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला, ''उच्च शिक्षा का भविष्य'', 7–8 सितंबर, 2017, नीपा, नई दिल्ली
- उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम पर विशेष पाठ्यक्रम, 20–24 नवंबर, 2017, नीपा, नई दिल्ली।
- उच्च शिक्षा में विशेष पाठ्यक्रम – उच्च शिक्षा में वित्त पोषण, 30 अक्टूबर – 3 नवंबर, 2017, इंफाल, मणिपुर।
- उच्च शिक्षा में नेतृत्व विकास पर कार्यशाला, दिसम्बर 7–8, 2017, नई दिल्ली।

- भारत में कॉलेजों की संस्थागत आत्मकथाएँ: शताब्दी, 6–7 अक्टूबर, 2017, नीपा, नई दिल्ली

शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग

- यू–डाईस और एसडीएमआईएस पर राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा कार्यशाला, राज्य/संघ शासित प्रदेशों के एम.आई.एस. समन्वयक, 4–8 जुलाई, 2017, नीपा, नई दिल्ली
- यू–डाईस और एसटीएस क्षेत्रीय समीक्षा कार्यशाला राज्य/केंद्रशासित प्रदेश और जिला स्तरीय एमआईएस समन्वयक के लिए, 7 कार्यशालाएं, 29 नवंबर, 2017 से 07 जनवरी, 2018।
- स्कूल शिक्षा की योजना और निगरानी में संकेतक का उपयोग करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 28–30 अगस्त, 2017, पुडुचेरी।
- स्कूल शिक्षा की योजना और निगरानी में संकेतक का उपयोग करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 29 जनवरी– 2 फरवरी, 2018 नीपा, नई दिल्ली

- यू–डाईसऔर एसडीएमआईएस पर राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक, राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों के समन्वयक, 10–11 अक्टूबर, 2017 नई दिल्ली
- प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा के लिए शैक्षिक विकास के संकेतक पर कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम, अक्टूबर, 2017, बिहार।

शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण विभाग

- शैक्षिक योजना और प्रशासन में तीसरा स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडेपा) (1 अगस्त, 2016 से 01 जुलाई, 2017), चरण IV और चरण V, 10–21 अप्रैल, 2017
- शैक्षिक योजना और प्रशासन में तृतीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडेपा) (1 अगस्त 2016 से 01 जुलाई, 2017), चरण VI – 27 जून से 1 जूलाई, 2017

- शैक्षिक योजना और प्रशासन में 33वां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा) चरण I, 1 फरवरी – 30 अप्रैल, 2017, नीपा, नई दिल्ली
- शैक्षिक योजना और प्रशासन में चतुर्थ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडेपा), 1 अगस्त, 2017 से 01 जुलाई, 2018।
- शैक्षिक योजना और प्रशासन में (प्रथम चरण) 34वां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा), 1 फरवरी, 2018 से 30 अप्रैल, 2018, नीपा, नई दिल्ली
- शैक्षिक प्रशासकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, 18 जुलाई – 11 अगस्त, 2017, नीपा, नई दिल्ली

- उच्च शिक्षा के अल्पसंख्यक प्रबंधन संस्थानों के लिए 8वां वार्षिक अभिविन्यास कार्यक्रम, 15–19 जनवरी 2018, नीपा, नई दिल्ली
- मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रबंधित वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रमुखों के लिए संस्थागत नियोजन पर दसवां वार्षिक कार्यक्रम, 25–30 अक्टूबर, 2017, नीपा, नई दिल्ली
- ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से शिक्षक शिक्षा योजना पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला, 03 नवंबर, 2017

राज्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

- अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के आश्रम स्कूलों में सेवारत स्कूल प्रमुखों के लिए क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (महाराष्ट्र–I) फरवरी 19–23, 2018, नासिक, महाराष्ट्र।
- अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के आश्रम स्कूलों में कार्यरत स्कूल प्रमुखों के लिए क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (महाराष्ट्र–II) 18–23, 2017
- अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के आश्रम स्कूलों में सेवारत स्कूल प्रमुखों के लिए क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आश्रम (आंध्र प्रदेश) 18–23 दिसंबर, 2017।

राष्ट्रीय स्कूल नेतृत्व केंद्र

एस.एस.ए. और आर.एम.एस.ए. के तहत ए.डब्ल्यू.पी.बी. बैठकें और कार्यशालाएं (राष्ट्रीय स्तर)

- 7 मार्च, 2018 को एक दिवसीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति की बैठक

पाठ्यक्रम और सामग्री विकास

- प्रणालीगत व्यवस्थापकों के लिए स्कूल नेतृत्व विकास पर कार्यशाला, 4–5 सितम्बर, 2017

राज्य संसाधन समूह (राज्य स्तर) का क्षमता निर्माण कार्यक्रम

- लक्षद्वीप के स्कूल प्रमुखों के लिए स्कूल नेतृत्व पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम, 17–28 अप्रैल, 2017, नीपा, नई दिल्ली
- स्कूल नेतृत्व पर व्यवस्था स्तर प्रशासन का क्षमता निर्माण कार्यक्रम गंगटोक, सिक्किम (बैच 1), मार्च 15–20, 2018,
- स्कूल नेतृत्व (बैच 2), जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यकताओं की क्षमता निर्माण के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, एनसीएसएल, नीपा, मई 2017।
- स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन में एक महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के संचालन हेतु संसाधन व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण, 15–20 जनवरी, 2018, नीपा, नई दिल्ली
- स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर एक महीने के सर्टिफिकेट कोर्स हेतु संसाधन व्यक्तियों का क्षमता निर्माण पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 19–24 मार्च, 2018, नीपा, नई दिल्ली
- स्कूल नेतृत्व अकादमी (बैच 3), जून 2017, एनसीएसएल, नीपा, नई दिल्ली के संकाय का क्षमता निर्माण
- हिमाचल प्रदेश राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) का क्षमता निर्माण, 12–22 अगस्त, 2017
- पश्चिम बंगाल राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) का क्षमता निर्माण (7 जिले) 16 जनवरी – फरवरी 22, 2018
- महाराष्ट्र राज्य में स्कूल स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) का क्षमता निर्माण 21–27 नवंबर, 2017

- उत्तर प्रदेश बैच–I में स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) की क्षमता निर्माण 25 अक्टूबर – 03 नवंबर, 2017
- उत्तर प्रदेश बैच–II में स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) की क्षमता निर्माण (06–15 नवंबर, 2017)
- स्कूलों के प्रमुखों के लिए स्कूल नेतृत्व विकास पर राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) कार्यशाला, पुदुचेरी, 22 मई–1 जून, 2017, पुदुचेरी
- तेलंगाना राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम पर राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) का क्षमता निर्माण, 6–10 जनवरी, 2018
- मणिपुर राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) का क्षमता निर्माण, 16–26 नवंबर, 2017
- अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) का क्षमता निर्माण, 15–25 जनवरी, 2018
- तमिलनाडु राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) का क्षमता निर्माण, 8–12 जनवरी, 2018
- जोन 1 (उत्तरी और मध्य राज्यों) में स्कूल नेतृत्व कार्यक्रम की समीक्षा और प्रतिक्रिया पर कार्यशाला, दिसंबर 3–5, 2017
- जोन 1 (केंद्रीय राज्यों) में स्कूल नेतृत्व कार्यक्रम की समीक्षा और प्रतिक्रिया पर कार्यशाला,
- जोन 3 (पूर्वी राज्यों) में स्कूल नेतृत्व कार्यक्रम की समीक्षा और प्रतिक्रिया पर कार्यशाला, 11–13 दिसंबर, 2017
- जोन 4 (पश्चिमी राज्यों) में स्कूल नेतृत्व कार्यक्रम की समीक्षा और प्रतिक्रिया कार्यशाला, 18–20 दिसंबर, 2017
- जोन 5 (दक्षिणी राज्यों) में स्कूल नेतृत्व कार्यक्रम की समीक्षा और प्रतिक्रिया कार्यशाला, 23–25 नवंबर, 2017
- केन्द्रीय विद्यालय में नव–निर्वाचित प्रधानाचार्यों के लिए स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर एक महीने का सर्टिफिकेट कोर्स, 12 जुलाई – 9 अगस्त, 2017, केन्द्रीय विद्यालय, जेएनयू कैम्पस, नई दिल्ली
- मध्य प्रदेश राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास पर राज्य संसाधन समूह का क्षमता निर्माण, 22–27 मई, 2017, मध्य प्रदेश
- राजस्थान राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास पर राज्य संसाधन समूह का क्षमता निर्माण, 12–21 जुलाई, 2017, राजस्थान
- मिजोरम राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास पर राज्य संसाधन समूह का क्षमता निर्माण, जुलाई 11–20, 2017, मिजोरम
- गुजरात राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास पर राज्य संसाधन समूह का क्षमता निर्माण, 3–13 अक्टूबर, 2017 गुजरात
- सिक्किम राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास पर राज्य संसाधन समूह का क्षमता निर्माण,12–22 जून, 2017, सिक्किम
- तमिलनाडु राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास पर स्कूल प्रमुख की क्षमता निर्माण, जून 16–25, 2017, मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाइकनाल, तमिलनाडु
- स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम में स्कूल प्रमुख का प्रशिक्षण, 13–23 सितंबर, 2017, मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाइकनाल, तमिलनाडु
- उत्तराखंड में स्कूल प्रमुखों के लिए स्कूल नेतृत्व विकास पर क्षमता निर्माण कार्यशाला, 15–24 मई, 2017, उत्तराखंड
- हरियाणा राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास पर स्कूल प्रमुखों की क्षमता निर्माण पर कार्यशाला, 3–4 नवंबर, 2017
- राजस्थान में स्कूल नेतृत्व कार्यक्रम की समीक्षा और प्रतिक्रिया कार्यशाला, 27–28 अप्रैल, 2017, राजस्थान
- राजस्थान में स्कूल नेतृत्व कार्यक्रम की समीक्षा और प्रतिक्रिया कार्यशाला, 10–11 मई, 2017, राजस्थान
- असम (आरएमएसए), असम में एक दिन 10+2+2+2 रूपरेखा पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 14 अगस्त, 2017

- केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एसएलडीपी की 2 दिन की समीक्षा, 7—8 फरवरी, 2018

स्कूल आकलन, नेतृत्व और स्कूल शिक्षा सांख्यिकी के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यक्रम के तहत एडब्ल्युपीबी

- राजस्थान राज्य में स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर एक महीने का सर्टिफिकेट कोर्स, 22 मई —18 जून, 2017, राजस्थान
- उत्तराखंड राज्य में स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर एक महीने का सर्टिफिकेट कोर्स, 01—30 जून, 2017 उत्तराखंड
- उत्तर प्रदेश राज्य में स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर एक महीने का सर्टिफिकेट कोर्स, 01—30 जून, 2017 उत्तर प्रदेश
- सिक्किम राज्य में स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर एक महीने का सर्टिफिकेट कोर्स, 16 अगस्त—15 सितंबर, 2017, सिक्किम
- असम राज्य में स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर एक महीने का सर्टिफिकेट कोर्स, 3—31 जुलाई, 2017, असम
- तमिलनाडु राज्य में स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर एक महीने का सर्टिफिकेट कोर्स, 30 अक्टूबर — 30 नवंबर, 2017

स्कूल नेतृत्व विकास पर ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए अभिविन्यास (शिक्षक और शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय योजना के तहत)

- मणिपुर राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास पर ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए अभिविन्यास, 27 नवंबर, 2017
- ओडिशा राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास पर ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए अभिविन्यास, 16 दिसंबर, 2017
- अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास पर ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए अभिविन्यास, 26 जनवरी, 2018
- केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्कूल नेतृत्व विकास पर ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए अभिविन्यास, 6 फरवरी, 2018
- सिक्किम राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास पर ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए अभिविन्यास, 17 जुलाई, 2017
- पुडुचेरी राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास पर ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए अभिविन्यास, 2 जून, 2017

एन.सी.एस.एल. संकाय द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रम

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (परामर्शकारी बैठक) द्वारा आयोजित स्कूल नेतृत्व प्रशिक्षण पर अनुपालन कार्यशाला, 12 अप्रैल, 2017, नीपा, नई दिल्ली।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (परामर्शकारी बैठक) द्वारा आयोजित स्कूल नेतृत्व प्रशिक्षण पर अनुपालन कार्यशाला, 23 मई, 2017, नीपा, नई दिल्ली
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (परामर्शकारी बैठक), नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित स्कूल नेतृत्व प्रशिक्षण पर अनुपालन कार्यशाला, 10 जुलाई, 2017।
- नीपा, नई दिल्ली में एकस्टेप के साथ बैठक, 28 सितंबर, 2017, नीपा, नई दिल्ली।
- पंजाब, एसएसए, चंडीगढ़ के माध्यम से संघशासित प्रदेश चंडीगढ़ की बैठक, 17—18 जुलाई, 2017,
- शिक्षक और शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन की योजना के तहत राष्ट्रीय कार्यशाला आइजीएनटीयू परिसर, अमरकंटक — मध्य प्रदेश, 14—15 सितंबर, 2017
- गुजरात द्वारा दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के संरक्षक की बैठक 24—26 जुलाई, 2017।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्कूलों के सुधार के लिए रोडमैप, जुलाई, 2017।

उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र

- यूजीसी कोचिंग योजनाओं के अध्ययन पर अनुसंधान पद्धति कार्यशाला, 2—3 मई, 2017, नीपा, नई दिल्ली

- उच्च शिक्षा के वित्तपोषण पर आईएचईआर प्रथम सहकर्मी शिक्षा बैठक, 30 मई, 2017, नीपा, नई दिल्ली
- राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बैठक, 15–16 फरवरी, 2018
- भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम पर अनुसंधान पद्धति कार्यशाला, 29–30 अगस्त, 2017, नीपा, नई दिल्ली
- भारत में उच्च शिक्षा के गुणवत्ता पर अनुसंधान पद्धति कार्यशालाः बाहरी और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन का संस्थागत स्तर पर एक अध्ययन, 6–7 सितंबर, 2017
- भारत में उच्च शिक्षा के प्रशासन और प्रबंधन पर अनुसंधान पद्धति कार्यशाला, 11–12 सितंबर, 2017, नीपा, नई दिल्ली।
- आइईआर उच्च शिक्षा के वित्त पोषण पर द्वितीय सहकर्मी बैठक, 14 सितंबर, 2017, नीपा, नई दिल्ली।
- भारत में सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों के वित्तपोषण पर अनुसंधान पद्धतिः धन का प्रवाह और उनके उपयोग का अध्ययन, 25–26 सितंबर, 2017, नीपा, नई दिल्ली।
- उच्च शिक्षा स्नातकों की रोजगार पर अनुसंधान पद्धति कार्यशाला, 18–19 जनवरी, 2018
- उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, 22–23 फरवरी, 2018

स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक

- शिक्षक शिक्षा में शासन, विनियमन और गुणवत्ता आश्वासन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, 15–16 मार्च, 2018
- शिक्षा में व्यावसायिक सार्वजनिक नीति निर्माण पर उन्मुखीकरण कार्यक्रमः समावेशी शिक्षा पर ध्यान केंद्रण, 18–22 सितंबर, 2017, नीपा, नई दिल्ली
- सी.डब्ल्यु.एस.एन. पर फोकस के साथ समावेशी शिक्षा की नीति और योजना पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, 9–10 नवंबर, 2017, नीपा, नई दिल्ली

- बाहरी मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश के विकास पर दो विशेषज्ञ समूह कार्यशालाएं, 10–12 जनवरी, 2018, नीपा, नई दिल्ली
- शाला सिद्धि (बाहरी मूल्यांकन) पर राष्ट्रीय परामर्शी बैठक, 23–24 जनवरी, 2018, नीपा, नई दिल्ली
- राज्य विशिष्ट क्षमता निर्माणः शाला सिद्धि पर कार्यक्रमः महाराष्ट्र, 21–24 जून, 2017
- राज्य विशिष्ट क्षमता निर्माणः शाला सिद्धि पर कार्यक्रमः हरियाणा, 03–04 जून, 2017
- राज्य विशिष्ट क्षमता निर्माणः शाला सिद्धि पर कार्यक्रमः राजस्थान, 15 सितंबर, 2017
- राज्य विशिष्ट क्षमता निर्माणः शाला सिद्धि पर कार्यक्रमः बिहार, 19–20 सितंबर, 2017
- राज्य विशिष्ट क्षमता निर्माणः शाला सिद्धि पर कार्यक्रमः हिमाचल प्रदेश, 15 दिसंबर, 2017
- राज्य विशिष्ट क्षमता निर्माणः शाला सिद्धि पर कार्यक्रमः महाराष्ट्र, 28–29 दिसंबर, 2017

सूचान प्रौद्योगिकी सेवाएं

- मूडल मूक प्लेटफार्म का उपयोग करके प्रौद्योगिकी के साथ शिक्षण अधिगम पर व्यवसायिक विकास कार्यक्रम, 10–12 जुलाई, 2017, नीपा, नई दिल्ली
- मूडल मूक प्लेटफार्म और मुक्त शिक्षा संसाधन के साथ शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन ऑनलाइन पर कार्यशाला, 7–9 अगस्त, 2017, नीपा, नई दिल्ली

वर्ष 2017–18 के दौरान, डिप्लोमा कार्यक्रमों के अलावा, नीपा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 146 अभिविन्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं सेमिनार, सम्मेलन और बैठकें आयोजित की।

कुल 8,618 प्रतिभागियों में से 8,544 (तालिका 2.4) भारतीय प्रतिभागी थे। तथा शेष 74 भागीदार अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों से थे (तालिका 2.3)।

संस्थान के स्थापना दिवस

संस्थान प्रतिवर्ष 11 अगस्त को अपना स्थापना दिवस मनाता है। प्रथम स्थापना दिवस व्याख्यान 2007 में प्रो. प्रभात पटनायक, उपाध्यक्ष, केरल राज्य योजना बोर्ड, 'आल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स ऑन हायर एजुकेशन इन द कांटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन' पर दिया गया। 2008 में 'डिजाईनिंग आर्किटेक्चर फॉर ए लर्निंग रिवोल्यूशन बेसड आन लाईफ साइकिल अप्रोच' पर प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन, संसद सदस्य (राज्य सभा), यूनेस्को इकोटेक्नोलॉजी पीठ, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउन्डेशन ने दिया, तीसरा व्याख्यान 2009 में प्रो. आंदेबेतिल, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर तथा प्रोफेसर ऐमिरेटस, समाजशास्त्र, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 'यूनिवर्सीटीज़ इन द ट्वेन्टी फर्स्ट संेचुरी' विषय पर दिया। 2010 में चौथा व्याख्यान प्रो. मृणाल मिरी, अध्यक्ष, शासी निकाय, सेंटर फार द स्टडी आफ डवलपिंग सोसायटीज़ ने 'एजुकेशन, ऑटोनॉमी एंड अकाउन्टेबिलिटी' विषय पर दिया। सातवां स्थापना दिवस व्याख्यान प्रो. कृष्ण कुमार, प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 'एजुकेशन एंड मोर्डनटी इन मौडर्न इंडिया' विषय पर दिया। आठवां स्थापना दिवस व्याख्यान अगस्त 2014 में ''इमेजिंग नॉलेजः ड्रीमिंग डेमोक्रेसी' पर प्रो. शिव विश्वनाथन, प्रोफेसर, स्कूल आफ गवर्नमेन्ट एंड पब्लिक पॉलिसी, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनीवर्सीटी ने दिया। अगस्त 2015 में नौवां स्थापना दिवस व्याख्यान, टी.के. ओमेन, प्रोफेसर एमिरटस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा 'एजुकेशन एस ऑन इंस्टटरूमेन्ट ऑफ सोशल ट्रांसफारमेशनः द रोल आफ मदर टंग' विषय पर दिया। दसवां स्थापना दिवस व्याख्यान अगस्त 2016 में प्रो. टी.एन. मदान, माननीय प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ इकानॉमिक ग्रोथ, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ने ''एम.आई.एम. एजूकेटेड पर्सन? रिफ्लेक्टिंग ऑन बिकमिंग एंड बीईंग'' पर दिया। 11वां स्थापना दिवस व्याख्यान अगस्त 2017 में समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रो. कुलदीप माथुर, भूतपूर्व निदेशक, नीपा तथा प्रोफेसर विधि और अभिशासन, जे.एन.यू., नई दिल्ली द्वारा 'चेंजिंग पर्सपैक्टिव्सः नियो लिबरल पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड एजुकेशन इन इंडिया'' विषय पर दिया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस

वर्ष के प्रत्येक 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वर्षगांठ पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक भारत के केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रहे थे। इस पावन अवसर पर नीपा प्रत्येक वर्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्मृति व्याख्यान का आयोजन करता है। इस स्मृति श्रृंखला में प्रतिष्ठित शिक्षाविद् जैसे प्रोफेसर के.एन. पाणिकर, मुशीरूल हसन, अमिया बागची, पीटर डीसुजा, जोया हसन, कपिला वात्सायन और अपर्णा बासु ने व्याख्यान दिया।

मौलाना आज़ाद व्याख्यान दिनांक 9 नवंबर 2017 को भारतीय पुनर्वास केन्द्र में प्रो. फुरकान कमर, प्रबंधन अध्ययन केद्र, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली और भूतपूर्व, महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा दिया गया। व्याख्यान का विषय था ''एसेन्शियल फॉर एक्सीलेन्स इन हायर एजुकेशनः व्हाई शुड द आब्वीयस बी सो एलुसिव?' इस व्याख्यान की अध्यक्षता प्रो. श्याम मेनन, कुलपति अंबेडकर विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा की गई। इस समारोह में नीपा के छात्र, संकाय सदस्य तथा आमंत्रित अतिथियों के अलावा दिल्ली के अन्य संस्थानों के शिक्षाविद् और छात्रों ने भाग लिया।

भारत
राज्यवार भागीदारी
2017-18

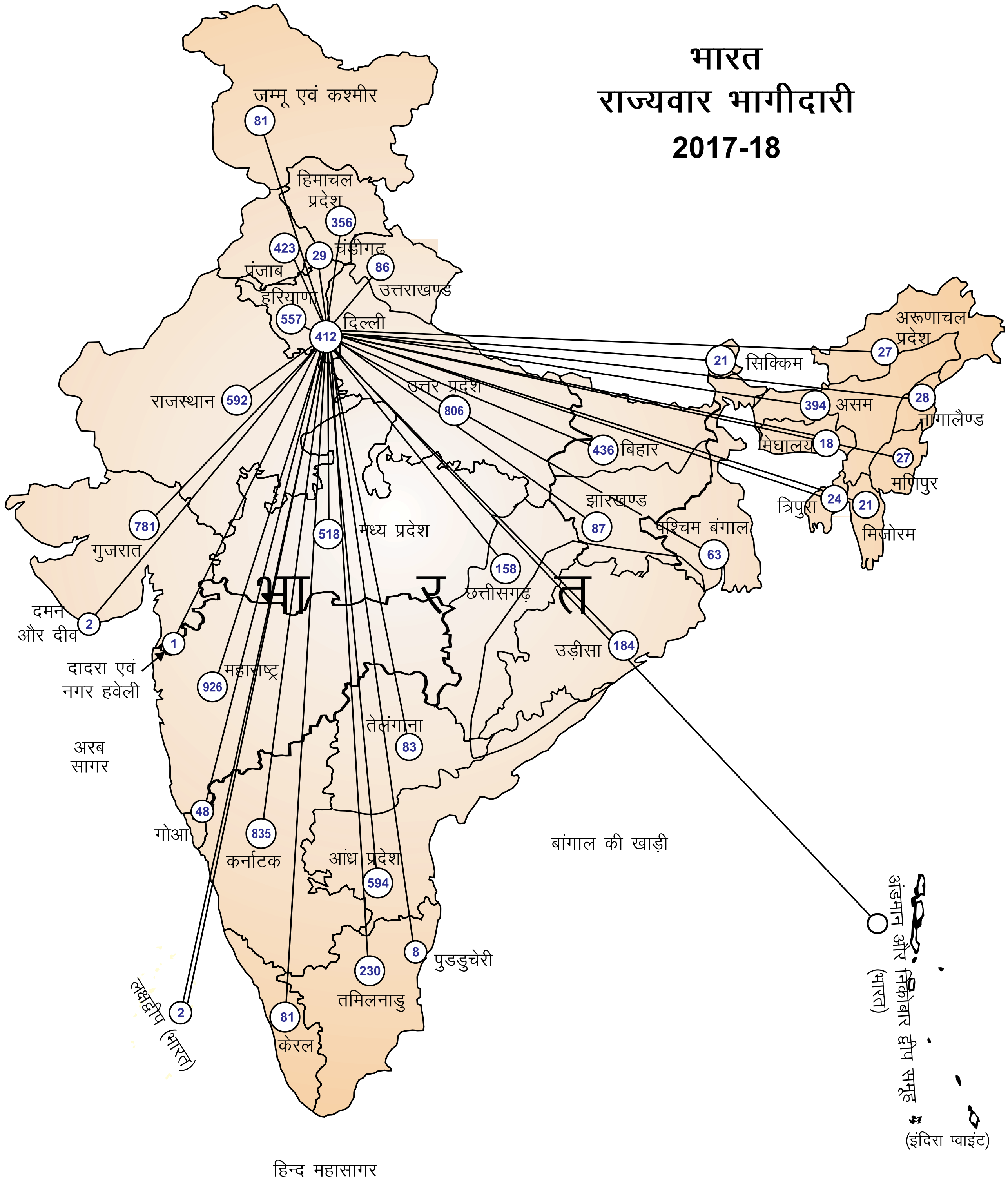

Map not to scale

3

अनुसंधान

अनुसंधान

संस्थान, शिक्षा क्षेत्र में विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु साक्ष्य आधारित विकल्पों और रणनीतियों को तैयार के लिए नवीन ज्ञान जुटाने हेतु, शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रबंधन को विशेषकर ध्यान में रखते हुए, विभिन्न विषयों में पारस्परिक शोध और अध्ययनों को बढ़ावा और सहायता प्रदान करता आ रहा है। संस्थान भारत के विभिन्न राज्यों और अन्य देशों में भी गुणात्मक तथा गणनात्मक दोनों प्रकार के शोध, वर्तमान नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का पुनरीक्षण और मूल्यांकन की तकनीकों तथा प्रशासनिक ढ़ांचों एवं प्रविधियों में तुलनात्मक अध्ययन करता है। अध्ययनों सहित ऐसे कार्य–शोध पर जोर दिया जाता है, जो शैक्षिक नीति,

योजना और प्रबंधन में सुधार के लिए मुख्य क्षेत्रों में नवीन ज्ञान को सृजित कर सकता है।

एम.फिल. और पी–एच.डी. कार्यक्रमों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय संस्थान के संकाय सदस्यों द्वारा किए जाने वाले शोध अध्ययनों, अन्य ऐजेंसियों द्वारा प्रायोजित शोध अन्तरर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त अध्ययनों कार्यक्रम मूल्यांकन अध्ययनों और आंकड़ा प्रबंधन अध्ययनों जैसे शोध कार्यक्रम को भी सहायता प्रदान करता है। शिक्षा प्रणाली में उठने वाले संभावित प्राथमिकता के मुद्दों अथवा भारतीय शिक्षा प्रणाली वास्तव में जिन मुद्दों से जूझ रही है, उनसे संबंधित शोध अध्ययन होते हैं। समीसाधीन वर्ष के दौरान, 7 शोध अध्ययन पूर्ण किए गए, जबकि 38 अध्ययन प्रगति पर थे।

पूर्ण शोध अध्ययन

(31 मार्च, 2018 तक)

1. **मध्य प्रदेश और बिहार में प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में स्थानीय निकायों के साझे दायित्वों और क्षमता पर अध्ययन**

अन्वेषकः प्रो. कुमार सुरेश

अध्ययन का मसौदा रिपोर्ट पूर्ण हो गया था लेकिन स्थानीय प्रशासन से संबंधित विषयगत अध्ययन के एक भाग के रूप में अधिक सूचना को शामिल करने के बाद अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

2. **शिक्षा नीति और सुधार के कार्यान्वयन में शिक्षा मंत्रालय नेतृत्व को मजबूत बनाना**

अन्वेषकः प्रो. के. सुजाता, डा. आर.एस. त्यागी, श्री ए.एन. रेड्डी, डा. वी. सुचरिता

रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

3. **जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए विशेष प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजनाः एक मूल्यांकन**

अन्वेषकः डा. वेटुकुरी पी.एस. राजू

अध्ययन रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत।

4. **नागरिक शिक्षा और लोकतांत्रिक नियोजन के लिए उच्च शिक्षाः उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और भेदभाव का अध्ययन**

अन्वेषकः डा. निधि एस. सभरवाल और डा. सी.एम. मलिश

परियोजना संपन्न, संश्लेषण रिपोर्ट और छह राज्य रिपोर्ट प्रस्तुत।

20 जून, 2017 को विविधता और भेदभाव पर नीति की संक्षिप्त समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक आयोजित की जाएगी।

नवंबर 2017 को प्रकाशित होने की उम्मीद, शीर्षक ''नीति संक्षिप्ति'' 1ः भारत में उच्च शिक्षा के लिए समान पहुँच; नीति संक्षिप्ति 2ः भारत में उच्च शिक्षा में अकादमिक एकीकरण हासिल करना; नीति संक्षिप्ति 3ः भारत में सामाजिक रूप से समावेशी उच्च शिक्षा परिसरों का विकास करना।

प्रत्येक मॉड्यूल के समग्र दृष्टिकोण और सामग्री की सामूहिक समझ विकसित हेतु मॉड्यूल के लेखकों की पहली बैठक 16 मार्च, 2017 को आयोजित की गई थी।

मॉड्यूल के लिए पहचाने गये क्षेत्रों में शामिल हैः

मॉड्यूल 1ः उच्च शिक्षा में छात्र विविधता और सामाजिक समावेशः अवधारणा और दृष्टिकोण

मॉड्यूल 2: उच्च शिक्षा में छात्र विविधता का वर्गीकरण

मॉड्यूल 3: परिसरों में अकादमिक एकीकरण प्राप्त करने के लिए दृष्टिकोण

मॉड्यूल 4: उच्च शिक्षा में भेदभाव के रूप

मॉड्यूल 5: परिसर में सामाजिक समावेश

मॉड्यूल 6: छात्र विविधता के प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र

मॉड्यूल 7: छात्र विविधता, नागरिक शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी

मॉड्यूल का लेखन प्रगति पर है

5. उच्चतर और तकनीकी संस्थानों में एकाग्रता और अधिपूर्ति

अन्वेषकः प्रो. एन.वी. वर्गीज, डा. जिणुशा पाणिग्रही और सुश्री अनुभा रोहतगी

अंतिम रिपोर्ट नवंबर 2015 में यूजीसी को सौंपी गई। परियोजना पूरी हो गई।

सीपीआरएचई रिसर्च पेपर सीरीज 8 के रूप में 'भारत में उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्तीः नेट परिणाम का विश्लेषण' शीर्षक वाली परियोजना पर आधारित शोध पत्र अक्टूबर 2017 में प्रकाशित होने की संभावना है।

6. मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना (एसपीक्यूईएम) का कार्यान्वयन के मूल्यांकन के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अध्ययन।

अन्वेषकः प्रो. ए.के. सिंह, प्रो. मंजू नरूला, डा. एस.के. मलिक, डा. नरेश कुमार

मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकनपरक अध्ययन अगस्त, 2017 से फरवरी, 2018 तक चार राज्यों (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तर पदेश) में किया गया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्यों में इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले मदरसों और मकतबों में गुणवत्तापरक शिक्षण योजना (एसपीक्यूईएम) के कार्यान्वयन का अध्ययन करना; और उन राज्यों को शामिल करना जहाँ यह स्कीम चलाई जा रही है और उसके अस्तित्व में आने के समय से ही निरन्तर वित्तीय सहयता दी गई है। राज्य से जिला स्तर तक अध्यापक के मानदेय सहित निधियों के संवितरण संबंधी प्रक्रिया और मानदेय के संवितरण में हुए विलम्ब का अध्ययन करना है; आधुनिक विषयों के शिक्षण हेतु शिक्षाशास्त्रीय (शैक्षणिक) सहायता, पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण, शिक्षण अधिगम सामग्री, विज्ञान/कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना जैसे संघटकों के लिए धनराशि के प्रभावी उपयोग का अध्ययन करना तथा योजना के कार्यान्वयन में सुधार और निगरानी के एिल उपयुक्त सुझाव देना शामिल था।

मूल्यांकन परक अध्ययन गौण और प्राथमिक दोनों प्रदत्त के संकलन पर आधारित था। जहाँ एक ओर द्वितीयक प्रदत्त (आंकड़े) दस्तावेजों, प्रगति प्रतिवेदनों, दिशा निर्देश इत्यादि से एकत्र किए गए वहीं प्राथमिक प्रदत्त अर्द्धसंरचनाबद्ध साक्षात्कार समय तालिका/प्रश्नावलियों और संबंधित हितधारकों (यथा विद्यार्थी, अध्यापकगण, मदरसा बोर्ड और मदरसा प्रबंधन समिति और अन्य संबंधित कार्यकारी अधिकारीगण, प्रभारी राज्य नोडल अधिकारी, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी एवं अन्य व्यक्तियों के साथ अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से एकत्र की गई। फरवरी, 2018 में पूर्ण प्रतिवेदन मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उनके अवलोकनार्थ और प्रतिपुष्टि एवं अग्रेतर कार्रवाई के लिए सौंपा गया। विचारार्थ विषय के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कहने पर अध्ययन किया गया।

7. प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक पहुँच और बच्चों की भागीदारी की वर्तमान स्थिति पर एक अध्ययनः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का तुलनात्मक अध्ययन।

अन्वेषकः डा. मधुमिता बंद्योपाध्याय

अध्ययन, शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग का हिस्सा था

शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. अरूण सी. मेहता के समक्ष प्रस्तुत किया।

अनुसंधान अध्ययन (जारी)

(31 मार्च, 2018 तक)

1. शैक्षिक प्रशासन और विषयगत अध्ययन का तीसरा अखिल भारतीय सर्वेक्षण

अन्वेषकः प्रो. कुमार सुरेश

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए दो शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण (1973 में, और दूसरा 1990 में) किया था। सर्वेक्षण का मूल उद्देश्य व्यवस्था की बदलती मांग के लिए शैक्षिक प्रशासन की स्थिति और इसकी जवाबदेही की जांच करना था। पिछले दो दशकों के दौरान, अनेक नीतिगत पहल और शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक ढांचे में सुधार और विभिन्न स्तरों, राज्य, क्षेत्र, जिला, उप–जिला और संस्थागत स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इन पहलकदमियों और हस्तक्षेपों ने शैक्षिक शासन में नए आयाम जोड़े हैं। विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक प्रशासन की स्थिति की जांच करने और शैक्षिक शासन में बदलाव का पता लगाने के लिए, नीपा ने 2013 में तीसरा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण शुरू किया जिसमें अनेक विषयगत अध्ययन शामिल थे, जिसमें शैक्षिक प्रशासन और शासन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया था। सर्वेक्षण के विशिष्ट उद्देश्य हैंः–

1. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संरचनाओं, प्रणाली और प्रक्रिया की अवधि में शैक्षिक प्रशासन की वर्तमान स्थिति की जांच करना।
2. शैक्षिक प्रशासन की प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कार्यनीति तैयार करने के लिए हस्तक्षेप के प्रमुख मुद्दों और क्षेत्रों की पहचान करना; तथा
3. राष्ट्रीय, राज्य और संघ राज्य–क्षेत्रों के स्तर पर स्कूली शिक्षा के संचालन में सुधार के उपाय सुझाना।

बड़े सर्वेक्षण के भाग के रूप में, निम्नलिखित अध्ययन और गतिविधियाँ की गई हैं–

4. केरल में शैक्षिक प्रशासन पर पायलट अध्ययन, डा. आर.एस. त्यागी
5. डा. मंजू नरुला द्वारा बिहार में शैक्षिक प्रशासन पर पायलट अध्ययन (अंतिम रूप में)
6. इन पायलट अध्ययनों के आधार पर, तीसरे सर्वेक्षण के लिए उपकरणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है; तथा
7. प्रो. कुमार सुरेश द्वारा मध्य प्रदेश और बिहार में प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में स्थानीय निकायों की साझा जिम्मेदारियों और क्षमताओं पर अध्ययन।

शैक्षिक प्रशासन के तीसरे अखिल भारतीय सर्वेक्षण पर परियोजना के तहत 23 राज्य रिपोर्टें पूर्ण और प्रस्तुत की गईं।

(1. आंध्र प्रदेश, 2. अरूणाचल प्रदेश, 3. असम, 4. बिहार, 5. छत्तीसगढ़, 6. गोआ, 7. कर्नाटक, 8. केरल, 9. मध्य प्रदेश, 10. महाराष्ट्र, 11. मणिपुर, 12. मिजोरम, 13. नागालैंड, 14. ओडिशा, 15. सिक्किम, 16. उत्तराखण्ड, 17. गुजरात, 18. हरियाणा, 19. हिमाचल प्रदेश, 20. पंजाब, 21. तलिमनाडु, 22. तेलंगाना, 23. उत्तर प्रदेश)

2. शैक्षिक प्रशासन की संरचना और कार्यों का अध्ययन (शैक्षिक प्रशासन के तीसरे अखिल भारतीय सर्वेक्षण के भाग के रूप में विषयगत अध्ययन)

अन्वेषकः प्रो. कुमार सुरेश, डा. मंजू नरूला और डा. विनीता सिरोही

प्रस्तावित परियोजना संरचना और शैक्षिक प्रशासन के कार्यों के पहलू पर संसाधन सामग्री की विशिष्टता को देखते हुए विशेष महत्व मानती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शैक्षिक प्रशासन की संरचना और कार्यों पर शायद ही

कोई जानकारी उपलब्ध है। शिक्षा विभाग की वेबसाइटें, निश्चित रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शैक्षिक प्रशासन की संरचना पर बुनियादी जानकारी शामिल करती हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से सचिवालय और निदेशालय स्तरों तक सीमित हैं। ज्यादातर मामलों में, निदेशालय स्तर से नीचे शैक्षिक प्रशासनिक ढांचे की जानकारी बहुत कम है। सभी स्तरों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शैक्षिक प्रशासनिक ढांचे की जानकारी की अनुपलब्धता के अलावाय शैक्षिक प्रशासन के प्रत्येक और हर स्तर से जुड़ी कार्यात्मक जिम्मेदारी पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। शैक्षिक विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं की पूरी श्रृंखला ने शैक्षिक प्रशासन में नए आयाम जोड़े हैं। राज्यों में कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रारूप ने प्रशासन के समानांतर ढांचे भी बनाए। अनेक मामलों में, राज्यों में शिक्षा की समानांतर संरचना और मुख्यधारा के प्रशासनिक ढांचे के बीच शायद ही कोई सीधा संबंध है। इसी तरह, वर्षों से अकादमिक सहायता प्रणाली की संरचना का विस्तार हुआ है।

उद्देश्य

1. शैक्षिक प्रशासन की संरचना और कार्यों पर विस्तृत जानकारी एकत्र करना।
2. एसएसए/आरएमएसए/एमडीएम/आरटीई, आदि की शुरूआत के विकास के लिए विशिष्ट संदर्भ के साथ, वर्षों में हुए परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण करना।
3. शैक्षिक प्रशासन के भीतर संरचनाओं और कारकों की विविधता को बांधना
4. शैक्षिक प्रशासन में एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से या जारी अद्यतनीकरण के प्रावधान के साथ मौजूदा व्यवस्था के हिस्से के रूप में शैक्षिक प्रशासन पर सभी प्रासंगिक जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू हुआ।

आंकड़ा संग्रह के लिए रूपरेखा और उपकरण अंतिम रूप देने की प्रारंभिक कार्य प्रक्रियाधीन

3. शैक्षिक प्रशासन में जिला और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की स्थिति, भूमिका और जिम्मेदारियां (तृतीय अखिल भारतीय सर्वेक्षण प्रशासन का हिस्सा के रूप में विषयगत अध्ययन)

अन्वेषकः प्रोफेसर कुमार सुरेश, डा. मंजू नरूला और डा. वी. सुचरिता*

जिला और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण शैक्षिक अधिकारी हैं। वे स्कूलों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिला और ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक प्रशासन उनकी निगरानी और समर्थन के मामले में स्कूलों से निकटता से जुड़ा हुआ है; वे स्कूलों और उच्च स्तर के शैक्षिक प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। स्कूल स्तर पर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन इन अधिकारियों की महत्वपूर्ण कार्यकारी जिम्मेदारियों को दर्शाता है। भूमिका और जिम्मेदारियों के विस्तार के संपूर्ण पहुंच को समझना महत्वपूर्ण है और यह भी कि कैसे ये अधिकारी क्षेत्र स्तर पर अधिकारियों की क्षमता में उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।

अध्ययन का लक्ष्यः—

1. जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की स्थिति और बदलती भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, यदि कोई हो, का अध्ययन करना।
2. राज्य/जिला और ब्लॉक स्तर के शैक्षिक प्रशासन में शुरू किए गए आरटीई, 2009 और अन्य विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप, डीईओ और बीईओ की कार्यकारी जिम्मेदारियों में आए बदलाव का अध्ययन,
3. बीईओ और डीईओ की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन करना।

अध्ययन मुख्य रूप से तीसरे अखिल भारतीय सर्वेक्षण शैक्षिक प्रशासन के साथ—साथ जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों से संबंधित क्षेत्र—आधारित डाटा संग्रह पर उपलब्ध डेटाबेस पर आधारित होगा। शैक्षिक प्रशासन के तीसरे अखिल भारतीय सर्वेक्षण की राज्य रिपोर्ट में जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा प्रशासन के बारे में कुछ

बुनियादी जानकारी शामिल है, जिसमें वर्णनात्मक प्रारूप के अनुसार स्थिति, भूमिका और कार्यकारी जिम्मेदारियां शामिल हैं। हालांकि, विश्लेषणात्मक आयाम शामिल नहीं हैं। वर्णनात्मक आंकड़ों का विश्लेषण एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य से किया जाएगा। वर्तमान अध्ययन मुख्य रूप से क्षेत्र अध्ययन के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों और जानकारी के अलावा इन आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित होगा।

प्रारंभिक कार्य तैयारी की प्रक्रिया के तहत आंकड़ा संग्रह के लिए ढांचे और उपकरणों से संबंधित कार्य शुरू है।

4. केंद्रीय प्रायोजित माध्यमिक शिक्षा के लिए छात्राओं के प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना का एक मूल्यांकन अध्ययन (मा.सं.वि. मंत्रालय से अनुरोध)

अन्वेषकः डा. वेटुकुरी पी.एस. राजू

अध्ययन का उद्देश्य एनएसआईजीएसई योजना के तहत देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के प्रभाव का मूल्यांकन करना है।

गहन अध्ययन तीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। नमूना राज्यों का चयन देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रोत्साहन के उपयोग पैटर्न के आधार पर किया जाएगा। सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में कक्षा IX और X में अध्ययनरत प्रत्येक नमूना राज्य की कम से कम 350 लाभार्थी छात्राओं का चयन किया जाएगा।

अंतरिम रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी गई है। क्षेत्र से प्राथमिक डाटा का संग्रह, डाटा की कोडिंग और प्रविष्टि प्रगति पर है। अंतिम रिपोर्ट 31 अगस्त, 2018 तक प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो जाएगी।

5. केंद्र प्रायोजित योजना 'राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना' का मूल्यांकन अध्ययन

अन्वेषकः डा. वेटुकुरी पी.एस. राजू

भारत सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों ने वर्षों में शिक्षा की घरेलू लागत के बोझ को कम करने में मदद के लिए अनेक छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता योजनाओं और प्रोत्साहन की घोषणा की है। सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूह (जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और छात्राएं) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (जैसे गरीबी रेखा से नीचे के परिवार) और इन लोगों की छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन के विशेष लक्ष्य समूह हैं। छात्रवृत्ति का उद्देश्य मेधावी छात्रों की पहचान करना और उन्हें माध्यमिक और साथ ही उच्चतर शिक्षा को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित करना है। ऊपर उठाए गए सभी मुद्दों के मद्देनजर, स्कूल स्तर पर केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा को पूरा करने के लिए अनेक छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। इस तरह की योजनाओं में से एक राष्ट्रीय साधन–सह–छात्रवृत्ति योजना'(एनएमएमएसएस) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने 2008 में ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यम से आरंभ किया था।

लक्ष्यः–

1. केंद्र प्रायोजित 'राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना' की कार्यान्वयन प्रक्रिया का अध्ययन करना।
2. 2008–09 से 2016–17 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना के उपयोग और उपलब्धि पैटर्न का अध्ययन करना।
3. समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के छात्रों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के प्रभाव का आकलन करना।
4. छात्रों को छात्रवृत्ति राशि के संवितरण से संबंधित प्रभावी कार्यान्वयन और मुद्दों में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।
5. योजना में सुधार के लिए सुझाव और सिफारिशें देना।

अध्ययन का उद्देश्य केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के

तहत देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। अध्ययन माध्यमिक और प्राथमिक डाटा का उपयोग करके वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का उपयोग करके किया जाएगा।

अंतरिम रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी गई। क्षेत्र से प्राथमिक डाटा का संग्रह, डाटा की कोडिंग और फीडिंग प्रगति पर है। अंतिम रिपोर्ट 31 अगस्त, 2018 तक तैयार हो जाएगी।

6. भारत में तुलनात्मक शैक्षिक लाभ की स्थानिक गतिशीलता

अन्वेषकः प्रो. मोना खरे

प्रस्ताव विकास, प्रस्तुति और अनुमोदन, साहित्य समीक्षा, भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक संकेतकों की पहचान के लिए विचार–विमर्श तथा स्कूल शिक्षा विकास के लिए सारणीकरण और डाटा विश्लेषण पूर्ण हो चुका है और पहले तीन मसौदा अध्याय तैयार है। उच्च शिक्षा विकास के संकेतक की पहचान की गई है और माध्यमिक स्रोतों से डाटा संकलन प्रगति पर है। पहचान किए गए स्थानिक विकास और डाटा संकलन के समग्र सूचकांक के निर्माण के लिए संकेतक प्रगति पर हैं। जिला स्तर पर डाटा की उपलब्धता का पता लगाने के लिए, राज्य के चुनिंदा अधिकारियों से संपर्क किया जाता है। सेमिनार में प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्रकाशित तीन तीन पत्र, प्रकाशन के लिए स्वीकार किए गए हैं, कुछ महीनों में प्रकाशित होने की उम्मीद है।

7. मॉड्यूलः उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विविधता और भेदभाव

अन्वेषकः डा. निधि एस. सभरवाल और डा. सी.एम. मलिश

मॉड्यूल के समग्र दृष्टिकोण और सामग्री की सामूहिक समझ विकसित करने में मदद के लिए मॉड्यूल के लेखकों की पहली बैठक 16 मार्च, 2017 को आयोजित की गई थी।

मॉड्यूल के लिए पहचाने गये क्षेत्रों में शामिल हैः

मॉड्यूल 1ः उच्चतर शिक्षा में छात्र विविधता और सामाजिक समावेशः अवधारणा और दृष्टिकोण

मॉड्यूल 2ः उच्च शिक्षा में छात्र विविधता का वर्गीकरण

मॉड्यूल 3ः परिसरों में अकादमिक एकीकरण प्राप्त करने के लिए दृष्टिकोण

मॉड्यूल 4ः उच्चतर शिक्षा में भेदभाव के रूप

मॉड्यूल 5ः परिसर में सामाजिक समावेश

मॉड्यूल 6ः छात्र विविधता के प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र

मॉड्यूल 7ः छात्र विविधता, नागरिक शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी

इन मॉड्यूलों का लेखन प्रगति पर है।

8. भारत में उच्चतर शिक्षा स्नातकों का रोजगार और रोजगार–शीलता

अन्वेषकः प्रोफेसर मोना खरे

अध्ययन के लिए अनुसंधान प्रस्ताव 2015 में विकसित किया गया था। प्रस्ताव विशेषज्ञों को भेजा गया और 26 अक्टूबर 2015 को आयोजित विशेषज्ञ समिति की बैठक में अनुमोदन के उपरान्त मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान उपकरण विकसित किए गए थे। 12 मई, 2016 को बाहरी विशेषज्ञों के एक समूह के साथ अनुसंधान उपकरणों पर एक चर्चा बैठक आयोजित कर राज्य की टीमों का गठन किया गया और टीम के सदस्यों की पहचान की गई। अनुसंधान उपकरणों को अंतिम रूप देने के बाद, छात्रों और कॉलेज के संकाय/प्रशासन के परिप्रेक्ष्य को उत्पन्न करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक प्रायोगिक सर्वेक्षण किया गया तथा नियोक्ताओं और कर्मचारियों के परिप्रेक्ष्य उत्पन्न करने के लिए केनरा बैंक में सर्वेक्षण भी किया गया था। प्रदत्त प्रश्नावली के अलावा, सर्वेक्षण में एफजीडी और साक्षात्कार शामिल थे। पूरी गतिविधि अगस्त और नवंबर 2016 के बीच पूरी हुई। प्रायोगिक सर्वेक्षण का आंकड़ा प्रविष्टि और विश्लेषण पूरा हो गया और उपकरण पक्के हो गए। पहली कार्यप्रणाली कार्यशाला 18–19 जनवरी, 2017 को आयोजित की गई जिसमें 17 राज्य टीमों के सदस्यों ने भाग लिया। अनुसंधान उपकरणों पर गहन चर्चा उपरान्त उनके संबंधित राज्यों में क्षेत्र सर्वेक्षण करने के लिए साझा किया गया।

i) बैंगलोर विश्वविद्यालय, बैंगलोर के सहयोग से "शिक्षा में लैंगिक बजट" पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

ii) हैदराबाद में हिटाची और एली कंपनियों में "भारत में उच्चतर शिक्षा स्नातकों का रोजगार और रोजगारशीलता योग्यता" पर गोल–मेज सम्मेलन और एफजीडी का आयोजन और संचालन किया गया।

iii) ओरिएंटल, लखनऊ में 'भारत में उच्च शिक्षा स्नातकों का रोजगार और रोजगारशीलता' परियोजना पर गोलमेज सम्मेलन और एफजीडी का आयोजन और संचालन किया गया।

iv) सिस्को, बेंगलुरु में "भारत में उच्च शिक्षा स्नातकों का रोजगार और रोजगारशीलता" परियोजना पर गोलमेज सम्मेलन और एफजीडी का आयोजन और संचालन किया गया।

v) एचसीएल, लखनऊ में "भारत में उच्चतर शिक्षा स्नातकों का रोजगार और रोजगारशीलता" पर गोलमेज और एफजीडी का आयोजन और संचालन।

vi) टीसीएस, बेंगलुरु में 'भारत में उच्च शिक्षा स्नातकों का रोजगार और रोजगारशीलता' परियोजना पर गोलमेज सम्मेलन और एफजीडी का आयोजन और संचालन।

vii) महिंद्रा–टेक, नोएडा में "भारत में उच्चतर शिक्षा स्नातकों के रोजगार और रोजगारशीलता" पर गोलमेज सम्मेलन और एफजीडी का आयोजन और संचालन किया गया।

viii) रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, नई दिल्ली में "भारत में उच्चतर शिक्षा स्नातकों के रोजगार और रोजगारशीलता" पर गोलमेज–सम्मेलन और एफजीडी का आयोजन और संचालन किया।

ix) बैंगलोर विश्वविद्यालय में 'भारत में उच्च शिक्षा स्नातकों का रोजगार और रोजगारशीलता' परियोजना पर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आमने–सामने साक्षात्कार आयोजित और संचालित किया गया।

x) मुंबई विश्वविद्यालय में 'भारत में उच्च शिक्षा स्नातकों का रोजगार और रोजगारशीलता' परियोजना पर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आमने–सामने साक्षात्कार आयोजित और संचालित किया गया।

xi) दिल्ली विश्वविद्यालय में 'भारत में उच्च शिक्षा स्नातकों का रोजगार और रोजगारशीलता' परियोजना पर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आमने–सामने साक्षात्कार आयोजित और संचालित किया गया।

xii) भारत में 'उच्चतर शिक्षा स्नातक की रोजगार और रोजगारशीलता' परियोजना पर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और हिताची और एली कंपनियों के साथ हैदराबाद में आमने–सामने साक्षात्कार आयोजित और संचालित किया गया।

xiii) लखनऊ में एचसीएल और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनियों में 'भारत में उच्चतर शिक्षा स्नातकों के रोजगार और रोजगारशीलता' पर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आमने–सामने साक्षात्कार आयोजित और संचालित किया गया।

xiv) राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में 'भारत में उच्च शिक्षा स्नातकों का रोजगार और रोजगारशीलता' परियोजना पर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आमने–सामने साक्षात्कार आयोजित और संचालित किया।

xv) महिंद्रा–टेक, नोएडा में परियोजना 'भारत में उच्च शिक्षा स्नातकों का रोजगार और रोजगार शीलता' पर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आमने–सामने साक्षात्कार आयोजित और संचालित किया।

xvi) रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, नई दिल्ली में 'भारत में उच्चतर शिक्षा स्नातकों का रोजगार और रोजगारशीलता' पर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आमने–सामने साक्षात्कार आयोजित और संचालित किया गया।

राज्यों में आंकड़ा संग्रह पूरा हो गया है।

जनवरी 2018 में राज्य टीमों के लिए दूसरी कार्यप्रणाली कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

अध्ययन से प्रकाशित दो शोध पत्र इस प्रकार हैंः–

i) टेकिंग द स्किल्स मार्च फॉरवर्ड इन इंण्डिया – ट्रांजिशनिंग टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, (2016) इन

माथियाज पिल्ज एड इंडियाः वर्क ऑफ द वर्ल्ड, के लिए तैयारी, स्प्रिंगर वी.एस.

ii) ग्रैजुएट इम्पलायिबिल्टीः इंडियॅास चैलेंज पोस्ट 2015 विकास एजेंडा, भारतीय आर्थिक जर्नल, दिसंबर 2015, पृ. 97–111

9. भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ताः संस्थागत स्तर पर बाह्य और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन का एक अध्ययन

अन्वेषकः डा. अनुपम पचौरी

शोध अध्ययन एक बहु–राज्य और बहु–संस्थागत अध्ययन है जिसका उद्देश्य बाहरी गुणवत्ता आश्वासन (ईक्यूए) की संरचना और कार्यों, उनके अंतर–संबंध और 10 उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्थागत स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन पर प्रतिभागियों की भागीदारी को पांच राज्यों अर्थात कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और तेलंगाना से मिश्रित तरीकों के माध्यम से शामिल किया है।

परियोजना कार्यान्वयन चरण में है, और इस अनुसंधान परियोजना के तहत पूरी की जाने वाली गतिविधियाँ हैंः–

i) अध्ययन के लिए अनुसंधान प्रस्ताव सीपीआरएचई आंतरिक संकाय की बैठक में 24 सितंबर, 2014 को विकसित और प्रस्तुत की गयी थी।

ii) प्रतिक्रिया के बाद और साहित्य समीक्षा के मद्देनजर, प्रस्ताव को संशोधित किया गया और 08 जनवरी, 2015 को आयोजित विशेषज्ञ समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

iii) पांच राज्यों में से प्रत्येक चयनित विश्वविद्यालयों से पांच विश्वविद्यालयों और एक संबद्ध कॉलेज से पांच संस्थागत स्तर की टीमों का गठन किया गया है।

iv) मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान उपकरणों को विकसित किया गया जिसमें छात्रों और संकाय सर्वेक्षण प्रश्नावली, संकाय और छात्रों के साथ एफजीडी के लिए फोकस समूह चर्चा विषय, चयनित विश्वविद्यालयों और संबंधित कालेजों में संस्थागत नेतृत्वकर्ताओं के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम शामिल हैं।

v) उच्च शिक्षा में अनुसंधान में लगे बाहरी विशेषज्ञों/शोधकर्ताओं के एक विशेषज्ञ समूह के परामर्श से अध्ययन के लिए शोध उपकरणों का विश्लेषण किया गया है।

vi) अनुसंधान कार्यप्रणाली कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

vii) परियोजना प्रारंभ की जा चुकी है।

viii) प्रश्नावली को नियमबद्ध किया जा रहा है और शोध टीमों की सुविधा के लिए कोडबुक विकसित की जा रही है।

ix) तीसरी अनुसंधान कार्यप्रणाली कार्यशाला 06–07, 2017 को आयोजित की गई, जहां मसौदा रिपोर्ट और संश्लेषण रिपोर्ट साथियों की टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत की गई।

x) संश्लेषण रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है; अंतिम बार प्रस्तुत करने के लिए राज्य रिपोर्टों को संशोधित किया गया।

10. भारत में उच्चतर शिक्षा का शासन और प्रबंधन

अन्वेषकः डा. गरिमा मलिक

अनुसंधान का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा कार्यों के शासन और प्रबंधन को समझने के साथ–साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को कैसे संचालित और प्रबंधित किया जाना है।

अनुसंधान परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य हैंः

i) राष्ट्रीय, राज्य और संस्थागत स्तरों पर शासन संरचना और प्रक्रियाओं के विकास पर चर्चा करना।

ii) राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण कर्ताओं और उनकी भूमिका का अध्ययन करना और यह अध्ययन करना कि शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा निदेशालय, राज्य उच्च शिक्षा परिषद और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच कैसे परस्पर तालमेल हैं; तथा

iii) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शासी निकायों की भूमिका और कार्यप्रणाली का अध्ययन करना; संस्थागत स्तर पर उच्च शिक्षा के प्रबंधन का अध्ययन करना।

परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है, और इस अनुसंधान परियोजना के दौरान पूरी होने वाली गतिविधियाँ निम्न हैं:

i) विकसित अनुसंधान प्रस्ताव;

ii) 04 दिसंबर 2014 को आयोजित विशेषज्ञ समिति की बैठक में प्रस्ताव की समीक्षा;

iii) मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण विकसित;

iv) अनुसंधान कार्यप्रणाली कार्यशाला सामग्री विकसित; तथा

v) अनुसंधान कार्यप्रणाली कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

vi) तीसरी अनुसंधान कार्यप्रणाली कार्यशाला 11–12 सितंबर, 2017 को आयोजित की गई, जहां साथियों की टिप्पणियों के लिए मसौदा राज्य रिपोर्ट और संश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

vii) संश्लेषण रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है; अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के लिए राज्य रिपोर्टों को संशोधित किया गया है। 'भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का शासन और प्रबंधन' शीर्षक से शोध पत्र फरवरी 2017 में सीपीआरएचई शोध पत्र श्रृंखला 5 के रूप में प्रकाशित।

11. भारत में सार्वजनिक उच्चतर शिक्षा संस्थानों का वित्तपोषणः निधियों के प्रवाह और उनके उपयोग का अध्ययन

अन्वेषकः डा. जिणुशा पाणिग्राही

अनुसंधान का उद्देश्य अनुदान के संदर्भ में प्राप्त संसाधनों के उपयोग के पैटर्न के साथ–साथ भारतीय संदर्भ में आय–जनक गतिविधियों के माध्यम से संसाधन आवंटन का अध्ययन करना। अध्ययन के उद्देश्य नव–उदारवादी बाजार सिद्धांत की पृष्ठभूमि में उच्च शिक्षा संस्थानों के वित्त पोषण के विविध स्रोतों का अध्ययन करना, ताकि संसाधनों की पर्याप्तता या अपर्याप्तता का विश्लेषण किया जा सके, ताकि विविध संसाधनों द्वारा अतिरिक्त संसाधनों के जुटाव में सापेक्ष चुनौतियों को समझा जा सके, उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा संसाधनों के व्यय और उपयोग के पैटर्न का विश्लेषण करना, धन की कमी के कारण किए जाने वाली गतिविधियों की पहचान करना। यह परियोजना पांच राज्यों अर्थात बिहार, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में 10 उच्च शिक्षा संस्थानों का एक केस अध्ययन है।

- तीसरी शोध कार्यप्रणाली 25–26 सितंबर, 2017 को आयोजित की गई, जहां मसौदा रिपोर्ट और संश्लेषण रिपोर्ट साथियों की टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत की गई।
- संश्लेषण रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया है; अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के लिए राज्य रिपोर्टों को संशोधित किया जाता है।
- 'रिसोर्स एलोकेशन एंड इनोवेटिव मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया' शीर्षक से शोध पत्र फरवरी, 2017 में सीपीआरएचई शोध पत्र श्रृंखला 6 के रूप में प्रकाशित ।

12. भारतीय उच्चतर शिक्षा में शिक्षण और अधिगम

अन्वेषकः डा. सायंतन मंडल

परियोजना का उद्देश्य भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षण और अधिगम के पहलुओं का विश्लेषण करना है। अनुसंधान परियोजना एक बहु–राज्य, बहु–संस्थागत अध्ययन है और छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के राज्यों में प्रत्येक के उच्च शिक्षा संस्थानों (एक विश्वविद्यालय और इसके संबद्ध कॉलेजों में से एक) के चुने हुए सेट पर विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में शिक्षण और अधिगम की जांच के लिए मिश्रित–तरीकों के दृष्टिकोण को नियोजित करता है।

परियोजना कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है, और इस अनुसंधान परियोजना के तहत पूरी की जाने वाली गतिविधियाँ निम्न हैं:–

i) अनुसंधान प्रस्ताव के विकास में शामिल प्रारंभिक कार्य;

ii) अनुसंधान उपकरण का विकास;

iii) अनुसंधान टीमों का चयन;

iv) उपकरण बैठक में विशेषज्ञों के साथ चर्चा में भागीदारी;

v) परियोजना की योजना;

vi) भारतीय उच्चतर शिक्षा में शिक्षण और अधिगम पर कार्यशाला के लिए तैयार दस्तावेज; तथा

vii) अनुसंधान कार्यप्रणाली कार्यशाला का संचालन करना।

viii) तीसरी शोध कार्यप्रणाली कार्यशाला 29–30 अगस्त, 2017 को आयोजित करना, जिसमें साथियों की टिप्पणियों के लिए मसौदा राज्य रिपोर्ट और संश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

ix) संश्लेषण रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्य रिपोर्टों को संशोधित किया गया है।

x) शोध पत्र जिसका शीर्षक है "टीचिंग–लर्निंग इन हायर एजुकेशनः इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट एण्ड एन अटैम्प्ट टूवर्डस डैवलपिंग अ न्यू टूल ऑफ एनैलिसिस" जो कि सीपीआरएचई आगामी शोध पत्र श्रृंख्ला 9 के रूप में आने वाला है।

13. उच्चतर शिक्षा की सफलता और सामाजिक गतिशीलताः विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. और अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग योजनाओं पर एक अध्ययन

अन्वेषकः डा. सी.एम. मलिश और डा. निधि एस. सभरवाल

शोध अध्ययन संस्थानों के अनुसंधान समन्वयकों के साथ पहली अनुसंधान कार्यप्रणाली कार्यशाला 02–03 मई, 2017 को आयोजित की गई, ताकि अनुसंधान उपकरण और अनुसंधान कार्यान्वयन प्रक्रिया पर एक साझा समझ विकसित की जा सके। आंकड़ा विश्लेषण अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है। अधिकांश राज्यों में सीपीआरएचई अनुसंधान समन्वयकों द्वारा क्षेत्र का दौरा पूरा कर लिया गया है।

14. निजी मानित विश्वविद्यालय में फीस का निर्धारण

अन्वेषकः डा. जिणुशा पाणिग्राही

शोध प्रस्ताव मा.सं.वि. मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित किया गया है। दोनों गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान उपकरण विकास की प्रक्रिया में हैं। चयनित संस्थानों में अध्ययन को लागू करने से पहले एक प्रायोगिक अध्ययन शुरू किया जाएगा।

15. भारत में चुनिंदा राज्यों में आरएमएसए के तहत जिला माध्यमिक शिक्षा योजना के विकास पर कार्य अनुसंधान परियोजना

अन्वेषकः प्रो. एस.एम.आई.ए. जैदी, प्रो. के. बिस्वाल और डा. एन.के. मोहंती

यह आरएमएसए के एक कार्य अनुसंधान के तहत अपने जिला माध्यमिक शिक्षा योजनाओं (परिप्रेक्ष्य और वार्षिक योजनाओं) की तैयारी में राज्यों द्वारा पालन की जाने वाली योजना प्रक्रिया, कार्यप्रणाली और तकनीकों की गंभीर समीक्षा करने का प्रयास है। जिसका मूल उद्देश्य योजना निर्माण के लिए मौजूदा सक्षम करने की स्थितियों और संस्थागत, तकनीकी और अन्य बाधाओं को समझना है और कार्यान्वयन के लिए आरएमएसए रूपरेखा को समझकर जिला स्तर की योजनाओं और माध्यमिक शिक्षा के प्रबंधन में लागू किया जाता है। इसके अलावा, डीएसईपी के निर्माण में संस्थागत, तकनीकी और व्यावसायिक बाधाओं का आकलन करने वाले योजना प्रक्रिया बैंड की खोज करने वाले जिला स्तर पर शायद ही कोई अध्ययन किया गया हो। इसलिए, अध्ययन का उद्देश्य शैक्षिक नियोजन में क्षमता निर्माण गतिविधियों के प्रभावी डिजाइन और वितरण के लिए प्रशिक्षकों के रूप में नीपा संकाय की व्यावसायिक दक्षताओं को बढ़ाने के लिए कार्य अनुसंधान के माध्यम से अतिरिक्त ज्ञान उत्पन्न करना है। इस संदर्भ में, तमिलनाडु और ओडिशा में कार्य अनुसंधान कार्यान्वित किया जा रहा है। शोध को लागू करने के लिए तमिलनाडु के चार जिलों (अर्थात सलेम, थेनी, कुड्डलोर और मदुरै) और ओडिशा के दो जिलों (अर्थात क्योनझार और गंजम) को चुना गया है।

अध्ययन का चरण I पूरा हो गया है और रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। दूसरे चरण में, तमिलनाडु और ओडिशा के पूरे चार नमूना जिला अनुसंधान दल अपने मॉडल को अंतिम रूप दे रहे हैं। जिला माध्यमिक शिक्षा योजना जून, 2018 में नीपा में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की साझा कार्यशाला में प्रस्तुत की जाएगी। इस कार्यशाला के बाद, चार जिला अनुसंधान दल अपने अंतिम डीएसईपी जमा करेंगे। चार डीएसईपी के साथ चरण I की रिपोर्ट परियोजना को पूरा करने के लिए नीपा को प्रस्तुत की जाएगी।

16. भारत में माध्यमिक शिक्षा में सार्वजनिक–निजी मिश्रणः आकार और इन–स्कूल सुविधाएं और इंटेक प्रोफाइल

अन्वेषकः डा. एन.के. मोहंती और प्रो. एस.एम. आई.ए. जैदी

शिक्षा में निजी क्षेत्र की भूमिका में बहस को ध्यान में रखते हुए, सामान्य रूप से, और शिक्षा सेवा के वितरण में सार्वजनिक–निजी मिश्रण, वर्तमान मैक्रो–स्तरीय अध्ययन का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय नेटवर्क की संरचना और आकार, प्रबंधन और क्षेत्र, सुविधाओं के मामले में उनकी विशेषताओं, स्टाफिंग पैटर्न और सभी राज्यों में सामाजिक पृष्ठभूमि के मामले में छात्र प्रोफाइल को ध्यान में रखना। अध्ययन आय समूह द्वारा राज्य में जनसंख्या के वितरण के लिए सार्वजनिक और निजी संस्थानों में भागीदारी दरों को जोड़ने का प्रयास भी करेगा। यह विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा के प्रावधानों और क्षेत्रीय भूमिका में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने आरएमएसए कार्यनीतियों की जांच करने, प्रबंधन और समानता के लिए उनके निहितार्थ, माध्यमिक शिक्षा में भागीदारी दरों में पैटर्न खोजने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, अध्ययन कुछ राज्यों (जैसे, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश) में माध्यमिक स्कूल नेटवर्क के बाजार–संचालित के बजाय संस्थागत रूप से संचालित निर्माणों के निहितार्थों को देखने में मदद करेगा। । यह अध्ययन विभिन्न राज्यों में माध्यमिक शिक्षा को व्यवस्थित और वितरित करने के तरीके के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।

अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैंः–

i. प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर संस्थागत मिश्रण (सार्वजनिक–निजी) के पैटर्न की स्थापना;
ii. स्कूल के प्रावधानों, स्टाफिंग पैटर्न और इंटेक विशेषताओं द्वारा सार्वजनिक और निजी संस्थानों की प्रोफाइल बनाना;
iii. स्कूलों के मिश्रण में विस्तारित पहुंच और समानता पर संभावित प्रभावों के लिए आरएमएसए के निहितार्थ की पहचान करना; तथा
iv. आरएमएसए के तहत कार्यक्रम की योजना और संसाधनों के आवंटन के लिए निहितार्थ।

यह अध्ययन प्रमुख राज्यों में माध्यमिक स्कूल नेटवर्क को प्रोफाइल करने और संस्थागत तथा अन्य कारकों पता लगाने का प्रयास करेगा, जो कि राज्यों में माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न मॉडलों के लिए योगदान देता है (उदाहरण के लिए, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों या गैर–सहायता प्राप्त संस्थानों या सरकार प्रबंधित संस्थान का बड़ा हिस्सा)। यह इंटेक आकार, स्कूल में सुविधाओं, सहभागिता दरों और ग्राहक समूह की सामाजिक–आर्थिक विशेषताओं के संदर्भ में सरकारी सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों को भी प्रोफाइल करेगा। यह राज्यों में माध्यमिक शिक्षा वितरण प्रणाली और समानता तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए उनके निहितार्थ में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।

अब तक, संबंधित साहित्य की समीक्षा की गई है; यू–डाईस और अन्य स्रोतों से सहायक आंकड़े और जानकारी एकत्र की गई है। आंकड़ा विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन प्रगति पर है। अध्ययन के चरण–1 की रिपोर्ट जून, 2018 तक पूरी होने की आशा है।

17. उच्चतर शैक्षिक बहि–प्रवास के कारणों और परिणामों पर एक स्थानिक परिप्रेक्ष्यः हिमाचल प्रदेश का एक केस अध्ययन

अन्वेषकः डा. सुमन नेगी

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इस तरह के प्रवास प्रवाह की अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करना और उन मुख्य कारणों की पहचान करना है जो शिक्षा और इसके आगे के परिणामों की तलाश करने के लिए किसी के अपने मूल स्थान से बाहर जाने का कारण बनते हैं। अधिकांश शोधों में शिक्षा और प्रवास के बीच संबंधों की जांच या आर्थिक कुशल प्रवास के उत्प्रेरक रूप में शिक्षित अथवा शैक्षिक अर्हता के संदर्भ से अधिक की गई है, क्योंकि अनेक अध्ययनों/रिपोर्टों ने कहा है कि पिछले सालों के प्रवास को कुशल पेशेवरों और विद्वत लोगों में देखा गया है (खड़रिया 1999; स्वार्ड और राव 2009)। लोगों के प्रवास पर शोध का ध्यान मुख्य रूप से आर्थिक कारणों और उसके परिणामों पर केंद्रित रहा है। शिक्षा विशेषकर 25 वर्ष से कम आयु के लोगों की प्रवास के कारण के रूप में, प्रवासन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू भी है।

यह अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगाः–

1. लैंगिक और सामाजिक समूहों में जनसांख्यिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं से संबंधित घटकों के साथ शैक्षिक प्रवासियों के संघटन की जांच करना।
2. व्यक्तिगत, घरेलू और संस्थागत दृष्टिकोण से पलायन शैक्षिक बहि–प्रवास के मुख्य कारणों की पहचान करना।
3. क्षेत्र से इस तरह के प्रवास के मुख्य परिणामों की पहचान करना।

शोध प्रश्न

1. कौन अपने बच्चों को बाहर भेजता है, क्यों और कहाँ?
2. क्या यह निवास स्थान पर उपलब्ध कम शैक्षणिक गुणवत्ता और सुविधाओं के कारण है जो युवाओं को दूसरे केंद्र में स्थानांतरित करने के लिए विवश कर देती है या गंतव्य पर इसके आकर्षक कारक अधिक मजबूत हैं।
3. प्रवास के स्रोत पर ऐसी शैक्षिक प्रवासन प्रक्रिया के परिणाम क्या हैं?
4. गंतव्य और उसकी दूरी के चुनाव में आय की क्या भूमिका है?
5. शैक्षिक प्रवास में स्थानीय या सामुदायिक परिवेश की भूमिका?

अध्ययन प्राथमिक और सहायक दोनों डाटाबेस को समझकर स्वाभाविक रूप से गुणात्मक और मात्रात्मक होगा। डी–3 सीरीज प्रवास तालिकाओं के सहायक आंकड़ों का इस्तेमाल प्रवास प्रवाह के पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए किया जाएगा, अर्थात प्रवास और बहि–प्रवास दोनों में और सामान्य रुप से हिमाचल प्रदेश से भारत के विभिन्न राज्यों में और विशेष रूप से शिक्षा प्रवास करने के कारणों में से एक के रूप में संरचित प्रश्नावली को विकसित किया जाएगा और उन परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनके पास कम से कम एक सदस्य है जिसने वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा पूरी कर ली है और 17 से 24 वर्ष की आयु में हैं। एकत्रित जानकारी को विभिन्न उपलब्ध सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करके सारणीबद्ध और विश्लेषित किया जाएगा। विश्लेषण के परिणामों के आधार पर, व्यापक रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत की जाएगी।

अंतिम रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जा रहा है और इस परियोजना के जुलाई 2018 तक पूरा होने की आशा है। अधिकांश कार्य, जैसा कि प्रस्तावित है, पूरा हो चुका है। प्राथमिक आंकड़ों से संबंधित कुछ पहलुओं को व्यवस्थित और विश्लेषिण किया जा रहा है।

18. लैंगिक पर एक शिक्षा–एटलस : एक जिला–स्तरीय प्रस्तुति

अन्वेषक : डा. सुमन नेगी और प्रो. मोना खरे

मानचित्र उपयोगी सूचना का दृश्य रूप प्रस्तुतिकरण है, जो विचारों और डिज़ाइनों को अभिव्यक्त करते हैं। आकड़ों की श्रृंखला (सीरिज़) के रूप में स्थानिक सूचना के प्रतिरूप और उन्हें संगठित करने के लिए ये एक प्रभावी रूपक प्रदान करते हैं। आज शिक्षा और शिक्षण संसाधनों में ग्राफिकल/छवि प्रस्तुति के रूप में इन भौगोलिक या बिम्ब निरूपणों का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। 'मानचित्र' साधन के महत्व के मद्देनज़र 'मानचित्र' के माध्यम से विभिन्न चीज़ों के लिए सूचना की प्रस्तुति की जा सकती है, इनमें एक शिक्षा और उससे संबद्ध घटक भी है जिन्हें इस माध्यम के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है।

नीपा, संगठन के रूप में, शैक्षिक आंकड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर एकत्रित, समेकित और विश्लेषित करता है। संयोग से, शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली (डाईस) और अब शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाईस) नीपा का एक अभिन्न अंग है और दुनिया भर में शैक्षिक आंकड़ों का मुख्य स्रोत है। यह भारत के 15 मिलियन से अधिक स्कूलों के लिए वार्षिक आधार पर विस्तृत सांख्यिकीय जानकारी एकत्र करता है, और इन इकाइयों के डाटाबेस आसानी से ऑनलाइन और नियमित प्रकाशन के माध्यम से उपलब्ध कराता है। इन शैक्षिक आंकड़ों के प्रसार को और सुविधाजनक बनाने के लिए, सूचना प्रसार के अन्य अनुपूरक रास्ते भी तलाशे जा सकते रहे है। इनमें से एक जीआईएस और मानचित्र आधारित सूचना प्रसार है जो कि एटलस के रूप में दुनिया भर में एक प्रभावी माध्यम है।

भारत जैसे विविधता वाले देश में असंख्य विषमताओं और भेदभाव के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लैंगिक असमानता प्रमुख क्षेत्रों में से एक हैं, जहाँ समूचे सामाजिक–आर्थिक पहलुओं में विषमता दृष्टिगत होती है और इस प्रक्रिया में शिक्षा भी पीछे नहीं है। शैक्षणिक विकास के विभिन्न पहलुओं में संबंधित आंकड़े पहुँच (सुलभता) और सामाजिक भागीदारी के संदर्भ में लैंगिक में व्याप्त भिन्नताओं को दर्शाते हैं, और यह पहलू ग्रामीण जनसमूह, उपेक्षित जातियों और दूरस्थ क्षेत्रों में ज्यादा दृष्टिगत होती है।

इस संबंध में, अध्ययन उन शिक्षा आंकड़ों का उपयोग करने का प्रयास करता है जिन्हें नीपा एकत्रित व समेकित करता है और पूरे भारत के विभिन्न जिलों में इन लैंगिक–अंतरालों को सुव्यवथित करता है। प्रदर्शित सूचकों की पुष्टि के लिए आंकड़ा निरूपणों के अन्य रूपों के साथ एक संक्षिप्त विश्लेषणात्मक नोट भी प्रदान किया जाएगा। यह पहल शैक्षणिक योजना, नीति–निर्माण, शिक्षाविदों और अनुसंधान में जुड़े लोगों को सुविधा प्रदान करने का एक प्रयास है। अनुसंधान प्रक्रिया में योगदान और इसके परिणाम मुख्यतः आँकड़ा समुच्चयों, के माध्यम में निरुपित किए गए। यहाँ हमारा उद्देश्य शैक्षणिक विकास के इन बारीकियों को दर्शाना और मानचित्रण उपकरणों का प्रयोग करके इसे मानचित्रों के माध्यम से निरूपित करना है।

अध्ययन का विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(i) लैंगिक संबंधित संकेतों का प्रस्तुतीकरण करने के लिए डाईस और यूडाईस आंकड़ों का प्रयोग करना।

(ii) राष्ट्रीय स्तर पर कुछ लौकिक प्रवृत्तियाँ को निरूपित करना।

(iii) सांख्यिकीय रूप में गणना की गई आंकड़ा प्रवृत्यिों को भी निरूपित करना।

क्रिया प्रणाली

यूनिसेफ द्वारा तैयार की गई डेविन सिस्टम का प्रयोग करके मानचित्र बनाए जाएँगे। जिला इस साफ्टवेयर में उपलब्ध सीमाओं का तीसरा और सबसे निम्नतम स्तर है और इस स्तर या इससे ऊपर के स्तर के आंकड़ों को भी प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है। नीपा के ई.एम.आई.एस. विभाग को यह सॉफ्टवेयर यूनिसेफ द्वारा प्रदान किया गया है और इस परियोजना के लिए इसे साझा करने के लिए तैयार है। डी.आई.एस.ई. और यू.डी.आई.एस.ई. आंकड़ों का प्रयोग उन विभिन्न चुने गए सूचकों को निरुपित करने के लिए किया जाएगा जो शैक्षिक पहुँच और सहभागिता में लैंगिक अंतराल को व्यक्त करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सूचकों और संबद्ध सूचकों से संबंधित कालिक प्रवृत्तियों के संक्षिप्त विश्लेषण का प्रयोग निरुपण के लिए भी किया जाएगा।

निरुपित किए गए कुछ सूचक निम्नलिखित हैं :

- विद्यालय शिक्षा में उत्तरजीविता दरें
- विशिष्ट आय समूहों में जनसंख्या वृद्धि
- प्रक्षेपित जनसंख्या और उसकी वृद्धि
- कुल नामांकन अनुपात
- निविल (नेट) नामांकन अनुपात
- विद्यार्थी उपलब्धि और पुनरावृत्ति
- लैंगिक समता (समानता) सूचकांक

जुलाई 2018 तक अध्याय तैयार कर लिए जाने की संभावना है। डाटा को एकत्र कर व्यवस्थित किया गया है। कुछ मानचित्र जिला स्तर पर भी तैयार किए गए हैं।

19. ओडिशा में माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों के बीच छात्रवृत्ति योजना और शैक्षिक गतिशीलता का अध्ययन (नीपा प्रायोजित)

अन्वेषकः डा. एस.के. मलिक

संविधान को अपनाने के बाद में, हम उच्च प्राथमिक शिक्षा की सर्व–व्यापकता का प्रयास कर रहे हैं। हमने नब्बे के प्रारंभिक दशक में डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम प्रारंभ किया और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की ताकि देश में प्रारंभिक शिक्षा का सर्व–व्यापकीकरण किया जा सके। स्कूल बीच में छोड़ने की दर अत्यधिक है, शिक्षा की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं हैं, विद्यालय–बाह्य बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। सभी सुधारों के बावजूद दर अभी भी पीछे है। जहाँ तक शैक्षणिक सूचकों का संबंध है सुविधावंचित वर्गों के बच्चे अन्य समूहों से पीछे हैं। आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालय के लिए एस.एम.सी. निर्धारित करना अनिवार्य है। इसी तरह आर.एम.एस.ए. ने

योजना, कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया में विद्यालय प्रबंधन समितियों और अभिभावक–अध्यापक संघ जैसे निकायों के माध्यम से सैकेंडरी शिक्षा के प्रबंधन के लिए पंचायतीराज संस्थानों और निकायों, समुदाय, अध्यापकों, अभिभावकों और अन्य सहयोगियों को शामिल किया। आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत यह सुझाव दिया है कि राज्य बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों जैसे सुविधावंचित समूहों के विद्यार्थियों को मुफ्त (निशुल्क) आवास और भोजन सुविधाएँ, छात्रवृत्ति और नकद प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों, केन्द्रीय सेक्टर की स्कीमों और राज्य स्कीमों का लाभ उठाया जाना चाहिए। अब यह अध्ययन करना महत्वपूर्ण है कि माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति कितनी सहयोगी (मददगार) है।

अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैंः–

क) माध्यमिक स्तर के पूरा होने और उच्च ग्रेड के लिए अनुसूचित जाति के बच्चों की शैक्षिक गतिशीलता पर छात्रवृत्ति योजना की प्रभावशीलता का अध्ययन करना;

ख) योजनाएं पूरा होने की दर और अवस्थांतर दर से संबंधित आगत और परिणामों की अवधि में योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन का पता लगाना;

ग) छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में पदाधिकारियों द्वारा सामना की गई समस्याओं और बाधाओं का पता लगाना;

घ) अनुसूचित जाति के बच्चों द्वारा माध्यमिक शिक्षा पूरी न करने के कारणों का पता लगाना; तथा

ड) छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपायों का पता लगाना।

साहित्य की समीक्षा संपन्न है। ओडिशा के दो जिले– पहला है जगतसिंहपुर और दूसरा है खोरधा को आंकड़ा संग्रह करने के लिए क्षेत्र को चुना गया है। प्राथमिक स्तर का आंकड़ा संग्रह से नमूना जिलों में से एक जगतसिंहपुर में पूरा हो गया है, और आंकड़ा संग्रह का दूसरा चरण ओडिशा के खोरधा जिले में जून, 2018 के दूसरे सप्ताह में शुरू होगा।

20. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत चयनित राज्यों में निजी स्कूलों में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों के प्रावधान के कार्यान्वयन का अध्ययनः नीति और व्यवहार

अन्वेषकः प्रो. अविनाश कुमार सिंह

उपरोक्त अनुसंधान परियोजना कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में है, जिसमें विषय के अनुसंधान और विकास से संबंधित साहित्य की समीक्षा और अनुसंधान उपकरणों का विकास शामिल है। साहित्य समीक्षा के तहत, चयनित राज्यों के प्रोफाइल और राज्यों में आरटीई मानदंडों का अनुपालन, माध्यमिक आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जा रहा है। अध्ययन के तहत निर्धारित मानदंडों पर चुने गए 10 राज्य शामिल हैंः केरल, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय। इसके अलावा, आंकड़ा संग्रह के उपकरण के प्रारूप तैयारी के तहत हैं। निम्नलिखित उपकरणों की रूपरेखा तैयार किये हैंः–

- घरेलू सूचना अनुसूचियां
- स्कूल सूचना अनुसूची
- मुख्य शिक्षक और अन्य शिक्षकों के लिए अनुसूची
- बच्चों के लिए अनुसूची (वंचित समूह और कमजोर वर्ग)
- उन बच्चों के माता–पिता और अन्य सामुदायिक सदस्यों के लिए अनुसूचियां
- स्कूल शासी समितियों के सदस्यों के लिए अनुसूचियां
- विभिन्न स्तरों पर (क्लस्टर, ब्लॉक, जिला, राज्य) के शिक्षा पदधारियों के लिए सूचियाँ

अध्ययन की प्रारंभिक कार्यप्रणाली पर कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें आंकड़ा संग्रह के मसौदा उपकरणों को विकसित और अंतिम रूप दिए गए हैं। उन्हें जल्द ही प्रदर्शित किया जाएगा। राज्य स्तरीय संसाधन संस्थानों/ अनुसंधान अन्वेषकों की पहचान के लिए प्रक्रिया जारी है। हालांकि अप्रैल 2015 में अनुसंधान परियोजना को अनुमोदित किया गया था, अनुसंधान कर्मचारियों की भर्ती

में समस्याओं के कारण अनुसंधान परियोजना में देरी हुई है। परियोजना अनुसंधान सलाहकार समिति के माध्यम से नए समय के साथ अनुसंधान परियोजना को जल्द ही पुनःआरंभ किया जाएगा।

21. भारत में उच्चतर शिक्षा सुधार की राजनीतिक अर्थव्यवस्थाः सुधार के सिद्धान्तों, नीतियों और संस्थानों पर तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य (1991–2012)

अन्वेषकः प्रो. मनीषा प्रियम

इस शोध प्रस्ताव को अकादमिक परिषद द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है, बाहरी परीक्षकों द्वारा समीक्षा की गई है, और दिसंबर 2017 में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त की है।

इस वर्ष के लिए प्रस्तावित

साहित्य की समीक्षा का समापन

1) मैसूर विश्वविद्यालय में दो क्षेत्रों का दौरा और विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि और संदर्भ पर एक मसौदा पूरा करना, प्रमुख अधिकारियों के साथ साक्षात्कार और आगे के क्षेत्र के काम और लेखन के लिए डेटा संग्रह प्रारूपों की कल्पना करना।

2) पटना विश्वविद्यालय में दो क्षेत्रों का दौरा और यूनिवर्सिटी की पृष्ठभूमि और संदर्भ पर एक मसौदा पूरा करना, प्रमुख कार्यकताओं के साथ साक्षात्कार और आगे के क्षेत्र के काम और लेखन के लिए डेटा संग्रह स्वरूपों की परिकल्पना।

3) वर्ष 2018–19 के लिए लिखित निर्गतः

- साहित्य की समीक्षा और पृष्ठभूमि
- पटना और मैसूर क्षेत्र के काम पर दो लिखित रिपोर्ट
- 2019–20 के लिए कार्य प्रस्ताव

22. आर.टी.ई. के अंतर्गत समता का पुनर्मूल्यांकनः नीति और परिप्रेक्ष्य लोकप्रिय

अन्वेषकः डा. नरेश कुमार

यह अध्ययन दौरा किए गए स्कूलों/क्षेत्रों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में समुदाय के साथ मिलकर स्कूलों के काम करने के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। अध्ययन बताता है कि सरकारी स्कूलों की विफलता का प्रमुख कारण 'सामाजिक भरोसे की कमी' है। निजी स्कूल प्रणाली, मुख्य रूप से एलबीएस ने यह महसूस किया है – और इसलिए वे इसका लाभ उठाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। अध्ययन में निजी स्कूल प्रणाली को देखने का आग्रह किया गया है। अब तक, हम निजी स्कूल प्रणाली (विशेष रूप से एलबीएस) के खिलाफ बहस करते रहे हैं लेकिन हमने कभी इस प्रणाली को समझने की कोशिश नहीं की। यदि क्षेत्र में 10 एलबीएस हैं, तो क्षेत्र अंतर्दृष्टि सूचित करती है – प्रत्येक स्कूल अलग–अलग गुणवत्ता का प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा। प्रतियोगिता के कारण, प्रत्येक स्कूल बने रहने के मोड में चलता है, इसलिए, कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञता की कोशिश से माता–पिता को प्रभावित किया जा सके। अध्ययन से पता चलता है कि, बहुत हद तक, निजी स्कूल सरकारी स्कूलों की तुलना में माता–पिता के साथ एक करीबी संबंध स्थापित करने में सक्षम हैं। इस तरह, एलबीएस भारतीय इतिहास में अधिलक्षण के रूप में सामने आया है, जो एक जीवंत 'सार्वजनिक क्षेत्र' बना सकता है जहां विविध पृष्ठभूमि के बच्चे भाग लेते हैं। अंतिम संकलन प्रक्रियाधीन है।

23. भारत में प्राथमिक स्तर पर बच्चों की स्कूल भागीदारी में सुधार के लिए सहभागी कार्रवाई अनुसंधान

अन्वेषकः डा. मधुमिता बंद्योपाध्याय

दौरा किए गए सभी 42 स्कूलों, 252 शिक्षकों, 103 एसएमसी, 1286 छात्रों की मूल्यांकन स्थिति और 4031 छात्रों की अनिर्मित जानकारी, छह राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और मिजोरम में आंकड़ा प्रविष्टि की गई है। एसपीएसएस स्प्रेडशीट में कुल मिलाकर 5,02,079 प्रविष्टियाँ की जा रही हैं। पांच राज्यों (हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, कर्नाटक और मिजोरम) की स्कूल रिपोर्ट (केंद्रण और गैर–केंद्रण) पूरी हो चुकी हैं और एक राज्य मध्य प्रदेश की – प्रगति पर है। दो राज्यों – हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से बच्चों के अधिगम आकलन पर आंकड़ा प्रविष्टि पूरी हो चुकी है और अन्य राज्यों की प्रविष्टियाँ चल रही हैं। एक राज्य (हरियाणा) के क्षेत्र का दूसरा दौरा किया गया है। 2017–18 के दौरान ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए हस्तक्षेप के बारे में जानकारी एकत्र की

गई है और अब आंकड़ा संकलन और विश्लेषण के लिए कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में, परियोजना विस्तार के लिए विचाराधीन है। अंतिम पीएसी बैठक के दौरान परियोजना की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की गई थी। दूसरे दौर के क्षेत्र के दौरे में सुझाव शामिल किए जा रहे हैं।

24. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता

अन्वेषकः डा. नीरू स्नेही

उच्च शिक्षा संसधानों की स्वायत्तता का मुद्दा भारतीय उच्च शिक्षा पद्धति में सुधारों को प्रस्तुत करने के लिए कार्यसूची का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। स्वायत्तता प्रदान करना ऐसा सूचित करता प्रतीत होता है कि स्वायत्तता असंख्य समस्याओं का सामना करने वालों के लिए रामबाण है। इस परियोजना का लक्ष्य इस बात का अन्वेषण करना है कि सामान्य रूप में स्वायत्तता किस हद तक भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रचलित है अर्थात विशेष रूप से स्नातकपूर्व कॉलेजों को कितनी स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए; क्या कॉलेजों के लिए स्वायत्तता होनी चाहिए; किस वर्ग–प्रबंधन, अध्यापक, विद्यार्थी को स्वायत्ता दी जानी चाहिए और केन्द्र, राज्य, विश्वविद्यालय, यू.जी.सी. किससे स्वायत्तता मिलनी चाहिए?

इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थानों की कार्य–पद्धति में स्वायत्तता की भूमिका को जानना है। विशिष्ट रूप में स्नातकपूर्व संस्थानों में, स्नातकपूर्व संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने में स्टैकहोल्डरों की भूमिका की छानबीन करना, संबद्ध कॉलेजों व स्वायत्त संबद्ध कॉलेजों की कार्यपद्धति का विश्लेषण व तुलना करना, और स्वायत्त और गैर–स्वायत्त संबद्ध कॉलेजों की कार्य–पद्धति के अनुभवों के प्रलेख देना।

इस परियोजना की कार्य–पद्धति उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वायत्तता की संकल्पना, स्वायत्तता प्रदान करने में हितधारकों की भूमिका, विभिन्न संस्थानों की कार्य–पद्धति में विद्यमान स्वायत्तता के प्रभाव को समझने के लक्ष्य पर आधारित है। अध्ययन में विषयवस्तु विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन का मिश्रण है। इस संबंध में विश्वविद्यालय और उनके कॉलेजों के अधिनियमों, संविधियों और अध्यादेशों के साथ–साथ विश्वविद्यालयों के लिए राज्यों के अधिनियमों और संविधियों का विश्लेषण किया जा रहा है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा पद्धति में स्वायत्तता की संकल्पना के विकास का विश्लेषण किया जा रहा है।

मसौदा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है इसके सितंबर 2018 तक पूरा होने की उम्मीद है।

25. उच्चतर शिक्षा में वित्तपोषण और वित्त सामर्थ्य (यूजीसी वित्त पोषित)

अन्वेषकः प्रो. सुधांशु भूषण

उच्चतर शिक्षा में नीति विस्तार और गुणवत्ता सुधार के मद्देनजर सामर्थ्य का मुद्दा एक कठिन कार्य है। हालांकि, एक ओर, सार्वजनिक खर्च महत्वपूर्ण है, और संसाधनों को जुटाने और गरीबों को सब्सिडी देने के तरीके खोजने पड़ते हैं, उच्च शिक्षा के निजी (घरेलू) वित्तपोषण का सवाल भी उठता है। निजीकरण के प्रति बढ़ते रुझान के मद्देनजर उच्च शिक्षा का घरेलू वित्तपोषण महत्व प्राप्त करता है। उच्च शिक्षा के निजीकरण ने फीस की बढ़ती प्रवृत्ति को जन्म दिया है और उच्च शिक्षा को वित्तपोषित करने के लिए घरेलू बोझ को जोड़ा है। यह वित्त सामर्थ्य के मुद्दों को उठाता है। इसलिए वित्त सामर्थ्य अनुशासन की पहुंच और पसंद पर इसका प्रभाव है। वित्तसामर्थ्य विभिन्न सामाजिक और अर्थशास्त्र समूहों में भिन्न रुझान दिखा सकती है। यह ग्रामीण और शहरी संदर्भों और विभिन्न व्यवसाय श्रेणियों के बीच भी भिन्न हो सकता है। उपर्युक्त के प्रकाश में, अनुसंधान परियोजना का केंद्रीय उद्देश्य निजीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के संदर्भ में वित्तसामर्थ्य का अध्ययन करना है।
मार्च, 2018 तक, मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तैयार है।

26. भारतीय निजी विश्वविद्यालय अधिनियमों और शुल्क का विनियमन (मा.सं.वि.मंत्रालय के अनुरोध पर परियोजना का अध्ययन)

अन्वेषकः डा. संगीता अंगोम

स्वतंत्रता के बाद से भारत में निजी तौर पर वित्तपोषित संस्थान अस्तित्व में हैं, लेकिन उन्हें निजी विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों के रूप में वर्गीकृत

अनेक निजी विश्वविद्यालय या संस्थान या जो खुद को विश्वविद्यालय के रूप में परिभाषित करते हैं, हाल ही में सामने आए हैं। इनमें से अनेक विश्वविद्यालय राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के समान बहु–विषयक व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। हालाँकि, एकल धारा विशेषज्ञता प्रदान करने वाले संस्थान भी अस्तित्व में हैं।

भारत सरकार ने राज्य सभा में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और विनियमन विधेयक, 1995 पेश किया और विचार प्राप्त करने के लिए स्थायी समिति को भेजा गया। तब से, इस विषय पर विभिन्न मंचों पर चर्चा की गई लेकिन संसद में इसे पारित नहीं किया गया।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन के औचित्य के प्रकाश में, प्रस्ताव अध्ययन के निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों को रेखांकित करता हैः

- चयनित निजी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक ढांचे और शासन का विश्लेषण करना।
- चयनित निजी विश्वविद्यालय की आय और व्यय पैटर्न के स्रोतों की जांच करना।
- प्रवेश प्रक्रियाओं और चयनित निजी विश्वविद्यालय में प्रदान की गई अवसंरचनात्मक सुविधाओं की जांच करना।
- शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया और कार्यभार के पैटर्न का अध्ययन करना।
- पाठ्यक्रमों के प्रकार बाजारोन्मुख हैं या नहीं यह पहचानना।
- निजी विश्वविद्यालय में उपलब्धि (यों) या कमियों, यदि कोई हो, का पता लगाना।
- भारत में उच्च शिक्षा के विकास में निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका और योगदान का समग्र मूल्यांकन करना।

अनुसंधान विधि को वर्णनात्मक के रूप में जिम्मेदार माना जा सकता है और यह प्राथमिक और सहायक दोनों प्रकार के डाटा पर आधारित होगा। अध्ययन सबसे अधिक प्रासंगिक आधिकारिक दस्तावेज का उपयोग करने की कोशिश करेगा और विकास, भूमिकाओं, समस्याओं, अवसरों और सरकार की प्रतिक्रियाओं के साथ–साथ निजी विश्वविद्यालयों की पूरी तस्वीर देगा। उच्च शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने वाले 23 निजी विश्वविद्यालयों (राज्य विधानमंडल के अधिनियमों के माध्यम से स्थापित) में से पांच निजी विश्वविद्यालयों के एक नमूने का अध्ययन करने के लिए चयन किया जाएगा। पांच विश्वविद्यालयों को अलग–अलग शासन शैलियों का प्रस्तुत करने के लिए सावधानी से चुना जा सकता है। अध्ययन में भारत में निजी डीम्ड विश्वविद्यालय शामिल नहीं हैं।

10 प्रतिशत संकाय और 2 प्रतिशत छात्र विभिन्न पहलुओं पर जानकारी का नमूना तैयार करेंगे। डाटा एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में छात्रों और शिक्षकों के लिए प्रश्नावली और प्रशासन में शामिल व्यक्तियों और अध्यक्षों के लिए एक साक्षात्कार अनुसूची का संचालन किया जाएगा। सरकारी प्रतिनिधियों के लिए एक अलग प्रश्नावली का उपयोग देश में निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका पर राय बनाने के लिए भी किया जाएगा।

i). साहित्य समीक्षा प्रगति पर है

ii). उपकरण तैयारी प्रगति पर है

iii). नमूना विश्वविद्यालयों के साथ संचार प्रगति पर है।

iv). क्षेत्र भ्रमण की योजना मार्च के अंत से मई 2018 तक चलेगी।

27. बिहार में उच्चतर शिक्षा का शासन

अन्वेषकः प्रो. सुधांशु भूषण

उच्चतर शिक्षा शासन विभिन्न आयामों पर सभी राज्यों में भिन्न होता है। यह विश्वविद्यालयों के राज्य सरकारों और कुलपति के कार्यालय के संबंध में भिन्न होता है। विश्वविद्यालयों के कामकाज का मार्गदर्शन करने वाले अधिनियम, कानून और परिनियम भी अलग–अलग हैं। उच्च शिक्षा के निजीकरण की तीव्रता भिन्न होती है। छात्रों की सामाजिक संरचना और शिक्षकों की कमी निजीकरण की तीव्रता में भी भिन्नता है। राज्य सरकार की नीतियां और कार्यक्रम राज्यों में अलग–अलग हैं। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और मान्यता की स्थिति अलग–अलग है। हालाँकि, राज्यों के उच्च शिक्षा प्रशासन का कोई व्यवस्थित प्रलेखन नहीं है। परिणामस्वरूप, उच्च शिक्षा के शासन के बारे में बुनियादी

जानकारी के संबंध में भी, जब आवश्यकता होती है तब जानकारी एकत्र की जाती है।

उद्देश्य

1. विभिन्न राज्यों में उच्च शिक्षा के शासन पर श्रृंखला संस्थागत संरचना, शासन, नीतियों, परिपाटियों, उच्च शिक्षा संस्थानों के वित्त पोषण पर बुनियादी जानकारी प्रदान करने में मदद करेगी।
2. शासन की श्रृंखला कुछ राज्यों में अच्छी परिपाटियों को उजागर करना और अन्य राज्यों को अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करना।
3. श्रृंखला केंद्र सरकार और नियामक परिषद को शासन में भिन्नता को समझने और नीति और योजना के माध्यम से परिपाटियों को कारगर बनाने में मदद करना।
4. शासन की श्रृंखला नेटवर्क अकादमिक, प्रशासन को विकसित करने और राज्यों में सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करना।
5. शिक्षकों की सामाजिक संरचना और उनके सेवानिवृत्ति की अवधि और पारिश्रमिक के संदर्भ में छात्रों को समझने में मदद मिलना।
6. उच्च शिक्षा के शासन पर श्रृंखला सही जानकारी और वास्तविक परिपाटियों में अंतर–राज्य विविधताओं के आधार पर व्यवस्थित तरीके से उच्च शिक्षा में सुधार लाने में मदद करना।

विभाग तीन वर्ष में सभी राज्यों के लिए ''उच्च शिक्षा शासन'' पर एक श्रृंखला प्रकाशित करने का प्रस्ताव करता है। पहले वर्ष में, बिहार और तमिलनाडु के लिए दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी और इसके बाद, सभी राज्यों को कवर करने वाली पूरी परियोजना के लिए उपकरण तैयार किए जाएंगे। बिहार राज्य के लिए प्रायोगिक का कार्य डॉ. सुधांशु भूषण द्वारा किया जाएगा और, तमिलनाडु के लिए, डॉ. पी. दुरईसामी द्वारा किया जाएगा। उपकरणों को अंतिम रूप देने के बाद, 2016–17 और 2017–18 के दौरान पूरी परियोजना को सभी राज्यों में शुरू किया जाएगा। उच्च शिक्षा में शासन के विभिन्न पहलुओं पर राज्यवार प्रकाशन होगा। दस्तावेज मुख्य रूप से राज्य के उच्च शिक्षा विभागों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से प्राप्त माध्यमिक जानकारी पर आधारित होगा। परियोजना औपचारिक रूप से शुरू हुआ परन्तु परियोजना स्टाफ रिक्त होने के कारण कार्य धीमा है।

28. यू–डीआईएसई आंकड़ों का उपयोग करके स्कूल शिक्षा पर अनुसंधान कार्यक्रम

अन्वेषकः अरुण सी मेहता

शिक्षा की जिला सूचना प्रणाली (डीआईएसई) देश में स्कूली शिक्षा पर आंकड़ा और सूचना के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक के रूप में उभरा है। 42 जिलों में प्राथमिक शिक्षा को कवर करने वाले जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीईपीई) के हिस्से के रूप में 1994 में इसकी शुरुआत के बाद से, इसने पूरे देश में स्कूली शिक्षा के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए एक लंबा रास्ता तय किया। डीआईएसई (जो प्रारंभिक शिक्षा पर आंकड़ा एकत्र करता है) और एसईएमआईएस (जो माध्यमिक शिक्षा पर आंकड़ें एकत्र करता है) के एकीकरण के साथ यूनिफाइड–डीआईएसई का उदय प्राथमिक विद्यालयों से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तक शुरू होने वाली संपूर्ण स्कूल शिक्षा प्रणाली को कवर करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यू–डीआईएसई की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि कुछ समस्याओं से बचने के लिए स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सभी स्तरों/ग्रेड से आंकड़ा एकत्र करने के लिए एकल डीसीएफ की डिजाइनिंग की जाती है, जैसे कि प्रयासों की दोहराव की तरह, दोहरी गिनती, डीसीएफ का लगातार भरना आदि का सामना करना पड़ा जब कई एजेंसियां आंकड़े एकत्र कर रही थीं।

यू–डीआईएसई अब देश में स्कूली शिक्षा प्रदान करने वाले 1.5 मिलियन से अधिक स्कूलों से आंकड़े एकत्र करता है। यू–डीआईएसई के तहत, स्कूल में यूनिट के रूप में आंकड़ा एकत्र किया जाता है। यू–डीआईएसई में सभी प्रकार के प्राथमिक; उच्चतर माध्यमिक के साथ प्राथमिक; उच्चतर माध्यमिक विद्यालय; प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के अनुभाग वाले समग्र विद्यालय शामिल हैं।

स्वीकृत और कार्यान्वित नौ अध्ययनों में से, छह रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। मई, 2016 में नीपा संकाय की तीन रिपोर्टों का इंतजार किया गया था।

29. स्कूल शिक्षा के भू–स्थानिक सूचना प्रणाली का एक प्रायोगिक अध्ययन

अन्वेषकः अनुगुला एन. रेड्डी

स्कूली शिक्षा के लिए भू–स्थानिक सूचना प्रणाली विकसित करने के प्रायोगिक परियोजना के दो उद्देश्य हैं। पहला है, भू–स्थानिक सूचना प्रणाली स्कूल शिक्षा के विकास में विभिन्न राज्य सरकारों के अनुभवों की समीक्षा करना, स्कूलों के भू–स्थानिक आंकड़ों के संग्रह में और शैक्षिक योजना और निगरानी में उनका उपयोग करना। दूसरा उद्देश्य ब्लॉक में स्कूली शिक्षा के लिए भू–स्थानिक सूचना प्रणाली का एक प्रोटोटाइप विकसित करना और स्थानीय स्तर पर शैक्षिक योजना में भू–स्थानिक आंकड़ों की पद्धति और अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करना है। भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) वेबसाइटों पर जाकर और वेबसाइटों की सामग्री की जांच, और वेबसाइट पर विभिन्न उपकरणों की उपलब्धता की समीक्षा करके राज्य के अनुभवों की समीक्षा की जा रही है, जिनका उपयोग स्कूल स्थान और निगरानी के नियोजन में किया जा सकता है। इसके बाद शिक्षा के लिए जीआईएस विकसित करने और योजना और निगरानी के लिए उसी का उपयोग करने के लिए अपनाई जाने वाली परिपाटियों पर गहन चर्चा के लिए राज्यों का दौरा किया जाएगा। एक प्रोटोटाइप भौगोलिक सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

- भू–स्थानिक सूचना प्रणाली वेबसाइटें और वेबसाइटों की सामग्री की जांच, और वेबसाइट पर उपलब्धता और कार्यक्षमता के लिए विभिन्न उपकरण जो स्कूल स्थान की योजना बनाने और निगरानी में उपयोग किए जा सकते हैं। मसौदा समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती है।
- भू–स्थानिक सूचना प्रणाली डेटा का उपयोग करके शिक्षक स्थानांतरण (हरियाणा) पर एल्गोरिथ्म पर एक पेपर तैयार किया गया है और यह विश्व विकास (एल्सेवियर) के सक्रिय विचार के तहत है।
- दो और अध्याय : स्कूल के अलगाव और स्कूल स्थान की प्रगति
- यह परियोजना 2018 में पूरी होगी

30. भारत में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार की सीमाएंः छात्र प्रवाह पैटर्न का विश्लेषण और प्राथमिक शिक्षा की आंतरिक दक्षता (कोई भी बजटीय समर्थन शामिल नहीं है)

अन्वेषकः प्रो. के. बिस्वाल

अध्ययन आरएमएसए के तहत भारत में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए नीति मार्गदर्शन नोट विकसित करते हुए 2009 में (प्रो कीथ लेविन यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, यूके) और नीपा की टीम द्वारा किए गए पहले के काम का विस्तार है । इस शोध का उद्देश्य प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, और उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक अवस्थांतर दर की संभावना को ध्यान में रखकर प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक स्तर के माध्यम से राज्य–वार प्रवाह दरों का अनुमान लगाना है। यह यू–डीआईएसई आंकड़ों और अन्य स्रोतों जैसे ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे (एआईएसईएस), एमएचआरडी प्रकाशन, भारत की जनगणना, आदि का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। अध्ययन में ओडिशा और तमिलनाडु को दो राज्यों के रूप में लिया गया है ताकि स्कूली शिक्षा के माध्यम से छात्र प्रवाह का अनुमान लगा सकें।

अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैंः

i. ग्रेड I से लेकर ग्रेड X से छात्र प्रवाह की गतिशीलता को समझना क्योंकि उन्होंने माध्यमिक विद्यालय के विस्तार की गतिशीलता और लागत को प्रभावित किया है;

ii. छात्रों के प्रवाह पैटर्न के आधार पर राज्य और जनसंख्या उप–समूहों के समूहों की पहचान करने के लिए जिन्हें उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना के विभिन्न स्तरों को प्रतिबिंबित करने के लिए समूहित किया जा सकता है;

iii. आरएमएसए द्वारा निर्धारित लक्ष्य और अनुमानित छात्रों के बीच के अंतराल की पहचान करने के लिए और पहचान की गई वृद्धि पर मुख्य बाधाओं का वर्णन करना;

iv. माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा के विस्तार की लागत और निहितार्थों का अनुमान लगाने के लिए और माध्यमिक विद्यालय में क्षमता के विस्तार के लिए निवेश के वर्तमान स्तरों के साथ इनकी तुलना करना; तथा

v. योजना बनाने और केस अध्ययनों (द्वितीय चरण में) को समझने के लिए कि कौन से कारक विभिन्न समुदायों के भीतर माध्यमिक स्कूल तक पहुँच के लिए मांग को गढते एवं आपूर्ति और प्रभाव को प्रभावित करते हैं।

वर्तमान में, प्रासंगिक डाटा एकत्र किया जा रहा है; और संबंधित साहित्य की समीक्षा की जा रही है। मुख्य रूप से यू–डीआईएसई और एमएचआरडी प्रकाशनों और भारत की प्रकाशनों की जनगणना आंकड़ों के आधार पर, तमिलनाडु के लिए प्रक्षेपण मॉडल का निर्माण प्रगति पर है।

31. दिल्ली में प्री–स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाली निजी फ्रेंचाइजी का एक अध्ययन

अन्वेषकः डा. सविता कौशल

प्री–स्कूल शिक्षा को अब प्राथमिक विद्यालय की तैयारी के लिए अनिवार्य आवश्यकता माना जा रहा है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए, पिछले दो दशकों में देश में प्री–स्कूलों की संख्या में तेजी से विस्तार हुआ है। हाल के वर्षों में, प्री–स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए निजी फ्रेंचाइजी के सक्रिय उद्भव हुए हैं। इस अध्ययन के उद्देश्य चयनित निजी फ्रेंचाइजी प्रो–स्कूल के शैक्षणिक और प्रशासनिक ढांचे और शासन का विश्लेषण करना था। इसके अलावा, चयनित निजी प्री–स्कूलों में प्रदान की गई प्रवेश प्रक्रियाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं की भी जांच की गई। इन स्कूलों में भाग लेने वाले बच्चों की पृष्ठभूमि का भी अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में शिक्षकों द्वारा अपनाई गई उपलब्धियों और कमियों के साथ–साथ दिल्ली, (30) और हरियाणा (10) के निजी फ्रेंचाइजी प्री–स्कूलों के कामकाज से संबंधित पाठ्यक्रम संचालन की तकनीकों का भी पता चला। चयनित नमुना प्री–स्कूलों के प्रशासनिक कर्मचारियों के सदस्यों, शिक्षकों और बच्चों के माता–पिता से एकत्र किया गया था। छोटे फ्रेंचाइजी प्री–स्कूलों के मामले में, नमूना में चार शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों के सदस्यों को शामिल करने के लिए ध्यान दिया गया था।

परियोजना की मसौदा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उम्मीद है कि 30 जून, 2018 तक पूरा होने की संभावना है।

32. प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए शैक्षिक प्रशासकों के वर्तमान की तुलना में भविष्यपरक कार्यों एवं भूमिकाओं की समलोचनात्मक जाँच करने के लिए एक गहन अध्ययन

अन्वेषकः प्रोफेसर बी.के. पांडा और डा. मोना सेदवाल

ई–नेटवर्क के माध्यम से रिपोर्ट और पुस्तकों के रूप में दस्तावेज ज्ञान की उपलब्धता की प्रतीक्षा किए बिना दुनिया भर से ज्ञान प्राप्त करने की तकनीक और गुंजाइश के आगमन ने सूचना और ज्ञान तक पहुंचने की समय–सीमा के अवरोध को हटा दिया है। परिणामस्वरूप, एक तरफ ज्ञान और सूचना का निरंतर प्रवाह, हमारे ज्ञान को अद्यतन कर रहा है, और दूसरी तरफ, यह हर पल अप्रचलित भी हो रहा है। इस प्रकार नए ज्ञान के साथ तालमेल बनाए रखना और निरंतर आधार पर उसे प्राप्त करना और उसका सदुपयोग करना एक बड़ी चुनौती है। शैक्षिक प्रशासक को नवीनतम तकनीकी ज्ञान से लैस करने और कर्मियों को बेहतर और कुशलतापूर्वक प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए सूत्रधार की भूमिका को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

अध्ययन का उद्देश्य

- शैक्षिक प्रशासकों को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के भविष्य के आयामों की पहचान करना;
- शैक्षिक प्रशासकों की क्षमता के निर्माण के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना;
- मौजूदा प्रशिक्षण सुविधाओं और ऐसे संस्थानों की क्षमताओं को समझने के लिए जो शैक्षिक प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं;
- शैक्षिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के संदर्भ में शैक्षिक प्रशासकों के व्यावसायिक विकास के लिए एक मॉडल प्रशिक्षण ढांचा विकसित करना; तथा
- एक मॉडल कार्यक्रम विकसित करना जो संसाधनों के संदर्भ में संभव हो, और कार्यान्वयन के संदर्भ में प्रभावी हो, प्रशिक्षण के कार्यान्वयन में स्थायी हो और मूक्स/ई–लर्निंग के नवीनतम तरीकों के उपयोग की लागत प्रभावी और आउटरीच व्यवहार्यता हो।

अध्ययन का विस्तार

अध्ययन में शामिल किया जाएगाः (1) जिन राज्यों में शैक्षिक प्रशासक राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से चुने गए हैं, (2) वे शैक्षिक प्रशासक जो अनुभव के आधार पर प्रवेश कर रहे हैं, इत्यादि। शैक्षिक प्रशासकों की भर्ती अनुकूलित प्रक्रियाओं से संबंधित है और राज्य अकादमियों और अन्य संस्थानों के माध्यम से उनके प्रशिक्षण के लिए प्रावधानों की राज्य स्तर की जानकारी को एकत्र किया जाएगा। शैक्षिक प्रशासकों से प्रशिक्षण के रूप में विषयों की आवश्यकताओं के बारे में सटीक जानकारी भी एकत्र की जाएगी।

अध्ययन तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा, जो तीन–चार वर्षों में देश के सभी राज्यों को शामिल करेगा। हालांकि, अध्ययन के पहले चरण को केवल 18 महीने तक ही सीमित रखा जाएगा, इस अध्ययन की खोज आगे के अनुसंधान के संचालन का आधार बनेगी। समीक्षा का काम प्रगति पर है।

33. शिक्षा में राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण संस्थानों का समलोचनात्मक मूल्यांकन

अन्वेषकः प्रो. नजमा अख्तर और डा. सविता कौशल

ऊपर दी गई परियोजना के लिए अनुमोदन की अधिसूचना अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित किए जाने के बावजूद दो साल की देरी हुई। अधिसूचना जारी करने में देरी के बावजूद, अब स्थिति यह है कि इसके लिए फील्ड कार्य शुरू करने के लिए कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है। कई बार अनुरोध किया गया है कि प्रावधान के अनुसार हमें स्टाफ प्रदान किया जाए। प्रशासन विभाग से इन सभी सीमाओं के साथ, यह सूचित करना है कि वर्तमान में परियोजना के लिए साहित्य समीक्षा का संग्रह चल रहा है।

34. राजस्थान के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक और गैर–शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में सामाजिक गतिशीलता और स्कूल प्रबंधन का तुलनात्मक अध्ययन

अन्वेषकः डॉ. मोना सेदवाल

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 ने राष्ट्र भर के स्कूलों में बच्चों को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान में भी, आरटीई ने स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) और जमीनी स्तर पर काम कर रहे अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर प्रमुख जिम्मेदारियों को बढ़ावा देकर इसे एक वास्तविकता बना दिया है। इसी तर्ज पर, भारत सरकार ने शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक (ईबीबी) की पहचान की है जहाँ सभी के लिए शिक्षा को वास्तविकता बनाने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं।

उपर्युक्त चर्चा से को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अध्ययन में स्कूल प्रबंधन में जाति की गतिशीलता के प्रकाश में एसएमसी की संरचना के प्रभाव की जांच करने का प्रस्ताव है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अनुसार, राजस्थान में राज्य में एससी की 59 श्रेणियां हैं। राजस्थान राज्य में 17 प्रतिशत एससी और 13 प्रतिशत एसटी शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, साक्षरता 53 प्रतिशत है।

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

- ईबीबी और गैर–ईबीबी गांवों में स्कूल प्रबंधन पर इसके सामाजिक संरचना, इसके संबंध और प्रभाव का आकलन करने के लिए।
- स्कूल प्रबंधन के कामकाज और स्कूल प्रबंधन के सदस्यों के रवैये और ईबीबी और गैर–ईबीबी में एससी समुदाय से आने वाले बच्चों के प्रति मुख्याध्यापक के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- ईबीबी और गैर ईबीबी में बीईओ, डीईओ, डायट और एसआईईआरटी द्वारा प्रदान किए गए शैक्षिक इनपुटों की मदद से एसडीपी को विकसित करने और इसे लागू करने में स्कूल प्रबंधन की भागीदारी का अध्ययन करना।
- यह अध्ययन करने के लिए कि ईबीबी और गैर–ईबीबी में एससी जनसंख्या के लिए गाँव स्तर पर स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली कितनी समावेशी है।
- सामग्री और कार्यप्रणाली के साथ–साथ एसएमसी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने और ईबीबी और गैर–ईबीबी गांवों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एससी सदस्यों की भागीदारी दर का आकलन करने के लिए।

अध्ययन का सहायक डाटा प्राथमिक और सहायक डाटा दोनों के संग्रह और विश्लेषण पर आधारित होगा। बड़े सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण और केस अध्ययन के दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा, और बाद में, बड़े सर्वेक्षण के आधार पर, एससी आबादी की बहुलता के आधार पर सामाजिक गतिशीलता के गहन अध्ययन के लिए दो गांवों का चयन किया जाएगा। ब्लॉक में समूहों की संख्या को ध्यान में रखा जाएगा और इसका लगभग 50 प्रतिशत, या यदि समूहों की संख्या कम है, तो उन सभी को अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर अध्ययन के लिए लिया जाएगा। लेकिन, बुनियादी पैरामीटर गांव में एससी आबादी की हिस्सेदारी और स्कूल प्रबंधन में इसके प्रतिनिधित्व पर होगा। घरेलू सर्वेक्षण दो ब्लॉकों में आयोजित किया जाएगा जो गहन अध्ययन के लिए गांवों के चयन का आधार बनेगा। स्कूल प्रबंधन को प्रभावित करने वाली सामाजिक गतिशीलता को प्रतिबिंबित करने के लिए चुनिंदा स्कूलों पर जाति अध्ययन विकसित किया जाएगा। प्रारंभिक कार्य किया जा रहा है।

35. भारत में शहरी मलिन बस्तियों में शिक्षा में बच्चों की भागीदारी का समलोचनात्मक मूल्यांकन

अन्वेषकः डॉ. सुनीता चुघ

- इस परियोजना को स्थानीय संस्थानों और शोधकर्ताओं के सहयोग से देश भर के दस शहरों में चलाया जा रहा है। तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें नमूना डिजाइन, डाटा संग्रह के लिए उपकरणों को अंतिम रूप दिया गया। रिपोर्ट लेखन का प्रारूप, शहर प्रोफाइल पर चर्चा की गई।
- सभी अनुसंधान समन्वयकों के साथ समन्वय और डाटा की छंटनी नियमित रूप से की जा रही है।
- घरों से डाटा संग्रह आठ शहरों में, और शेष दो शहरों (मुंबई और रायपुर) में बहुत प्रगत चरण में पूरा किया गया है। भोपाल और हैदराबाद में स्कूल सर्वेक्षण किया गया है। हैदराबाद के स्कूलों का दौरा स्कूलों से डाटा संग्रह प्रक्रिया की देखरेख करने और फोकस समुह चर्चा करने के लिए किया।
- भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, लुधियाना और कानपुर के संबंध में आंकड़ा प्रविष्टि समाप्त हो गई है। अन्य दो शहरों के मामले में आंकड़ा प्रविष्टि पूर्णता के उन्नत चरणों में है। आंकड़ों की निरंतर निगरानी और सफाई की जा रही है।
- घरेलू आंकड़ों के आधार पर लखनऊ और हैदराबाद के लिए एक छोटी रिपोर्ट तैयार की गई है।
- रिपोर्ट प्रारूप के बारे में चर्चा करने के लिए अनुसंधान समन्वयकों की बैठक बुलाई गई थी।
- माध्यमिक आंकड़ों के आधार पर आठ शहरों का प्रोफाइल तैयार किया गया है।
- अनुसंधान के निष्कर्षों को साझा करने पर दिसंबर 2018 में एक संगोष्ठी आयोजित करने का प्रस्ताव। सेमिनार में भाग लेने के लिए अनुसंधान समन्वयकों, शिक्षा अधिकारियों और शिक्षाविदों को आमंत्रित किया जाएगा।

36. स्कूलों में 'विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता' वाले बच्चों को शामिल करने के लिए नीति और परिपाटियों पर एक अध्ययन

अन्वेषकः डा. वीरा गुप्ता

स्कूली शिक्षा में बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले दिव्यांगताओं की भिन्न प्रकृति के प्रति बढ़ती जागरूकता के साथ, सीखने की दिव्यांगता शैक्षणिक और नीतिगत चिंता के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरी है। आरटीई अधिनियम–2009 और पीडब्ल्यूडी विधेयक– 2012 दोनों ने समस्या से निपटने के लिए सीखने की दिव्यांगता को अपने दायरे में शामिल किया है। हालांकि नीतिगत पहल की जा रही है, लेकिन मूल्यांकन और कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप के संबंध में संस्थागत और स्कूल स्तरों पर बहुत स्पष्टता नहीं है। सीखने की प्रकृति और सीमा गोवा (डीआईएसई, 2011–12) में 45% और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 0 % विशिष्ट अधिगम अक्षमता (एसएलडी) से राज्यों में बहुत भिन्न है। यह समझने की आवश्यकता है कि नीति और परिपाटियों के संदर्भ में सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित वर्तमान और उभरती समस्याओं से निपटने के लिए स्कूल और संस्थागत स्तरों पर सीखने की दिव्यांगता की अवधारणा

को कैसे संचालित किया जाता है। प्रस्तावित अनुसंधान इस दिशा में एक ईमानदार कदम है। भले ही भारत में एसएलडी पर नीति एक नवजात अवस्था में है, लेकिन क्षेत्र में उपलब्ध सर्वोत्तम परिपाटियों के साक्ष्य जुटाने के लिए खोजपूर्ण अध्ययन की आवश्यकता है। प्रस्तावित अध्ययन नीति और नीति प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए सबूतों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से जमीनी स्तर पर वास्तविकता का पता लगाने के उद्देश्य से है। इसलिए, अध्ययन में डिस्लेक्सिया के विशिष्ट संदर्भ के साथ स्कूली शिक्षा में दिव्यांग बच्चों को सीखने की नीति को शामिल करने की नीति और व्यवहार का प्रस्ताव है। अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

अ. नीतियों और परिपाटियों के संदर्भ में विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (एसएलडी) और कार्यक्रम के हस्तक्षेप की समस्या की प्रकृति और परिमाण का पता लगाना।

ब. भारत में विशिष्ट राज्यों में विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (एसएलडी) के लिए पहचान, संदर्भ और शैक्षिक हस्तक्षेप के लिए राज्य और जिला स्तर की नीतियों और परिपाटियों का अध्ययन करना।

स. विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (एसएलडी) के सीखने के प्रतिफलों पर कार्यक्रम के हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करने और क्षेत्र में उपलब्ध सर्वोत्तम परिपाटियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए।

द. मूल्यांकन, निदान, शिक्षण कार्यनीतियों और कार्यक्रम प्रावधानों के लिए एसएलडी पर नीति निर्माण के लिए इनपुट प्रदान करना।

अध्ययन बीआरसी और स्कूल स्तर पर माध्यमिक दस्तावेज के क्षेत्र–आधारित अनुभवजन्य डाटा और विश्लेषण दोनों के संयोजन पर आधारित है। यह एसएलडी की पहचान, मूल्यांकन और हस्तक्षेप के लिए जिलों, बीआरसी और स्कूलों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा–निर्देशों, परिपत्रों और आदेशों का विश्लेषण करेगा। इसके अलावा, परिचालन वास्तविकताओं का पता लगाने के लिए क्षेत्र–आधारित अनुभवजन्य डाटा एकत्र किया जाएगा और उनका विश्लेषण किया जाएगा। स्कूल आधारित अनुभवजन्य डाटा चयनित स्कूलों से एकत्र किया जाएगा। डाटा अवलोकन और साक्षात्कार अनुसूची की मदद से एकत्र किया जाएगा। ये शिक्षकों, परामर्शदाताओं और छात्रों के लिए डिजाइन किए जाएंगे। क्षेत्र–आधारित डाटा 30 स्कूलों से एकत्र किया जाएगा। रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

37. स्थानीय स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली

अन्वेषकः प्रो. के. श्रीनिवास

चूंकि आरएमएसए–टीसीए बंद है, इसलिए अध्ययन का चरण–1 शुरू नहीं किया जा सका। अकादमिक परिषद के विचार के लिए प्रस्ताव को संशोधित और पुनः प्रस्तुत किया गया है। परियोजना के संचालन के लिए पूर्व–सॉफ्टवेयर विकास कार्य पूर्ण हो गए हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर की पहचान और चयन चल रहा है।

38. प्राथमिक स्तर पर मुस्लिम बच्चों के बीच गैर–नामांकन और ड्रॉपआउट के कारणः आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का तुलनात्मक अध्ययन

अन्वेषकः डा. वेटुकुरी पी.एस. राजू

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत में दो राज्यों में प्रारंभिक स्तर पर मुस्लिम बच्चों के गैर–नामांकन और ड्राप–आउट के कारणों की पहचान करना है। तदनुसार, प्रारंभिक स्तर पर मुसलमानों के बीच गैर–नामांकन और ड्राप–आउट के कारणों के मुद्दे को संबोधित करते हुए अनुसंधान/शैक्षणिक नियोजन की प्रकृति का प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए उपलब्ध साहित्य की समीक्षा पूरी हो गई है। साहित्य की समीक्षा से पता चलता है कि कोई भी पर्याप्त शोध या अकादमिक साहित्य नहीं पाया गया है जो प्राथमिक स्तर पर मुसलमानों के बीच गैर–नामांकन और ड्राप–आउट को जानने की कोशिश में जुटा है। इसके अलावा, प्रासंगिक माध्यमिक डाटा भी एनएसएसओ, डीआईएसई और जनगणना रिपोर्ट से एकत्र किए गए हैं। मसौदा तैयार किया जा रहा है और परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतिम रिपोर्ट 31 मई, 2018 तक तैयार होने की उम्मीद है।

4

पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं

पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं

ज्ञान और सूचना की साझेदारी

संस्थान ने शैक्षिक नीतियों, योजना और प्रबंधन से संबंधित मौजूदा और नवीनतम ज्ञान को सुलभ बनाने के लिए श्रृंखलाबद्ध कार्य आरंभ किए हैं। संस्थान का पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र शैक्षिक नीति, योजना और प्रबंधन के क्षेत्र में ज्ञान और सूचना प्रलेखन और प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र द्वारा वर्ष 2017–18 में की गई प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं :

पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं

संस्थान का पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र संस्थान के संकाय और स्टाफ सदस्यों, देश–विदेश के शोधकर्ताओं, विश्वविद्यालय के एम.फिल. तथा पी.एच.डी. के विद्यार्थियों, नीपा द्वारा आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों और अतिथि संकाय सदस्यों तथा पाठकों की सूचना संबंधी जरुरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन एवं अधिगम केंद्र के रूप में कार्य करता रहा है। पुस्तकालय, संस्थान के अध्यापन, अधिगम और शोध में सहयोग के लिए आधुनिक अध्यापन– अधिगम सामग्री, कंप्यूटर तथा इलेक्ट्रानिक सुविधाएं जैसे– वाई–फाई से सुसज्जित है।

पिछले चार–पांच वर्षों के अन्तर्गत पुस्तकालय ने अपनी संग्रह नीति में व्यापक परिवर्तन किया है। पुस्तकालय लगभग 80 प्रतिशत जर्नल मुद्रित और ऑनलाईन स्वरूप में मंगाता है। हालांकि, पुस्तकों को मुद्रित रूप में ही प्राथमिकता दी जाती है।

पाठकों की सुविधा के लिए पुस्तकों तथा अन्य सामग्री के संपूर्ण संग्रह को चार प्रमुख अनुभागों– सामान्य, संदर्भ, श्रृंखला, और क्षेत्र अध्ययन संग्रह में वर्गीकृत किया गया है। समीक्षित काल में पुस्तकालय में 299 नई पुस्तकों/दस्तावेजों का संग्रह किया गया। वर्तमान वर्ष में पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र के पास संयुक्त राष्ट्र, युनेस्को, ओ.ई.सी.डी, आई.एल.ओ., यूनिसेफ, विश्व बैक आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों और सम्मेलनों की रिपोर्टों इत्यादि के अलावा 60,965 पुस्तकों और दस्तावेजों का संग्रह है। समीक्षाधीन वर्ष 2017–18 में पुस्तकालय ने शैक्षिक योजना, प्रशासन, प्रबंधन तथा इससे संबंधित विषयों पर 250 राष्ट्रीय तथा अतंर्राष्ट्रीय जर्नल एवम् 14 पत्रिकाएं मंगाईं। इन पत्र–पत्रिकाओं से 2,522 प्रमुख आलेखों का सूचीकरण किया गया। समीक्षाधीन वर्ष 2017–18 में पुस्तकालय ने 8,127 जर्नलों को उपयोगकर्त्ताओं को सूचना प्रदान करने के लिए जिल्द में तैयार किए। नीपा ने चार आनलाईन डाटाबेस एलसेवियर सेज, एमेराल्ड, डाटाबेस तथा जे. स्टोर खरीदे। पुस्तकालय के पास 523 ई–बुक का संग्रह है। नीपा पुस्तकालय में मल्टीमीडिया केंद्र है। वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट, फिल्म, माइक्रोफिल्म, माइक्रोचिप्स और सी.डी. के रूप में गैर–मुद्रित सामग्री उपलब्ध है।

नीपा पुस्तकालय ने नई आनलाइन सूचना सेवाएँ जैसे कि– ''न्यूज फ्लैश'', 'नीपा इन द प्रेस', एस.डी.आई. (नीपा संकाय के अकादमिक कार्य का प्रसार) तथा 'न्यू अराईवल' प्रारम्भ किया है। पुस्तकालय ने विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की ग्रन्थ सूची तैयार की है। उपभोक्ताओं को संदर्भ सामग्री, आलेखों, रिपोर्टों इत्यादि के लिये फोटोग्राफी सेवाएँ प्रदान की गई हैं।

नीपा पुस्तकालय में सभी गतिविधियाँ, जैसे सूची बनाना, प्राप्तियाँ, प्रसार तथा श्रेणी नियंत्रण पूर्णरूप से कम्प्यूटरीकृत है। इसके लिये लिबसिस 7 साफ्टवेयर पैकेज का नवीनतम वर्ज़न का प्रयोग किया जा रहा है। नीपा में लैन से इंटरनेट या फिर इंटरानेट के माध्यम से सीधे या यू.आर.एल. के माध्यम से नीपा की वेबसाईट पर वेब ओपेक का प्रयोग करके ओपेक का उपयोग किया जा सकता है। इसके माध्यम से नीपा पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों, जर्नलों और लेखों का डाटाबेस देख सकते हैं।

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों की साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु नीपा पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र डेलनेट का सदस्य हैं इससे नीपा पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र में उपलब्ध शैक्षिक योजना और प्रशासन पर वृहद रूप से उपलब्ध अमूल्य अधिकारिक दस्तावेज़ों के पहचान की सुविधा उपलब्ध हुई है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुये सभी दस्तावेज़ों तथा रिकार्ड का डिजीटलीकरण हेतु परियोजना चलाई जा रही है। यह अपेक्षा की जा रही है कि इससे देश में शिक्षा पर वृहद ऑनलाईन अभिलेखीय सूचना उपलब्ध हो पायेगी।

प्रलेखन केन्द्र

नीपा प्रलेखन केन्द्र में शैक्षिक योजना, प्रबंधन और प्रशासन पर 20,000 से अधिक का वृहद और समृद्ध संग्रह है। इसके संग्रह में केन्द्र –राज्य सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन जैसे राज्य तथा जिला गणना, राज्य तथा जिला गैजेटियर केन्द्र तथा राज्य विश्वविद्यालय के नियम और संविधि, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) तथा सर्व शिक्षा अभियान, राज्यों की सांख्यिकी पुस्तकें, अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण आयोग तथा समिति की रिपोर्ट, राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, राज्य शैक्षिक योजनाएं, राज्य मानव संसाधन विकास रिपोर्टें तथा पंचवर्षीय योजनाएं सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त संस्थान के विभिन्न प्रकाशनों जैसे अनुसंधान अध्ययन, समसामयिक आलेख श्रृंखला, विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्टें (1962–2013), प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्टें, विभिन्न मंत्रालयों की रिपोर्टें, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पेरिस के प्रकाशन शामिल हैं। केन्द्र में थीसिस का एक वृहद संग्रह है तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन पर क्रमशः स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पर शोध संग्रह उपलब्ध है। केन्द्र अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, (आई.आई.ई.पी.) पेरिस के प्रकाशनों का संग्रह–केन्द्र है। इसके पास गैर–पुस्तक पाठ्य सामग्री जैसे इंडेक्सिंग डाटाबेस, भारत की जनगणना, राज्य मानव संसाधन विकास रिपोर्ट तथा शिक्षा और इससे संबंधित क्षेत्रों पर अन्य प्रकाशनों पर संग्रह है।

प्रलेखन केन्द्र ने अपने सभी कार्यकलापों का कंप्यूटरीकरण कर लिबसेस 7.0 (रिलीज 1.0) सॉफ्टवेयर के प्रयोग द्वारा कर दिया है। इसके अतिरिक्त उपयोगकर्त्ता को डेस्कटॉप पर ऑनलाईन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग (ओपेक) तथा सूचना संसाधन तथा सेवाओं की विस्तृत जानकारी के साथ इलैक्ट्रानिक डाटाबेस की पहुंच, प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, इसके समृद्ध संग्रह, विस्तृत सरणी और विविध सेवाएं तथा सुविधाएं भारत तथा विदेशों से उपयोगकर्ताओं को इसकी सूचना संसाधन और सेवाओं का प्रयोग करने के लिये आकर्षित करती है। उपयोगकर्त्ताओं को पठन हेतु प्रलेखन केन्द्र में सुविधाजनक शान्तिपूर्ण और अनुकूल परिवेश उपलब्ध है तथा उपयोगकर्त्ताओं के लिए वातानुकूलन, पर्याप्त रोशनी और जनरेटर बैक–अप की सुविधा उपलब्ध है। प्रलेखन केन्द्र की पठन सुविधाओं का लाभ संकाय, संस्थान के अनुसंधानविद् परियोजना स्टाफ, भारत तथा विदेश के अनुसंधानविद्, डेपा एवं आईडेपा के भागीदार तथा आगन्तुक संकाय द्वारा उठाया जाता है। प्रलेखन केन्द्र पूरे वर्ष सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः नौ बजे से सायं 5.30 बजे तक खुला रहता है।

डिज़ीटल संसाधनों की पहुंच

इसके अंतर्गत संस्थान संकाय तथा अनुसंधानविदों के बीच विभिन्न प्रकार की सूचना की साझेदारी, संपर्कता, सहभाजन के लिए इंटरनेट गतिविधियों को सुदृढ़ तथा विकसित किया गया है। यह सूचना तथा ज्ञान का संग्रह, सृजन, हस्तांतरण तथा एकीकरण करता है। इसके डिज़ीटल संसाधन जैसे पुस्तकें, आलेख, अनुसंधान अध्ययन, समसामयिक आलेख श्रृंखला, प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्टें, सम्मेलन संगोष्ठी के कार्यकलाप, विख्यात शिक्षाविद् व्याख्यान श्रृंखला, दृश्य–श्रव्य व्याख्यान, समिति तथा समिति रिपोर्टें, इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। डिजीटल अभिलेखागार शिक्षा तथा इससे संबंधित क्षेत्रों के 11,000 नीतिगत दस्तावेज़ों के डिजीटल अभिलेख उपलब्ध कराता है। यह दस्तावेज़ इंटरनेट या इंटरानेट के माध्यम से [http://14.139.60.153/ or http://www.nuepa.org/New/darch.aspx]. पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त नई प्राप्तियों की सूची, नए जर्नलों की सूची, पाक्षिकों के वर्तमान घटक; जे. स्टोर तथा ऑनलाईन जर्नल डाटाबेस का सम्पूर्ण टेक्स्ट एक्सेस; संदर्भ ग्रंथ सूची – मांग पर साहित्य की खोज तथा इलैक्ट्रानिक दस्तावेज़ वितरण प्रणाली (ई.डी.डी.एस.) के लिये इंटरनेट के माध्यम से चौबीस घंटे ऑनलाईन

सूचना संसाधन तथा प्रलेखन सेवाएं पाठकों को प्रदान की गई है।

यह 300 मुद्रित जर्नलों (राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय) और ऑनलाईन डाटा बेस जैसे सेज, सेज शिक्षा संग्रह ऑनलाईन, एलसेवियर तथा जे. स्टोर की पहुंच प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त पाठकों को मुक्त शैक्षिक संसाधन हेतु पहुंच जैसे 11,831 पूर्ण लिखित जर्नल के संदर्भ में मुक्त पहुंच जर्नल डायरेक्टरी, 280 प्रकाशकों से 12646 अकादमिक सहकर्मी समीक्षा पुस्तकों की डायरेक्टरी, 32,10,157 आलेख, इलैक्ट्रानिक शोध और अनुसंधान हेतु 5 मिलियन ई.टी.डी. (51,11,718 ई.टी.डी.) और शोधगंगा (1,96,901 ई.टी.डी.) एवं अन्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण–पठन डाटाबेस, इंडेक्सिंग डाटाबेस, पाक्षिकों की वर्तमान सामग्री और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण पठन–सामग्री उपलब्ध कराता है। इससे अंतः पुस्तकालय ऋण तथा डेलनेट के माध्यम से पुस्तकों, दस्तावेजों, आलेखों इत्यादि के लिए प्रयोगकर्त्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ण करने में सुदृढ़ीकरण हुआ है। प्रलेखन केन्द्र की सेवाओं का लाभ संकाय, नीपा के अनुसंधानकर्त्ताओं, परियोजना स्टाफ, पीजीडेपा तथा आईडेपा, आई.पी.ई.ए., प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा भारत और अन्य देशों के विश्वविद्यालयों अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा उठाया जाता है।

व्यक्तिगत योगदान (डॉ. डी.एस. ठाकुर का शैक्षणिक योगदान – 2017–18

प्रकाशन

शोध पत्र/आलेख प्रकाशित

1. ठाकुर, डी.एस. (2018). वर्चुअल लर्निंग इनवायरमेंटः भारत में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के लिए मिश्रित सीखने के दृष्टिकोण के रूप में मूडल का उपयोग करना। अब्दुल मजीद बाबा, राज कुमार भारद्वाज, एस.एस. ढाका, तारिक अशरफ और नबी हसन (सं), बिल्डिंग स्मार्ट लाइब्रेरीजः चैंजेस चैलेंजेस इश्यूज एंड स्ट्रेटजीज़ 6–8 अगस्त, 2018 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर में

आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आलेख। नई दिल्लीः एशियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, पीपी. 177–188

सेमिनार / सम्मेलनों / कार्यशालाओं में भागीदारी

राष्ट्रीय

प्राइड प्लाजा होटल, एयरोसिटी, नई दिल्ली में नीपा द्वारा आयोजित 7–8 दिसंबर 2017 को कुलपतियों के लिए उच्च शिक्षा में नेतृत्व विकास पर कार्यशाला।

अंतरराष्ट्रीय

22–23 फरवरी 2018 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में सी.पी.आर.एच.ई., नीपा और ब्रिटिश काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशालाएँ

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) द्वारा आयोजित मूडल के साथ अध्यापन–अधिगम पर कार्यशाला, नई दिल्ली 10–12 जुलाई, 2017।

प्रशिक्षण सामग्री का विकास और संपादन

1. स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एससीईआरटी), दिल्ली द्वारा 6 जुलाई, 2017 को डाईट, राजिन्दर नगर, नई दिल्ली में आयोजित स्कूल पुस्तकाध्यक्षों के लिए तीन दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सूचना साक्षरता' पर व्याख्यान दिया।
2. स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एससीईआरटी), दिल्ली द्वारा 6 जुलाई, 2017 को दोपहर 12.00 बजे से 02:30 बजे तक डायट राजिन्दर नगर, नई दिल्ली में आयोजित स्कूल लाइब्रेरियन के लिए तीन दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सूचना साक्षरता और सूचना प्रौद्योगिकी' विषय पर व्याख्यान दिया।

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और अकादमिक सहायता

मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत की वार्षिक रिपोर्ट के लिए जानकारी व्यवस्थितः एक वार्षिक संदर्भ सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।

1. नीपा की गतिविधियों के बारे में सभी विभागों और प्रशासन के प्रमुखों से एकत्रित जानकारी जैसे कि शोध अध्ययन, एम.फिल. और पीएचडी कार्यक्रमों में नामांकन, सम्मानित पीएचडी डिग्री और प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूची। जानकारी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए की जाती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. नीपा के सभी विभागाध्यक्षों और प्रशासन से नीपा की अकादमिक और प्रशासनिक गतिविधियों जैसे आदिवासी और अल्पसंख्यक पर किए कए अध्ययन और प्रशिक्षण कार्यक्रम, भारत 2018, की तैयारी के लिए एकत्र करना : एक संदर्भ, वार्षिक प्रकाशन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय विभाग, भारत सरकर द्वारा प्रकाशित

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

कंप्यूटर कौशलः

लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस)	:	मूडल (मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट–ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट) लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम
कार्य का ज्ञान लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर / पैकेज	:	लिबसिस–4, टैक्लीबप्लस, ज्ञानोदया, विद्या, सीडीएस / आईएसआईएस 3.0।
कंप्यूटर प्रवीणता	:	विंडोज 2000, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज (HTML), फ्रंटपेज 2002

वेब पेज निर्माण और इंट्रानेट का ज्ञान

नीपा के प्रलेखन केंद्र की वेब साइट बनाई और अद्यतन की गई और लाइब्रेरी और पुस्तकालय एवं प्रलेखन केंद्र में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए संस्थान में एक इंट्रानेट विकसित किया, जैसे कि भारतीय और विदेशी पत्रिकाओं की सदस्यता, गैर–पुस्तक सामग्री मद, समसामयिक पर

सामग्री, डिजिटल संसाधनों और ऑनलाइन डेटाबेस की सूचना। इसके अलावा, प्रलेखन केंद्र द्वारा दी जाने वाली प्रलेखन सेवाएं जैसे अनुसंधान अध्ययन की सूची, सामयिक पेपर श्रृंखला, प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट, पीजीडेपा और आईडेपा के शोध प्रबंध, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग (ओपीएसी) और शोध अध्ययन के अन्य पूर्ण पाठ दस्तावेज, सामयिक पेपर श्रृंखला, प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट और नीपा वृत्तचित्र, प्रख्यात विद्वान व्याख्यान श्रृंखला इंट्रानेट पर भी उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, संस्थान के इंट्रानेट के लिए एक ऑनलाइन लाइब्रेरी विकसित की गई है जो लाखों खुले शैक्षिक संसाधनों जैसे किताबें, जर्नल, जर्नल लेख, इलेक्ट्रॉनिक शोध और शोध प्रबंध (ईटीडी), अनुक्रमण डेटाबेस आदि तक पहुंच प्रदान करती है।

विभिन्न प्रशासनिक और शैक्षणिक समितियों में सदस्य

3.1. नीपा में डिजिटल पहल के कार्यान्वयन के लिए नीपा डिजिटल अधिगम अनुश्रवण कक्ष के सदस्य।

3.2. संस्थान में सभी अकादमिक पुरस्कारों के लिए सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हाउस बनाने के लिए मा.स.वि.मंत्रालय और वि.अ.आयोग द्वारा अनिवार्य राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी (एनएडी) के कार्यान्वयन के लिए मैसर्स सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड (सीवीएल) के साथ समन्वय करने के लिए प्राधिकृत शैक्षणिक संस्थान अधिकारी।

3.3. शोधगंगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इन्फिलबिनेट (सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क) से संबंधित गतिविधियों के लिए विश्वविद्यालय समन्वयक।

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

1. भारतीय पुस्तकालय संघ (आई.एल.ए.), दिल्ली। (आजीवन सदस्य)
2. भारत सरकार पुस्तकाध्यक्ष संघ (आई.एल.ए.), दिल्ली। (आजीवन सदस्य)

5

कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

कंप्यूटर केंद्र संस्थान की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेटवर्क संस्थान की रीढ की हड्डी है तथा इसके सक्रिय संघटकों को कंप्यूटर केंद्र द्वारा संचालित, रखरखाव तथा नियंत्रित किया जाता है। कंप्यूटर केंद्र एन.एम. ई.आई.सी.टी परियोजना के अंतर्गत एन.के.एन./एम.टी.एन.एल. द्वारा प्रदान की गई 1 जी.बी.पी.एस ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट संपर्कता से सुसज्जित है। संस्थान में सतत रूप से हर समय इंटरनेट की संपर्कता 24x7x365 सुनिश्चित करने के लिए एरनेट से 10 एम.बी.पी.एस. का बैकअप की सुविधा उपलब्ध है। कंप्यूटर केंद्र सभी स्टाफ सदस्यों, प्रशिक्षुओं, परियोजना स्टाफ, कार्यक्रम भागीदारों, अनुसंधानविदों को कंप्यूटर सुविधा तथा इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराता है। नेटवर्क संसाधनों का प्रयोग करने हेतु सभी स्टाफ सदस्यों तथा संकाय सदस्यों को उच्च गति वाली इंटरनेट संपर्कता तथा नेटवर्क प्वाइंट प्रदान किये गये हैं। नीपा डोमेन पर सभी स्टाफ तथा संकाय सदस्यों को व्यक्तिगत ई–मेल खाता की सुविधा दी गई है। कुलपति तथा अन्य सभी संकाय सदस्यों के निवास पर ब्राड–बैन्ड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई गई है। सभी स्टाफ सदस्यों तथा संकाय को डेस्कटाप/लैपटाप कंप्यूटर सुविधा दी गई है। कंप्यूटर केंद्र की सुविधाएं बिना किसी व्यावधान के लगातार 12 घंटे उपलब्ध रहती हैं। कंप्यूटर केन्द्र पर संस्थान के अपने कंप्यूटरों तथा संबंधित उपकरणों के रखरखाव की जिम्मेदारी है।

कंप्यूटर केन्द्र संस्थान की दैनिक अकादमिक तथा गैर अकादमिक गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने हेतु सुविधाएं प्रदान करता है। कंप्यूटर केंद्र विभिन्न प्रकार के नवीनतम कंप्यूटर और प्रिंटरों तथा मल्टी–फंक्शन डिवाईज़ेज से सुसज्जित है। संस्थान के सभी तलों पर सभी कमरे नेटवर्क (साईबररोम सीआर 500) से जुड़े हुए हैं।

नीपा भवन से नीपा हास्टल को उच्च गति इंटरनेट संपर्कता उपलब्ध कराई गई है। नीपा छात्रावास के सभी तलों के कमरों में अतिथियों के लिये प्रमाणित तथा सुरक्षित वाई–फाई संपर्कता उपलब्ध–कराई गई है।

यह केंद्र अकादमिक एककों को प्रशिक्षण, अनुसंधान, मात्रात्मक आंकड़ा विश्लेषण और प्रणाली स्तर के प्रबंधन संबंधी मुद्दे तथा दूसरे कार्यकलापों में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त गैर–अकादमिक एककों जैसे – पुस्तकालय, प्रशासन तथा वित्त विभागों को भी सहायता प्रदान की जाती है। संस्थान की डाटा प्रोसेसिंग तथा वर्ड प्रोसेसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा कंप्यूटर केंद्र विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों/कार्यक्रमों के लिए अन्य विशिष्ट कंप्यूटर आधारित सेवाएं प्रदान करता है।

लेखा अनुभाग को भी कंप्यूटर अनुप्रयोग के लिए समर्थन दिया जाता है। इसमें शामिल है, वेतन संगणना, आयकर गणना, पेंशन, भविष्य निधि गणना आदि। इसके लिए एस.पी.एस.एस. सांख्यिकी पैकेज नेटवर्क वर्जन सर्वर के साथ स्थापित किया गया है ताकि प्रयोगकर्त्ता नेटवर्क पर गणना कर सकें। कंप्यूटर केंद्र दैनिक गतिविधियों के लिये ओपन स्रोत साफ्टवेयरों को प्रोत्साहन देता है।

संस्थान की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आधुनिक डाटा केन्द्र स्थापित किया गया है। डाटा केन्द्र उच्च गुणवत्तायुक्त डाटा सर्वर तथा वेब सर्वर से जुड़ा है जोकि चौबीसों घंटे 24x7x365 उपभोक्ताओं के लिये ऑन–लाईन उपलब्ध है। डाटा सेंटर समर्पित समानांतर यू.पी.एस. सिस्टम से समर्थ है जो सर्वर को पावर बैक–अप प्रदान करता हैं। घरेलू डाटा सेंटर को सुदृढ़ बनाने हेतु एस.ए.एन. स्टोरेज़ के साथ ब्लेड सर्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। संस्थान में इंटरनेट संलग्नता में वृद्धि तथा समर्थतता हेतु एवं डाटा केन्द्र का इंटरनेट लिंक हेतु बैक–अप कनेक्टिविटी के लिये 10 एम.बी.पी.एस. रेडियो फ्रीक्वेन्सी लिंक (आर.एफ. लिंक) किया गया है।

भारत सरकार के मुख्य कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के फ्लैगशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत जाने–माने कार्यक्रम एकीकृत शैक्षिक जिला प्रणाली सूचना (यू–डाईस) के लिये सर्वर का रखरखाव संगणक केंद्र करता है। इसके अलावा संगणक केंद्र विद्यालय मानक एवं मूल्यांकन – शाला सिद्धि के राष्ट्रीय कार्यक्रम के वेब पोर्टल का भी रखरखाव करता है।

6

प्रकाशन

NIEPA PUBLICATIONS

प्रकाशन

संस्थान का प्रकाशन एकक संस्थान द्वारा की गई शोध और विकास गतिविधियों के निष्कर्षों के प्रकाशन और प्रसारण द्वारा ज्ञान की साझेदारी संबंधी कार्यकलापों का अनुसमर्थन व्यापक स्तर के लिए करता रहा है। संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने के अनुक्रम में प्रकाशन एकक समसामयिक आलेख/जर्नल/पाक्षिक न्यूजलेटर, पुस्तकें, एम.फिल. और पी–एच.डी. की विवरणिका और प्रशिक्षण कार्यक्रम का कैलेण्डर प्रकाशित करता है। यह विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों के शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षणों की रिपोर्टों की श्रृंखला भी प्रकाशित करता है। प्रकाशन एकक कंप्यूटरों तथा प्रिंटरों से सुसज्जित है और विश्वविद्यालय के डीटीपी कार्य भी करता है।

वर्ष 2017–18 के अंतर्गत संस्थान द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन निकाले गए – जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (अंग्रेजी), परिप्रेक्ष्य (हिंदी) जर्नल और सी.पी.आर.एच.ई. अनुसंधान आलेख, एम.फिल तथा पी–एच.डी. कार्यक्रमों की विवरणिका तथा पाठ्यचर्या गाईड। संस्थान ने अनेक शोध और संगोष्ठियों/सम्मेलनों की रिपोर्टें पुस्तक और मोनोग्राफ के रूप में प्रकाशित की। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संस्थान ने निम्नांकित प्रमुख प्रकाशन निकाले :

जर्नल

- जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिल्द XXXI, 2017 (अंक 1,2, और 3)
- परिप्रेक्ष्य (शैक्षिक योजना और प्रशासन में सामाजिक–आर्थिक संदर्भ हिन्दी जर्नल) जिल्द XXIII, 2016 (अंक 1 और 2)

एंट्रीप न्यूज़लेटर

- एंट्रीप न्यूज़लेटर (जुलाई–दिसंबर 2016)
- एंट्रीप न्यूज़लेटर (जनवरी–जून 2017)

समसामयिक आलेख:

- नीपा समसामयिक आलेख सं. 50: ***यूनियन– स्टेट रिलेशन इन इंडियाज़ हायर एजुकेशन:*** **जे.बी. जी. तिलक,** नई दिल्ली, नीपा
- नीपा समसामयिक आलेख सं. 51: ***रिप्रजेंन्टेशन आफ वूमेन इन स्कूल लीडरशिप पोज़िशन इन इंडिया,*** **एन. मैथिली,** नई दिल्ली, नीपा, 50 पृष्ठ

सी.पी.आर.एच.ई. शोध आलेख:

- सीपीआरएचई अनुसंधान आलेख 2 (पुर्नमुद्रण) : ***रिफार्म्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, ए रिव्यू आफ रिकमन्डेशन्स आफ कमीशन्स एंड कमीटीस ऑन एजुकेशन,*** **ए. मैथ्यू,** नई दिल्ली: नीपा
- सीपीआरएचई अनुसंधान आलेख 7: ***इंगलिश एस.ए. मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन इन इंडियन एजुकेशन इनक्वैलिटी आफ एक्सेस टू एजुकेशनल अर्पाच्युनिटीज,*** **वाणी के. बूराह** और **निधि एस. सभरवाल**, नई दिल्ली: नीपा
- सीपीआरएचई अनुसंधान आलेख 8: ***टीचर्स रिक्यूरमेन्ट इन हायर एजकेशन इन इंडिया: एन अनालिसिस ऑफ नेशनल एलिजिबिटी टेस्ट (नेट) रिसल्टस,*** **एन.वी. वर्गीज, गरिमा मलिक, और धर्म रक्षित गौतम** द्वारा, नई दिल्ली: नीपा

सःशुल्क प्रकाशन

- ***इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2016ः इक्विटी* (एन.वी. वर्गीज, निधि एस. सभरवाल, और सी. एम. मलिश** द्वारा संपादित, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली

निःशुल्क प्रकाशन :

1. एम.फिल. और पी.एच.डी. पाठ्यचर्या गाईड 2017
2. एलिमेन्ट्री एजुकेशन इन इंडिया : फ्लैश स्टैस्टिक्स 2015–16
3. सेकेण्डरी एजुकेशन इन इंडिया : फ्लैश स्टैस्टिक्स 2015–16
4. स्कूल लीडरशिप डवलपमेन्ट : ए करीकुलम फ्रेमवर्क (पंजाबी संस्करण)
5. न्यूपा – एट ए ग्लान्स
6. नेशनल अवार्ड्स फार इनोवेशन इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन (सूचना विवरणिका)
7. सी.पी.आर.एच.ई. रिपोर्ट 2016–17
8. कुलपतियों के लिए उच्च शिक्षा में नेतृत्व विकास पर कार्यशाला हेतु सूचना विवरणिका (07–08 दिसंबर 2017)
9. सी.पी.आर.एच.ई. नीतिगत सार (1, 2 तथा 3) (अंग्रेजी संस्करण)
10. उच्च शिक्षा में वित्तपोषण में नवाचार पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की रिपोर्ट (16–17 फरवरी 2017)
11. उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पर विवरणिका (22–23 फरवरी 2017)
12. विश्वविद्यालय प्रशासकों के लिए उच्च शिक्षा में नेतृत्व विकास पर कार्यशाला हेतु विवरणिका (26–28 फरवरी, 2018)
13. उच्च शिक्षा में छात्र विविधता और भेदभाव पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की रिपोर्ट (27–28 फरवरी 2017)
14. चेंजिंग पर्सपेक्टिवः नियो–लिबरल पॉलिसी रिफामर्स एंड एजुकेशन इन इंडिया (प्रो. कुलदीप माथुर) (नीपा XI स्थापना दिवस व्याख्या)
15. मानव संसाधन विकास मंत्रालय / स्कूल मानक और मूल्यांकन एकक, नीपा के प्रकाशन
    अ) शाला सिद्धि : विद्यालय स्वः मूल्यांकन हेतु निर्देशिका (अंग्रेजी संस्करण)
    ब) शाला सिद्धि : विद्यालय स्वः मूल्यांकन हेतु निर्देशिका (हिंदी संस्करण)

अन्य

इन प्रकाशनों के अतिरिक्त, नीपा ने निम्नांकित प्रकाशन प्रकाशित किये : विवरणिका (एम.फिल. तथा पी–एच. डी. कार्यक्रम) 2017–18; ईयर प्लानर 2018; शीट प्लानर 2018; डेस्क कैलेंडर 2018; नीपा कार्यक्रम हेतु प्रमाण–पत्र, ग्रीटिंग कार्ड; आईडेपा और पीजीडेपा तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए घोषणा पत्र; राईटिंग पैड; डॉकेट फोल्डर; स्थापना दिवस तथा मौलाना आजाद शिक्षा दिवस एवं अन्य दूसरे कार्यक्रमों के लिए पोस्टर आदि।

मिमियोग्राफ प्रकाशनः समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संस्थान ने विभिन्न अनुसंधान अध्ययनों के मिमियोग्राफ, प्रतिलिपि प्रकाशन, नीपा द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों / संगोष्ठियों की पठन सामग्री, रिपोर्टें प्रकाशित किए।

नीपा वेबसाइट को योगदान : प्रकाशन विभाग ने अपने प्रकाशनों से संबंधित निम्नांकित अद्यतन सूचनाएं अपलोड करने हेतु उपलब्ध कराई है : नीपा के समूल्य तथा निःशुल्क प्रकाशनों की वृहद सूची तथा नीपा के लिए निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की सूची; जेपा के वर्तमान तथा भविष्य के अंकों के बारे में सूचना; नीपा प्रशिक्षण कार्यक्रम का कैलेंडर तथा नीपा एट ए ग्लान्स; एम.फिल और पी–एच.डी. विवरणिका; निगम ज्ञापन और नियम (नीपा); चतुर्मासी हिंदी जर्नल परिप्रेक्ष्य; नीपा समसामयिक तथा सी.पी.आर.एच.ई. आलेखों को अपलोड करना; नीपा वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी तथा हिंदी संस्करण) 2014–15, तथा डाईस प्रकाशन का वेब वर्जन इत्यादि।

नीपा में सहायता अनुदान योजना

7

नीपा में सहायता अनुदान योजना

कार्य योजना के विस्तार के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्यवाही योजना में उनकी पुनः व्याख्या के विभिन्न मानकों का क्रियान्वयन हेतु उद्देश्यों का वृहद प्रचार आवश्यक है तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों तथा सामाजिक संगठनों के साथ निकटतम सहयोग आवश्यक है। नीति के क्रियान्वयन में बेहतर समन्वयन हेतु, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर समर्थन व्यवस्था समेत अंतःशास्त्रीय उपागम आवश्यक है।

इस संदर्भ में ये आवश्यक हैंः (अ) देश में शैक्षिक नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रति वृहद जागरूकता पैदा करना, (ब) नीति उन्मुख अध्ययनों तथा संगोष्ठियों को आरंभ करना ताकि मध्य–पाठ्यक्रम सुधार, संशोधन तथा नीति हस्तक्षेपों के साथ समायोजन किया जा सके (स) अध्यापकों, छात्रों, युवाओं तथा महिलाओं और संचार माध्यमों को प्रायोजित संगोष्ठी के आयोजन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके साझा मंच प्रदान करना। (द) शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारी तथा अच्छे व्यवहार एवं सफल प्रयोग को बढ़ावा देना (य) राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्य योजना की समीक्षा को सुविधाजनक बनाना।

उपरोक्त प्रयोजन के लिये, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सहायता अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वित किया है जिसके अंतर्गत योग्य संस्थानों तथा संगठनों को वित्तीय सहायता शिक्षा नीति के प्रबंधन तथा क्रियान्वयन पक्ष पर सीधे प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के आधार पर प्रदान की जायेगी। इसके अंतर्गत सम्मेलनों का आयोजन, प्रभावी तथा मूल्यांकन अध्ययन, सर्वोत्तम विकल्पों पर परामर्शकारी अध्ययन, भारत सरकार को सलाह देने हेतु तथा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु मॉडल, विडियो फिल्म इत्यादि का निर्माण सम्मिलित हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने इस विश्वविद्यालय के माध्यम से यह योजना संचालित की है जो सहायता अनुदान समिति के द्वारा इसे संचालित करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता अनुदान योजना के तहत विभिन्न संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन तथा अनुमोदन के लिए एक समिति का गठन किया गया है। 31 मार्च, 2018 के अनुसार इस समिति के निम्नांकित सदस्य हैंः

प्रोफेसर ए.के. सिंह	–	अध्यक्ष
प्रोफेसर ए.के. शर्मा	–	सदस्य
प्रोफेसर उमा मेदुरी	–	सदस्य
प्रोफेसर एन.आर. भानुमूर्ति	–	सदस्य
प्रोफेसर नीलम सूद	–	सदस्य
प्रोफेसर कुमार सुरेश	–	सदस्य
प्रोफेसर वीरा गुप्ता	–	सदस्य
प्रोफेसर प्रमिला मेनन	–	सदस्य
प्रोफेसर के. बिस्वाल	–	सदस्य
श्री बसवराज स्वामी	–	सदस्य सचिव

सहायता अनुदान समिति ने इस योजना के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन के रिकार्ड और प्रस्तावों पर निगरानी हेतु डाटाबेस विकसित करने का निर्णय लिया। इसके अनुसार डाटाबेस तैयार किया गया और सहायता अनुदान समिति की बैठकों में प्रस्तुत किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष 2017–18 के दौरान समिति ने निम्नांकित सहायता अनुदान की संस्तुति प्रदान की। जिसका विवरण नीचे तालिका में प्रस्तुत है :

1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान आयोजित की गई बैठकें

क्र. सं.	संगठन का नाम	सेमिनार/सम्मेलन/अनुसंधान अध्ययन का विषय	बैठक की तिथि	स्वीकृत सहायता अनुदान राशि रू. में
1.	भारथी हैल्थ एजुकेशन एंड रूरल डवलपमेंट सोसायटी	केंद्रीय बजट 2017 में शिक्षा क्षेत्र पर मुख्य निर्णय	जीआईएसी की 35वीं बैठक 12.07.2017	3,00,000.00
2.	साई एजुकेशनल रूरल एंड अर्बन डवलपमेंट सोसायटी (एसईआरयूडीएस)	भारत में प्रत्यायनः उच्च शिक्षा में शैक्षिक उत्कृष्टता का मार्ग		3,00,000.00
3.	नवनीत फाउंडेशन	प्रारंभिक शैशवकालीन देखभाल और राष्ट्रीय शिक्षा नीति		3,00,000.00
4.	संगीता राव एजुकेशनल सोसायटी (एसआरईएस)	आरटीई अधिनियम के तहत आयु उपयुक्त प्रवेशः चुनौतियां और अवसर		3,00,000.00
5.	उर्मिला फाउन्डेशन, मधुबनी	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के तहत निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के छात्रों को दाखिला लेने के लिए आरक्षण की समस्या और संभावनाएंः इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर विशेष ध्यान देने के साथ नीतिगत मुद्दों पर चर्चा		3,00,000.00
6.	सेंटर फॉर केटालाइजिंग कम्यूनिटी	निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 में बच्चों के अधिकार का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण		3,00,000.00
7.	शिव शक्ति महिला मंडल	जीवंत कला तथा सांस्कृतिक शिक्षा विकल्प		3,00,000.00
8.	मदर सोसायटी (मिरैक्क्ल आग्रेनाइजेशन टूवार्ड्स हैल्थ एंड एजूकेशनल रेमेडिअल सोसायटी), कुरनूल	विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच अंतराफलक के माध्यम से कौशल अंतराल को दूर करना	जीआईएसी की 36वीं बैठक 08.11.2017	3,00,000.00
9.	साना एजुकेशनल डवलपमेंट सोसायटी, नंदयाल, कुरनूल	प्रस्तावित उच्च शिक्षा सशक्तीकरण विनियमन एजेंसी (हीरा)		3,00,000.00
10.	कश्मीर इन्वायरमेंटल एंड सोशियल ऑग्रेनाइजेशन, बांदीपोरा, जम्मू एंड कश्मीर	कश्मीर के गुज्जर और बकरवालों के लिए शिक्षा तक पहुँच		1,50,000.00
11.	राजगिरि कॉलेज ऑफ सोशियल साइंसेज, कोचीन	परिणाम आधारित परिप्रेक्ष्य और व्यवहार सामाजिक कार्य का पुनः संयोजन		3,00,000.00
12.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	भारतीय तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ''सम्मेलन का विषय समकालीन शैक्षिक प्रवचनों में आलोचना, सहानुभूति और कल्याण है''		5,00,000.00

क्र. सं.	संगठन का नाम	सेमिनार/सम्मेलन/अनुसंधान अध्ययन का विषय	बैठक की तिथि	स्वीकृत सहायता अनुदान राशि रू. में
13.	मणिपुर एजुकेशनल डवलपमेंट एंड रिसर्च एसोसिएशन, इम्फाल–पश्चिम मणिपुर	उच्च शिक्षा में महिलाएँः मुद्दे और चुनौतियां	जीआईएसी की 36वीं बैठक 08.11.2017	2,19,780.00
14.	वाटर, एग्रीकल्चरल, टैक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड रिर्सोस, हैदराबाद, तेलंगाना	स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति और छोड़ने की घटती दर को सुधारने में स्वच्छ विद्यालय योजना की भूमिका		3,00,000.00
15.	इंडियन एकेडमी ऑफ सोसियल साइंसेज, इलाहाबाद	XLI भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस विषयगत प्रस्तावनाः भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणालीः एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन		5,00,000.00
16.	ऑल इंडिया काउंसिल फॉर मास एजुकेशन एंड डवलपमेंट (एआईसीएमईडी) पटौटोला लेन, कोलकाता	आजीवन सीखने के संदर्भ में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण और विकास		3,00,000.00
17.	गार्गी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नई दिल्ली	नव–उदारवाद कॉल में नीतिगत परिवर्तनः मुख्य सरोकार तथा महत्वपूर्ण विषय		2,50,000.00
18.	सोसायटी फॉर डिसेबिलिटी एंड रिहाबिलिटेशन स्टडीज, नई दिल्ली	भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए विकलांगता अध्ययन पर एक मॉडल पाठ्यक्रम विकसित करना		3,00,000.00
19.	इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	भारतीय इतिहास कांग्रेस का 78वाँ सत्र		3,00,000.00
20	हूमन एंड रूरल इंटिग्रेशन फॉर टकनीकल एक्शन (एचएआरआईटीए), अनंतपुर	स्वयम प्रभा– उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए निःशुल्क डीटीएच चैनलः चुनौतियाँ और सुझाव	जीआईएसी की 37वीं बैठक 16.02.2018	2,70,000.00
21.	वोलंटरी इंटिग्रेटेड डवलपमेंट सोसायटी, अनंतपुर	स्कूलों में विज्ञान शिक्षाः मुद्दे और चुनौतियाँ		3,00,000.00
22.	नेहरू युवाजन सेवा संघम (एनवाइएसएस), चित्तूर	21वीं सदी की गुणवत्ता शिक्षा के लिए शिक्षक शिक्षा में नए प्रतिमान।		2,70,000.00
23.	सेंटर फॉर एजुकेशनल एंड सोशियल स्ट्डीज (सीईएसएस), बंगलौर	भारत में राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में स्नातक शिक्षा का कायाकल्प।		3,00,000.00
24.	वूमन एंड इन्वायरमेंट डवलपमेंट सोसायटी (डब्ल्यूईडीएस), कोप्पल	साक्षर भारतः प्रौढ़ शिक्षा में प्रयासों में वृद्धि को बनाए रखना		2,70,000.00
25.	मोलेक्यूलर वैलफेअर सोसायटी, ग्वालियर	अधिगम की समस्या		3,00,000.00
26.	हूमन रिसोर्स एंड इकोनोमिक डवलपमेंट, पश्चिम इम्फाल, मणिपुर	उत्तर पूर्व भारत में उच्च शिक्षा– अवसर और चुनौतियां।		2,33,000.00
27.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल, मिजोरम	शांति, मानवाधिकार और सहिष्णुता के लिए शिक्षा		3,00,000.00

क्र. सं.	संगठन का नाम	सेमिनार/सम्मेलन/अनुसंधान अध्ययन का विषय	बैठक की तिथि	स्वीकृत सहायता अनुदान राशि रू. में
28.	प्रतीक्षा, नुआपाड़ा	ओडिशा के नुआपाड़ा में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत पात्र और पलायन करने वाले बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।	जीआईएसी की 37वीं बैठक 16.02.2018	2,85,800.00
29.	सुरक्षा, गजपति	भारत के आदिवासी जिलों, गजपति, ओडिशा के स्कूल प्रबंधन समिति के प्रभावी कामकाज के लिए लंजिया–सौरा जनजाति (विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों) के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के मुद्दे, चुनौतियाँ और संभावित रणनीतियाँ।		2,78,650.00
30.	रूरल ऑर्गनाइजेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट (आरओएसई), हैदराबाद, तेलंगाना	राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी योजना और आगे की ओर जागरूकता के लिए सम्मेलन।		3,00,000.00
31.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़,	सतत मानव विकास के लिए मानसिक स्वास्थ्य।		4,34,000.00
32.	द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी (TIES), नई दिल्ली	टीआईईएस का 54वाँ वार्षिक सम्मेलन		3,00,000.00
		वर्ष 2017–18 के दौरान कुल राशि स्वीकृत		**₹ 96,61,230.00/–**

8

प्रशासन और वित्त

प्रशासन और वित्त

प्रशासन

संस्थान के पास हाउसकीपींग तथा सुरक्षा सेवाओं के लिये बाह्य सेवा–स्रोतों के अतिरिक्त निम्नांकित स्वीकृत पद हैं।

प्रशासन तथा अकादमिक एंव तकनीकी समर्थन सेवाएं प्रशासन के कार्य के अनुसार स्थापित अनुभागों द्वारा नियंत्रित तथा समन्वित की जाती हैं।

इसके अनुभाग कार्यकलापों के अनुसार स्थापित किये गए हैं जिन्हें संगठनात्मक आरेख में प्रदर्शित किया गया है। संस्थान में स्वीकृत पदों के अलावा विभिन्न अकादमिक और अनुसचिवीय पदों पर 70 परियोजना कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं।

बाह्य संवर्ग पद	**संख्या**
कुलपति	01
कुलसचिव	01
संवर्ग पद	
संकाय (कुलपति, प्रोफेसर, सह–प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर)	42
अकादमिक समर्थन स्टाफ़	11
प्रशासन, वित्त, सचिवीय तथा अन्य तकनीकी स्टाफ	70
सहायक स्टाफ (एम.टी.एस.)	37
कुल	162

समीक्षाधीन वर्ष 2017–18 के अंतर्गत, निम्नांकित नियुक्तियां/सेवानिवृत्तियां की गईं।

सेवानिवृत्तियां

समूह 'ए'

क्र.सं.	नाम	पद	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	प्रो. जांध्याला बी.जी. तिलक	प्रोफेसर	31.05.2017
2.	प्रो. नलिनी जुनेजा	प्रोफेसर	31.07.2017
3.	प्रो. नीलम सूद	प्रोफेसर	31.01.2018
4.	श्री बसवराज स्वामी	कुलसचिव	08.03.2018

समूह 'सी'

क्र.सं.	नाम	पद	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री सुन्दर लाल	चालक	30.04.2017
2.	श्रीमती रम्भा कुमारी	आशुलिपिक ग्रेड–I	30.04.2017
3.	श्रीमती नीलम मुतरेजा	सहायक	30.04.2017
4.	श्री पदम सिंह बिष्ट	डी.ई.ओ.–सी	30.04.2017
5.	श्रीमती जसविन्दर कौर	अ.श्रे. लिपिक	31.07.2017
6.	श्रीमती संतोष कुमारी	आशुलिपिक ग्रेड–I	31.07.2017
7.	श्रीमती अनीता कपूर	सहायक	28.02.2018

नई नियुक्ति

क्र.सं.	नाम	पद	नियुक्ति की तिथि
1.	प्रो. एन.वी. वर्गीज	कुलपति	07.12.2017

वित्त तथा लेखा विभाग

नीपा में वित्त तथा लेखा सेवाएं लेखा अनुभाग द्वारा संचालित की जाती हैं जिसका अध्यक्ष वित्त अधिकारी होता है जिसके अंतर्गत अनुभाग अधिकारी, लेखाकार और कार्यालय के आठ सदस्य तथा अनुसचीवीय स्टाफ होता है। यह अनुभाग बजट की तैयारी, मासिक वेतन तथा पेंशन बिल, अन्य व्यक्तिगत प्रतिपूर्ति जैसे चिकित्सा, एल.टी.सी. बिल, अग्रिम इत्यादि, वस्तुओं की खरीद के लिये बिल भुगतान प्रक्रिया, कार्य, संविदा इत्यादि, पूर्व लेखा परीक्षा, बाह्य परीक्षा के साथ समन्वयन तथा वित्त तथा लेखा से जुड़े अन्य मसलों के लिये उत्तरदायी होता है।

यह सभी वित्तीय मसलों पर समयबद्ध परामर्श देता है तथा वित्तीय भागीदारी, लेखा बयान, उपयोगिता प्रमाण–पत्र इत्यादि हेतु सभी प्रस्तावों के परीक्षण हेतु प्रभावी सहायता प्रदान करता है। वित्त अधिकारी वित्त समिति का सदस्य सचिव होता है जो विश्वविद्यालय के वित्त, निर्देशन तथा विभिन्न श्रेणियों के लिये व्यय की सीमा तय करता है। पिछले पांच वर्षों में मंत्रालय से प्राप्त अनुदान निम्नांकित है :

प्राप्त अनुदान का व्यौरा (2013–2018) (रु. लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	सहायता अनुदान (योजना)	1185.00	1206.97	1425.28	1010.87	26.12.95
	सहायता अनुदान (योजनेतर)	1415.00	1511.60	1769.80	1816.11	
	आंतरिक प्राप्तियां	102.81	71.75	131.70	74.47	59.32
	योग	**2702.81**	**2790.32**	**3326.78**	**2901.45**	**2672.27**

2.	व्यय (योजना)	1,272.97	1239.00	1239.97	1078.42	2956.09
	व्यय (योजनेतर)	1441.86	1643.35	1690.36	1721.81	
	योग	**2714.83**	**2882.35**	**2930.33**	**2800.23**	–

3.	आंतरिक प्राप्तियां व्यय के प्रतिशत के रूप में	1%	1%	1%	1%	2%

4.	सहायता अनुदान व्यय का प्रतिशत	100%	100%	100%	100%	100%

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान सहायता अनुदान में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है और इसी अनुपात में इसका व्यय भी बढ़ा है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नीपा अपनी मुख्य गतिविधियों को पर्याप्त महत्व दे रहा है।

राजभाषा कार्यान्वयन/ हिंदी कक्ष

हिंदी कक्ष

हिंदी कक्ष अनुवाद की सुविधा के माध्यम से अनुसंधान प्रशिक्षण और प्रशासन में अकादमिक सहायता प्रदान करता है। यह कक्ष विभिन्न प्रकाशनों के हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के साथ–साथ राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में भी सहायता प्रदान करता है।

विश्वविद्यालय के हिंदी कक्ष द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान रोजमर्रा के कार्यों के अलावा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गएः

(क) हिंदी में प्रगामी प्रयोग के लिए विश्वविद्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

(ख) शैक्षिक योजना और प्रशासन के सामाजिक–आर्थिक संदर्भ से संबंधित हिंदी जर्नल परिप्रेक्ष्य के दो अंक प्रकाशित किए गये।

(ग) हिंदी में निम्नलिखित सामग्री का अनुवाद करके उन्हें प्रकाशन के लिए तैयार किया गयाः

(i) वार्षिक रिपोर्ट : 2016–17

(ii) प्रशिक्षण कार्यक्रम : 2016–17

(iii) हैंडबुक, पाठ्यचर्या तथा अनेक शोध उपकरणों का हिंदी अनुवाद

(iv) परिपत्रों, पत्रों, अधिसूचनाओं, नोटिस, कार्यालय ज्ञापनों आदि का हिन्दी अनुवाद

(घ) हिंदी दिवस समारोह : हिंदी दिवस के उपलक्ष में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गएः

(i) हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 14–28 सितम्बर 2017 के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गए। हिंदी पखवाड़े 2017 के दौरान हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी प्रारूपण और टिप्पण प्रतियोगिता, हिन्दी अनुवाद प्रतियोगिता, हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता, हिंदी प्रश्नमंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुल संस्थान के 15 अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षत किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ग 'क' के कर्मचारियों के लिये हिंदी सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

(ii) हिंदी कक्ष ने योग और स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग किया।

(ङ) एनसीएसएल, सीपीआरएचई तथा शाला सिद्धि के लिए प्रशिक्षण सामग्री का हिंदी अनुवाद।

अनुलग्नक

संकाय का अकादमिक योगदान

अनुलग्नक

संकाय का अकादमिक योगदान

शैक्षिक योजना विभाग

पी. गीता रानी

प्रो. पी. गीता रानी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय (राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर)।

जर्नल्स में प्रकाशन

गीता रानी, पी. (2017), डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशन लोन्स इन इंडियाः हू गेन्स एंड हू लोसेज? (सह–लेखक) जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, अंक. 9, संख्या1, 2017, पृ. 17–30.

गीता रानी, पी. (2017), एजुकेशन लोन्स एंड फाइनेंसिंग हाइयर एजुकेशन इन इंडियाः ट्रेंड्स, ड्राइविंग फोर्सेज एंड डिस्टोर्संस, आईएएसएसआई क्वार्टर्ली कंट्रीब्यूशन्स टु सोशल साइन्सेजः शिक्षा और विकास पर विशेष अंक, 2017, 36 (2 और 3), पीपी. 152–173.

गीता रानी, पी. (2017), फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन एंड एजुकेशन लोन्स इन इंडियाः इंटरस्टेट डिफरेंसियल्स एंड डिटर्मिनेंट्स, जर्नल ऑफ सोशल एंड एकोनोमिक डेवलपमेंट, 2017, 19 (1), 42–59 स्प्रिंगर.

संपादित संस्करणों में अध्याय

"क्रेडिट मार्केट्स इन इंडियाः द केस ऑफ एजुकेशन लोन इन डेवेप्लोपिंग ए क्रेडिट मार्केट फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया" नामक अध्याय (सं.) एम. एम. अंसारी; सिद्धार्थ सोनवत; शाश्वती घोष, यस ग्लोबल इंस्टीट्यूट, यस बैंक, 2017.

यूथ डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2016, आरजीआईवाईडी, श्रीपेरंबुदूर, आगामी, 2017 की तैयारी के लिए "डेवलपमेंट ऑफ यूथ एजुकेशन इन इंडियाः पैटर्न एंड प्रोस्पेक्ट्स" नामक अध्याय का योगदान दिया।

आयोजित की गईं सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी व्यावसायिक विकास गतिविधियाँ

प्रो. पी. गीता रानी, अर्थशास्त्र विभाग, तमिलनाडू केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा 17–18 जनवरी, 2018 को आयोजित 'मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तमिलनाडू केंद्रीय विश्वविद्यालय का संयुक्त संकाय संगोष्ठी।

वर्ष 2017–2018 के लिए प्रो. पी. गीता रानी, अर्थशास्त्र विभाग, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विद्यार्थी संगोष्ठी।

वर्ष 2017–2018 के लिए प्रो. पी. गीता रानी, अर्थशास्त्र विभाग, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पीएचडी. शोध समीक्षा संगोष्ठी।

वर्ष 2016–2018 बैच के लिए प्रो. पी. गीता रानी, अर्थशास्त्र विभाग, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एमए शोध प्रबंध संगोष्ठी।

संकाय विकास कार्यक्रम (यूजीसी–एचआरडीसी पाठ्यक्रम), सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशालाएँ आदि में संकाय भागीदारी, विवरण सहित

एआईबीओसी (AIBOC) द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS), चेम्बूर, मुंबई में 24–25 मई, 2017 को आयोजित पीपल्स पार्लियामेंट फॉर डेव्लपमेंट के परामर्श पर 'रिसेंट डिकेड्स ऑफ क्रेडिट एंड डेव्लपमेंट' नामक पैनल डिस्कशन में पैनलिस्ट।

सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा 17–18, जून, 2017 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशनः टूवर्ड्स सुसटेनेबल्ल डेव्लपमेंट गोल 4" नामक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मे ''पैटर्न ऑफ एनरोलमेंट इन स्कूल इजुकेशन इन इंडियाः पोसिबल इंटरफेस ऑन इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन" में सहभागिता।

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी), बैंगलोर में 21–22 मार्च, 2018 के दौरान आयोजित होने वाले मूल्यांकनकर्ताओं अभिविन्यास कार्यक्रम में सहभागिता हेतु आमंत्रण।

अर्थशास्त्र विभाग, भतिृहार विश्वविद्यालय, कोयंबटूर, तमिलनाडु द्वारा 22–24 जनवरी, 2018, आयोजित 'रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर सोशल साइन्सेज' "डाटा एनालिसिस युसिंग लार्ज स्केल सर्वेज – कोरिलेशन एंड रिग्रेशन" नामक कार्यशाला में सहभागिता।

आरडी फाउंडेशन सेंटर फॉर रिसर्च इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट (आरडी सीआरईएसडी) एवं अर्थशास्त्र विभाग, पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम, तमिलनाडु द्वारा 18–20 जनवरी, 2018 को आयोजित 'कम्प्यूटिंग मेथ्ड्स इन सोशल साइंस रिसर्च' कार्यशाला में 'डाटा एनालिसिस युसिंग लार्ज स्केल सर्वे' शीर्षक पर आमंत्रित व्याख्यान दिया।

कार्यक्रम के शीर्षक, आयोजक, तिथियां, स्तर (राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय) के विवरण सहित संगोष्ठी/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए प्रपत्र आदि।

2 मार्च, 2018 को पीजी एंड रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ए. वी. सी. कॉलेज (स्वायत्त), मयिलादुदुरै द्वारा 'आर्थिक विकास और वृद्धि' पर यूजीसी–सहयोगित अतिथि व्याख्यान श्रृंखला की एक विशेष बातचीत देने के लिए आमंत्रित किया गया।

23 फरवरी, 2018 को वीपीएन महल, नागपट्टनम में तमिलनाडु सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग द्वारा आयोजित "डेटा साझाकरण" पर क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलन में "डाटा शेयरिंगः प्रिलिमिरी रिफ्लेक्सन" पर आमंत्रित व्याख्यान दिया।

गोवा विश्वविद्यालय, गोवा में 11–12 सितंबर, 2017 को आयोजित एनएसएसओ के 70 वें और 71वें दौर के दौरान विषय से संबंधित परिणामों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'हाउसहोल्ड एक्स्पेंडीचर ऑन हायर एजुकेशन इन इंडियाः वॉट डू वी नो एंड वॉट डू रिसेंट डाटा हैव टु से?'' नामक एक संयुक्त पत्र प्रस्तुत किया।

अर्थशास्त्र विभाग, गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान, में 18 दिसंबर, 2017 को 'डिमॉनेटाइजेशन टू जीएसटी' विषय की एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'डिमॉनेटाइजेशन टू जीएसटी : पाथ टु ग्रोथ' नामक पत्र प्रस्तुत किया।

भारतीय आर्थिक संघ के शताब्दी वर्ष में उच्च और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 7–8 सितंबर, 2017 को ''फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन'' नामक राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'एजुकेशन लोन एंड फाइनेंसिंग हायर एजुकेशनः द स्टाइलाइज्ड फैक्ट्स' नामक एक पत्र प्रस्तुत किया।

अर्थशास्त्र विभाग, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी द्वारा आयोजित 10–11 अप्रैल, 2017 को 'ग्लोबलाइजिंग द फायनेंस' पर राष्ट्रीय सम्मेलन में अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया।

मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तथा अर्थशास्त्र विभाग, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय की संयुक्त संकाय संगोष्ठी, 17–18 जनवरी, 2018 को 'डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडियाः डिफरेंशियल एंड डिसेंटेंट्स' नामक एक प्रपत्र प्रस्तुत किया।

एन.के. मोहंती

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भागीदारी

23 फरवरी, 2018 को नीपा, नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (एनआईएलईआरडी) के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की यात्रा को समन्वित किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम/आयोजित/संचालित कार्यशालाएँ

17–21 जुलाई, 2017 ओडिशा के भुवनेश्वर में ओडिशा के शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआइ) के प्रमुखों के लिए शिक्षक शिक्षा की योजना पर प्रो. एस.एम.आई.ए. जैदी और प्रो. के. बिस्वाल के साथ क्षमता निर्माण कार्यक्रम का डिजाइन निर्माण और संचालन।

21–25 अगस्त, 2017 को नीपा, नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा कार्यक्रमों की योजना और निगरानी पर एस.एम.आई.ए. जैदी और प्रो. के. बिस्वाल के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम (पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए) का डिजाइन निर्माण और संचालन।

04–08 सितंबर, 2017 को गुवाहाटी, असम में पूर्वोत्तर प्रदेशों के लिए स्कूल शिक्षा कार्यक्रमों की योजना और निगरानी पर एस.एम.आई.ए. जैदी और प्रो. के. बिस्वाल के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम का डिजाइन निर्माण और संचालन।

29 जनवरी से 02 फरवरी, 2018 को गंगटोक, सिक्किम में एससीईआरटी एवं डीआईईटी के संकाय के लिए योजना और रिसर्च प्रोजेक्ट्स डिजाइनिंग पर डॉ सुमन नेगी के साथ प्रशिक्षण प्रोग्राम का डिजाइन निर्माण एवं संचालन।

प्रशिक्षण सामग्री/पाठ्यक्रम निर्माण/संचालन

प्रो. के. बिस्वाल के साथ एम. फिल/पीएचडी कार्यक्रम, 2017–19 के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रम सं. सीसी–6 (एडवांस्ड प्लानिंग टेक्निक्स इन एजुकेशन) का संचालन।

पाठ्यक्रम समन्वयक के रूप में, फरवरी 2018 में आईडेपा पाठ्यक्रम संख्या 204ः एजुकेशनल प्लानिंग का संचालन किया।

पाठ्यक्रम संख्या 205ः मेथडोलोजी एंड टेक्निकस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग में पद्धति और तकनीक के संचालन हेतु मार्च 2018 में सम्बद्ध।

पाठ्यक्रम समन्वयक के रूप में, सितंबर–नवंबर 2017 के दौरान पीजीडेपा पाठ्यक्रम संख्या 903ः एजुकेशनल प्लानिंगः कांसेप्ट, टाइप्स एंड अप्रोचेज का संचालन किया।

शैक्षिक योजना के साथ काम करने वाले नीपा के कई अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों से संबद्ध।

एस.एम.आई.ए. जैदी के साथ अगस्त 2017 में क्षेत्र निदान पर मिथ्याअभ्यासः प्रवेश और भागीदारी के संकेतक का निर्माण।

एस.एम.आई.ए. जैदी के साथ अगस्त 2017 क्षेत्र निदान पर मिथ्याअभ्यासः आंतरिक दक्षता के संकेतक का निर्माण।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूजीसी, राज्य सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण परामर्श तथा सलाहकार सेवाएँ

आरएमएसए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार फ्रेमवर्क और निगरानी दस्तावेजों को तैयार करने और अंतिम रूप देने में योगदान (प्रो. के. बिस्वाल के साथ)। एसईएमआईएस 2009/10 और यूडीआईएसई 2016–17 डेटा के विश्लेषण के आधार पर आरएफडी में सभी संकेतक आँकड़ों के लिए 2016–17 डेटा प्रदान किया गया। साथ ही, माध्यमिक शिक्षा उप–क्षेत्र में आरएमएसए और अन्य संबंधित मध्यवर्तनों के कार्यान्वयन

के कारण पिछले रुझानों के विश्लेषण और संभावित भविष्य के परिवर्तनों के आधार पर आरएफडी में प्रत्येक संकेतक आँकड़ों के लिए लक्ष्य प्रदान किए। इसने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आरएमएसएमें प्रगति की निगरानी के लिए दाताओं को आरएफडी के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाया। इसके अलावा 4 राज्यों के आरएफडी विकसित कर 8वें जेआरएम को प्रदान किए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरएमएसए के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए आरएमएसए के तहत राज्य और जिला माध्यमिक शिक्षा योजनाओं (परिप्रेक्ष्य और एडबल्यूपी–बी) की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता प्रदान की।

मई 2017 से फरवरी 2018 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में आयोजित आरएमएसए की विभिन्न परियोजना अनुमोदन बोर्ड बैठकों में भाग लिया।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

श्री लियेलो एपॅान, उप–प्राचार्य, जॉन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, विस्वेमा, जाखना, कोहिमा, कोहिमा, नागालैंड के डीआईपीए 2016 के शोध प्रबंध 'ए स्टडी ऑफ द टीचर मैनेजमेंट इन द कम्पोजीट गवर्नमेंट हायर सेकंडरी स्कूल इन कोहिमा डिस्ट्रिक्ट, नागालैंड" का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन किया।

अफगानिस्तान सरकार के आईएआरसीएससी के प्रशासनिक अधिकारी श्री ओबैदुल्लाह रहीमी द्वारा आईडीएपीए 2016 के शोध प्रबंध 'ए स्टडी ऑफ गोवेर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन अफगानिस्तान" का पर्यवेक्षण।

एम.फिल/पीएचडी प्रवेश समिति के सदस्य के रूप में, एम.फिल/पीएचडी कार्यक्रम 2017–19 में प्रवेश के लिए आवेदनों आदि से संबंधित अन्य गतिविधियों में सहायता की।

एम.फिल/पीएचडी प्रवेश कार्यक्रम 2017–19 के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा को संपन्न कराने में सहायता की।

शोध अध्ययन

तमिलनाडु और ओडिशा में आरएमएसएके तहत जिला माध्यमिक शिक्षा योजना के विकास पर एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का उपक्रम। इन दो सैंपल राज्यों में आरएमएसए के राज्य परियोजना कार्यालयों के साथ बातचीत के बाद, हमारी (प्रो. एसएमआईए जैदी, प्रो. के. बिस्वाल सहित) परियोजना टीम इन दो राज्यों के सहयोग से अनुसंधान परियोजना को लागू किया। हमने पहले ही कई राज्य और जिला स्तर की कार्यशालाएँ आयोजित की हैं और प्रासंगिक डेटा और जानकारी एकत्रित की हैं। परियोजना के चरण–1 की डेटा विश्लेषण और तैयारी पूरी हो गई है। चरण–2 में, तमिलनाडु और ओडिशा में सैंपल जिलों की एक्शन रिसर्च टीमें मॉडल जिला माध्यमिक शिक्षा योजनाओं को विकसित करने में लगी हुई थीं। नीतिगत अस्थिरता (यानी आरएमएसए और एसपीओ के एसपीडी के लगातार स्थानांतरण और जिला स्तर पर एक्शन रिसर्च टीम के सदस्यों के लगातार स्थानांतरण) के कारण मॉडल जिला माध्यमिक शिक्षा योजनाओं को विकसित होने में दो साल से अधिक का समय लगा। 2016 में, मॉडल डीएसईपी को चेन्नई और भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय कार्यशालाओं में प्रस्तुत किया गया तथा जिला कार्य अनुसंधान टीमों को राज्य स्तरीय कार्यशालाओं से प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों के मद्देनजर योजनाओं को संशोधित करने के लिए कहा गया। तमिलनाडु और ओडिशा के सभी चार सैंपल जिलों के अनुसंधान दल अपने आदर्श जिला माध्यमिक शिक्षा योजनाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।

'पब्लिक–प्राइवेट मिक्स इन सेकेंडरी इजुकेशन इन इंडियाः साइज, इन–स्कूल फाइसिलिटीज एंड इंटेक प्रोफाइल' प्रोजेक्ट प्रगति पर है। अब तक, संबंधित साहित्य की समीक्षा कर ली गई है; यू–डीआईएसई और अन्य स्रोतों से माध्यमिक डेटा और जानकारी भी एकत्र कर ली गई है। डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन प्रगति पर है। चरण–1 अक्टूबर 2018 तक पूरा होने की उम्मीद है।

दिसंबर 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों (आईडीएमआई) की योजना में

अवसंरचना विकास के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर एक शोध अध्ययन पूरा किया।

सुमन नेगी

प्रकाशन

प्रकाशित शोध पत्र/आलेख

अंडरस्टैंडिंग इजुकेशनल आउट–माइग्रेशनः ए केश स्टडी ऑफ हिमाचल प्रदेश, रिसर्च मोनोग्राफ श्रृंखला, डायस्पोरा और ट्रांसनेशनलिज्म पर वैश्विक अनुसंधान फोरम, अंक 3, संख्या 1, जनवरी 2017, पृ. 1–16।

संगोष्ठी/सम्मेलनों में सहभागिता

18–19 अप्रैल, 2017 को विश्व बैंक कार्यालय लोदी एस्टेट, नई दिल्ली द्वारा आयोजित दो–दिवसीय कार्यशाला 'ओपन डाटा एंड नॉलेज फॉर ट्रांसपरेंसी, एडवोकेसी एंड रिसर्च' में सहभागिता।

12 मार्च, 2018 को ग्लासगो विश्वविद्यालय, यूके के सहयोग से सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'द यूज ऑफ क्रॉस–सेक्शनल डाटा लिंकेज टू इन्फॉर्म एनालिसिस ऑफ द सोशल डिटर्मिनेंट्स इन हेल्थ इन लो एंड मिडल–इन्कम कोंटरीज' कार्यशाला में अध्यक्षता की।

कार्यशाला/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

17–28 दिसंबर, 2017 को दो सप्ताह की एम.फिल कार्यशाला 'यूज ऑफ सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन इन एजुकेशनल रिसर्च' का समन्वय किया।

17 अगस्त, 2018 को नीपा, नई दिल्ली पर समन्वित श्रम अर्थशास्त्र, अनुसंधान और विकास के राष्ट्रीय संस्थान (एनआईएलईआरडी) के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की यात्रा का समन्वय किया।

29 जनवरी से 02 फरवरी, 2018 के दौरान गंगटोक, सिक्किम में एससीईआरटी और सिक्किम के संकायों के लिए योजना और डिजाइनिंग अनुसंधान परियोजनाओं के प्रशिक्षण प्रोगाम का समन्वय।

23 फरवरी, 2018 को नीपा, नई दिल्ली पर समन्वित श्रम अर्थशास्त्र, अनुसंधान और विकास के राष्ट्रीय संस्थान के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की यात्रा का समन्वय किया।

रिपोर्ट अवधि में प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम सामग्री विकास/संचालन

प्रशिक्षण सामग्री विकास

परिपत्र – स्टेटस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन सिक्किमः डेव्लपमेंट, इसूज, एंड चौलेंजेज एससीईआरटी और डीआईईटी फरवरी 2017 के संकाय हेतु अनुसंधान परियोजनाओं की योजना बनाने और डिजाइन करने के लिए प्रशिक्षण सामग्री के हिस्से के रूप में स्थिति पत्र।

पाठ्यक्रम संचालन

एम.फिल. शैक्षिक योजना पर पाठ्यक्रम, अनिवार्य पाठ्यक्रम (सीसी–6)

शैक्षिक अनुसंधान में सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के उपयोग पर एम.फिल. कार्यशाला

पीजीडेपा पाठ्यक्रम संख्या 903ः शैक्षिक योजना

पीजीडेपा शैक्षिक योजना पर उन्नत पाठ्यक्रम

आईडेपा पाठ्यक्रम नं. 204ः शैक्षिक योजनाः अवधारणा, प्रकार और दृष्टिकोण

आईडेपा पाठ्यक्रम संख्या 205ः शैक्षिक योजना की पद्धति और तकनीक

आईडेपा पाठ्यक्रम नं 206ः शैक्षिक योजना में मात्रात्मक तकनीकों का उपयोग

अन्य पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्ति

नीपा, नई दिल्ली में 21–25 अगस्त, 2017 को स्कूल शिक्षा कार्यक्रमों की योजना और निगरानी पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए)।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गुवाहाटी, असम में 04–08 सितंबर 2017 को स्कूल शिक्षा कार्यक्रमों की योजना और निगरानी पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम।

नीपा, नई दिल्ली में 17–28 दिसंबर, 2017 के दौरान 'क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन' पर ओरिएंटेशन कार्यशाला।

आईडेपा पाठ्यक्रम – अनुसंधान प्रविधि एवं सांख्यिकी, फरवरी 2018।

शोध अध्ययन (पूर्ण)

दिसंबर 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालयके लिए 'एवाल्यूशन ऑफ द इम्प्लीमएंटेशन ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन (IDMI) स्कीम' पर एक शोध अध्ययन पूरा किया।

पर्यवेक्षण और मूल्यांकन

क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र, सामाजिक विज्ञान स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में जमा किए गए एम.फिल. शोध प्रबंध 'ग्रोथ ऑफ अरबनाइजेशन इन उदयपुर डिस्ट्रिक्टः ए केस स्टडी ऑफ टूरिजम डेव्लपमेंट इन उदयपुर सिटी' का मूल्यांकन किया।

सुश्री आयशा रहमान द्वारा प्रस्तुतः एम.फिल. शोध प्रबंध 'स्कूल कंसोलिडेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंटसः एन अनालिसिस ऑफ द राजस्थान स्कूल मर्जर पॉलिसी' को निर्देशित किया।

म्यांमार से सुश्री एई फू द्वारा प्रस्तुत आईडेपा शोध प्रबंध 'ए स्टडि ऑन द रिपिटेशन रेट्स इन ग्रेड–XI एट द अपर सेकंडरी लेवलः ए केस स्टडि ऑफ मोन स्टेट, म्यांमार' को निर्देशित किया।

अरुणाचल प्रदेश से श्री लिमर भोजेद्वारा प्रस्तुत पीजीडेपा शोध प्रबंध 'ए स्टडि ऑफ टीचर मैनेजमेंट अंडर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) इन पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश' को निर्देशित किया।

रिपोर्ट अवधि में सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहयोग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुरोध पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 'इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट इन मैनोरिटी इन्सटीट्यूशन (आईडीएमआई) स्कीम' के मूल्यांकन अध्ययन का एक हिस्सा रहा।

अन्य शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योगदान

एम.फिल. एवं पी.एच.डी. कार्यक्रम के लिए एक संचालन समिति के सदस्य के रूप में विभिन्न तरीके का योगदान।

सदस्य, स्थायी खरीद समिति।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय–एमओयू समिति के सदस्य सहित एमओयू दस्तावेज तैयार करने में योगदान।

स्क्रीनिंग कमेटी के एक सदस्य रूप में आवेदन पत्रों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग में योगदान।

नीपा से बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

सदस्य, कार्यक्रम सलाहकार समिति (पीएसी), एससीईआरटी, देहरादून, उत्तराखंड।

सदस्य, अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी), एससीईआरटी, देहरादून, उत्तराखंड।

शैक्षिक प्रशासन विभाग

कुमार सुरेश

प्रकाशन

कुमार सुरेश और वी. सुचरिता, 2017. *कंपोडियम ऑफ इनोवेशन्स एंड गुड प्रैक्टिसेज इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन*, नई दिल्लीः नीपा।

वर्ष 2017–2018 में सम्पन्न शोधपरक अध्ययन

परीक्षण की संस्कृतिः सामाजिक–सांस्कृतिक प्रेरकतत्व और एशिया–प्रशांत क्षेत्र में युवा वर्ग पर उनका प्रभाव (एशिया–प्रशांत क्षेत्र के नौ देशों के भाग के रूप में यूनेस्को के आग्रह पर किया गया अध्ययन)

मध्य प्रदेश और बिहार में प्रारम्भिक शिक्षा के प्रबंधन में स्थानीय निकायों के साझा दायित्व और सक्षमता के बारे में अध्ययन।

आयोजित सम्मेलन/कार्यशाला/कार्यक्रम

जिला शिक्षा अधिकारियों और ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन

वर्ष 2017–2018 के दौरान शैक्षिक योजना और प्रशासन विषय पर जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा पदाधिकारियों के चार राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, दो सम्मेलन महाराष्ट्र में (19–20 जून, 2017 को नासिक में और 6–7 फरवरी, 2018 को पुणे में) और दो सम्मेलन तमिलनाडु में (30–31 अगस्त, 2017 और 20–21 सितंबर, 2017 को चेन्नई में) आयोजित किए गए।

10–14 जुलाई, 2017 को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विविधता और साम्यता के प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम।

अप्रैल 2017–मार्च 2018 तक जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा पदाधिकारियों के लिए शैक्षणिक प्रशासन में नवोन्मेष के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना का कार्यान्वयन।

शोध अध्येताओं के लिए लेखन कौशल विषयक कार्यशाला।

संसाधन व्यक्ति के रूप में शैक्षणिक कार्यक्रमों में संगोष्ठियों/सम्मेलन/कार्यशाला/आमंत्रित व्याख्यानों में सहभागिता

15 दिसंबर, 2017 को संकाय विकास केंद्र, बनस्थली विद्यापीठ द्वारा आयोजित संकाय प्रेरण कार्यक्रम में ''वैश्विक उच्चतर शिक्षा का वर्तमान समय में रुझान और इसका भारत पर प्रभाव'' के बारे में प्रस्तुति।

10 मार्च, 2018 को एचआरडीसी, संत गडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र में महाविद्यालय के प्राचार्यों की बैठक में ''उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में संस्थानिक शासन और नेतृत्व की चुनौतियाँ'' विषयक आमंत्रित व्याख्यान दिया।

19 जनवरी, 2018 को भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, भोपाल, मध्य प्रदेश में उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में आईक्यूएसी की भूमिका पर राष्ट्रीय सेमीनार में ''उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता के मुद्दे'' के बारे में मुख्य भाषण।

5 अक्टूबर, 2017 को ग्लोबल ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय में ''उच्चतर शिक्षा संस्थान में समानता और विविधता'' विषय पर विशेष व्याख्यान दिया।

31 जनवरी, 2018 को टाउनहाल, कोझीकोड, केरल में आईईसीआई के आधिकारिक शुभारम्भ में ''नीति सुधार और शैक्षणिक शासन में रुझान'' पर मुख्य संबोधन।

27 मार्च, 2018 को यूजीसी तथा एचआरडीसी, जे.एन.यू. द्वारा 'बहुसंस्कृतिवाद, संविधान और शिक्षा' विषय पर व्याख्यान दिया गया।

दिसंबर 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना (पीएमएमएमएनएमटीटी) के तहत नीपा द्वारा कुलपतियों के लिए आयोजित ''उच्चतर शिक्षा में नेतृत्व विकास'' पर हुई कार्यशाला में दो सत्रों की अध्यक्षता की।

जनवरी, 2018 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना (पीएमएमएमएनएमटीटी) के अंतर्गत नीपा द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासकों के लिए उच्चतर शिक्षा में नेतृत्व विकास संबंधी कार्यशाला में एक सत्र की अध्यक्षता की।

सार्वजनिक निकायों को परामर्शदायी और शैक्षणिक सहायता

पश्चिम बंगाल, कोलकाता में राज्य स्तरीय अर्हता परीक्षण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रेक्षक

नीपा से बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

सदस्य, अकादमिक परिषद, एनआईओएस

सदस्य, यूजीसी–सीईसी का अकादमिक परिषद

सदस्य, शासी निकाय– मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

शासी निकाय–मैत्री कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

सदस्य, अकादमिक परिषद, अकादमिक परिषद– संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र।

विशेषज्ञ समिति के सदस्य

प्रमुख अनुसंधान के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए आईसीएसएसआर विशेषज्ञ समिति

शैक्षणिक अध्ययन विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के अध्ययन बोर्ड के सदस्य

समाजशास्त्र विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के अध्ययन बोर्ड के सदस्य

5 अगस्त, 2017 को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद द्वारा आयोजित शिक्षक नवोन्मेष पुरस्कार को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ समिति के सदस्य

शैक्षणिक व्यावसायिक निकायों में सदस्यता

इंडियन सोशियोलोजिकल सोसायटी के आजीवन सदस्य

आईआईपीए, नई दिल्ली के आजीवन सदस्य

इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन

अन्य शैक्षणिक योगदान

संपादकः नीपा समसामयिक पेपर श्रृंखला

इस अवधि के दौरान दो समसामयिक पत्र प्रकाशित किए गए।

एम.फिल. और पी–एच.डी. का पर्यवेक्षण

सुश्री प्रतिक्षा त्रिपाठी के एम.फिल. शोध प्रबंध का पर्यवेक्षण

चार पीएचडी विद्वान सुश्री सोनाली चीतलकर, सुश्री पूजा शुक्ला, सुश्री अनुराधा बोस और मानसी थपलियाल नवानी (सह–पर्यवेक्षक) अपनी–अपनी डॉक्टरेट शोध को आगे बढ़ा रही हैं।

पीजीडेपा परियोजना के कार्य का पर्यवेक्षण

पीजीडेपा परियोजना का पर्यवेक्षण किया।

एम.फिल./पीएचडी कार्यक्रम का समन्वय और शिक्षण

शैक्षणिक प्रशासन और प्रबंधन पर मुख्य पाठ्यक्रम सीसी–07 का समन्वय कार्य किया और पच्चीस सत्रों को कार्यान्वित किया।

साम्यता और बहुसांस्कृतिक शिक्षा पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम ओसी–07 का समन्वय कार्य किया और 10 सत्रों में कार्यान्वित किया।

सीसी–01 के कोर्स टीम के सदस्य के रूप में शिक्षा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में 10 सत्रों का कार्यान्वित किया।

शैक्षणिक प्रशासन में पीजीडेपा कोर्स और एडवान्स कोर्स का समन्वय और शिक्षण

पाठ्यक्रम समन्वयक के रूप में कोर्स के संचालन की व्यापक रूपरेखा तैयार की और अन्य व्यक्तियों के साथ कोर्स का संचालन किया।

आईडेपा कोर्सः आईडेपा कोर्स के शैक्षणिक प्रशासन के बारे में कोर्स का संचालन किया।

आईडेपा म्यांमार कार्यक्रम में शैक्षणिक प्रशासन के बारे में कोर्स का संचालन किया।

अन्य कार्यक्रमों में शिक्षण

नीपा में शैक्षणिक प्रशासन विभाग और अन्य विभागों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में संसाधक के रूप में कार्य किया और 15 से अधिक व्याख्यान दिए।

नीपा के विभिन्न शैक्षणिक निकायों के सदस्य के रूप में योगदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नीपा की समीक्षा के लिए प्रतिवेदन तैयार करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष

जिला और ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक प्रशासन में नवाचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के कार्यक्रम निदेशक के रूप में इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित बहुत से जिम्मेदारियों का निर्वहन किया।

पाठ्यक्रम सीसी–07 शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के पाठ्यचर्या पुनरीक्षण का समन्वयक।

इक्विटी और बहुसांस्कृतिक शिक्षा के बारे में वैकल्पिक पाठ्यक्रम ओसी–07 की पाठ्यचर्या पुनरीक्षण के समन्वयक

लेखन कौशल पाठ्यक्रम कार्यशाला के बारे में पाठ्यचर्या पुनरीक्षण के समन्वयक

पर्यवेक्षकों के आवंटन के लिए समिति

एम.फिल./पीएचडी कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए बनी समिति

एम.फिल./पीएचडी कार्यक्रम की निगरानी समिति

छात्र परामर्श केंद्रः एम.फिल./पीएच.डी. स्थायी समिति

सदस्य, जीआईएसी

एम.फिल. प्रवेश साक्षात्कार समिति और स्क्रिप्ट का मूल्यांकन,

सेमीनार अनुदान के लिए प्रस्ताव की समीक्षा

कार्यक्रमों के संचालन से संबंधित नीपा के विभागों की परामर्शदात्री समिति और विभिन्न कार्य बलों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

विनीता सिरोही

संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में सहभागिता

07–08 दिसंबर, 2017 को उच्च शिक्षा में नेतृत्व पर कुलपति सम्मेलन में भाग लिया।

कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

13–17 नवंबर, 2017 (5 दिन) को "व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की योजना और प्रबंधन" पर समन्वित और संगठित अभिविन्यास कार्यक्रम।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकास/संचालन

संशोधित एम.फिल./पीएचडी वैकल्पिक पाठ्यक्रम ओसी–2 – शिक्षा और कौशल विकास

संशोधित एम.फिल./पीएचडी मुख्य पाठ्यक्रम सीसी–1 – शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य

मुख्य पाठ्यक्रम सीसी–7 के संशोधन में योगदान – शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन

स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम के संशोधन में योगदान

शिक्षण सीसी–1 पाठ्यक्रम (10 सत्र)

पीजीडेपा में शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन पर शिक्षण पाठ्यक्रम में योगदान

पीजीडेपा में शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन पर एडवांस पाठ्यक्रम के समन्वयक और प्रबंधन

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहयोग

"गैर–शिक्षण गतिविधियों में शिक्षकों का समावेश और शिक्षा पर इसके प्रभावः भारत में चुनिंदा राज्यों का एक अध्ययन" पर एक अध्ययन आयोजित कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अकादमिक सहयोग।

टीवीईटी इंडिया कंसल्टेंट के रूप में यूनेस्को के लिए परामर्श और ''एशिया और प्रशांत क्षेत्र में टीवीईटी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संस्थानों'' पर एक अध्ययन।

12–14 जुलाई, 2017 को एनसीईआरटी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित "हरियाणा में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन" नामक कार्यशाला में भाग लिया और सहयोग प्रदान किया।

यूनाइटेड किंगडम में 2018 राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए चयन समिति के नामित सदस्य विशेषज्ञ के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शैक्षणिक सहयोग, 15 मार्च, 2018

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

आईडेपा परियोजना का पर्यवेक्षण और निर्देशन

दो पीएचडी शोधार्थी का पर्यवेक्षण और निर्देशन

नीपा में विभाग के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तथा विभाग के बाहर व्याख्यान दिए।

शैक्षिक प्रशासन में नवाचार के अनुप्रयोगों के लिए स्क्रीनिंग समिति के सदस्य, 11 दिसंबर, 2017

बाह्य विशेषज्ञों/मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा शैक्षिक प्रशासन में नवाचारों के अनुप्रयोगों के मूल्यांकन के संयोजक, 12–13 दिसंबर, 2017

शैक्षिक प्रशासन में नवाचारों में पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन को अंतिम रूप देने में योगदान – 19 दिसंबर, 2017

नीपा और एनईएफ–एसयूएनवाई, यूएसए के मध्य समन्वयन बैठक में सहभागिता, 11 जनवरी, 2018

नीपा से बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

प्रशिक्षण सलाहकार समिति, सीबीएसई के सदस्य

एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के आजीवन सदस्य

इंडियन एसोसिएशन ऑफ एप्लाइड साइकोलॉजी के आजीवन सदस्य

इंडियन जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, पीएसएससीआईवीई की संपादकीय दल के सदस्य

मंजू नरूला

सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाओं में भागीदारी

अंतरराष्ट्रीय

16–18 नवंबर 2017 को शीर्षक 'समकालीन शैक्षिक प्रवचनों में आलोचना, सहानुभूति और कल्याण' जम्मू आयोजित 8वें अंतर्राष्ट्रीय सीईएसआई सम्मेलन में भाग लिया और 'महिला शैक्षिक प्रशासकः चुनौतियां और अवसर' पर एक पत्र प्रस्तुत किया।

शोध अध्ययन पूरा हुआ

2017, गैर–शिक्षण गतिविधियों में शिक्षकों भागीदारी और शिक्षा पर इसका प्रभावः भारत के चयनित राज्यों में एक अध्ययन, (सह–लेखक (द्वितीय) प्रो. विनीता सिरोही के साथ), मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित

मा.सं.वि.मं. मूल्यांकन अध्ययन में शामिल

दो राज्यों में मदरसों (SPQEM) में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकनः

1. छत्तीसगढ़
2. मध्य प्रदेश

पुस्तक

मंजू नरूला और अजीत मंडल संपादक (2017), *एजूकेशन इन इमर्जिंग इंडिया*, अटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली (प्रेस में)

लेख

मंजू नरूला (2017), वैश्वीकरण के युग में भारतीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा में महत्वपूर्ण मुद्दे, संपादित जिल्द, कल्पज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

शैक्षिक प्रशासन में सुधार पर विचारः बिहार, भारत का केस अध्ययन, परिप्रेक्ष्य जर्नल में स्वीकृत (नीपा)

कार्यशालाएं/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

राज्य और जिला स्तर की महिला प्रशासकों के लिए शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन पर अभिविन्यास–सह–कार्यशाला, 21–25 अगस्त 2017

संस्थागत प्रमुखों के लिए स्कूल का प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण पर अभिविन्यास–सह–कार्यशाला, 7 सितंबर 2017

कार्यशालाओं/सम्मेलनों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी

नासिक, महाराष्ट्र में शैक्षिक योजना और प्रशासन पर जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन, 19–20 जून 2017

समन्वय और शिक्षण

कोर्स टीम सदस्य और पाठ्यक्रम में शिक्षण ''शैक्षिक प्रशासन'' पीजीडेपा में शैक्षिक प्रबंधन (आमने–सामने)

पाठ्यक्रम में सामग्री और शिक्षण की तैयारी ''शैक्षिक प्रशासन'' पीजीडेपा में शैक्षिक प्रशासन पाठ्यक्रम पर एडवांस पाठ्यक्रम में शैक्षिक प्रबंधन

आईडेपा में शैक्षिक प्रशासन पाठ्यक्रम में शिक्षण

अन्य कार्यक्रमों में शिक्षण

जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक शासन में नेतृत्व पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम

एम.एड. छात्रों के लिए विभाग द्वारा मेजबान एम.एड. इंटर्नशिप कार्यक्रम में भागीदारी। इस वर्ष, आरआइई भोपाल के छात्रों ने इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए दौरा किया।

पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन

पीजीडीईपीए प्रतिभागी

पीजीडेपा प्रतिभागी सुश्री भानुडेका, ''ए स्टडी ऑन द स्टेटस' ऑफ गर्ल्स एजुकेशन ऑन स्पेशल रेफरेंस विद केजीबीवी टू बारपेटा डिस्ट्रिक्ट, असम'' के शोध प्रबंध का पर्यवेक्षण किया।

श्री अशोक कुमार कैंथ के विषय "ए स्टडी ऑन इंप्लीमेंटेशन आफ इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन डाइट विलासपुर एट जुखाला, हिमाचल प्रदेश'' के शोध प्रबंध का पर्यवेक्षण किया।

सेनेगल से आईडेपा प्रतिभागी श्री ममदौ फेय के शोध विषय ''स्कूल सिस्टम इंस्पेक्शन इन द एकेडेमी ऑफ कौलैक टीचर्स एंड हेडमास्टर्स एक्सपेक्टेशंस एंड रिफ्लेक्शंस'' शोध प्रबंध का पर्यवेक्षण किया।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

एम.फिल./पीएचडी कार्यक्रम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य

लिखित परीक्षा लिपियों के मूल्यांकन के लिए सदस्य

एम.फिल./पीएचडी पाठ्यक्रम के संशोधन में सदस्य

शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासनः कोर कोर्स

शिक्षा, साक्षरता और जीवन लंबी सीख– वैकल्पिक पाठ्यक्रम

व्यावसायिक विकास और शिक्षकों का प्रबंधन– वैकल्पिक पाठ्यक्रम

स्कूल नेतृत्व– वैकल्पिक पाठ्यक्रम

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

1. ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ टीचर एजुकेटर्स (AIATE) की आजीवन सदस्यता
2. भारत की तुलनात्मक शिक्षा संस्था की आजीवन सदस्य
3. शिक्षा और आर्थिक विकास संस्था की आजीवन सदस्य

वी. सुचरिता

प्रकाशनः

इंगेजिंग विद सोशियल इंक्लूजन थ्रू आरटीईः ए केस स्टडी आफ टू प्राइवेट स्कूल्स इन दिल्ली वी. सुचरिता और के. सुजाता (2018) इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन (रूटलेज), डीओआईः10.1080/13603116.2018.1430179, (इंटरनेशनल डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू जर्नल)

पुस्तक शीर्षक ''एडुकेटिंग एक्स–क्रिमिनल ट्राइब्स – इशूज एंड कंसर्न ऑफ माल्ली गांधी'' पुस्तक समीक्षा जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (जेपा), वॉल्यूम XXXI, नंबर 2 में प्रकाशित की।

सम्मेलनों में भागीदारीः

29 जनवरी और 30 अगस्त, 2017 को हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद में "रीविजिटिंग ट्राइबल पॉलिसीज, रिसर्च एंड इनोवेशन" पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया और पत्र शीर्षक "जनजातीय शिक्षा के लिए नीति निर्माण – चुनौतियां" प्रस्तुत किया।

18–20 अप्रैल, 2017 को एनसीईआरटी, नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा में नवाचार (नवोन्मेष) पर तीन दिवसीय सम्मेलन में भागीदारी

प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं आयोजनः

जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक शासन में नेतृत्व' पर अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन, 31 जुलाई – 4 अगस्त 2017, नीपा, नई दिल्ली

आरआईई भोपाल के छात्रों के लिए 18 से 22–सितंबर, 2017 तक 5–दिवसीय इंटर्नशिप कार्यक्रम।

पाठ्यक्रम निष्पादितः

एम.फिलः

शैक्षिक प्रशासन पाठ्यक्रम (कोर्स सं. सीसी–07) में सत्र सम्पादित

पीजीडेपाः

'शैक्षिक प्रशासन' पाठ्यक्रम (कोर्स सं. 907) में सत्र सम्पादित

आईडेपाः

एक सूत्रधार और मूल्यांकनकर्ता के रूप में आईडेपा प्रतिभागियों के लिए 'प्रतिभागियों संगोष्ठी' में शामिल।

अनुसंधान परियोजनाएं पूरी हुईः

(एक टीम के सदस्य के रूप में) शिक्षा नीति और सुधारों के कार्यान्वयन में मंत्रालय के शिक्षा नेतृत्व को मजबूत करना (188–आरएएस 0401) आईआईईपी यूनेस्को।

मार्गदर्शन और पर्यवेक्षणः

श्री केलीखा केने को 'प्राथमिक शिक्षा में सामुदायिक भागीदारीः पुत्सेरो ब्लाक, फेक जिला नागालैण्ड के तहत एक अध्ययन' परियोजना के लिए पीजीडेपा प्रतिभागी का मार्गदर्शन।

एम.फिल के छात्र सुश्री नीलंजन मोइत्रा को उनके शोध प्रबंध का शीर्षक 'उच्च शिक्षा प्राप्त आदिवासी युवाओं के बीच रोजगार के प्रति उत्साह और बाधाओं को समझनाः झारखंड के अनुसूचित जनजातियों के बीच एक अध्ययन' के लिए मार्गदर्शन।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदानः

राज्य और जिला स्तर के प्रशासकों के लिए महिला शैक्षिक प्रशासकों पर अभिविन्यास कार्यशाला में 'शिक्षक प्रबंधन में मुद्दे' पर एक समूह कार्य सत्र की अध्यक्षता, 21.25 अगस्त, 2017, नीपा, नई दिल्ली

व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम में ''राज्य के अनुभवों को साझा करना'' पर एक सत्र की अध्यक्षता की। 13–17 नवंबर, 2017, नीपा, नई दिल्ली

शैक्षिक प्रशासन में नवाचारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2017–18 के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच के लिए जांच समिति के सदस्य और समन्वयक

शैक्षिक प्रशासन में नवाचारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2017–18 के लिए विशेषज्ञों की मूल्यांकन समिति की बैठक का समन्वय

यूडीसी के पद के लिए पदोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य।

शैक्षिक प्रशासन पर पाठ्यक्रम के लिए एम.फिल पाठ्यक्रम संशोधन टीम में सदस्य

एम.फिल/पीएचडी अनुप्रयोगों के लिए ''प्रारंभिक एम.फिल./पीएचडी आवेदन जांच समिति' में सदस्य।

एम.फिल/पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन

पूरा किये गये शोध अध्ययन के बारे में संक्षिप्त जानकारी

1. परीक्षण की संस्कृतिः सामाजिक–सांस्कृतिक परिचालक और एशिया–प्रशांत क्षेत्र में युवाओं पर प्रभाव (यूनेस्को ने अध्ययन का अनुरोध किया)

प्रोफेसर कुमार सुरेश

यूनेस्को, बैंकॉक कार्यालय के समावेशी गुणवत्ता शिक्षा की अनुभाग अनुरोध पर एशिया–प्रशांत क्षेत्र के नौ देशों के अध्ययन के भाग के रूप में एक अध्ययन का आयोजन किया गया और भारत के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस अध्ययन में ''परीक्षण की संस्कृति'' के पीछे के सामाजिक–आर्थिक प्रेरक तत्वों और युवा वर्ग की शिक्षा और उनकी आकांक्षाओं के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता पर उनके प्रभावों को समझना प्रस्तावित था।

एशिया–प्रशांत क्षेत्र में बहुत से देशा में में ''परीक्षण की संस्कृति'' में अपनी शिक्षा नीतियों में मूलतः विद्यार्थी के अधिगम की प्राप्ति के स्तर में अभिवृद्धि करने का प्रयास और शिक्षा प्रणाली के कार्यनिष्पादन की प्रात्यक्षिक माप के रूप में किया जा रहा है। शिक्षा प्रणालियों में अधिगम परिणाम की माप हेतु उपयोग किए जाने के लिए न्यून और उच्च दोनों जोखिमों में पूदरे प्रदेश में विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन और प्रदेश में विभिन्न प्रकार के

मूल्यांकन और परीमाएं विद्यमान हैं। जबकि इन परीमाओं के अस्तित्व को शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास के रूप में युक्तियुक्त बनाया जा सकता है, विशुद्ध रूप से ''उच्च प्राप्तांक'' पर इतना अधिक बल दिए जोन से अधिगम के अन्य मूलभूत पहलुओं को कम करना भी हो सकता है जिन्हें अक्सर परीक्षणों और परीक्षाओं से कम से कम उनके परम्परागत स्वरूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों और शिक्षा प्रणालियों विशेष रूप से परीक्षाओं के मध्य संबंधों की जांच करने के लिए, यूनेस्को, बैंकॉक में ''संस्कृति परीक्षण'' पर एक प्रादेशिक अध्ययन कराया गया। इस क्षेत्र के नौ देशों को तुलनात्मक समझ के लिए मामलों के रूप में लिया गया है। भारत इन केस अध्ययनों में से एक है। भारत के संबंध में प्रतिवेदन तैयार किया गया है और प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रीय प्रतिवेदश्न का संलिश्ट रूप प्रकाशनाधीन है।

भारत में परीक्षा और परीक्षण की अध्ययन संस्कृतिः सामाजिक–सांस्कृतिक प्रेरक तत्व और एशिया–प्रशांत क्षेत्र में युवा वर्ग पर इसके प्रभाव के विस्तृत अध्ययन का एक भाग है। भारत के इस केस अध्ययन का लक्ष्य भारत में परीक्षाओं की विद्यमान संस्कृति को समझना है। इसमें इसके संबंध में भी सूझ–बूझ उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है कि समाज संस्कृति और अर्थव्यवस्था के बदलते संदर्भ में परीक्षा और परीक्षण की संस्कृति किस प्रकार प्रभावित हुई है। इसके इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का भी प्रयास किया गया है कि क्या भारत भी कन्फ्यूशियस परम्परा वाले देश जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से परीक्षण और परीक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया है, की भांति ही परीक्षण की बढ़ती हुई संस्कृति की दिशा में अग्रसर हो रहा है अथवा उसकी पद्धति का अनुसरण कर रहा है। यह विश्लेषण प्रदत्त के प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों पर आधारित है।

प्राथमिक प्रदत्त मुख्यतः छह राज्यों के दस विद्यालयों/महाविद्यालयों से संकलित किये गये हैं। रायपुर के मामले में सूचना के अंतराल को पूरा करने के लिए, एक और विद्यालय को सम्मिलित किया गया है। ऐसी स्थिति में विद्यालयों/महाविद्यालयों कुल संख्या ग्यारह हो जाती है। चयनित विद्यालयों/महाविद्यालयों में भारत के निम्नलिखित राज्यों अर्थात् दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (पूर्वी विनोद नगर, पूर्वी दिल्ली) और नौएडा, उत्तर प्रदेश); छत्तीसगढ़ (बस्तर और रायपुर), ओडिशा (संबलपुर), कर्नाटक (बैंगलोर) और तेलंगाना (हैदराबाद) में से प्रत्येक राज्य से दो–दो (एक सरकारी और एक निजी) विद्यालयों/महाविद्यालय शामिल थे। परीक्षा और परीक्षण के साथ–साथ शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में प्रश्नावली, गहन साक्षात्कार के इन संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों के साथ विषय केन्द्रित सामूहिक चर्चा के माध्यम से विचार और अभिमत संकलित किए गए। राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक जगत के विशेषज्ञों और प्रशासकों के भी विचार और मतों का संकलन किया गया।

मुख्यतः प्रत्यार्थियों (उत्तरदाताओं) के तीन समूहों– अर्थात पांच प्रमुख अंतःसंबंधित भाव जिनमें परीक्षण, प्रत्याशा, अभिप्रेरण और प्रभाव, परीक्षाओं, निजी ट्यूटर से प्रत्याशा औरपरीक्षा का अवबोध और अधिगम पर प्रभाव जैसे तत्व शामिल थे के बोर में विद्यार्थियों, शिक्षकों और माता–पिता/अभिभावकों से डेटा एकत्र किए गए। आंकड़ों के विश्लेषण से इस तर्क की पुष्टि होती है कि परीक्षण और प्राप्तांक अधिगम और उपलब्धि के माप के रूप में अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। विद्यार्थीगण और शिक्षकगण दोनों अपना अधिकांश समय परीक्षा या परीक्षा से संबंधित गतिविधियों पर व्यतीत करते हैं। छात्रों और माता–पिता दोनों तीन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कारणों से परीक्षा को महत्व देते हैं जो इस प्रकार हैं– i) परीक्षा अधिगम का माप है; ii) परीक्षा से कैरियर (जीविकोपार्जन) के मार्ग की पहचान करने में मदद मिलती है; और iii) यह अगले स्तर तक पदोन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तरदाताओं से प्राप्त कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के स्रोत, प्रतिस्पर्धी भावना विकसित करने में सहायक तत्व, अपने स्वयं की योग्यता और क्षमता के आकलन का अवसर, सही और गलत के मध्य निर्णय की भावना विकसित करना आदि शामिल था।

जहाँ तक उच्च जोखिम वाली परीक्षाओं से प्रत्याशा का संबंध है, छात्र और अभिभावक दोनों इस बात से सहमत थे कि सभी विषयों में शीर्षस्थ ग्रेड प्राप्त करना, स्नातक स्तर तक की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् सर्वोत्तम अवसरों का चयन करने में समर्थ होना और

कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्र होना परीक्षाओं से की जाने वाली प्रमुख प्रत्याशा हैं। माता–पिता और शिक्षक का विद्यार्थी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अतः परीक्षा और परीक्षण के प्रति छात्रों के दृष्टिकोण का निर्माण भी उनके द्वारा ही होता है।

परीक्षाओं में विद्यार्थियों और उनके कार्यनिष्पादन से बहुत अधिक उम्मीदें हैं। इस प्रकार प्रत्याशा विभिन्न स्रोतों जैसे माता–पिता, शिक्षक, सहकर्मी समूह, परिवार के सदस्यों और समुदाय आदि से आती हैं, लेकिन अधिकांश उम्मीदें माता–पिता की रहती हैं। परीक्षा में छात्रों का कार्यनिष्पादन केवल छात्र विशेष की चिंता विषय नहीं है, बल्कि माता–पिता, परिवार के सदस्यों, सगे भाई–बहनों और समुदाय अन्य लोग भी इस बात को लेकर उतने ही चिंतित रहते हैं। इसलिए, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो परीक्षाफल से इन सभी व्यक्तियों में आनन्द का संचार होता है। यहां तक कि विद्यालयों के लिए इसे उपलब्धि माना जाता है। सामान्यतः विद्यार्थी को विद्यालय द्वारा आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाता है। इससे परीक्षा और समाज और संस्कृति का व्यापक संदर्भ परिलक्षित होता है। परीक्षाओं और कार्यनिष्पादन से संबंधित प्रत्याशा से विद्यार्थी बहुत अधिक दबाव में आ जाते हैं। इन प्रत्याशाओं पर खरा उतरने के लिए विद्यार्थी स्वयं को केवल अध्ययन तक ही सीमित रखते हैं। वे अपने अध्ययन के घंटे बढ़ाते हैं। उनमें से अधिकांश छात्र टीवी, सोशल मीडिया या सामाजिक गतिविधियों से पूर्णतः अलग हो जाते हैं।

प्रत्येक विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उच्च अंक के आधार पर उन्हें अपनी पसंद के संस्थानों में प्रवेश पाने में मदद मिलेगी। विद्यार्थियों में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा के कारण विद्यार्थी तनाव और चिंता की स्थिति में आ जाते हैं। अधिक साख–जोखिम वाली परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने की अभिभावक की प्रत्याशा के कारण छात्रों पर अत्यधिक दबाव आ जाता है। इस रूझान का शिक्षकों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। समकालीन भारत में अध्यापक–अधिगम प्रक्रिया का समग्र संदर्भ शिक्षा के प्रति परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण द्वारा संसूचित होता है।

विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रक्रियाओं के कारण छात्रों को निजी ट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। अधिकांश विद्यार्थी निजी ट्यूशन लेते हैं। प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले छात्रों का प्रतिशत बहुत अधिक है। अध्ययन में उत्तरदाताओं ने प्राइवेट ट्यूशन पर किए गए घरेलू व्यय के बारे में बहुत स्पष्ट ब्यौरा नहीं दिया, लेकिन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि गृहस्थी के खर्च की बहुत बड़ी रकम प्राईवेट ट्यूशनों पर खर्च की जाती है। बहुत से अध्ययन और सर्वेक्षण रिपोर्ट (सुजाता, 2013; जयचंद्रन, 2014; नंदा, 2015; मोहंती, 2017) ने प्राईवेट ट्यूशन के बारे में कराए गए थे, इनमें भी इसी बात को प्रमाणित किया गया है। प्राईवेट ट्यूशन के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों में से कुछ प्रमुख कारकों में स्नातक/प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना और स्कूल में ग्रेड में सुधार करना शामिल था। प्राईवेट ट्यूशन लेने के कारण पर पूछे गये सवालों के जवाब में, 37.14 प्रतिशत छात्रों का कहना है कि इससे उन्हें और अधिक अध्ययन करने की प्रेरणा मिलती है, 25.71 प्रतिशत छात्रों के लिए यह परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने का एक साधन है जबकि 20 प्रतिशत विद्यार्थियों का मानना है इसके फलस्वरूप उनकी सूझबूझ और समझ को व्यापक करने में सहायता मिलती है।

प्राप्त उत्तरों के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया कि शिक्षा प्रणाली की प्रकृति और गुणवत्ता ने भी ट्यूशन देने की व्यापकता पर प्रभाव पड़ा, तथापि, छात्रों को उन विषयों में ट्यूशन की तलाश होती है जिन्हें वे विद्यालय में कठिन विषय मानते थे। यह भी देखा गया कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले छात्रों के माता–पिता भी निजी ट्यूशन की तलाश करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बच्चों को विद्यालय में पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। माता–पिता की शिक्षा और आर्थिक परिस्थितियों से भी संभवतः प्राईवेट ट्यूशनों के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित हुई है।

वस्तुतः, भारत में एशिया–प्रशांत के बहुत से अन्य देशों की भाँति भारत में समकालीन शिक्षा प्रणाली में जाँच और परीक्षण मुख्य स्थान प्राप्त कर लिया है। मुख्य रूप से परीक्षाओं में पाठ्यपुस्तक में उल्लिखित जानकारी को रटकर याद करने ओर परीक्षा में संबंधित जानकारी पुनःप्रस्तुत

करने के आधार पर प्राप्तांक की जांच करने पर बल दिया जाता है। परीक्षण प्राप्तांक माध्यमिक शिक्षा के पश्चात के प्रमुख संस्थानों में प्रवेश के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारकों में से एक है। भारत में शिक्षा प्रणाली की उभरती हुई प्रवृत्ति परीक्षा, परीक्षण और प्राप्तांक पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। परीक्षण और परीक्षा पर अत्यधिक जोर दिये जाने से शिक्षा के मुख्य प्रयोजन का अल्पीकरण होता है। परीक्षा और परीक्षण से संबंधित नीति भी परीक्षण और परीक्षा की संस्कृति का समर्थन करती है।

अध्ययन के निष्कर्ष से पता चलता है कि विद्यार्थी की सफलता के रूप में सफल होने के लिए अत्यधिक दबाव का सामना करने की दौर पर पूर्णतः ध्यान केंद्रित किया जाता है इसकी परिभाषा केवल मानकीकृत परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने, उच्च अंक प्राप्त करने और फिर एक अच्छे माहाविद्यालय/विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलने के रूप में की जाती है। उनकी खुशी, मानसिक स्वास्थ्य, की इस संदर्भ में कोई भी सार्थकता नहीं है। माता–पिता और विद्यालय की ओर से दबाव, असफलता का भय और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने के भय का परीक्षाओं के प्रति युवाओं की अभिवृत्ति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है क्योंकि विद्यार्थी के स्व–मूल्य का अवधारणा शैक्षणिक सफलता और ग्रेड के आधार पर होता है ना कि उनकी वैयक्तिक अभियोग्यता के आधार पर।

2. शिक्षणेत्तर कार्यकलापों में शिक्षकों अंतर्ग्रस्तता और शिक्षा पर इसका प्रभावः भारत के चुनिंदा राज्यों में एक अध्ययन (स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरोध पर आयोजित अध्ययन)

डा. विनीता सिरोही और डा. मंजू नरूला

बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम 2009) की धारा 27 के तहत दिए गए अधिदेश के अनुसार किसी भी अध्यापक को दस वर्षीय जनगणना, आपदा राहत ड्यूटी अथवा स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधायिका या संसद जैसी भी स्थिति हो, के अलावा किसी अन्य गैर–शैक्षणिक प्रयोजनों से प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में विद्यालय में शिक्षकों की पर्याप्त उपस्थिति का उपबंध किया गया है। शिक्षकों द्वारा इस प्रकार निष्पादित शिक्षणेत्तर कार्य से शिक्षा गुणवत्ता दुष्प्रभावित होने के साथ–साथ विद्यार्थियों के अधिगम स्तर पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) से शिक्षणेत्तर गतिविधियों में अध्यापकों की अंतरग्रस्तता और शिक्षा पर इसका प्रभावः भारत के चयनित राज्यों मं एक अध्ययन विषय पर अध्ययन कराने का अनुरोध किया था।

वर्तमान अध्ययन देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार राज्यों में आयोजित किया गया है। गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और उत्तराखंड के चार 8 जिलों के 200 स्कूलों के 872 शिक्षकों का प्रतिदर्श लिया गया। इसके अलावा, 153 प्रधानाध्यापक (हैडमास्टर), 47 ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) और 8 जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को प्रश्नावली दी गई थी। प्रत्येक राज्य से दो जिलों का आकस्मिक रूप से चयन किया गया, प्रत्येक जिले में 25 राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन सुव्यवस्थित या प्रतिचयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया, जिसमें यूडाईस में उपलब्ध विद्यालयों की सूची वर्ष 2015–16 का उपयोग किया गया। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्कूलों का चयन किया गया। जब बिना पूर्व घोषण के संकलन के उद्देश्य से विद्यालयों द्वारा प्रदत्त जानकारी और आकड़ों के सत्यापन हेतु कुछ एक विद्यालयों का दौरा किया गया। उसके पश्चात परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों विधियों का उपयोग करके किया गया था।

इस अध्ययन में विभिन्न प्रकार के शिक्षणेत्तर गतिविधियों में शिक्षकों द्वारा खर्च दिए गए समय पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह समय कक्षा के अंदर या बाहर के बच्चों के शिक्षण के क्रम में व्यतीत समय के अतिरिक्त है। प्रत्यक्ष शिक्षण के अलावा अन्य सभी गतिविधियों को गैर–शिक्षण गतिविधियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। कुल 47 ऐसी गैर–शिक्षण गतिविधियाँ स्कूल के भीतर और बाहर सूचीबद्ध की गईं, इन शिक्षणेत्तर गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर, इन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है– मूल गतिविधियों में 10 गतिविधियाँ शामिल हैं जैसे– पाठ योजना निर्माण, गृहकार्य की जाँच, अधिगमकत्ताओं

का मूल्यांकन, अभिभावक–शिक्षक बैठक शामिल थी। विद्यालय संबंधी गतिविधियों में 29 गतिविधियाँ शामिल हैं जैसे– मध्याह्न भोजन के लिए अलग से रिकार्ड का रखरखाव, छात्रवृत्ति, वर्दी, पाठ्य पुस्तक, छात्रों का चिकित्सकीय जाँच, सीआरसी/बीआरसी, डीईओ कार्यालय के साथ सम्पर्क, अधिकारियों के दौरे की सुविधा प्रदान करना तथा अन्य विभागों को दी जाने वाली सेवा में 8 गतिविधियाँ शामिल हैं जैसे– जनगणना सूची को अद्यतन बनाना, निर्वाचन ड्यूटी, पल्स पोलियो शिविर का आयोजन आदि शामिल था।

विद्यालय में शिक्षक द्वारा बिताए गए कुल समय में से 42.6 प्रतिशत समय शिक्षणेत्तर मूल गतिविधियों में; 31.8 प्रतिशत समय और शिक्षणेत्तर विद्यालयी गतिविधियों पर 6.5 प्रतिशत समय अन्य विभागों को दी गई शिक्षणेत्तर सेवा कार्य में व्यतीत हुआ। दूसरी ओर, मात्र 19.1 प्रतिशत समय शिक्षण पर व्यतीत हुआ।

अन्य विभागों को प्रदत्त सेवा के अग्रेतर विश्लेषण से पता चलता है कि अध्यापकगण अपना अधिकांश समय मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) के रूप में बिताते हैं। अन्य विभागों को प्रदत्त आठ सेवाओं में 32.62 प्रतिशत समय बीएलओ के कार्य से संबंधित विभिन्न कर्तव्यों में व्यतीत होता है। शिक्षकों को विभिन्न कार्यकलापों का निष्पादन करते हुए सालों भर काम करना पड़ता है। अध्यापकों ने यह भी बताया कि चूंकि बीएलओ की ड्यूटी निष्पादित करने के क्रम में भाग लेने वाले लोगों से बातचीत करने, नए मतदाताओं को पंजीकृत करने आदि उपेक्षित है, उन्हें विद्यालय के समय के बाद और यहाँ तक कि छुट्टियों के दिनों में भी कार्य करना पड़ता है। कई बार उन्हें स्कूल के समय के दौरान भी अनुरोधों में शामिल होना पड़ता है। जनगणना संबंधी कार्य केवल 10 वर्षों में एक बार किया जाता है और इस पर व्यतीत समय का अनुपात बहुत कम (4.3 प्रतिशत) है, अध्यापक मतदान के दिनों में निर्वाचन कराने में बहुत कम समय व्यतीत करते हैं। मतदान के दिनों में भी चूंकि विद्यालय बंद होते हैं, अध्यापन का समय प्रभावित नहीं होता है।

चार राज्यों में उच्च प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षणरत शिक्षकों की तुलना में प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकगण विद्यालय से संबंधित कार्यकलाप और अन्य विभागों को दी गई सेवा की दो श्रेणियों में अधिक समय व्यतीत करते हैं। विद्यालयों की अवस्थिति के संबंध में शहरी क्षेत्रों के अध्यापक ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापकों की अपेक्षा अन्य अन्य विभागों को दी गई सेवा में अपेक्षाकृत अधिक समय व्यतीत करते हुए पाये गये थे।

इस अध्ययन का एक प्रयोजन गैर–शिक्षण गतिविधियों में शिक्षक की भागीदारी के प्रभाव विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धि पर होने वाले प्रभाव का भी अध्ययन करना था। प्रतिगमन विश्लेषण से पता चलता है कि जब शिक्षकों के लिए शिक्षणेत्तर गतिविधियों पर व्यतीत होने वाला समय अधिक होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षणों में ग्रेड ए या ग्रेड बी प्राप्तांक का प्रतिशत घट जाता है। इसलिए, शिक्षकों की गैर–उपलब्धता का छात्रों के उपलब्धि स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

शिक्षा विभाग को नीतिगत उपायों सहित ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शिक्षकगण कक्षा में बालक–बालिकाओं के प्रत्यक्ष शिक्षण और शिक्षण में सहायक प्रमुख गतिविधियों में अपना अधिकांश समय व्यतीत कर सके। वर्तमान अध्ययन से सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह बिन्दु उभरकर आया कि शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं और जिम्मेदारियों जो उनके व्यवसाय के लिए उचित हो और गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित एवं विद्यालय के प्रबंधन में उनकी भूमिका के बारे में नीति बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

3. मध्य प्रदेश और बिहार में प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में स्थानीय निकायों के साझा दायित्व और उनकी अभिक्षमता

प्रो. कुमार सुरेश

अध्ययन की पृष्ठभूमि और सार

भारत में प्रारंभिक स्कूली शिक्षा को समुदाय, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के मध्य साझाकृत दायित्व माना गया है। स्थानीय शासन और शिक्षा से संबंधित विभिन्न नीतिगत दस्तावेजों में प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में स्थानीय शासन और समुदाय के महत्व को रेखांकित किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन में स्थानीय निकायों की अनिवार्य भूमिका की परिकल्पना के संबंध में

कोठारी आयोग, शिक्षा नीति, 1868, शिक्षा नीति, 1986 और प्रोग्राम ऑफ ऐक्शन, 1992; और सीएबीई प्रतिवेदन, 1993 विशिष्टतः उल्लेखनीय है। सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय निकायों की सक्रिय भूमिका सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनिवार्य अपेक्षा मानी गई है। इसके अलावा शैक्षणिक विकास कार्यक्रम और शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र के हस्तक्षेप के फलस्वरूप स्थानीय स्तर पर शिक्षा के प्रबंध और प्रदायगी में स्थानीय निकायों की भूमिका और उनकी अन्तर्ग्रस्तता उजागर हुई है। डीपीईपी के केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम और सर्वशिक्षा अभियान इस संदर्भ में विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार, स्थानीय शासन से संबंधित5 विभिन्न समितियों और आयोगों में स्थानीय शासन के महत्व को स्थानीय लोकतंत्र, सामुदायिक भागीदारी, योजना और विकास का उर्ध्वमुखी दृष्टिकोण और स्थानीय स्तर पर संसाधन और सेवा का प्रभावी प्रबंध को संस्थागत तंत्र के रूप में दर्शाया गया है। एक और बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति की सिफारिशें और दूसरी ओर 73वां और 74वां संविधान संशोधन इस संबंध में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निर्विवादतः प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में स्थानीय निकायों की भूमिका का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में, विद्यालय के विभिन्न कार्यकलापों में स्थानीय निकायों की अंतर्ग्रस्तता के साथ स्कूल प्रबंधन समिति का उपबंध महत्वपूर्ण है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन के मध्य तीन दिशीय साझेदारी का उल्लेख है। अधिनियम के उपबंध के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध तीनों क्रम/टियर/क्षेत्रों– केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शासन का साझाकृत दायित्व है।

संघीक सरंचना में बहु–स्तरीय शासन की दृष्टि से अद स्थानीय सरकारों को शासन के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। शासन के इस क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर कुशल दक्ष और लागत–प्रभावी सेवा–प्रदायगी के दायित्व से युक्त है। किंतु सेवा–प्रदायगी तंत्र की भूमिका निर्धारित करने के अलावा, हालिया वर्षों में स्थानीय शासन को स्थानीय लोकतंत्र का मॉडल माना जा रहा हे। इस अदबोध की भारत में स्थानीय स्व–शासन की संस्थाओं के सृजन में मुख्य भूमिका रही है। यह भारत में विकेन्द्रीकरण के मुख्य प्रेरक तत्वों में से एक रहा है। यदि इस प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंध में स्थानीय निकायों की भूमिका और सक्षमता पर विशिष्टतः बल देते हैं तो नीतिगत दस्तावेजों और विद्वतापूर्ण लेखन दोनों में इसे स्वीकृत किया गया है। भारत में प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में साझा दायित्व की संकल्पना गत दो दशकों के दौरान शुरू किए गए विभिन्न शैक्षणिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित दिशानिर्देश, अधिनियम, परिपत्र; सरकारी ओदश से प्रेरिभूत होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में समुदाय और राज्य के मध्य साझेदारी की समग्र प्रक्रिया की मुख्य एजेंसी माना गया है।

तथापि प्रश्न यह है कि संबंधित राज्यों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को किस हद तक शक्ति और दायित्व दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि अधिकांश और वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजित नहीं की है। यदि उन्हें राज्य के अधिनियमों के आधार पर प्रारंभिक विद्यालयों के प्रबंधन का दायित्व समनुदिष्ट किया भी गया है तो क्या वे इन दायित्वों का निर्वाह करने में स्व–क्षम हैं?

वस्तुतः जहाँ तक क्षमताओं और शक्ति के साझा करने का संबंध है, विडम्बना पूर्ण स्थिति विद्यमान है। यद्यपि राज्यों की आकांक्षा संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्व–शासन के राज्य अधिकार के रूप में अधिक से अधिक शक्ति और स्कायत्तता प्राप्त करने की रहती है। तथापि जब स्थानी शासन के साथ शक्ति और संसाधनों के बंटवारे का प्रश्न आता है तब समस्या उत्पन्न होती है। अधिकांश मामलों में राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को संघीय शासन व्यवस्था के तीसरे स्कंध के रूप में शक्ति और स्वायत्तता देने के इच्छुक नहीं रहते हैं। अधिकतर मालों में स्थानीय निकायों की क्षमता पर इसका अड़चनकारी प्रभाव पड़ता है। पिछले कई वर्षों में देखा गया है कि राज्य सरकारों ने संघीय शक्ति साझा करने की समन्वित संरचना के रूप में स्थानीय निकायों के विकास को सुकरनरी बनाया है। कुल मिलाकर, स्थानीय निकाय आश्रित संरचना ही बनी रही है। स्थानीय निकायों की क्षमतायें सर्वाधित अड़चनकारी कारक वित्तीय क्षमता है। स्थानीय निकायों को वित्तिय क्षमता नहीं प्रदान की जाती है जबकि यह स्थानीय शासन की सक्षम संरचना का मूल है। इस स्थिति में स्थानीय सरकार की भूमिका और क्षमता केंद्र से परेहोना

निश्चित है। साझाकृत दायित्व और हिस्सेदारी अभिक्षमता में कमी के अड़चनों के कारण परिसीमित होती है।

इस पृष्ठभूमि में यह अध्ययन तीसरे अखिल भारतीय शैक्षणिक प्रशासन सर्वेक्षण की एक गुरूतर परियोंजना के लघु अध्ययन के रूप में कराया गया। इस अध्ययन में प्रमुखतया शक्ति साझा करने के संघीय परिप्रेक्ष्य और आनुबांगिकता सिद्धांत के कार्यकरण के आधार पर प्रारंभिक विद्यालयों के प्रबंध में राज्य और स्थानीय निकायों के मध्य संबंध की प्रकृति का खाका तैया करने का प्रयास किया गया।

संबंध की रूपरेखा के दो स्तर हैं। पहले स्तर पर, जिसमें अध्ययन पर प्रमुखता से बल दिया गया, इसका उद्देश्य राज्य अधिनियमों, शासनादेश और परिपत्रों के माध्यम से प्रदत्त शक्ति और उत्तरदायित्व के आधार पर स्थानीय निकायों की अभिक्षमता की जांच करना था। जांच के दूसरे स्तर में यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव था कि व्यवहार में जमीनी स्तर पर राज्य और स्थानीय निकायों के मध्य किस सीमा तक शक्ति और दायित्वों का बंटवारा किया गया है। इस अध्ययन में मुख्य रूप से शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित शासनादेश और परिपत्रा और स्थानीय निकायों की क्षपता पर इस के प्रभाव का विश्लेषण करना प्रस्तावित था। व्यवहार में संसूचित जमीनी सच्चाई के क्रांतिक विश्लेषण के भाग के रूप में, दो राज्य बिहार और मध्य प्रदेश में से प्रत्येक राज्य के दो–दो जिले अर्थात् बिहार से पटना और अरवल और मध्य प्रदेश से रायसेन और विदिशा और आठ प्रखंडों अर्थात प्रत्येक जिले से दो–दो प्रखंडों का अध्ययन के लिए चयन किया गया है।

अध्ययन के नतीजे से संकेत मिलता है कि अभी भी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने तथा स्थानीय निकायों को अनुषंगिकता के संघीय सिद्धांत के अनुसार स्थानीय शासन का सक्षम संस्थागत ढांचे के रूप में बनाने और व्यवहार में बहुत बड़ी खाई है। अधिनियमों, परिपत्रों और शासनादेशों की रूपरेखा से निरूपित होता है कि इन निकायों को शक्तियाँ दी गई हैं किन्तु प्रकार्यात्मक वास्तविकता से पता चलता है कि शक्तियों का प्रयोजन अपर्याप्त है इन निकायों के प्रतिधि स्थानी निकायों को सौंपे गए स्कूलों के प्रबंधन से संबंधित दायित्वों पर पूरी तरह ध्यान नहीं देती है। शिक्षा अधिकारियों के साथ गहन साक्षात्कार में इस बात पर विशेष रूप से पता चलता है कि शिक्षा स्थानीय निकायों की न्यूनतम प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। अधिकांश मामलों में उनकार प्रतिनिधित्व औपचारिक मात्र है। स्थानीय निकायों की भागीदारी मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा के प्रबंधन के वित्तीय क्षेत्र तक सीमित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उपबंध के अन्तर्गत सृजित एसएमसी के रूप में स्कूल स्तर पर शासन की भागीदारी संरचना और राज्य सरकारों के नियमों के फलस्वरूप शक्ति प्राप्त संरचना का निर्माण नहीं के बराबर हुआ है। सहभागी स्कूल प्रशासन व्यवस्था के सशक्त संरचना के रूप में एसएमसी (स्कूल प्रबंधन समिति) को स्कूलों की जमीनी हकीकत से पृथक रूप में नहीं देखा जा सकता है। ये केवल कागज पर ही प्रकार्यात्मक हैं। स्कूलों का दौरा, स्कूल के कामकाज के प्रेक्षण में भागीदारी का अभाव और शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों, विद्यालय प्रबंधन समितियों के अध्यक्षों और एसएमसी के कुछ सदस्यों के साथ साक्षात्कार से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि संरचना और अधिदेशित भूमिका के सृजन के आशय के अनुरूप विद्यालय प्रबंधन समितियां कार्य नहीं कर रही हैं।

4. मदरसा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना (एसपीक्यूईएम) के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

डा मंजू नरूला (एक टीम सदस्य के रूप में)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कहने पर, नीपा चार राज्यों– उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में मदरसों के कामकाज का एक मूल्यांकनपरक अध्ययन (मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना) आयोजित कर रहा है जिसमें संकाय के 4 सदस्य अध्ययन दल शामिल हैं। यह योजना 2009–10 में आरम्भ हुई थी और इस योजना के अन्तर्गत मदरसों और मकतबों ने अनुदान के लिए आवेदन किया था, उन्हें भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। यह योजना वे मदरसों और मकतबों जिन्होंने अनुदान के लिए आवेदन किया था। उन्हें भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। इस योजना में मदरसों और मकतबों को औपचारिक विषयों अर्थात् विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी को शिक्षण कार्य आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि मदरसों

और मकतबों में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं को कक्षा 1 से 12वीं के लिए शैक्षणिक दक्षता प्राप्त हो सके। यह योजना मदरसों के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानकों के समकक्ष शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।

5. शिक्षा नीति और सुधार के कार्यान्वयन में शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व को सशक्त बनाना

के. सुजाता, ए.एन. रेड्डी, वी. सुचारिता, आर.एस. त्यागी

भारत वर्तमान में जन्मदर, मृत्युदर, जनसंख्या घनत्व और उम्र संरचना में तेजी से आ रहे बदलाव के कारण जनसांख्यिकीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। यद्यपि यह परिवर्तन पूरे देश में समान रूप से नहीं हो रहा है और अलग–अलग क्षेत्रों में इस परिवर्तन का स्वरूप अलग–अलग है। ठीक उसी तरह विगत दशक में शिक्षा क्षेत्र में कई तरह के परिवर्तन हुए हैं और अलग–अलग राज्यों में इसमें भिन्नता है। इस अध्ययन का उद्देश्य नामांकन दरों को प्रभावित करने वाली विभिन्न शिक्षा नीतियों को समझने के साथ–साथ इस बात का भी विश्लेषण करना है कि क्या जनसांख्यिकीय परिवर्तन के कारण शिक्षा नीति की प्राथमिकताएं बदल गई हैं।

चूँकि इस अध्ययन में तीन एशियाई देशों (भारत, मलेशिया और कोरिया गणराज्य) के मामलों को सम्मिलित किया गया है जो जनसांख्यिकीय तथा सामाजिक–आर्थिक रूप से एक दूसरे से भिन्न है तथा इसके उद्देश्य इस तरह से निर्धारित किए गए हैं कि उन्हें भारतीय संदर्भ में और अधिक उपयुक्त तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए प्रसांगिक बनाया जा सके। इस प्रकार भारतीय अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य थे

- भारत तथा प्रतिदर्श राज्यों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा शिक्षा, विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा पर इसके प्रभावों का अध्ययन करना;
- चुनिंदा प्रतिदर्श राज्यों में विद्यालय जाने वाले बच्चों तथा प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन पद्धति पर जनसांख्यिकीय परिवर्तन के प्रभाव की जांच करना;
- उपलब्धता भागीदारी समान हिस्सेदारी और गुणवत्ता पर विशेष बल देते हुए प्रारंभिक शिक्षा को संचालित करने वाले मौजूदा नीतिगत ढांचे की समीक्षा करना;
- जनसांख्यिकीय परिवर्तन के आलोक में शिक्षा की गुणवत्ता और समान भागीदारी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीतिगत उपाय के संबंध में सुझाव देना

भारतीय अध्ययन में डेटा संग्रह के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण दोनों का संयोजन शामिल था।

विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता तथा विद्यालय, नामांकन विद्यालयों के बदलते आकार, निजी क्षेत्र के उद्भव आदि के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयी शिक्षा के विस्तार आदि में रूझानों का विश्लेषण करने के लिए परिमाणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया किया गया। जनसांख्यिकीय परिवर्तन के रुझानों की जांच अखिल भारतीय स्तर पर तथा 20 प्रमुख राज्यों में की गई। जनसांख्यिकी परिवर्तन का विश्लेषण जनसंख्या के आकार, लिंग, जनसंख्या के सामाजिक और धार्मिक, ग्रामीण/शहरी संरचना 1991 के बाद जन्म दर, परिवर्तन, मृत्यु दर और उत्पादकता दर में परिवर्तन से संबंधित रुझानों के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन संबंधी आंकड़ा विभिन्न द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त किया गया। हालांकि जनगणना एक महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत रहा, जन्म दर, मृत्यु दर और उत्पादकता दर संबंधी आंकड़े प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) से प्राप्त किए जाएंगे। शिक्षा सुविधाओं से संबंधित आकड़ा चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी/विद्यालयी शिक्षा संबंधी सांख्यिकी तथा जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डाईस) से प्राप्त किया गया था।

जनसांख्यिकीय परिवर्तन और शिक्षा में बदलाव को देखते हुए उठाये गये नीतिगत कदमों को समझने के लिए गुणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया गया। नीतिगत दस्तावेजों, वार्षिक योजनाओं, दृष्टिपत्रों, सरकारी आदेशों, कार्यक्रमों के संयुक्त समीक्षा मिशनों आदि की समीक्षा करके आकड़े एकत्रित किये गये। व्यापक शोध प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, विगत दस वर्षों में कार्यान्वित की गई शिक्षा नीतियों और विधानों की समीक्षा की जा रही है। विशेषतौर पर अनुसंधान टीम ने सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया क्योंकि यह कार्यक्रम विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए चलाया गया था और विगत दस वर्षों से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

प्रमुख निष्कर्ष:

जब हम स्कूलों की संख्या में वृद्धि को देखते हैं, तो प्राथमिक स्कूलों की संख्या वर्ष 1990–91 में 560.9 हजार से 1.5 गुणा बढ़कर 2014–15 में 847.1 हजार हो गई है। इसी तरह, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में भी 2.7 गुणा वृद्धि हुई है। अर्थात् वर्ष 1990–91 में जहाँ इनकी संख्या 151.5 हजार थी। वर्ष 2014–15 में यह बढ़कर 425 हजार हो गई। इसी प्रकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक चरण में नामांकन की संख्या में विशेष रूप से हालिया वर्षों में बालकों के घटते हुए रूझान को दर्शाता है। प्राथमिक स्तर पर नामांकन 97.4 मिलियन से बढ़कर 129.1 मिलियन हो गया है और अपर प्राइमरी विद्यालय में लगभग दो गुनी बढ़ गयी है। अर्थात् वर्ष 1990–91 में 34 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 67.6 मिलियन हो गया है। अध्यापकों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रही है, यद्यपि वर्ष 2010 के बाद विभिन्न कारणों से जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ शिक्षकों की उपलब्धता में मामले में बड़ी संख्या में खाली पद शामिल हैं, ह्रासमान रूझान रहा है प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या वर्ष 2000–01 में लगभग 190 हजार से बढ़कर 2010–11 में लगभग 2500 हजार और 2015–16 में और अधिक बढ़कर 2670 हजार हो गई है। इसी तरह, उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों की संख्या 2000–01 के 1326 हजार से बढ़कर 2010–11 में 2239 हजार और वर्ष 2015–16 में और अधिक बढ़कर 2612 हजार हो गई। प्राथमिक कक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जीआइआर) 1990 के दशक के 100 प्रतिशत से थोड़ा कम होकर 1992–93 से 1996–97 के दौरान 90 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 1997–98 से वर्ष 2003–04 के दौरान यह बढ़कर 90 प्रतिशत से अधिक हो गया है। वर्ष 2004–05 से यह 100 प्रतिशत से अधिक है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर जहाँ यह वर्ष 1990–91 से 1992–93 के दौरान 60 प्रतिशत से अधिक था, वर्ष 1993–94 से 2000–01 के दौरान यह घटकर 60 प्रतिशत से कम हो गया है। यद्यपि कई वर्षों में इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है तथापि यह अब तक 100 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पाया है। विभिन्न राज्यों में जीईआर में व्यापक भिन्नता भी देखी जा सकती है। यहाँ तक कि वर्ष 2014–15 में भी अनेक राज्यों में जीईआर 100 प्रतिशत से कम रहा है, जबकि कुछ अन्य राज्यों ने सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा में अपनी उपलब्धियों को स्वीकार किया है। इन राज्यों में केरल, हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। अन्य राज्यों में जहां जीईआर 100 प्रतिशत से कम है, उनमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि शामिल हैं, लेकिन कुछ शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में जहाँ जीईआर शत–प्रतिशत अथवा उससे अधिक पाया गया है, उनमें झारखंड, असम, छत्तीसगढ़ आदि शामिल हैं। इन असंगत प्रतिरूप का विश्लेषण करना कठिन है।

शिक्षा पर जनसांख्यिकीय संक्रमण काल का सर्वाधिक दृष्टव्य प्रदर्शन विद्यालय के घटते हुए आकार में निहित है। पिछले कुछ वर्षों में प्रवेश के मामले में विद्यालय के आकार में निरन्तर गिरावट आई है। हालांकि, विद्यालय के आकार में विभिन्न कारणों से कमी आ रही है, जिसमें नए विद्यालयों के खोले जाने के कारण विद्यार्थियों की कमी होना शामिल है। निजी स्कूलों की बढ़ती हुई संख्या को भी राजकीय विद्यालयों के घटते हुए आकार का एक कारण माना जाता है। तथापि जैसा कि आकड़ों से पता चलता है, गैर–सरकारी विद्यालयों में भी विद्यार्थियों की संख्या में कमी आ रही है।

नीतिगत स्तर पर विद्यालयों में अधिगमकर्त्ताओं की निरंतर कम होती संख्या के मुद्दे के समाधान के लिए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जारी है, जिसमें राज्यों में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर स्कूलों को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक और उच्च प्राथमिक से उच्च विद्यालय में परिणत किया जा रहा है। ताकि स्कूलों में पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी उपलब्ध रहें और प्रत्येक कक्षा में एक शिक्षक की उपस्थिति व्यवहार्य हो सके।

जनांकिकीय संक्रमण से संबंधित विचार–विमर्श और चर्चा में तथाकथित जनांकिकीय लाभांश से होने वाले फायदे पर बल दिया जा रहा है। जनांकिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए बढ़ती हुई युवा आबादी को फायदा उठाने के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण, स्टार्ट–अप आदि जैसी कई नीतियां शुरू की जा रही हैं। इस प्रकार, जनकिकीय संक्रमण अभी भी शैक्षिक योजना, विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में अभी भी चर्चा का विषय नहीं बना है।

शैक्षिक वित्त विभाग

मोना खरे

प्रकाशन

प्रकाशित पुस्तकें

डिस्परिटीज इन ग्रेजुएट एम्प्लोयबिलिटी स्किल्स, वर्गीज एनवी, निधि सभरवाल और मलिश, सी.एम. (सं.), इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2016ः इक्विटी सेज, 2018. नई दिल्ली।

प्रकाशित शोध पत्र/आलेख

'चैलेंजिंग द ऐड इंडस्ट्री स्ट्रक्चरः शिफ्टिंग डायनामिक्स ऑफ इंडियाज एजुकेशन डेव्लपमेंट कोऑपरेशन" रेविस्त्रा दे एकोनोमिया पोलिटिका ए हिस्टोरीका एकोनोमिका, अंक 40, जुलाई–अगस्त 2018।

चैलेंजिंग ऑफ फाइनेंसिंग एलेमेंटरी एजुकेशन इन इंडियाः पास्ट टेंड्स एंड फ्यूचर पोटेन्सियल" बहु–विषयक अध्ययन और शिक्षा एआईसीएमएसई 2016 (ऑक्सफोर्ड) पर अकादमिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा तैयार पुस्तक आईएसबीएन संख्या 978–1–911185–16–1 (ऑनलाइन) एफएलई लर्निंग लिमिटेड ब्रिटेन।

''टेकिंग द स्किल्स मार्च फारवर्ड इन इंडिया– ट्रांजिशनिंग तो द वर्ल्ड ऑफ वर्क,'' मैथियास पिल्ज एड इंडियाः क्रियाशील दुनिया के लिए तैयारी, स्प्रिंगर वी.एस.।

प्राथमिक शिक्षा का वित्तपोषण, पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप की संभावनाएं, नई शिक्षा नीति के लिए कॉर्पोरेट्स की सामाजिक जिम्मेदारी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पृष्ठभूमि प्रपत्र प्रस्तुत किया।

उच्च शिक्षा, नई दिल्ली में टीचिंग–लर्निंग और नई तकनीकों पर आउटकम आधारित उच्चतर शिक्षा प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का त्रिकोणीय मॉडल (आगामी)।

द वर्चुयस साइकल ऑफ ग्रोथ, एम्लोयमेंट एंड एजुकेशन इन इंडिया–पाथ टू ईक्विटेबल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली (प्रेस में)।

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाओं में भागीदारी

राष्ट्रीय

बैंगलोर विश्वविद्यालय में 25–26 नवंबर, 2017 के दौरान सतत विकास अनुसंधान के मॉडल पर वैश्विक सम्मेलन "मेकिंग मैनेजमेंट स्टडीज मैटर (एमएमएसएम 2017)" में संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन करने की रूपरेखा पर प्लेनरी की नोट।

आईजीएनटीयू, अमरकंटक में 29–30 नवंबर, 2017 को "रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलॉजिकल इंटर्वेंशन फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट" पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में उच्च शिक्षा संस्थानों के सतत विकास के मॉडल पर प्लेनरी की नोट।

शारदा विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज द्वारा आयोजित भारतीय बजट 2018–19 के विश्लेषण पर एक प्रतिष्ठित पैनल के सदस्य और मुख्य वक्ता।

नीपा द्वारा 7–8 दिसंबर, 2018 को कुलपतियों के लिए उच्च शिक्षा नेतृत्व विकास पर कार्यशाला के दौरान समूह प्रस्तुतियों पर सत्र की अध्यक्षता।

नई दिल्ली के शंग्रिला होटल में 10 जनवरी, 2018 को इंडियन चौंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित इंडियन इकोनॉमिक आउटलुक 2018 में भाग लिया।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40, लोदी एस्टेट, मैक्स मुलर मार्ग, नई दिल्ली में 7 सितंबर, 2017 को वर्ल्ड एजुकेशन एंड स्किल कॉन्क्लेव में सहभागिता।

आईएचसी में 12 फरवरी, 2018 को उमास, आमेरस्ट द्वारा आयोजित 'इंक्लूसिव यूनिवर्सिटीजः लिंकिंग एक्यूटी, डायवर्सिटी एंड एक्सिलेन्स फॉर द 21 सेंचुरी' नामक संगोष्ठी में रिपोर्ट का लोकार्पण।

‘चेजिंग पैरडाइम इन सर्विस मार्केटिंग विथ स्पेशल फोकस ऑन टूरिजम एंड होस्पिटलिटी (आईसीसीपीएमएस), यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद’ नामक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में अध्यक्षता और सत्र मुख्य वक्ता।

वर्ल्ड बैंक इंपीरियल होटल, नई दिल्ली द्वारा 12 अगस्त, 2017 को उच्च शिक्षा राउंडटेबल।

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा 1 मार्च, 2017 को आयोजित आईसीएसएसआर– प्रायोजित अनुसंधान पद्धति कार्यशाला में उद्घाटन भाषण।

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा 1 से 10 मार्च, 2017 को आयोजित आईसीएसएसआर– प्रायोजित अनुसंधान पद्धति कार्यशाला में मुख्य अतिथि।

अंतरराष्ट्रीय

एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की संभावनाओं पर बैंकाक, थाईलैंड में 9–10 नवंबर, 2017 के दौरान हितधारकों की दूसरी बैठक में ‘वॉट आर द करंट गैप्स एंड प्रिओरिटीज फॉर इंडिकेटर्स ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन एशिया–पैसिफिक?’ पैनल के लिए विशेषज्ञ पैनलिस्ट।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की संभावनाओं पर बैंकाक, थाईलैंड में 9–10 नवंबर, 2017 के दौरान हितधारकों की दूसरी बैठक में ‘मैपिंग इंडिकेटर्स एंड डेयर यूटीलाइजेशन ऐट द इन्स्टीट्यूशनल लेवल फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन एशिया–पैसिफिक’ में समूह नेतृत्व एवं चेयर।

कोलोन विश्वविद्यालय, जर्मनी, 24 अक्टूबर, 2017 को जर्मन हाउस, नई दिल्ली में सेंटर फॉर मॉडर्न इंडियन स्टडीज (सीएमआईएस) और जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर कंपरेटिव वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (जीआरईएटी), कॉलॉन, जर्मनी द्वारा आयोजित ‘पास्ट एंड द फ्यूचर ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ स्कूल टू वर्क ट्रंजीशन, सकिल फोर्न्मेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया’ नामक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ”फ्यूचर ऑफ वीईटी रिसर्च“ पर विमर्श।

जर्मनी के कोलोन विश्वविद्यालय द्वारा 25 अक्टूबर, 2017 को आयोजित ‘पास्ट एंड द फ्यूचर ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ स्कूल टू वर्क ट्रंजीशन, सकिल फोर्न्मेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया’ नामक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में अध्यक्ष सभापति।

आयोजित किए गए कार्यशालाएँ/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम

‘विश्वविद्यालय प्रशासकों के लिए उच्च शिक्षा नेतृत्व विकास’ (26–28 फरवरी, 2018) पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहाँ भारतीय विश्वविद्यालयों के 100 प्रशासकों ने भाग लिया।

राज्य की टीमों के लिए सीपीआरएचई में रोजगार परियोजना हेतु द्वितीय शोध प्रविधि कार्यशाला आयोजन किया। (6 राज्यों से 6 विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 प्रतिभागी सम्मिलित हुए)।

बैंगलोर विश्वविद्यालय, बेंगलुरु 2017 के सहयोग से ‘शिक्षा में लैंगिक बजट’ पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

हैदराबाद में हिताची और एली कंपनियों में ‘इम्प्लोयमेंट एंड इंप्लोयबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स इन इंडिया’ पर गोलमेज सम्मेलन और एफजीडी का आयोजन और संचालन।

ओरिएंटल, लखनऊ में ‘इम्प्लोयमेंट एंड इंप्लोयबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स इन इंडिया’ पर गोल टेबल्स और एफजीडी का आयोजन और संचालन।

सीआईएससीओ, बेंगलुरु में ”इम्प्लोयमेंट एंड इंप्लोयबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स इन इंडिया“ पर गोलमेज सम्मेलन और एफजीडी का आयोजन और संचालन।

एचसीएल, लखनऊ में ”इम्प्लोयमेंट एंड इंप्लोयबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स इन इंडिया“ पर गोलमेज सम्मेलन और एफजीडी का आयोजन और संचालन।

टीसीएस, बंगलुरु में ‘भारत में उच्चतर शिक्षा स्नातक के रोजगार और रोजगार’ पर गोलमेज सम्मेलन और एफजीडी का आयोजन और संचालन।

महिंद्रा–टेक, नोएडा में ”इम्प्लोयमेंट एंड इंप्लोयबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स इन इंडिया“ पर गोलमेज

सम्मेलन और एफजीडी का आयोजन और संचालन।

रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, नई दिल्ली में "इम्प्लोयमेंट एंड इंप्लोयबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स इन इंडिया" पर गोलमेज सम्मेलन और एफजीडी का आयोजन और संचालन।

बंगलौर विश्वविद्यालय, बैंगलोर में "इम्प्लोयमेंट एंड इंप्लोयबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स इन इंडिया' परियोजना पर वरिष्ठ अधिकारियों के प्रत्यक्ष साक्षात्कार का आयोजन किया गया।

मुंबई विश्वविद्यालय में "इम्प्लोयमेंट एंड इंप्लोयबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स इन इंडिया' परियोजना पर वरिष्ठ अधिकारियों के प्रत्यक्ष साक्षात्कार का आयोजन किया गया।

दिल्ली विश्वविद्यालय में "इम्प्लोयमेंट एंड इम्प्लोयबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स इन इंडिया' परियोजना पर वरिष्ठ अधिकारियों के प्रत्यक्ष साक्षात्कार का आयोजन किया गया।

हिताची और एली कंपनी, हैदराबाद में "इम्प्लोयमेंट एंड इंप्लोयबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स इन इंडिया' परियोजना पर वरिष्ठ अधिकारियों के प्रत्यक्ष साक्षात्कार का आयोजन किया गया।

एचसीएल और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, लखनऊ में "इम्प्लोयमेंट एंड इंप्लोयबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स इन इंडिया' परियोजना पर वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के प्रत्यक्ष साक्षात्कार का आयोजन किया गया।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में "इम्प्लोयमेंट एंड इंप्लोयबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स इन इंडिया' परियोजना पर वरिष्ठ अधिकारियों के प्रत्यक्ष साक्षात्कार का आयोजन किया गया।

महिंद्रा–टेक, नोएडा में "इम्प्लोयमेंट एंड इम्प्लोयबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स इन इंडिया' परियोजना पर वरिष्ठ अधिकारियों के प्रत्यक्ष साक्षात्कार का आयोजन किया गया।

रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, नई दिल्ली में "इम्प्लोयमेंट एंड इंप्लोयबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स इन इंडिया' परियोजना पर वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के प्रत्यक्ष साक्षात्कार का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकास/संचालन

निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के शिक्षण कार्यः

विकसित पृष्ठभूमि/पठन सामग्री एवं विचार–विमर्श सत्र

i) विश्वविद्यालय प्रशासकों के लिए उच्च शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम।

ii) शिक्षा में लैंगिक बजट पर कार्यशाला।

iii) अनुसंधान परियोजना पर द्वितीय शोध प्रविधि कार्यशालाः इम्प्लोयमेंट एंड इंप्लोयबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स इन इंडिया

iv) एम. फिल. पीएचडी – सीसी3, सीसी5 और ओसी 11।

v) शैक्षिक योजना और प्रशासन (आईडेपा) में अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा।

vi) शैक्षिक योजना और प्रशासन (आईडेपा) में राष्ट्रीय डिप्लोमा।

एम.फिल./पीएचडी का पर्यवेक्षण

1. पीएचडी कार्य (जारी)

i) शोविक मुखर्जी (शोधार्थी) – शैडो एजुकेशन एट सेकंडरी लेवल स्कूलिंग इन बर्दवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगालः ए मल्टीलेवल एनालिसिस।

ii) सुमित कुमार (शोधार्थी) – इंटर–रिलेशनशिप बिटबीन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड माइग्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया।

iii) संध्या दुबे – एक्सेस एंड क्वालिटी डायनयमिक इन फायनाइन्सिंग ऑफ हायर एजुकेशन।

iv) श्री नरेश शर्मा, प्रवक्ता, डीआईईटी, मंडी द्वारा पीजीडेपा शोध प्रबंध : ए स्टडी ऑफ फंड फ्लो एंड युटिलाइजेशन पैटर्न अंडर आरएमएसए इन सदर ब्लॉक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश।

2. एम. फिल. अध्ययन (प्रस्तुत)

i) सुहैल अहमद मीर (शोधार्थी) – इनइक्वेलिटी ऑफ ऑपर्चुनिटी इन एजुकेशन इन इंडिया (अवार्ड)।

ii) संध्या दुबे – इंपैक्ट ऑफ द पब्लिक एजुकेशन एक्सपेन्डिचर अक्रोस डिफरेन्ट लेवल्स ऑन हायरएजुकेशन अक्रोस इन इंडियाः ए पैनल डाटा एनालिसिस

पाठ्य सामग्री विकास

सार्वजनिक निकायों को परामर्श एवं शैक्षणिक सहयोग

एक्सपेंडेचर मैनेजमेंट कमीशन (ईएमसी), भारत सरकार के अनुरोध पर 'शिक्षा प्रदर्शन सूचकांकः वैकल्पिक तरीके' नामक पद्धति तैयार की गई, ताकि उपयोग, लक्ष्य और परिणामों के आधार पर भारत के शिक्षा प्रदर्शन के व्यय को मापने के लिए भारत की परिचालन दक्षता में सुधार किया जा सके।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर कार्यशाला हेतु मंत्रालय द्वारा वांछित 'एजुकेशन फायनन्सिंग इन्क्लुडेस एक्सप्लोरिंग पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट सोश्ल रेस्पॉन्सिबिलिटी" विषयक प्रपत्र तैयार किया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मानव संसाधन विकास मंत्रालय), भारत सरकार के लिए "डिफाइनिंग पैरामीटर्स फॉर मेजरींग एंड आइडेंटिफाइंग एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स" विषयक प्रविध्यात्मक टिप्पणी तैयार की, जिसमें उन मानदंडों का सुझाव दिया गया है जो ईबीबी (जून 2016) को फिर से परिभाषित करने के लिए वर्तमान परिदृश्य में अधिक उपयुक्त होंगे।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

15वें वित्त आयोग के लिए आवश्यक निधि के अनुमान हेतु गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्य

सांख्यिकी और पीआई, सीएसओ के शिक्षा क्षेत्र में सेवा उत्पादन के सूचकांक पर उप–समिति के सदस्य

स्टडीज फॉर माइक्रोइकॉनॉमिक्स, सेज प्रकाशन में समीक्षक

लाइफ साइंस ग्लोबल, कनाडा के विशेष अंक के लिए अतिथि संपादक

प्रबंधन और अर्थशास्त्र अनुसंधान जर्नल के लिए समीक्षक

नीपा वेब पोर्टल का समन्वयक, रखरखाव और प्रबंधक

एम.फिल./पीएचडी प्रगति की समीक्षा समिति के सदस्य सचिव

एम.फिल./पीएचडी प्रवेश समिति के सदस्य।

एम.फिल./पीएचडी की प्रवेश परीक्षा के लिए प्रश्न निर्धारण समिति के सदस्य

डीएसी, उच्च शिक्षा विभाग

डीएसी, शैक्षिक वित्त विभाग

एम.फिल. पाठ्यक्रम संशोधन और पुनर्गठन समिति के सदस्य

कुलपति द्वारा निर्देशित एवं आवश्यकतानुसार मंत्रालय की विभिन्न बैठकों सहभागिता।

नीपा से बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

सदस्य, स्थायी अनुसंधान सलाहकार उप–समिति (आरएसी), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, (नोएडा)

सदस्य, विभागीय सलाहकार बोर्ड (डीएबी), योजना और निगरानी प्रभाग, एनसीईआरटी, नई दिल्ली

यूजीसी–दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो में जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर के डीई कार्यक्रम के एसएलएम के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ

स्प्रिंगर्स, सिंगापुर के लिए बुक प्रस्ताव के समीक्षक

संपादकीय सलाहकार बोर्डः हिमगिरी एजुकेशन रिव्यू, ISSN 2321–6336

विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए वाह्य परीक्षक (पीएचडी मूल्यांकन हेतु)

विभिन्न विश्वविद्यालयों और अन्य सरकारी निकायों के लिए चयन समिति के सदस्य।

वी.पी.एस. राजू

प्रकाशन

शोध पत्र/आलेख/नोट्स

हरियाणा के मेवात जिले में प्राथमिक स्तर पर मुस्लिम बच्चों का गैर–नामांकन और ड्रॉपआउट।

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता के लिए छात्र सहायता प्रणाली, सीपीआरएचई, नीपा (विचाराधीन)।

शोध अध्ययन (पूर्ण)

उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के लिए 'सेंटर सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलर्शिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स' का मध्यावधि मूल्यांकन।

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 'एन एवाल्युशन स्टडी ऑफ द सेंटरली–स्पोंसर्द नेशनल मीन्स–कम–मेरिट स्कॉलर्शिप स्कीम" पर अंतरिम रिपोर्ट सौंपी।

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 'एन एवाल्युशन स्टडी ऑफ द सेंटरली–स्पोंसर्द स्कीम ऑफ नेशनल स्कीम ऑफ इन्सेंटिव टु गर्ल्स फॉर सेकंडरी एजुकेशन"।

अनुसंधान परियोजनाएँ (जारी)

आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक स्तर पर मुस्लिम बच्चों के गैर–नामांकन और ड्रॉपआउटः एक तुलनात्मक अध्ययन

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के लिए केंद्र प्रायोजित 'नेशनल मीन्स–कम–मेरिट स्कॉलर्शिप स्कीम' का मूल्यांकनात्मक अध्ययन।।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के लिए केंद्र प्रायोजित 'नेशनल स्कीम ऑफ इन्सेंटिव टु गर्ल्स फॉर सेकंडरी एजुकेशन' का मूल्यांकनात्मक अध्ययन।

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाएँ

राष्ट्रीय

उच्च और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपा द्वारा 7–8 सितंबर, 2017 को आयोजित संगोष्ठी में 'आल्टर्नेटिव मेथड्स इन फायनन्सिंग ऑफ हायर एजुकेशनः ए स्टडि ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलर्शिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स' पर प्रपत्र प्रस्तुत किया।

नीपा में 3–5 अक्टूबर, 2017 को शैक्षिक नीति विभाग, नीपा द्वारा आयोजित महात्मा गांधी सम्मेलन में भाग लिया।

पी.एच.डी. शोधार्थियों के लिए 09 मई, 2017 को पियर एवं संकाय समीक्षा संगोष्ठी 2016–17 में सहभागिता।

नीपा, नई दिल्ली में एम.फिल. छात्रों के प्री–सबमिशन संगोष्ठी में भाग लिया।

प्राइड प्लाजा होटल, एयरोसिटी, नई दिल्ली में 26–28 फरवरी, 2018 के दौरान नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'लीडरशिप डेवलपमेंट फॉर हायर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर' की कार्यशाला में भाग लिया।

एमआईटी, वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, पुणे द्वारा 2 अक्टूबर 2017 को कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब, नई दिल्ली में 'शांति' पर आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया।

विभाग नीपा, नई दिल्ली द्वारा प्राइड प्लाजा होटल, एयरोसिटी, नई दिल्ली में 7–8 दिसंबर, 2018 को उच्च शिक्षा में नेतृत्व विकास पर आयोजित 'लीडरशिप डेव्लपमेंट इन हायर एजुकेशन फॉर वाइस चांसलर्स' कार्यशाला में भाग लिया।

नीपा में एम.फिल छात्रों द्वारा पूर्व–जमा संगोष्ठी में प्रस्तुतिकरण में भागीदारी, नीपा, नई दिल्ली।

स्कूल और गैर–औपचारिक शिक्षा विभाग नीपा, नई दिल्ली द्वारा 15–16 मार्च, 2018 को 'गवर्नमेंट, रेगुलशन एंड क्वालिटी एस्युरेंस इन टीचर एजुकेशन' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय

सीईएसआई, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू और कश्मीर में 16–18 नवंबर, 2017 को इनोवेटिव मेथड्स ऑफ फायनन्सिंग हायर एजुकेशन : ए स्टडी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कोलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स'विषयक प्रपत्र प्रस्तुत किया।

इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में 22–23 फरवरी, 2018 को 'क्वालिटी एंड एक्सिलेन्स इन हायर एजुकेशन' नामक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी (सीपीआरएचई, नीपा और ब्रिटिश काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित) में 'स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम फॉर क्वालिटी एंड एक्सिलेन्स इन हायर एजुकेशन' विषयक प्रपत्र प्रस्तुत किया गया।

आयोजित किए गए कार्यशालाएँ/सम्मेलन/ प्रशिक्षण कार्यक्रम

नीपा, नई दिल्ली में 11–15 सितंबर, 2017 को राज्यों में वित्तीय योजना और शिक्षा के प्रबंधन में अभिविन्यास कार्यक्रम।

राजस्थान विश्वविद्यालय में 19–21 मार्च, 2018 को कॉलेज वित्त की योजना और प्रबंधन में अभिविन्यास कार्यक्रम।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम निर्माण व संपादन

नीपा, नई दिल्ली में अभिविन्यास कार्यक्रम के दौरान राज्यों में वित्तीय योजना और शिक्षा प्रबंधन पर शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं संपादन।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में 19–21 मार्च, 2018 को ओरिएंटेशन कार्यक्रम में कॉलेज वित्त की योजना और प्रबंधन पर प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण एवं संपादन।

नीपा, नई दिल्ली में, शैक्षिक योजना और प्रशासन (ग्गग्प्प्, आईडेपा) अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा के पाठ्यक्रम संख्या 207 'वित्तीय योजना और शिक्षा में प्रबंधन' की प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण एवं संपादन।

नीपा, नई दिल्ली में, शैक्षिक योजना और प्रशासन (पीजीडेपा) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पाठ्यक्रम संख्या 903: 'शैक्षिक योजना' में प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण एवं संपादन।

नीपा, नई दिल्ली में, पाठ्यक्रम क्रमांक 905: 'प्रोजेक्ट वर्क एंड राइटिंग' में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (पीजीडेपा) प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण एवं संपादन।

एम.फिल. वयस्क शिक्षा पर पाठ्यक्रम विकास।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

04 अप्रैल, 2017 को पीजीडेपा प्रतिभागियों का मूल्यांकन एवं वाइवा–वाइस।

पीजीडेपा प्रतिभागियों को परियोजना कार्य/शोध प्रबंध हेतु मार्गदर्शन।

आईडेपा प्रतिभागियों को परियोजना कार्य/शोध प्रबंध हेतु मार्गदर्शन।

विद्याभारती स्कूल के प्राचार्यों के लिए 2 नवंबर, 2017 को 'स्कूल के कामकाज के बेहतर प्रबंधन के लिए स्कूल नेतृत्व के विकास की आवश्यकता और महत्व' पर व्याख्यान।

शैक्षिक वित्त विभाग के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना।

4–12 फरवरी, 2018 के दौरान 'शैक्षिक प्रशासन –2018 में नवाचारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' के लिए मामलों की वैधता मूल्यांकन।

विभाग के लिए विभागीय सलाहकार समिति की बैठक का एजेंडा तैयार करना

एम.फिल./आईडेपा/पीजीडेपा में निर्देशन

पहली पीढ़ी के कॉलेज के स्नातक शिक्षार्थियों की शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक चुनौतियों के अध्ययन पर एम. फिल. प्रस्तुत (सबमिट) (शिखा दिवाकर)।

जम्मू और कश्मीर के प्रशासनिक प्रभाग में सशस्त्र संघर्ष और शिक्षा का अध्ययन (मोहम्मद इलियास) एम.फिल।

पापुमपारे जिला, अरुणाचल प्रदेश पीजीडीपीए के सागले ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पर एक अध्ययन (श्री सेंडो लोम्बि)।

गाले शैक्षिक क्षेत्र, गेल्ले जिला, श्रीलंका (श्री डब्ल्यू. टी. रावेन्द्र पुष्प कुमारा) आईडेपा में टूटे हुए परिवार के प्राथमिक छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन।

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहयोग

उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के लिए तीन केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन का आयोजन।

नीपा से बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

कंपरेटिव एजुकेशन सोसायटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के आजीवन सदस्य।

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग (आईआईईपी/यूनेस्को), पेरिस के पूर्व छात्र सदस्य।

विभिन्न प्रशासनिक और शैक्षणिक समितियों में सदस्य

एम.फिल. आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग समिति के सदस्य।

एम.फिल./पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजन समिति के सदस्य।

एम.फिल./पीएचडी प्रवेश परीक्षा के संचालन के पर्यवेक्षक।

स्क्रीनिंग कमेटी और प्रोजेक्ट स्टाफ चयन के साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य।

एम.फिल./पीएचडीप्रवेश परीक्षा के लिए पर्यवेक्षक कार्य।

नीपा की निविदा उद्घाटन समिति के सदस्य।

नीपा डिजिटल लर्निंग मॉनिटरिंग सेल के सदस्य।

शैक्षिक नीति विभाग

अविनाश कुमार सिंह

प्रकाशन

2017'द कमिंग क्राइसिस ऑफ सोशल साइंस एजुकेशन इन इंडिया – इश्यूज एंड चैलेंजेज' वानखेड़े जी और इवान रीड,'हायर एजुकेशनः फुटप्रिंटस ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, आकर बुक्स, नई दिल्ली।

अनुसंधान कार्य

पूर्ण

मद्रास में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन की संयुक्त परियोजना (एसपीक्यूईएम) (प्रो. एके सिंह, डॉ. मंजू नरूला, डॉ. एसके मलिक और डॉ. नरेश कुमार)।

जारी

'चयनित राज्यों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत निजी

स्कूलों में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों के प्रावधान के कार्यान्वयन का अध्ययनः नीति और व्यवहार'

संगोष्ठियों/सम्मेलनों में सहभागिता

21–25 अगस्त, 2017 को नीपा, नई दिल्ली में 'एजुकेशन ऑफ द डिसएडवांटेज एंड एकोनोमिकली वीकर सेक्टशंस एट द एलीमेंट्री लेवेलः पॉलिसी ईसूज एंड प्रोग्राम इंटरवेनशन' नामक अभिविन्यास कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप भाग लिया।

11–15 सितंबर 2017 को गुवाहाटी,असम में 'फंक्शनिंग ऑफ लोकल अथॉरिटी एंड आटोनोमस काउसिल्स (सिस्ट शैड्यूल ऑफ द कांस्टिट्यूशन इन मैनेजमेंट ऑफ एलेमेंट्री एजुकेशन इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट' नामक अभिविन्यास कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप भाग लिया।

3–5 अक्टूबर, 2017 को नीपा, नई दिल्ली में 'एजुकेशन, वर्क एंड रुरल डेव्लपमेंटः गांधीज एजुकेशनल आइडियास इन पॉलिसी पेर्सपेक्टिव' पर राष्ट्रीय विमर्श सम्मेलन में 'गांधीज एक्सपरिमेंट विथ एजुकेशन इन बिहारः रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट्स' विषयक प्रपत्र प्रस्तुत किया।

14 सितंबर, 2017 को शैक्षिक अध्ययन में बहुविषयक केंद्र स्वामी विवेकानंद केंद्र, बेलूर मठ में पीएचडी अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक में संसाधन व्यक्ति।

7–8 सितंबर, 2017 को 'फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशनः एकोनोमिक एंड सोशल कांटेक्स्ट' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'एक्यूटी एंड क्वालिटी' पर एक सत्र की अध्यक्षता की।

18 सितंबर, 2017 को नीपा, नई दिल्ली में 'पॉलिसी मेकिंग इन एजुकेशनः फोकसिंग ऑन इनक्लूसिव एजुकेशन 'पर ओरिएनेशन वर्कशॉप में पॉलिसी मेकिंग इन एजुकेशनः सोशियो–पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स' पर एक वक्तव्य दिया।

12 दिसंबर, 2017 को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में राष्ट्रीय एसएमसी कन्वेंशन में 'फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन कमेटीज' पर एक वक्तव्य दिया।

कार्यशाला/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

3–5 अक्टूबर, 2017 को नीपा, नई दिल्ली में 'गंधीयन एजुकेशनल इडियस इन पॉलिसी पेर्स्पेक्टिव' (चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शताब्दी) विषय पर राष्ट्रीय विमर्श बैठक।

24 मार्च, 2018 को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन (आईएसईसी) संस्थान, बेंगलूर में डॉ. एस.के. मलिक के साथ संयुक्त रूप से 'स्ट्रेन्थिंग ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अंडर आरटीआई' पर अभिविन्यास कार्यक्रम।

26–28 मार्च, 2018 को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) बेंगलूर में डॉ. एसके मलिक के साथ संयुक्त रूप से 'इंप्लेमेंटेशन ऑफ राइट तो एजुकेशन एक्टः प्रोग्रेस एंड वे फॉरवर्ड' विषय पर राष्ट्रीय परामर्शी बैठक का आयोजन।

9 नवंबर, 2017 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 'एसेंसियल्स फॉर एक्सिलेंट इन हायर एजुकेशन' विषय पर मौलाना आजाद मेमोरियल लेक्चर का आयोजन।

रिपोर्ट अवधि में विकसित प्रशिक्षण सामग्री

नीपा में एम.फिल/पीएचडी पाठ्यक्रम संशोधन, 2017–18

रिपोर्ट अवधि में सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहयोग

डॉक्टरल एडवाइजरी बोर्ड, स्वामी विवेकानंद शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, बेलूर मठ, 2016 (जारी)।

अध्यक्ष, अनुदान–सहायता समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय/नीपा, 2016 (जारी)।

सदस्य, कार्यकारी समिति, महाराष्ट्र प्रथमिक शिक्षा परिषद, मुंबई।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

नीपा में 'स्टडी ऑफ टी वे डायनामिक्स ऑफ एक्सक्लूजन इन स्कूल एंड कम्युनिटी' विषय पर पीएचडी शोधार्थी (अंशकालिक) अजय कुमार चौबे को मार्गदर्शन।

'सोशल जस्टिस एंड लोकल गर्वनेंस इन एलीमेंट्री एजुकेशन विथ रेफेरेंस टू द पार्टीशिफेशन ऑफ दिस अडवांटेज ग्रुपस' विषय पर पीएचडी शोधार्थी (अंशकालिक) लबोनी दास को मार्गदर्शन।

'एजुकेशन, कल्चर एंड लाइबेलिहुडः ए स्टडी ऑफ द नोमाइडिक पस्टोरलिस्ट बकरवल्स इन जम्मू एंड कश्मीर' विषय पर पीएचडी शोधार्थी सज्जाद अहमद को मार्गदर्शन।

'आईडेंटिटी एंड पार्टीसीपेशन इन हायर एजुकेशन" ए स्टडि ऑफ नॉर्थईस्ट इथनिक माइनॉरिटि स्टूडेंट्स इन सिलैक्टेड एजुकेशनल इंस्टिट्युशन इन दिल्ली' विषय पर पीएचडी शोधार्थी दलसी गंगमी को मार्गदर्शन।

2017–18 के दौरान नीपा में इंटर्न आस्था जैन (क्राइस्ट कॉलेज, बैंगलोर) को मार्गदर्शन।

'एजुकेशन, रिहैबिलिटेशन एंड पीस इन कैमरुनः ए केश स्टडि ऑफ द केंटरर्ल अफ्रीकन रिफ्यूजी चिल्ड्रेन इन गड़ो बदजेरे' लघु शोध प्रबंध पर न एटीन प्रोस्पर को मार्गदर्शन।

वीरा गुप्ता

प्रकाशन

2017 (संपादक) 'पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ एंक्लूसिव एजुकेशन विथ फोकस ऑन सीडबल्यूएसएन' एक्सेल इंडिया द्वारा प्रकाशित; आईएसबीएन 978–93–86724–60–1; 9–10 नवंबर, 2017।

'यूज़ ऑफ आईसीटी टू अड्रेस स्पेसिफिक लेर्निंग डिसबिलिटी इन इंडिया' पर लेखः एन्ट्रीप अंक–23, संख्या–1, जनवरी–जून 2017।

एजुकेशन फॉर ऑलः रोल ऑफ एक्समिनेशन बोर्ड, कोबसे वार्षिक सम्मेलन की कार्यवाही, 2–4 नवंबर, 2017; थीमः इन्नोवेशन इन इवैल्यूएशन।

'एसेस्मेंट ऑफ स्कूल परफॉर्मेंस ऑन इंक्लूजन इन इंडिया' पर प्रपत्र 978–93–86724–60–1; एक्सेल इंडिया द्वारा प्रकाशित।

'प्रोफेशनल पब्लिक एजुकेशनल पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया', हायर एजुकेशन रिव्यू, मई 2017, पेज 34–35; http://www.thehighereducationreview.com/mag±ines/six-sigma-training-special-may पर उपलब्ध

अनुसंधान जारी और पूर्ण

जारी

स्कूलों में 'स्पेसिफिक लर्निंग डिसबिलिटी' वाले बच्चों को शामिल करने के लिए नीति और अभ्यास पर एक अध्ययन।

रिपोर्ट अवधि में संगोष्ठी/सम्मेलनों में सहभागिता

'शिक्षा में भूमिका का पृथक्करण' पर गोलमेज में भाग लिया, 20 मार्च, 2018, सिविल सोसायटी, नई दिल्ली के लिए केंद्र।

23 मार्च, 2018 को गुड़गांव के सरदार पटेल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में दीक्षांत समारोह।

24 मार्च, 2018 को मनोविज्ञान विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य' में प्रपत्र प्रस्तुत किया।

22–23 फरवरी 2018 को सीपीआरएचई में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 'गुणवत्ता और उत्कृष्टता उच्च शिक्षा में" में एक प्रपत्र 'गुणवत्ता का एक उपाय के रूप में एपीआई' प्रस्तुत किया।

रिपोर्ट अवधि में विकसित प्रशिक्षण सामग्री

18–22 सितंबर, 2017 को सीडब्ल्यूएसएन पर फोकस के साथ नीति निर्धारण पर अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए पठन सामग्री।

पीजीडेपा के लिए एडवांस पाठ्यक्रम के लिए 'प्रोफेशनल पॉलिसी मेकिंग'।

सीडब्ल्यूएसएन पर फोकस के साथ समावेशी शिक्षा — एम.फिल. के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रम।

रिपोर्ट अवधि में सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहयोग

सलाहकार समिति की बैठक आइसीआइई 2018, 15 मार्च, 2018, अमर ज्योति, नई दिल्ली।

'नेचर ऑफ इङ्क्लुजन फॉर स्टूडेंट्स विथ इंटेलेच्युयल एंड डेव्लपमेंट डिसबिलिटीजः डू इंडियन एजुकेशन पोलिसिज ड्राइव इंक्लूसिओन एजुकेशन/मैनुस्क्रिप्ट आईडी टीआइईडी 2017—18—0379, समावेशी शिक्षा का अंतरराष्ट्रीय जर्नल।

डॉ निरुपमा जैमिनी के मार्गदर्शन में रितु बाला द्वारा 'परीक्ष प्राणाली एंड शाक्षिल विस्मताः एक समाज शास्त्रीय अध्ययन' पर थीसिस के मूल्यांकन हेतु परीक्षक, 23 जनवरी, 2018, दिल्ली विश्वविद्यालय।

विकलांगता अधिनियम के बारे में 5—3—2018 को जवाब के लिए लोकसभा प्रश्न डी संख्या 5193।

उचित आवास के लिए विभिन्न मुद्दों की जांच समिति के सदस्य ताकि विकलांग कर्मचारियों को उनकी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके, शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली।

श्री जुगल किशोर बनाम निदेशक (शिक्षा) के मामले में समिति की बैठक माननीय न्यायालय राज्य विकलांग आयोग, दिल्ली सरकार, एनसीटी दिल्ली सरकार के माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में, केस सं। 4/1473/2016/wel/CD/1993—94 दिनांक 26.09. 2017।

शिक्षक—शिक्षा नियोजन कार्यशाला में "मॉडल ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग' और "चेंज मैनेजमेंट"के लिए परियोजना नियोजन पर सत्र में संसाधन व्यक्ति।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान और ब्रिटिश काउंसिल के मध्य एक सहयोगात्मक कार्यशाला, 13 नवंबर, 2017।

यूपीएससी के लिए सामान्य अध्ययन के प्रपत्र के लिए मूल्यांकनकर्ता; 20—29 नवंबर, 2018; यूपीएससी, नई दिल्ली।

'पर्सिप्शनस ऑफ टिपिकली देवेलोपींग चिल्ड्रेन इन इंडिया अबाउट देयर सिबलिंग्स विथ डिसबिलिटी", जप्म्क 2017—19, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन, टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप के आलेखके लिए समीक्षक।

परीक्षा नियंत्रकय 30 नवंबर जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली।

स्कूल बैग के वजन के लिए समीक्षा—सह—परामर्श बैठक, 24 अगस्त; एनसीपीसीआर और एनसीईआरटी।

हरियाणा में व्यावसायिक कार्यक्रम का मूल्यांकन; 12—14 जुलाई; एनसीईआरटी, नई दिल्ली।

पीजीडीईएम की वाइवा—वॉयस परीक्षा के लिए परीक्षक; 4 मई; जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली।

ई—पाठशाला मॉड्यूल की समीक्षा; 14—15 अप्रैल; एनसीईआरटी, नई दिल्ली।

'शाला सिद्धि' पर व्याख्यान, 11 जनवरी, 2018, डीआइईटी, करदरोमा, दिल्ली।

12 जनवरी, 2018 को 'एसेस्मेंट ऑफ चिल्ड्रेन व्हाइ, हाउ, एंड वेन" इन—सर्विस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक महिंद्रा' पर व्याख्यान।

एआईयू के साथ 15 जनवरी, 2018 को सीबीसीएस और क्रेडिट ट्रांसफर पर व्याख्यान, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर।

पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन के तहत जम्मू और श्रीनगर के बीईओ के शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता; 9 अक्टूबर, सेंट्रल जम्मू विश्वविद्यालय।

शैक्षिक नीतियों पर व्याख्यान, 17 अगस्त, वायु सेना स्कूलों के निदेशालय।

राज्य परीक्षा बोर्ड कॉन्क्लेव 2017 'परीक्षा सुधार और नए संदर्भः विधान (आरपीडब्ल्यूडी 2016) और एसडीजी', 31 अगस्त, 2017, बिहार राज्य परीक्षा बोर्ड पर मुख्य वक्ता।

12 जून को यूजीसी मानव संसाधन विकास केंद्र में एएमयू स्कूल शिक्षकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम में व्याख्यान; यूजीसी मानव संसाधन विकास केंद्र, एएमयू।

संज्ञानात्मक विकलांगता पर सत्र; 14 जून; विकलांगता और पुनर्वास अध्ययन के लिए सोसायटी।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

पीएचडी शोधार्थी संगीता डे के अध्ययन 'पॉलिसी अनालिसिस ऑफ मिड डे मील प्रोग्रामः फ्रम गवर्नमेंट्स पेर्स्पेक्टिव" के पर्यवेक्षक।

पीएचडी शोधार्थी दीपिन्दर सेखों के अध्ययन प्रैक्टिस और अभ्यास सीडब्ल्यूएसएन संख्या एफ 11–8/2014–15/एए/सीएएस दिनांक 27 अगस्त, 2015 के पर्यवेक्षक।

निवेदिता सहानी के एम. फिल. लघु शोध प्रबंध "ए स्टडि ऑन द कान्सैप्ट ऑफ डिसबिलिटी इन इंडिया विथ स्पेशल एंफासिस ऑन द एसेस्मेंट प्रोसीजर ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स–जीआईएसी की 36 वीं बैठक; नीपा के पर्यवेक्षक।

एम. फिल और पीएचडी के लिए संचालन समिति।

अकादमिक परिषद की बैठक।

नीपा से बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, कोयंबटूर के शासी निकाय सदस्य; डीओ संख्या एफ–2–26 (7) 2004 (एसी) अक्टूबर 2017।

सलाहकार समिति के सदस्य, आइसीआइई 2018, अमर ज्योति।

मनीषा प्रियम

प्रकाशन

2017ः एन. जयराम द्वारा संपादित 'सोशल डायनेमिक्स ऑफ द अर्बन', स्प्रिंगर में "फोरम क्लिएंट्स तो सिटीजनः लर्निंग फ्रम ब्रजिल्स बोल्सा फॅमिलीआ प्रोवाइड्स अपोरच्यूनिटीज़ टू दिल्ली'।

2017ः जॉर्ज डब्ल्यू नोबेल्ट द्वारा संपादित ऑक्सफोर्ड रिसर्च इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन, न्यूयॉर्क में 'एजुकेशन पॉलिसी एंड डेव्लपमेंट'।

अनुसंधान जारी और पूर्ण

जारी

द पॉलिटिकल इकॉनमी ऑफ हायर एजुकेशन रेफोर्म इन इंडियाः कंपरेटिव पेरस्पेक्टिव ऑन द प्रिंसीपल्स पॉलिसीज एंड इंस्टीटुशन्स फॉर रेफोर्म (1991–2012)।

रिपोर्ट अवधि में संगोष्ठियों/सम्मेलनों में सहभागिता

8 सितंबर 2017ः ''ग्लोबल वार्स, नेशनल लेगसीज एंड स्टेट कंट्रोल्सः द डाइलेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज'' 7–8 सितंबर, 2017 को इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन, शताब्दी वर्ष में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी ''द फ्यूचर्स ऑफ हायर एजुकेशनः इकोनोमिक एंड सोशल कॉन्टेक्ट्स'' राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

3 अक्टूबर 2017ः 'सोशल वेल्फेयर पॉलिसीज एंड द पोइलिटिक्स ऑफ डेव्लपमेंट" आमंत्रित व्याख्यान, भारतीय लोकतांत्रिक नेतृत्व संस्थान, मुंबई।

3 अक्टूबर 2017ः 'विकासवाद, द पूयर एंड एमर्जीङ्ग सिनरियों इन कास्ट पॉलिटिक्स', आमंत्रित व्याख्यान, भारतीय लोकतांत्रिक नेतृत्व संस्थान, मुंबई।

7 अक्टूबर 2017ः 'पीसा एडुकेशन पॉलिसी एंड टीचर्सः इमार्जिंग एसयूज", प्रधानाध्यापक मीट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कोच्चि।

27 अक्टूबर 2017ः 'एथनोग्राफी, इलैक्शन, एंड पॉलिटिक्सः लेसन फ्रम इमार्जिंग फील्ड वर्क इन डेलही", अशोका विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा।

1 नवंबर 2017: 'फ्रम सिटीजन टू क्लाइंट्स: लेसन्स फ्रम ब्रजिल्स बोल्सा फमिला फॉर डेलही" आमंत्रित व्याख्यान, आईआईटी, गांधीनगर।

17 नवंबर 2017: 'फ्रम सिटीजन टू क्लाइंट्स: लेसन्स फ्रम ब्रजिल्स बोल्सा फमिला फॉर दिल्ली" आमंत्रित व्याख्यान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद।

30 नवंबर 2017: 'पाथ डेपेंडेंस, एजुकेशनल डेव्लपमेंट, एंड केरल मॉडल: अनपैकिंग कंट्रीस्ट हिस्ट्रीज', आमंत्रित व्याख्यान, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, दिल्ली।

15 दिसंबर 2017: 'एकीकृत लर्निंग सॉल्यूशंस', प्रधानाध्यापक मीट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पटना।

जनवरी 2018 : "जेंडर इक्वेलिटी एंड एजुकेशन" मुश्किल संवादों पर पैनल चर्चा, गोवा यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल सेंटर गोवा।

16 फरवरी 2018: 'अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल प्रोसैस एंड अड्वान्सिंग डेमोक्रेटिक थ्योरी: कोंसिडेरेशन्स ऑन द यूज ऑफ पॉलिटिकल एथनोग्राफी", सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (एसपीपीयू)।

16 मार्च 2018: 'रिगर बिफोर रिलेवेंस? ए 'क्रॉस'–कास्ट फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेज इन स्टडीज ऑफ पोवर्टी एंड डेव्लपमेंट", शोध प्रविधि पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल।

मार्च 2018: 'एजुकेशन पॉलिसी रेफोर्म्स", शैक्षिक शिक्षा में पहला रिफ्रेशर कोर्स, जेएनयू–एचआरडीसी।

मार्च 2018: 'मिड डे मील स्कीम इन इंडिया", शैक्षिक शिक्षा में पहला रिफ्रेशर कोर्स, जेएनयू–एचआरडीसी।

कार्यशाला/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

"महाराजा कॉलेज मैसूर: एन एथनोग्राफी", शताब्दी कॉलेजों के नृजाति विज्ञान पर प्रस्तुति, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपा (6 अक्टूबर, 2017)।

'अर्बन मार्जिनलिटी, सोशल पॉलिसी, एंड एजुकेशन इन इंडिया' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, मनीषा प्रियम, नीपा, नई दिल्ली (12–13 फरवरी, 2018)।

'पॉलिसी डेलीबेरेशन्स ऑन पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन इंडिया: ऑटोनोमी एज एन आइडिया एंड प्रैक्टिस' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, नीपा, नई दिल्ली (8–9 मार्च, 2018)।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

एस. आरोकिया मैरी (पार्ट टाइम पीएचडी) को 'सोशल जस्टिस, जेंडर एंड एजुकेशनल पार्टीसिपेशन: एन एथ्नोग्राफिक स्टडि ऑफ गर्ल्स फ्रम अर्बन मार्जिन्स' पर मार्गदर्शन।

लकपचुई सिरो (पीएचडी) को 'इम्पैक्ट ऑफ एथिनिसिटी इन अक्सेस टू हायर एजुकेशन इन मणिपुर' पर मार्गदर्शन।

नाओमी प्राची हजारिका को 'अर्बन मार्जिनलिटी, सोशल पॉलिसी एंड एजुकेशनल एस्पायरेसन्स: एन एथ्नोग्राफिक इंक्वायरी' पर मार्गदर्शन प्रदान।

एस.के. मलिक

अनुसंधान

पूर्ण

मद्रास में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन की संयुक्त परियोजना (एसपीक्यूईएम) (प्रो. एके सिंह, डॉ. मंजू नरूला, डॉ. एसके मलिक और डॉ. नरेश कुमार)।

जारी

ओडिशा में माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों के बीच छात्रवृत्ति योजना और शैक्षिक गतिशीलता का अध्ययन।

रिपोर्ट अवधि में संगोष्ठियों/सम्मेलनों में सहभागिता

नीपा, नई दिल्ली में 'अर्बन मार्जिनलिटी, सोशल पॉलिसी, एंड एजुकेशन इन इंडिया' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी (12–13 फरवरी, 2018)।

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी (22–23 फरवरी, 2018)।

विश्वविद्यालय प्रशासकों के लिए उच्च शिक्षा में नेतृत्व विकास पर कार्यशाला (26–28 फरवरी, 2018)।

'एंगेजिंग विथ पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन इंडियाः ऑटोनोमी एस एन आइडिया एंड इट्स प्रैक्टिस' पर राष्ट्रीय कार्यशाला (8–9 मार्च, 2018)।

डाईट, मोतीबाग (अक्टूबर 2017) में व्याख्यान दिया गया।

डाईट, मोतीबाग (जनवरी 2018) में व्याख्यान दिया गया।

शैक्षिक प्रशासन में नवाचारों की मान्यता के लिए ओडिशा का दौरा (5–9 फरवरी, 2018)।

कार्यशाला/सम्मेलन/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

एजुकेशन ऑफ द डिसअडवांटेज चिल्ड्रेन एंड इकॉनोमिकली वीकर सेक्शनस एट एलीमेंटरी लेवेलः पॉलिसी ईसूज एंड प्रोग्राम इंटरवेनसंस' पर अभिविन्यास कार्यक्रम (नीपा, नई दिल्लीः 21–25 अगस्त, 2017)।

फंक्शनिंग ऑफ लोकल एथोरीटी एंड ओटोनोमस काउंसिल अंडर सिक्स्थ शैड्यूल ऑफ द कोन्स्तितुशन इन मैनेजमेंट ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स' पर अभिविन्यास कार्यक्रम (होटल राजधानी रिगोरिया, गुवाहाटीः 11–15 सितंबर, 2017)।

प्रो. ए.के. सिंह के साथ से संयुक्त रूप से 'स्ट्रेन्थिंग ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज अंडर आरटीई' पर अभिविन्यास कार्यक्रम (आईएसईसी, बैंगलोरः 20 – 24 मार्च, 2018)।

प्रो ए के सिंह के साथ से संयुक्त रूप से 'इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्टः प्रोग्रेस, इशूज एंड वे फॉरवर्ड' (एनएलएसयू, बैंगलोरः 26–28 मार्च, 2018)।

रिपोर्ट अवधि में प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण/संचालन

प्रोजेक्ट वर्क के लिए ग्रंथ सूची/संदर्भ कैसे तैयार करें? 2017, नीपा, नई दिल्ली।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

एम.फिल./पीएचडी में वैकल्पिक पाठ्यक्रम संख्याः 05 का अध्यापन

(शिक्षामें सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय प्रशासन)

प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुसंधान समूह के सदस्य

एम. फिल./पीएचडी पाठ्यक्रम के सदस्य

एम. फिल./पीएचडी प्रवेश स्क्रूटनी समिति के सदस्य।

शैक्षिक योजना और प्रशासन जर्नल (नीपा जर्नल) में संपादकीय सहायता

एम.फिल. निर्देशन

वदना तिवारीः स्टेकहोल्डस अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिसी ईंटेंटः ए स्टडी ऑफ सेक्शन 12 (1) सी ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट (2009) इन सेलेक्टेड प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स ऑफ डेलही (अवार्ड)।

काव्या चंद्राः कम्यूनिटी पार्टीसीपेशन एंड एकौंट्बिलिटीः ए केस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इन स्कूल ऑफ न्यू डेलही (जारी)।

पाठ्यक्रम प्रभारीः

प्रतिभागी संगोष्ठी; पीजीडेपा; आईडेपा

निर्देशित आईडेपा प्रतिभागी

निर्देशित पीजीडेपा प्रतिभागी

नीपा से बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सदस्य

नरेश कुमार

प्रकाशन

शोध पत्र/आलेख

कुमार, नरेश और सोनाली हाजरा. 2018. एजुकेशन, पार्टीसिपेशन एंड डिसपेरिटीः ए डिस्क्रिप्टिव पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू और कश्मीर, भारतीय शिक्षा का जर्नल, XLIII (1): 60–71।

कुमार, नरेश 2017.: सेकंडरी एजुकेशन एट द क्रॉसरोडः ए रेफ्लेक्शन ऑन सोशल, जेंडर एंड रीजनल डिस्परिटी इन जम्मू और कश्मीर', मैन एंड डेवलपमेंट, सीआरआरआईडी, चंडीगढ़, XXXIX (2): 89–102।

रिपोर्ट अवधि में संगोष्ठियों / सम्मेलनों में सहभागिता

(राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय)

17 अप्रैल 2017–'कोन्सेप्चुयल कोंटेस्टशनः प्रोडुसिंग जेंडर नॉलेज इन एंड फॉर हायर एजुकेशन' पर सम्मेलन, द्वारा एमिली एफ हैंडरसन, शैक्षिक अध्ययन केंद्र, वारवीक विश्वविद्यालय, इंग्लैंड।

18 अप्रैल 2017– 'इंडियाज एड एंड सॉफ्ट पावर इन अफ्रीकाः द केस ऑफ एजुकेशनएंड ट्रेनिंग' द्वारा प्रो. केनेथ किंग और प्रवीना किंग, यूके।

05 जुलाई 2017– 'टीच द रोल ऑफ टीचर्स इन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ एडटेकः इमर्जिंग इश्यूज एंड क्वेश्चंस' द्वारा डॉ. पेट्रीसिया बर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्स कैलिफोर्निया, यूएसए।

22 अगस्त 2017– वॉट डज माय आईआईटीयन टैग अक्चुयाली मीन? रिलेशन्स बिट्वीन एजुकेशनल टाइटल्स एंड पोस्ट्सः थे कसे ऑफ आईआईटी स्टूडेंट्स' द्वारा प्रो. ओडिल हेनरी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस 8, फ्रांस।

31 अगस्त 2017– 'गवर्नमेंट एंड एजुकेशन इन यूएस' द्वारा डॉ क्रेग एल डिकर, सांस्कृतिक और शैक्षिक मामलों के काउंसेलर, यू.एस. दूतावास, नई दिल्ली।

13 सितंबर 2017– 'डूइंग फील्डवर्क एंड इट्स चौलेंजेसः रिफ्लेक्शंस फ्रम रिसर्च इन दिल्ली' द्वारा सैयदा जेनिफा जहान, भूगोल विभाग, एफएएसएस, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर।

21 सितंबर 2017– 'ग्लोबल स्किल्स एंड ग्रेजुएट आउटकम्स' पर कोलोजियम द्वारा डॉ. सारा रिचर्डसन, रिसर्च डायरेक्टर, ऑस्ट्रेलियन काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च इन इंडिया।

02 नवंबर 2017– 'विल फेलिंग स्टूडेंट्स हेल्प देम लर्न? द आरटीई 2009 एंड द रेवेरसल ऑफ ही नो डेटेन्शन पॉलिसी' पर कोलोजियम द्वारा नलिनी जुनेजा, पूर्व प्रोफेसर, नीपा।

13 नवंबर 2017– 'नॉलेज फॉर चेंज – लॉन्च ऑफ इंटरनैशनल कंसोर्टियम ऑन 13 कम्यूनिटी बेस्ड रिसर्च', यूनेस्को चेयर द्वारा आयोजित कम्युनिटी–बेस्ड एजुकेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन एंड नीपा।

20 नवंबर, 2017– 'ड्रेन ऑफ गवेर्नमेंट स्कूल इन इंडिया. इज श्चोल कोंसोलिडेशन, द आन्सर? एविडेंस फ्रम कर्नाटक' पर कोलोजियम द्वारा डॉ. शिव कुमार जोलाड, पूर्व प्रोफेसर, आईआईटी, गांधीनगर।

25 जनवरी, 2018– 'इंडियन मायग्रेशन टू यूएस' पर कोलोजियम द्वारा डॉ. नील जी. : इज, एसोसिएट डायरेक्टर, ग्लोबल माइग्रेशन एंड डेमोग्राफी, प्यू रिसर्च सेंटर, वाशिंगटन, डीसी।

रिपोर्ट अवधि में सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहयोग (शिक्षण और सत्र)

एम.फिल. / पीएचडी अनुसंधान पद्धति–II '(सीसी–5) पर अनिवार्य पाठ्यक्रम – कुल सत्र (20)।

शिक्षा और विकास पर आईडेपा अनिवार्य पाठ्यक्रमः एक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य (पाठ्यक्रम संख्या 202)' – कुल सत्र (1)।

पीजीडेपा 2017 – 'भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा और समाज' पर एक सत्र पढ़ाया गया।

पर्यवेक्षण और मूल्यांकन

2017– सिप पगनासोले, कंबोडिया द्वारा प्रस्तुत 'एजुकेशन रिफॉर्मः एचआरएम स्तफ्फिंग नोर्म इंप्लांटेशन एट कंडाल प्रोविन्स। चौलेंज एंड इम्पैक्ट ऑफ न्यू स्तफ्फिंग नोर्म एट पायलट एरिया', पर 33वें आईडेपा लघु शोध प्रबंध का मार्गदर्शन, शैक्षणिक वर्ष 2015–16।

2017 (दिसम्बर–फरवरी) – दुर्गा मणि प्रधान द्वारा प्रस्तुत 'ए स्टडि ऑफ टीचर मैनेजमेंट अप टू सेकंडरी

लेवेल इन गवर्नमेंट स्कूल्स अंडर सोरेंग सब–डिविजन इन वेस्ट सिक्किम' लघु शोध प्रबंध का मार्गदर्शन।

शैक्षणिक सहयोग और बैठकें

2017, मार्च 30– वरिष्ठ कंसल्टेंट, कंसल्टेंट और कनिष्ठ कंसल्टेंट के पदों के लिए प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग।

2017, मई 30 – एम. फिल. और पीएचडी कार्यक्रम 2017–18 की प्रवेश समिति की बैठक।

2017, जून 5,एम. फिल. और पीएचडी कार्यक्रम 2017–18 में प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग।

2017, जुलाई 01– एम. फिल. और पीएचडी कार्यक्रम 2017–18 में प्रवेश के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के लिखित टेस्ट स्क्रिप्ट का मूल्यांकन।

2017, अप्रैल 21– डीम्ड विश्वविद्यालयों के कामकाज की यूजीसी समीक्षा के लिए मसौदा तैयार करना।

जुलाई 2017– स्थापना दिवस व्याख्यान 2017 के लिए आमंत्रितों की सूची तैयार की।

2017, सितंबर 08– वरिष्ठ कंसल्टेंट, कंसल्टेंट और कनिष्ठ कंसल्टेंट के पदों के लिए प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग।

राष्ट्र भाषा समिति, 2017

संचालन समिति, 2018–19

सत्र और व्याख्यान

30 दिसंबर, 2017, आईएएसई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी 'साइकोसोशल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशनः ए एक्सप्लोरेशन इन एक्शन रिसर्च एंड ग्राउंड्ड थ्योरी रिसर्च'' पर 30 दिसंबर, 2017 को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में ग्राउंड थ्योरी रिसेर्च पर आमंत्रित विशेषज्ञ वक्ता।

19–20 जनवरी, 2018 को भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज (बीएसएसएस) में 'इन्नोवेशन इन टीचिंग लेर्निंग प्रोसेस – इंफुजन ऑफ आईसीटी – रिसर्च इन टीचिंग लेर्निंग एंड इवैल्यूएशन' नामक राष्ट्रीय संगोष्ठी में उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए IQAC की भूमिका पर प्लेनरी सेशन पर आमंत्रित विशेषज्ञ वक्ता।

30 जनवरी – 01 फरवरी, 2018, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला 'शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए शिक्षण और शिक्षण का निर्माण दृष्टिकोण'' पर में आमंत्रित वक्ता।

13 फरवरी, 2018 – शिक्षा नीति विभाग, नीपा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी 'अर्बन मार्जिनलिटी' पर 12–13 फरवरी 2018 को 'न्यू इंस्टिटूशंलिज्म – स्कूलिंग फॉर द अर्बन मार्जिनलाइज्डः इनसाइट फ्राम वाराणसी' पर आमंत्रित वक्ता।

06 जनवरी, 2018 – केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आइएएसई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला 'सायकोलोजिकल पेर्स्पेक्टिव इन एजुकेशनः एन एक्स्प्लोरेशन थ्रू एक्शन रिसर्च एंड ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च" में विशेषज्ञ मेंटर के रूप में आमंत्रित।

10 मार्च, 2018 – केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आइएएसई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय सिंपोजियम 'सायकोलोजिकल पेर्स्पेक्टिव इन एजुकेशनः एन एक्स्प्लोरेशन थ्रू एक्शन रिसर्च एंड ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च" में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित।

22 मार्च, 2018 – समाजशास्त्र विभाग, लक्ष्मीबाई कालेज, दिल्ली में 'प्राइवेट स्कूलिंग एंड द एजुकेशन ऑफ द मार्जिनलइज्ड" में आमंत्रित वक्ता।

अन्य

सिंह, अवनीश के, मंजू नरूला, मलिक और नरेश कुमार. 2018 'एवल्यूशन ऑफ द इंप्लेमेंटेशन ऑफ द स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मद्रास (एसपीक्यूईएम): ए रिपोर्ट' मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सौंपी गई।

विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग

प्रणति पंडा

प्रकाशन

पुस्तकें/अध्याय

भारत में स्कूल शिक्षा और जवाबदेही: वर्तमान नीतियों और प्रथाओं का मानचित्रण. (2017)। जैकब ईस्ले II और पियरे तुलोवित्स्की (सं.): शैक्षिक जवाबदेही: समालोचना के लिए एक प्रतिक्रिया; अंतरराष्ट्रीय सोच को आगे बढ़ाते हुए। अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस स्कूल प्रभावशीलता और सुधार के लिए: ऑस्ट्रेलिया

स्कूल मानक और मूल्यांकन दस्तावेज

बाह्य–स्कूल मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश (2018). स्कूल मानक और मूल्यांकन एकक, नीपा: नई दिल्ली (अंग्रेजी और हिंदी दोनों)।

शाला सिद्धि: प्रगति और कार्यान्वयन पर राज्य की विशिष्ट रिपोर्ट (2017)। स्कूल मानक और मूल्यांकन एकक, नीपा: नई दिल्ली।

शाला सिद्धि: राज्य विशिष्ट विद्यालय स्व मूल्यांकन ग्रेडिंग रिपोर्ट (2017)। स्कूल मानक और मूल्यांकन एकक, नीपा: नई दिल्ली।

स्कूल प्रदर्शन विश्लेषण पर राष्ट्रीय रिपोर्ट: विकास, प्रगति और कार्यान्वयन, स्कूल मानक और मूल्यांकन एकक, नीपा: नई दिल्ली।

शाला सिद्धि: स्कूल सेल्फ इवैल्यूएशन एनालिटिक्स महाराष्ट्र, (2017)। स्कूल मानक और मूल्यांकन एकक, नीपा: नई दिल्ली।

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाओं में भागीदारी

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय

20 फरवरी, 2018 को सलाहकार समिति, नीपा, नई दिल्ली की बैठक में शाला सिद्धि कार्यक्रम की प्रगति और उपलब्धि प्रस्तुत और साझा की,

22 फरवरी, 2018 को नई दिल्ली में एसएसईपी के संबंध में डीओईऔर अन्य स्थानीय निकायों के उच्च अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया।

7–8 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली में कुलपतियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए नेतृत्व विकास पर कार्यशाला में भाग लिया।

6–7 फरवरी, 2018 को पुणे मेंशैक्षिक योजना और प्रशासन पर जिला और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में एक विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया।

6 सितंबर, 2017 को शिक्षक शिक्षा निदेशालय और एससीईआरटी, ओडिशा में भाग लिया।

7 मार्च, 2018 को नीपा, नई दिल्ली में एनसीएसएल राष्ट्रीय सलाहकार समूह की बैठक (2017–18) में भाग लिया।

26–28 फरवरी, 2018 को नई दिल्ली में विश्वविद्यालय प्रशासकों के लिए उच्च शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम में एक विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित।

30–31 अगस्त, 2017 को डीईओ और बीईओ, चेन्नई के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन पर राज्य स्तरीय सम्मेलन में एक विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया।

17–21 जुलाई, 2017 को थिंकटैंक के सदस्य के रूप में भाग लिया और ओडिशा के शिक्षक शिक्षा संस्थानों

(टीईआई) के प्रमुखों के लिए शिक्षक–शिक्षा की योजना पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

व्यापक स्कूल सुरक्षा – भविष्य की आवश्यकता और समय की आशा', विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, 14 मार्च, 2018 को सत्र लेने के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किया गया।

डीईओ और बीईओ, पुणे, महाराष्ट्र के लिए 6 फरवरी, 2018 को शैक्षिक योजना और प्रशासन पर राज्य स्तरीय सम्मेलन में एक विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित।

जिला, ब्लॉक, और क्लस्टर स्तर, पुराने सचिवालय, दिल्ली में 22 फरवरी, 2018 को सेवानिवृत्त स्कूल प्राचार्यो और अधिकारियों के लिए राज्य मानक समिति के लिए राज्य कोर समिति में बाह्य मूल्यांकन पर एक व्याख्यान दिया।

स्कूल मानकों और मूल्यांकन (शाला सिद्धि) पर एक सत्र लेने के लिए एक वक्ता के रूप में आमंत्रितः स्कूल सुधार के प्रति एक पहल; एनआइएलईआरडी से नीपा, नीपा, 23 फरवरी, 2018 को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा।

अनुसंधान अध्ययन और परियोजनाएं

प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएँ/सम्मेलनों का आयोजन

15–16 मार्च, 2018 को, शासन, विनियमन और शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन और समन्वय।

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (नीपा)

स्कूल स्व–मूल्यांकन (शाला सिद्धि) पर राज्य विशिष्ट क्षमता निर्माण कार्यक्रमः

21– 24 जून, 2017को महाराष्ट्र में 48 प्रतिभागियों के लिए शाला सिद्धि पर स्कूल स्व–मूल्यांकन क्षमता निर्माण कार्यक्रम का समन्वय और संचालन।

03–04 जून, 2017 को हरियाणा में 525 शिक्षक प्रशिक्षकों, शिक्षाधिकारियों और स्कूल प्रमुखों के लिए शाला सिद्धि (स्कूल स्व–मूल्यांकन) पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन।

15 सितंबर, 2017 को राजस्थान में 55 शिक्षक प्रशिक्षकों, शिक्षाधिकारियों और स्कूल प्रमुखोंके लिए शाला सिद्धि पर स्कूल स्व–मूल्यांकन क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए सुविधाएं प्रदान की एवं संचालन किया।

19–20 सितंबर, 2017 को बिहार में 250 शिक्षक प्रशिक्षकों, शिक्षाधिकारियों और स्कूल प्रमुखों लिए शाला सिद्धि (स्कूल स्व–मूल्यांकन) पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया।

15 दिसंबर, 2017 को हिमाचल प्रदेश में 58 शिक्षक प्रशिक्षकों, शिक्षाधिकारियों और स्कूल प्रमुखों के लिए शाला सिद्धि पर स्कूल स्व–मूल्यांकन क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए सुविधाएं प्रदान की एवं संचालन किया।

28–29 दिसंबर, 2017 को जम्मू और कश्मीरमें 45 शिक्षक प्रशिक्षकों, शिक्षाधिकारियों और स्कूल प्रमुखों के लिए शाला सिद्धि (स्कूल स्व–मूल्यांकन) पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का समन्वयन एवं संचालन।

27–28 मार्च, 2017 को ओडिशा में 70 शिक्षक प्रशिक्षकों, शिक्षाधिकारियों और स्कूल प्रमुखों के लिएशाला सिद्धि (स्कूल स्व–मूल्यांकन) पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया।

वेब पोर्टल विकास और प्रबंधन पर कार्यशालाएँ

शाला सिद्धि, 2017, नीपा, नई दिल्ली के लिए उन्नत सुविधायुक्त वेब पोर्टल विकास पर कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम निर्माण/संचालन

भारत में शिक्षा पर एम.फिल. एवं पीएचडी के लिए एक आधार पाठ्यक्रम (मुख्य पाठ्यक्रम–2) विकसित किया।

स्कूल मानक और मूल्यांकन एकक (शाला सिद्धि), नीपा, नई दिल्ली पर राष्ट्रीय कार्यक्रम पर रणनीतिक योजना और निगरानी रूपरेखा विकसित किया।

स्कूल मानक और मूल्यांकन एकक, नीपा, नई दिल्ली के लिए स्कूल बाह्य मूल्यांकन दिशानिर्देशतैयार किया।

अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ

एम. फिल. के लिए और पीएचडी कार्यक्रम मुख्य पाठ्यक्रम (सीसी–2) 'भारत में शिक्षा' का संयोजन एवं शिक्षण।

पोस्ट–डॉक्टरल फैलोशिप के लिए समिति की बैठक में पोस्ट–डॉक्टोरल फैलोशिप प्रस्ताव की समीक्षा करना।

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहयोग

8 नवंबर, 2017 को विशाखापट्टनम में आपदा प्रबंधन पर तृतीय विश्व कांग्रेस को विस्तारित शैक्षणिक समर्थन।

18 दिसंबर, 2017 को केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन समिति, नई दिल्ली की बैठक में एक विशेषज्ञ।

10 मार्च, 2018 को पटना विश्वविद्यालय में बाह्य विशेषज्ञ के रूप में चयन समिति की बैठक में भाग लिया।

अनुसंधान पर्यवेक्षक

शोधार्थी शादमा अबसर की पीएचडी "पर्यवेक्षण स्कूल प्रमुखों के नेतृत्व का अध्ययन और शिक्षकों के कार्य व्यवहार पर इसके प्रभाव" को सुपरवाइज किया।

शोधार्थी साक्षी कालरा की पीएचडी "समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक–पूर्व तैयारीः प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में नीतियों और प्रथाओं का अध्ययन" को सुपरवाइज किया।

नीपा से बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

सदस्य, जर्नल सलाहकार बोर्ड, एनसीटीई

सदस्य, एससीईआरटी, नई दिल्ली के कार्यक्रम सलाहकार बोर्ड

सदस्य, शिक्षक शिक्षा अनुमोदन बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

सदस्य, कार्यकारी बोर्ड, आरएमएसए (टीसीए)

सदस्य, कार्यकारी बोर्ड, शिक्षक शिक्षा में सुधार, यूनिसेफ और एससीईआरटी, पुणे

सदस्य, केडी जर्नल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी (केजेईपी) के अंतरराष्ट्रीय संपादकीय बोर्ड

सदस्य, स्कूल प्रभावशीलता और सुधार पर अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस

सदस्य, भारतीय शिक्षक शिक्षक संघ

संस्थापक सदस्य, इंटरनेशनल फोरम ऑफ रिसर्चर्स इन एजुकेशन (आइआरओआरई)

सदस्य, पूर्व छात्र संघ, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली

आजीवन सदस्य, अखिल भारतीय शैक्षिक अनुसंधान संघ

मधुमिता बंद्योपाध्याय

प्रकाशन

पुस्तक में अध्याय

'भारत में प्राथमिक शिक्षा में सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताः समावेशी कक्षाओं की गतिशीलता में पुनरावलोकन और संभावना' भारत में सामाजिक विविधता, असमानता और स्कूली शिक्षा। मनोज के. तिवारी, संजय कुमार, अरविंद के मिश्रा, ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली, 2017 आईएसबीएनः 9789352870134 द्वारा संपादित।

अंतर–क्षेत्रीय परिवर्तन के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, भारतीय शिक्षा में प्रमुख मुद्दे में सं. अजित मंडल, कलपाज़ प्रकाशन, 2017, आई.एस.बी.एन.रू 978–93–512–8259–4.

भारत में प्रारंभिक शिक्षा में पहुंच और समता, शिक्षा का अधिकार और स्कूल पर दीपा इदनानी की पुस्तक में, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, भारत, 2017, आई.एस.बी.एन. 978–81–316–0839–5.

रिपोर्ट अवधि में प्रकाशित शोध पत्र/आलेख

'टीचर्स एंड टीचर एजुकेशन इन इंडियाः इश्यूज, ट्रेंड एंड चैलेंजेज' एडुलाइट में अंक–6, अंक 11, मई 2017।

'क्वान्टिटी, क्वालिटी एंड एक्यूटी इन सेकंडरी एजुकेशन इन इंडिया' भारतीय सामाजिक विज्ञान, IASSI, वाल्यूम 36, संख्या–4, अक्टूबर–दिसंबर, 2017।

''प्रसेन्ट स्टेट्स आफ इन्फ्रास्ट्राक्चर फैसीलीटीज़ इन स्कूलस्स इन इंडियाः फ्राम नेशनल एंड स्टेट लेवल पर्सपेक्टिक्स, सरकारी स्कूलों में सुधार हेतु के उप–समिति के लिए प्रारूप तैयार, 2017, डाईस वेबसाईट पर प्रकाशित, http://www.dise.in/downloads/paper on physical facilities (Draft prepared for Cobe) Report. pdf

दसवीं एंट्रीप नीति संगोष्ठी और सदस्य बैठक, एंट्रीप न्यूज़लेटर, सं. जिल्द 23, अंक 2, जुलाई–दिसंबर 2017, नीपा, नई दिल्ली

विद्यालयों में शिक्षण–अधिगम हेतु आई.सी.टी. का अनुप्रयोग एंट्रीप न्यूज़लेटर, सं. जिल्द 23, अंक 1, जनवरी–जून 2017, नीपा, नई दिल्ली

रिपोर्ट अवधि में संगोष्ठियों/सम्मेलनों में सहभागिता

संस्थान अमीनुद्दीन बकी (IAB), मलेशिया में 3–5 मई, 2017 को 'डेमोग्राफिक चेंजेसः वॉट आर द इंप्लीकेशन फॉर एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्लानिंग?' पर वार्षिक नीति संगोष्ठी में सहभागिता।

उच्च शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम के प्रथम सत्र की रिपोर्ट तैयार करी, 26–28 फरवरी 2018, होटल प्राईड प्लाजा, ऐरो सिटी, नई दिल्ली

सार्वजानिक निकाय को परार्मशकारी एवं अकादमिक सहायता

भारत मे बालिका शिक्षा पर केब उप समिति की बैठक में भागीदारी, 2017

11 जनवरी 2018 को आर.टी.एक्ट 2009 के अंतर्गत बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा–प्री–स्कूल शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा पर केब उप–समिति की बैठक में भाग लिया।

नीपा से बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

भारत के तुलनात्मक शिक्षा समुदाय की आजीवन सदस्यता (CESI)

दिल्ली के गैर सरकारी संगठन ASPIRE भारत, की सदस्यता

BAICE, यूके के सदस्य

कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षिक अनुसंधान के भारतीय जर्नल के सलाहकार बोर्ड के सदस्य

अन्य

एन्ट्रीप के लिए नीपाके फोकल पॉइंट और एन्ट्रीप न्यूजलेटर के संपादक।

स्कूली शिक्षा में जैंडर मुद्देः एंट्रीप न्यूज़लेटर का संपादनः वर्तमान नीति और व्यवहार, जिल्द 22, अंक 2, जुलाई दिसंबर 2016, नीपा नई दिल्ली आई.एस.एस. एन. 0972–7507

'स्कूलों में टीचिंग–लर्निंग के लिए आईसीटी का उपयोग' और 'द दसवीं एन्ट्रीप नीति संगोष्ठी और सदस्यों की बैठक', एन्ट्रीप न्यूजलेटर अंक–23, नं. 1–2, जनवरी–जून, 2016 और जुलाई–दिसंबर, 2016, नीपा, नई दिल्ली के संपादक।

कोर्सवर्क (अनुसंधान पद्धति) पर एम.फिल. कक्षाओं में अध्यापन।

'प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शैक्षिक पहुँच और भागीदारी की वर्तमान स्थितिः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का तुलनात्मक अध्ययन' पर शोध परियोजना पूरी की।

'भारत में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की भागीदारी में सुधार के लिए पार्टीशिपेटरी एक्शन रिसर्च' पर अनुसंधान परियोजना।

एम.फिल. कोर्स वर्क के पुनरीक्षण हेतु समन्वय और भागीदारी, सी.सी. 5, अनुसंधान पद्धति कोर्स (गुणात्मक पद्धति) ओ.सी. 5ः सामुदायिक भागीदारी और शिक्षा में स्थानीय अभिशासन तथा ओ.सी. 9ः शिक्षा, जेंडर तथा विकास

उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग

सुधांशु भूषण

प्रकाशन

भूषण एस और वर्मा ए, 2017 "उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन – एक भारतीय अनुभव", महसूद शाह क्वीन डू, द राइज ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन एशियन हायर एजुकेशन, चंदोस प्रकाशन।

प्रस्तुत प्रपत्र

30–31 मार्च, 2018 को AJK कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, कोयंबटूर में 'परिणाम आधारित शिक्षा' पर एक दिवसीय कार्यशाला में परिणाम–आधारित शिक्षा पर एक प्रपत्र प्रस्तुत किया।

22 दिसंबर, 2017 को दिल्ली विश्वविद्यालय के एसजीटीबी खालसा कॉलेज में टीचिंग लर्निंग सेंटर में एक फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में 'उच्च शिक्षा के मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर व्याख्यान दिया।

19 दिसंबर, 2017 को AIFUCTO 29वें वैधानिक सम्मेलन में 'सुधार उच्च शिक्षाः चुनौतियां और अवसर' में मुख्य वक्तव्य प्रस्तुत किया।

18–22 दिसंबर, 2017 के दौरान पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम में XLI भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस में, 'उच्च शिक्षा वित्तपोषण का भविष्य' पर एक पत्र प्रस्तुत किया।

कार्यशालाओं में भागीदारी

18–19 अप्रैल, 2017 को दिशानिर्देश तैयार करने के लिए आईसीएआर मान्यता के एक सदस्य के रूप में भाग लिया।

10 अप्रैल, 2017 को ऑस्ट्रेलिया–भारत नॉलेज पार्टनरशिप्स राउंडटेबल में 'नियोजन एवं गतिशीलता' पर एक पैनल चर्चा की सह–अध्यक्षता की।

11 अप्रैल, 2017 को साझा अनुसंधान प्राथमिकताओं और मानव पूंजी विकास में संभावित साझेदारी का पता लगाने के लिए वरिष्ठ गो 8 प्रतिनिधियों के साथ संगोष्ठी में भाग लिया।

28–30 दिसंबर, 2017 को सोसायटी फॉर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नई दिल्ली में कॉलेजों के प्रधानाध्यापकों के राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व विकास में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य किया।

7 मार्च, 2018 को आईएचसी दिल्ली में एनआरसीई गतिविधियों को प्रस्तुत करने के लिए पीएमएमएमएनएमटटी की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

8–9 मार्च, 2018 को नीपा में "भारत में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ावः स्वायत्तता एक विचार और इसकी परंपरा" पर राष्ट्रीय कार्यशाला में अध्यक्षता सत्र।

6 अप्रैल, 2018 को आइआइएसईआर, भोपाल में एनआरसीई गतिविधियों को प्रस्तुत करने के लिए पीएमएमएमएनएमटीटी की दूसरी क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

आरती श्रीवास्तव

प्रकाशन

श्रीवास्तव, आरती. (2017). टॉम ड्वायर एड में 'यूथ, एजुकेशन, एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडियाः हार्वेस्टिंग गोल्ड'. ब्रिक्स देशों में युवाओं की समाजशास्त्र की पुस्तिका; विश्व वैज्ञानिक।

सह–संपादित पुस्तक, 'द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन लर्निंग एंड टीचिंग', भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई क्रॉस सांस्कृतिक सहयोग, 2017।

श्रीवास्तव, आरती और जोन एम. लिंड. (2017). 'वुमेन इन हायर एजुकेशन रिसर्च' पुस्तक – 'फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन लर्निंग एंड टीचिंग – इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रॉस कल्चरल सहयोग'।

श्रीवास्तव, आरती. (2018). 'फाइनेंसिंग एंड क्वालिटीः द रिहापिंग ऑफ हायर एजुकेशन', भारत उच्चतर शिक्षा रिपोर्ट 2018।

श्रीवास्तव, आरती और एस घोष. (2017). हायर एजुकेशन इन इंडियाः हाऊ डाटा कैन ट्रान्स्फोर्म, एजुकेशन इंडिया जर्नल; अगस्त, वाल्यूम–6 (3), 3–17, आईएसएसएन 2278–2435।

श्रीवास्तव, आरती और एस. घोष. (2017).हायर एजुकेशनः इंपीरियल फॉर पॉलिसी, द साइनेज, जनवरी–जून, अंक, 5 (1), 18–29, ISSN 2321–6530।

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाओं में भागीदारी

14–16 अप्रैल, 2017 को सीसीएस विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा आयोजित "वैश्वीकरण और कल्याण" पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

अप्रैल 2017 को सेंटर फॉर रशियन स्टडीज, एसआईएस, जेएनयू द्वारा ब्रिक्स विश्वविद्यालय की स्थापना पर प्रपत्र आमंत्रित।

अप्रैल 2017 को 'लुक–ईस्ट पॉलिसी', CLMV, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय उद्योगपतियों द्वारा सेवा उद्योग में संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किया गया।

मई 2017 को 'उच्च शिक्षा में आईसीटी' पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्य रूप से आमंत्रित।

नीपाद्वारा जुलाई 2017 में आयोजित "उच्च शिक्षा में समानता" पर कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति।

उच्च शिक्षा पर एफ.एम. 102.6 रेडियो टॉक, अगस्त 2017।

कार्यशाला 'उच्च शिक्षा में नेतृत्व विकास के लिए कार्यक्रम के लिए मॉड्यूल का विकास', जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली, सितंबर 2017।

अल्मोनी एसोसिएशन ऑफ जेएनयू (एएजे) के भाग के रूप में 'नई शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों की बैठक' का आयोजन 24 सितंबर, 2017 को किया गया।

'उच्च शिक्षा में अनुसंधान' पर विशेष बातचीत (इनसाइट) के लिए लोकसभा चौनल पर पैनलिस्ट।

अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली के होटल हयात रीजेंसी में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित एजुकेशन कॉन्क्लेव के 6वें संस्करण में भाग लिया।

'उच्च शिक्षा में वित्त पोषण पर विशेष पाठ्यक्रम', इंफाल, मणिपुर, अक्टूबर 2017 में संसाधन व्यक्ति।

नवंबर 2017 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा आयोजित "चिंतनशील शिक्षक" पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

दिसंबर 2017 में अमर सिंह कॉलेज, श्रीनगर द्वारा संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

जनवरी 2018 में बनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान द्वारा आयोजित फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

जनवरी 2018 में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा द्वारा आयोजित 'निर्माण और मूल्यांकन' पर संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

24 जनवरी, 2018 को ललित, नई दिल्ली में भारत सरकार के साथ साझेदारी में फिक्की द्वारा आयोजित भारत सरकार–आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत–आसियान व्यापार परिषद मंच और 'मेकांग गंगा सहयोग (एमजीसी) व्यापार मंच' में भाग लिया।

19 फरवरी, 2018 को राष्ट्रीय श्रम संस्थान में संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

22–23 फरवरी, 2018 को सीपीआरएचई और नीपा, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता' विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगो'ठी में भाग लिया गया।

24 फरवरी, 2018 को 'विश्वविद्यालय शिक्षा में महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धियाँ : नीतियां और विधान', पर जेएमआई में व्याख्यान।

समन्वयक, रजिस्ट्रार मीट (पीएमएमएनएमटीटी योजना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्राइड प्लाजा), 26–28 फरवरी, 2018।

27 फरवरी, 2018 को टीआईएफएसी द्वारा आयोजित 'रोडमैप फॉर एजुकेशन 2035' पर पहली प्रसार कार्यशाला में भाग लिया।

पीएमएमएमएनएमटीटी योजना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 7 मार्च, 2018, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली के पहली क्षेत्रीय कार्यशाला (उत्तरी क्षेत्र) के लिए संसाधन व्यक्ति।

8 मार्च, 2018 को सीआईईई दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली में संगोष्ठी में एक सत्र के लिए अध्यक्ष।

8–9 मार्च, 2018 को नीपा पर उच्च शिक्षा में स्वायत्तता पर कार्यशाला 'भारत में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के साथ संलग्नः स्वायत्तता का विचार और अभ्यास', में समूह कार्य के लिए सत्र अध्यक्ष।

16 मार्च, 2018 को नीपा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 'शिक्षक शिक्षा में विनियमन, और गुणवत्ता आश्वासन' में'शिक्षक शिक्षा में प्रमुख नीतिगत बदलाव : परिवर्तन प्रबंधन पर कार्यान्वयन' पर विषयगत सत्र के लिए पैनलिस्ट।

29 मार्च, 2018 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ टीएलसी में 'मूल्यांकन प्रारूप और रणनीतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए, मूल्यांकन के बुनियादी अवधारणाओं के परिचय' सत्र मेंसंसाधन व्यक्ति।

25–26 मार्च, 2018 को टीचिंग लर्निंग सेंटर, भटिंडा में संसाधन व्यक्ति।

प्रस्तुत प्रपत्र

19–20 अप्रैल, 2017 को जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली में 'एशिया में शासन, मानवाधिकार और क्षेत्रीय सहयोग के अवसरः भूमंडलीकरण के अवसर और चुनौतियां' विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 'कौशल अंतराल के बीच युवा' पर एक पत्र प्रस्तुत किया।

29 अगस्त, 2017 को ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस वीक में सीआईआई बैठक के लिए 'महिला और नेतृत्व' पर एक पत्र प्रस्तुत किया।

7 सितंबर, 2017 को आईईए संगोष्ठी 'महिला और उच्च शिक्षा में नेतृत्वः ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग' पर एक प्रपत्र प्रस्तुत किया।

6–7 अक्टूबर, 2017 को लेखकों की बैठक में 'भारत में कॉलेजों की संस्थागत जीवनीः शताब्दी' पुस्तक के लिए 'सेंट जोंस कॉलेज आगरा का एक केस स्टडी' पर एक पत्र प्रस्तुत किया।

15–19 जनवरी, 2018 को नीपा में मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रमुखों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम में 'उच्च शिक्षा में शिक्षण शिक्षा' पर एक पत्र प्रस्तुत किया।

विभागीय कार्यक्रम आयोजन

जून 2017 के लिए ए.आई.एस.एच.ई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डेटा सपोर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया।

6–7 अक्टूबर, 2017 को (21 प्रतिभागियों) के लिए भारत में कॉलेजों की संस्थागत जीवनीः शताब्दी, पर आयोजित लेखक की कार्यशाला।

20–24 नवंबर, 2017 को (26 प्रतिभागियों) के लिए 'कॉलेज प्राचार्यों के लिए उच्च शिक्षा में शिक्षण–शिक्षा' पर एक विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन।

7–8 दिसंबर, 2017 को (70 से अधिक कुलपति सहभागी) के लिए उच्च शिक्षा में नेतृत्व विकास पर कुलपति बैठक का आयोजन किया।

2017–18 के दौरान प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम निर्माण/संचालन

एम.फिल/पीएचडी के लिए पाठ्यक्रम संचालन

अनिवार्य पाठ्यक्रम, सीसी–2

वैकल्पिक पाठ्यक्रम, ओसी–1

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहयोग

नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर एजुकेशन, नीपा, के समन्वयक

एम.फिल/पीएचडीके लिए प्रवेश परीक्षा समिति (नीपा)

एम.फिल/पीएचडी. प्रवेश परीक्षा (नीपा) के लिए मूल्यांकन समिति

नीपा में विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

नीपा से बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

निम्नलिखित निकायों के आजीवन सदस्यः

एसोसिएशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली (1999)

भारतीय ज्ञानपीठ परिवार, नई दिल्ली (1999)

भारतीय आर्थिक संघ (2004)

इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स (1998)

नेशनल बुक ट्रस्ट (1998)

यूपी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स (2003)

थियोसोफिकल सोसायटी, वाराणसी (2004)

सीईएसआई, नई दिल्ली (2010)

अखिल भारतीय शैक्षिक अनुसंधान संघ (2009)

इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एजुकेशन (2015)

भारतीय सामाजिक विज्ञान अकादमी (2016)

पीएचडी निर्देशन

पीएचडी – अपराजिता गंतायेत

पीएचडी– अनुनीता मित्रा

पीएचडी स्वाति वाघमारे

पीजीडेपा निर्देशनः अंजू तिन्ना, राजस्थान

नीरू स्नेही

प्रकाशन

शोध पत्र/आलेख/टिप्पणियाँ

'भारत में स्नातक शिक्षा में सुधारः क्या संस्थागत स्वायत्तता मुख्य विचारणीय विषय है?', संस्करण 6, अंक 12, पृ. 205–214, नवंबर 2017।

'तृतीयक क्षेत्र में संकाय विकासः वैश्विक प्रथाओं की समीक्षा', जामिया जर्नल ऑफ एजुकेशन, खंड 4, संख्या 2, मार्च 2018।

'उच्च शिक्षा पर डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव', विश्वविद्यालय समाचारः मानव मूल्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ उच्च शिक्षा में नवाचार, उद्यमशीलता और विघटनकारी प्रौद्योगिकी पर विशेष अंक 56 नं. 12, 19–25 मार्च, 2018।

प्रशिक्षण

22 जून, 2017 को नीपा, नई दिल्ली में 'एआईएसएचई' के सुधार के लिए समन्वित 'एआईएसएचई' पर मूल्यांकन अध्ययन' कार्यशाला का समन्वय।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में भागीदारी

राष्ट्रीय

7–8 सितंबर, 2017, नीपा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी 'फ्यूचर्स ऑफ हायर एजुकेशनः इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट' में 'तृतीयक क्षेत्र में संकाय विकासः वैश्विक प्रथाओं की समीक्षा' पर एक शोधपत्र प्रस्तुत किया।

6–7 अक्टूबर, 2017 को उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपा द्वारा आयोजित, 'कॉलेजों की संस्थागत आत्मकथाएँः शताब्दी' में भाग लिया और पुस्तक के फीडबैक कार्यशाला के दौरान 'केस स्टडी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर' पर एक पत्र प्रस्तुत किया।

16–18 नवंबर, 2017 को सीईएसआइ, वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू में 'इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस फॉर क्वालिटी हायर एजुकेशन' पर एक पत्र प्रस्तुत किया।

28 अक्टूबर – 3 नवंबर, 2017 को मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल में 'उच्च शिक्षा में विशिष्ट पाठ्यक्रम – उच्च शिक्षा का वित्त पोषण' में 'उच्च शिक्षा बजट मॉडल' पर एक पत्र प्रस्तुत किया।

'टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्यूएशन इन हायर एजुकेशन इमर्जिंग ट्रेंड्स' पर नेशनल वर्कशॉप में 'टीचिंग इवैल्यूएशन ऑफ टीचर लर्निंग स्ट्रेटेजीज इन हायर एजुकेशन' का

एक प्रपत्र पेश किया जो अब 20—21 दिसंबर, 2017 को अमर सिंह कॉलेज, श्रीनगर में निर्धारित है।

15—19 जनवरी, 2018 को नीपा में उच्च शिक्षा के मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रमुखों के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम में 'भारतीय उच्च शिक्षा में संकाय विकास' पर एक पत्र प्रस्तुत किया।

अंतरराष्ट्रीय

25—27 फरवरी 2018 को एरियल विश्वविद्यालय, इजराइल में "वर्चुअल हायर एजुकेशन कैंपस इन ए ग्लोबल वर्ल्ड — द रोल ऑफ एकेडमिक कैंपस इन एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस'', सम्मेलन में "टेक्नॉलॉजी इन टीचिंग लर्निंग एट इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस—प्रॉस्पेक्ट्स एंड चौलेंज' पर एक प्रपत्र प्रस्तुत किया।

सहभागिता

20—24 नवंबर, 2017 नई दिल्ली में को उच्च शिक्षा में टीचिंग एंड लर्निंग पर विशिष्ट पाठ्यक्रम में भाग लिया।

30 अक्टूबर — 3 नवंबर, 2017 को मणिपुर के इम्फाल में 3 उच्च शिक्षा में विशिष्ट पाठ्यक्रम — उच्च शिक्षा में वित्त पोषण में भाग लिया।

7—8 दिसंबर 2017 को प्राइड प्लाजा में नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कुलपति के लिए उच्च शिक्षा में नेतृत्व विकास कार्यशाला में भाग लिया और सत्र की रिपोर्ट तैयार की।

15—16 मार्च, 2018 को नीपा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी 'गवर्नेंस, रेगुलेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन टीचर एजुकेशन' में भाग लिया।

15—16 फरवरी, 2018 को नीपा, नई दिल्ली में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों (SHECs) की सलाहकार बैठक में भाग लिया।

22—23 फरवरी, 2018 को इंडिया हैबिटेशन सेंटर, नई दिल्ली में नीपा के सेंटर फॉर हायर एजुकेशन (सीपीआरएचई) द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 'क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन' में भाग लिया तथा एक सत्र की रिपोर्ट तैयार की।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

पर्यवेक्षण / मूल्यांकन

शालिनी तिवारी — एम.फिल., विषय 'भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अंतरराष्ट्रीयकरणः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का एक वैयक्तिक अध्ययन', स्नातक 2018

चेतन पंचोली, विषयः 'गुजरात के डांग जिले में केजीबीवी का अध्ययन' (पीजीडेपा)

पाठ्यक्रम समन्वय

पाठ्यक्रम 212 के संयोजकः आईडेपा में अनुसंधान पद्धति और सांख्यिकी

पाठ्यक्रम 902 के संयोजकः भारतीय शिक्षा — पीजीडेपा एक परिप्रेक्ष्य

शिक्षण

पाठ्यक्रम 212 के संचालन में शामिलः आईडेपा में अनुसंधान पद्धति और सांख्यिकी

पाठ्यक्रम 902 के संचालन में शामिलः भारतीय शिक्षा — पीजीडेपा एक परिप्रेक्ष्य

अन्य गतिविधियां

एम.फिल. और पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन करने के लिए समिति के सदस्य।

एम.फिल. और पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए मूल्यांकन समिति के सदस्य (नीपा)।

'वैश्विक दुनिया में आभासी उच्च शिक्षा परिसर?' पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की आयोजन समिति के सदस्य एरियल यूनिवर्सिटी, इजराइल, 25—27 फरवरी, 2018।

सदस्य, शैक्षणिक परिषद, नीपा

सदस्य, अध्ययन मंडल, नीपा

सदस्यता

आजीवन सदस्य, भारत की तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी (सीईएसआइ)

आजीवन सदस्य, तुलनात्मक और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (सीईएसआइ)

संगीता अंगोम

प्रकाशन

पत्रिकाओं में शोध पत्र/आलेख

'एजुकेशन फॉर फ्यूचर्सः इश्यूज एंड चौलेंजेस', नामक पुस्तक में एक पुस्तक अध्याय में ''भारतीय डॉक्टरेट शिक्षा के बदलते परिदृश्य', डी. बलरामुलु, आर.के. मूर्ति, जी. बालाजी और श्रीनिवास दासु द्वारा संपादित, प्रकाशक– कैंडियन अकादमिक प्रकाशन, इंडिया लिमिटेड जुलाई 2017

'उच्च शिक्षा और व्यावसायिक नैतिकताः शिक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ' नामक पुस्तक में 'उच्च शिक्षा के लिए शैक्षणिक सुधारों में शिक्षकों की भूमिका', सत्य सुंदर सेठ द्वारा संपादित, रूटलेज इंडिया 2018।

कार्यशालाएँ/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

30 अक्टूबर–3 नवंबर, 2017 को शिक्षक शिक्षा विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल में उच्च शिक्षा में वित्त पोषण में पांच दिवसीय 'विशिष्ट पाठ्यक्रम' का समन्वय।

संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भागीदारी

राष्ट्रीय

7–8 सितंबर, 2017 को राष्ट्रीय और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपा, द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला 'उच्च शिक्षा के भविष्यः आर्थिक और सामाजिक संदर्भ', के दौरान 'एक विश्वविद्यालय के विचारः भारतीय निजी विश्वविद्यालयों के संदर्भ' पर एक शोधपत्र प्रस्तुत किया।

23–24 नवंबर, 2017 को नॉर्थ ईस्ट इंडिया एजुकेशन सोसाइटी (NEIES) के वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में शिक्षा विभाग, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश में 'पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिपः ए रिफॉर्म फॉर क्वालिटी हायर एजुकेशन' पर भाग लिया और प्रपत्र प्रस्तुत किया।

6–7 अक्टूबर, 2017 को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपा द्वारा आयोजित पुस्तक के फीडबैक कार्यशाला के दौरान 'सेंट जोसेफ कॉलेज, दार्जिलिंग के वैयक्तिक अध्ययन' पर भाग लिया और एक प्रपत्र प्रस्तुत किया–'कॉलेजों की संस्थागत आत्मकथाएँः शताब्दी'।

11–15 सितंबर, 2017 को एनई में गुवाहाटी में शिक्षा नीति विभाग द्वारा आयोजित अभिविन्यास कार्यशाला 'स्थानीय प्राधिकरण और स्वायत्त परिषद के कामकाज परः प्राथमिक शिक्षा, उत्तर–पूर्वी राज्यों के प्रबंधन में संविधान की छठी अनुसूची के दौरान 'पूर्वोत्तर में शिक्षा परिदृश्य (स्कूल)ः समस्याएँ एवं संभावनाएँ'' मुद्दे पर व्याख्यान दिया।

23 सितंबर, 2017 को मणिपुर अनुसंधान मंच, एसएसएस–1 जेएनयू, नई दिल्ली में 'भारत में निजी विश्वविद्यालयः विकास की स्थिति और चिंता' पर आमंत्रित व्याख्यान।

12–13 मार्च, 2018, पूर्वोत्तर अध्ययन और नीति अनुसंधान, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली में केंद्र के लिए आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 'इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसीः नीड्स एंड प्रीओरिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड म्यांमार' में 'एक्ट ईस्ट पॉलिसीः रीथिंकिंग द नॉर्थ ईस्ट इंडिया हायर एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट' पर एक प्रपत्र प्रस्तुत किया।

2–3 मार्च, 2017 को नीति विभाग, नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित नीपा (113), 'स्वदेशी ज्ञान प्रणाली और युवा सशक्तिकरण' पर नीति संगोष्ठी में भाग लिया।

शैक्षिक नीति विभाग, नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'भारत में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ावः विचार और स्वायत्तता का अभ्यास' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया।

15–16 फरवरी, 2018 को सीपीआरएचई, नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा के राज्य परिषदों के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों की परामर्शी बैठक के दौरान भारत में निजी विश्वविद्यालयों पर अनुभवजन्य अनुसंधान में भाग लिया और प्रमुख निष्कर्षों को प्रस्तुत किया।

7–8 दिसंबर, 2017, होटल प्राइड प्लाजा, नई दिल्ली में नीपा द्वारा आयोजित "लीडरशिप डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन" पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला के एक सत्र में भाग लिया और रिपोर्ट किया।

20–24 नवंबर, 2018 को उच्च शिक्षा विभाग, नीपा, 2017 द्वारा आयोजित, नीपामें 'उच्च शिक्षा में शिक्षण और शिक्षण पर विशेष पाठ्यक्रम'' कार्यक्रम में भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय

8–9 जुलाई, 2017 को शिक्षा विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में उच्च शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ''भारत में डॉक्टरेट अध्ययन के बदलते परिदृश्य' पर एक प्रपत्र प्रस्तुत किया।

16–18 नवंबर, 2017 को जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू में भारत की तुलनात्मक शिक्षा सोसाइटी (CESI) (सीईएसआइ) वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन "भारत में उच्च शिक्षा के निजीकरणः रुझान और परिणाम" पर एक पत्र प्रस्तुत किया।

23 सितंबर, 2017, मणिपुर रिसर्च फोरम, एसएसएस–1 जेएनयू, नई दिल्ली में ''भारत में निजी विश्वविद्यालयः विकास की स्थिति और चिंता'' पर व्याख्यान।

25–27 फरवरी 2018 को एरियल विश्वविद्यालय, इजराइल में "वर्चुअल हायर एजुकेशन कैंपस इन ए ग्लोबल वर्ल्ड'', सम्मेलन में "इंडियन यूनिवर्सिटीजः अंडरस्टैंडिंग इट्स एक्सपिरियन्स इन टेक्नोलोजिकल एज" पर एक प्रपत्र प्रस्तुत किया।

22–23 फरवरी, 2018 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में सीपी–23, नीपा द्वारा आयोजित "क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन" नामक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

17–18 जून 2017 को आईआईसी, नई दिल्ली में सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'समावेशी विकास शिक्षा की दिशा में सतत विकास लक्ष्य 4 और केरल मॉडल से सीख' के दौरान ''सब–थीम 4 स्कूल फॉर फाउंडेशन फॉर इनक्लूसिव स्किल्स डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज' सत्र की रिपोर्टिंग की।

अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ

एम.फिल. पर्यवेक्षण

1. अभिषेक पांडेय की एम.फिल. का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन–'शासन की समस्या और विश्वविद्यालयों का उभरनाः उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में भारत और ऑस्ट्रेलिया का तुलनात्मक अध्ययन', 2018।

नीपा प्रशिक्षुओं का पर्यवेक्षण

1. चतुर्थ–पीजीडेपा प्रतिभागी एच.बी. थिन्सन ऐनल के शोध कार्य का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन, 'जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, चंदेल, मणिपुर का एक वैयक्तिक अध्ययन'।
2. आईडेपा–34 प्रतिभागी हेलेलुले गेटनेट 'इथियोपिया, के शोध कार्य का पर्यवेक्षण, 'शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया पर आईसीटी/प्रौद्योगिकी का प्रभावः अदिस अबाबा विश्वविद्यालय का एक वैयक्तिक अध्ययन'।

पाठ्यक्रम समन्वयक

पाठ्यक्रम 201 के समन्वयक, आईडेपाः विषयगत संगोष्ठी

पाठ्यक्रमों के संचालन में शामिल

आईडेपा

पाठ्यक्रम 212 के संचालन में शामिल – अनुसंधान पद्धति और सांख्यिकी

पीजीडेपा कार्यक्रम

पाठ्यक्रम 906 में शामिलः प्रतिभागियों की संगोष्ठी

पाठ्यक्रम 905 के संचालन में शामिलः अनुसंधान पद्धति और सांख्यिकी

पाठ्यक्रम 902 के संचालन में शामिलः भारतीय शिक्षाः एक परिप्रेक्ष्य

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकास

उच्च शिक्षा में वित्त पोषण पर उच्च शिक्षा मॉड्यूल विकसित

नीपा समिति के सदस्य

परीक्षा समिति के सदस्य, नीपा

नीपा से बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

आजीवन सदस्य, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एजुकेशन सोसाइटी, शिलांग (NEIES)

आजीवन सदस्य, भारत की तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी (CESI)

आजीवन सदस्य, तुलनात्मक और अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक सोसायटी (CESI)

25–27 फरवरी, 2018, एरियल यूनिवर्सिटी, इजराइल में 'वर्चुअल वर्ल्ड एजुकेशन कैंपस इन ए ग्लोबल वर्ल्ड?' पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की आयोजन समिति के सदस्य।

शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग

अरुण सी मेहता

प्रकाशन

भारत में प्राथमिक शिक्षा, हम कहाँ खड़े हैं, यू–डाईस फ्लैश सांख्यिकी 2015–2016, नीपा, नई दिल्ली

यू–डाईस सफलता पर एक ओलख तैयार किया।

नीपा समसामयिक पत्र श्रृंखला के तहत भारत में ई.एम. आई.एस. को मजबूत करने में यू–डाईस की भूमिका पर एक आलेख प्रस्तुत, जनवरी 2018

संगोष्ठियों / सम्मेलनों / कार्यशालाओं में भागीदारी

यू–डाईस और छात्र आंकड़ा आधार प्रबंधन और आंकड़ा ग्रहण प्रारूप पर राष्ट्रीय कार्यशाला में एक सत्र 5–8 जुलाई, 2017, होटल टीजे विवेन्ता, सूरजकुण्ड, फरीदाबाद।

गूगल उपयोगकर्त्ता अध्ययन में भाग लिया, राज, 13 सितम्बर, 2017

शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। नियो–लिबरल टाइम्स, बुनियादी सरोकार और महत्वपूर्ण मुद्दों में नीतिगत बदलाव, गार्गी कॉलेज, दिल्ली, 14 और 15 सितंबर, 2017

शैक्षिक योजना और प्रशासन पर राज्य शिक्षा अधिकारियों और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के लिए स्कूल प्रशासन और सुधार के लिए, आंकड़ा प्रबंधन पर एक आलेख प्रस्तुत, राज्य स्तर पर एक सम्मेलन में समूह कार्य के अध्यक्ष, 20–21 सितम्बर, 2017, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई

सिफी 2017: साइबर सुरक्षा और इंटरनेट पर सम्मेलन, ताज मानसिंह, नई दिल्ली, 3–4 अक्टूबर, 2017

राज्य शिक्षा अधिकारियों और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के लिए संसाधन व्यक्ति, आकड़ा प्रबंधन के मुद्दों पर आलेख प्रस्तुत और समूह काम परिणाम पर सत्र की अध्यक्षता, 6–7 फरवरी, 2018, पुणे, महाराष्ट्र

समूह कार्य सरलीकरण हेतु उच्च शिक्षा में नेतृत्व पर 3 दिवसीय संगोष्ठी में भाग लिया, 26–28 फरवरी, 2018

अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ

तीन आलेखों के लिए समीक्षा, तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन: पुनः मापन, वैष्विक शिक्षा, दक्षिण–उत्तर संवाद, सीआईईएस 2018 मैक्सिको सिटी (1) भारतीय उच्च शिक्षा के शासन; (2) उच्च शिक्षा के स्वदेषी विकास (3) विश्वविद्यालय रैंकिंग

पीजीडेपा प्रतिभागी की मार्गदर्शन, ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के कार्यकरण का एक अध्ययन, मयूरभंज, ओडिशा

भारतीय शिक्षा व्यवस्था (निजी बनाम सार्वजनिक मुद्दे और चुनौतियांः पारंभिक शिक्षा) और कुलपति नीपा को प्रस्तुत एक संक्षिप्त नोट तैयार किया, 11 दिसंबर, 2017

पीएसी अनुसंधान कार्यक्रम के तहत प्रक्षेपण कार्यविधि और संबंधित मापदंडों को अंतिम रूप देने के लिए कार्यशाला में एक विषेशज्ञ के रूप में प्रतिभाग, एनसीईआरटी, नई दिल्ली, 21–22 दिसंबर, 2017

सदस्य सलाहकार बोर्डः भर्ती प्रक्षेपण और विद्यालय शिक्षा का रूझान, 2025 तक स्कूल शिक्षा, एनसीआरटी (2017)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रक्षेपण हेतु तकनीकी समिति, कुलपति, नीपा द्वारा नामित, 03 जनवरी, 2018

अभिनव पुरस्कार समीक्षा एव सबरकांठा जिला का दौरा, गुजरात और लोअर देवांग वातबी, फरवरी, 2018

ईएमआईएस विभाग की विभागीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन, नीपा, 12/13/2018

प्रशिक्षण कार्यक्रम

यू–डाईस, आईएएस प्रशिक्षुओं को प्रस्तावना पर एक व्याख्यान दिया, 25 जुलाई, 2017

संघ प्रदेश पुडुचेरी के एसएसए अधिकारियों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के नियोजन और निगरानी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित, 28–30 अगस्त, 2017

मुख्य प्रारंभिक व्याख्यान दिया, 28 अगस्त, 2017

शैक्षिक संकेतक + व्यावहारिक अभ्यास पर व्याख्यान, 29 अगस्त, 2017

जनसंख्या प्रक्षेपण और व्यावहारिक अभ्यास, 30 अगस्त, 2017

पीजीडेपा 2017–18ः शिक्षा योजना, में आंकड़ा की भूमिका पर व्याख्यान दिया, 25 सितंबर, 2017

प्राथमिक शिक्षा की योजना और अनुश्रवण पर 16–17 अक्टूबर 2017 को संकेतक का उपयोग करनेपर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजिक और शैक्षिक संकेतक और प्रक्षेपण तकनीकों पर सत्र लिया।

स्कूली शिक्षा की योजना और पर्यवेक्षण पर संकेतकों के प्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित और श्री ए.एन. रेड्डी के साथ निम्नांकित सत्र– (1) यू–डाईस के माध्यम से ईएमआईएस का विकास; (2) संकेतकों और आंतरिक क्षमता शिक्षा की व्यवस्था; (3) नामांकन और जनसंख्या प्रक्षेपण (4) यू–डाईस आंकड़ा पर एक समूह कार्य की अध्यक्षता।

अन्य शैक्षणिक और पेशेवर योगदान

एफ.फिल. पाठ्यक्रम में संशोधन कार्यक्रम के लिए 12–13 जुलाई, 2017 को गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय डूंडीगल का दौरा किया।

एम.फिल. और पीएचडी प्रवेष परीक्षा प्रबंधन में परीक्षा नियंत्रक के रूप में साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य, 3 से 5 जून, 2017

01 सितम्बर, 2017 को एनसीईआरटी स्थापना दिवस के आयोजन में भागीदारी

समीक्षाधीन वर्ष में पीएचडी के दो छात्रों को मार्गदर्षन

2017 एस.के.ओ.सी.एच. मेरिट पुरस्कार में भाग लिया, सांविधानिक क्लब, नई दिल्ली, 08 सितंबर 2017

एससीईआरटी, दिल्ली के शैक्षिक छात्रवृत्ति में परिवर्तन के सिलसिले में चयन प्रक्रिया में सदस्य, 18–19 सितंबर, 2017

एनसीईआरटी, नई दिल्ली में सहायक प्रोफेसर के लिए सीएएस के तहत सांख्यिकी सदस्य चयन समिति, 09 जनवरी 2017 और 24 अगस्त, 2017

स्कूल नामांकन की प्रवृत्ति और प्रक्षेपण पर एक दिवसीय बैठक में भागीदारी, एनसीईआरटी, नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2017

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकसित/संचालित

शैक्षिक अनुसंधान में साफ्टवेयर अनुप्रयोग पर पाठ्यक्रम का संचालन, (डॉ. सुमन नेगी के साथ) 10 जुलाई, 2017

– बड़े पैमाने पर डेटाबेस का परिचय

– सूचना प्रणाली और शिक्षा संकेतक पर दो सत्र, षोध कार्यप्रणाली पाठ्यक्रम, 26 अक्टूबर 2017

– ईएमआईएस, एम.फिल. और पीएचडी पर संशोधित वैकल्पिक पाठ्यक्रम (ओसी4), जनवरी, 2018

– डेपा में ईएमआईएस पर पाठ्यक्रम, 26–27 मार्च, 2018

– ईएमआईएस की बुनियादी शुरूआत का परिचय

– यू–डाईस का परिचय

के. बिस्वाल

प्रकाशन कार्य

पुस्तकें/मैन्यूअल/रिपोर्ट

1. "यू–डाईस फ्लश स्टेटिस्टिक्स ऑन स्कूल एज्यूकेशन2016/17". नीपा, नईदिल्ली प्रकाशित की

2. वर्ष 2017–18 के यू–डाईस डाटा के आधार पर नीपा के ऑनलाइन यू–डाईस प्रकाशनों को अद्यतन किया।

राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों में प्रतिभागिता

1. यूनेस्को–आईआईईपी,पेरिस और शिक्षा विभाग, फिलीपींस सरकार द्वारा मनीला में 24–26 जनवरी, 2018 से संयुक्त रूप से आयोजित 'शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए ओपन स्कूल डाटा का उपयोग करने पर अंतर्राष्ट्रीय नीति फोरम 'में भाग लिया।

2. 21 अगस्त 2017 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में एमएचआरडी,भारत सरकार और यूएनएफपीए इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'भारत में एसजीडी 4 निगरानी के लिए कार्यशाला' में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

3. टीएसजी/एमएचआरडी द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में 17 जनवरी 2018 को 'भारत में स्कूली शिक्षा में बालिकाओं की स्थिति' पर भाग लिया और बालिकाओं की स्थिति पर एक प्रस्तुति दी।

आयोजित/संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं

17–21 जुलाई, 2017 को ओडिशा के भुवनेश्वर में 'ओडिशा के शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) के प्रमुखों के लिए शिक्षक शिक्षा की योजना पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम' (प्रो. एस.एम.आई. जैदी और डॉ. एन.के. मोहंती के साथ) डिजाइन कर आयोजित किया।

4–8 जुलाई, 2017 को यूनिसेफ इंडिया कंट्री ऑफिस के सहयोग में'यू–डीआईएएसई और एसडीएमआईएस पर राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा कार्यशाला' विवांता, ताज, सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित की।

21–25 अगस्त 2017 को नीपा, नई दिल्ली में(प्रो. एस.एम. आई. जैदी और डॉ. एन.के. मोहंती के साथ) 'उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा सभी राज्यों और संघ राज्य–क्षेत्रों के लिए स्कूल शिक्षा विकास कार्यक्रमों की योजना और निगरानी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम) डिजाइन करआयोजित की।

04–08 सितम्बर, 2017को गुवाहाटी, असम मे (प्रो. एस.एम. आई. जैदी और डॉ. एन.के. मोहंती के साथ)उत्तर–पूर्वी राज्यों में 'स्कूल शिक्षा विकास कार्यक्रमों की योजना और निगरानी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम' डिजाइन कर आयोजित किया।

10–11 अक्टूबर, 2017को होटल प्राइड प्लाजा, एयरोसिटी, नई दिल्ली में यूनिसेफ इंडिया कंट्री ऑफिस के सहयोग में, 'यू–डीआईएसई और एसडीएमआईएस पर राष्ट्रीय समीक्षा बैठक'आयोजित की।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों/अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम में भाग लिया

शैक्षिक योजना विभाग द्वारा 29 जनवरी से 02 फरवरी, 2018 तक गंगतोक सिक्किम में एससीईआरटी और सिक्किम के संकाय के लिए शिक्षा में योजना और डिजाइनिंग अनुसंधान परियोजनाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य किया।

28 नवंबर से 01 दिसंबर, 2017 को गंगतोक, सिक्किममें टीएसजी/एमएचआरआरडी द्वारा एसएसए और यू–डाईस के तहत आयोजित 'नॉर्थ–इस्टर्न रीजनल वर्कशॉप फॉर स्टेट/डिस्ट्रिक्ट लेवल एनआईएस कोऑर्डिनेटर्स ऑन फॉर्मुलेशन एण्ड एप्रेजल ऑफ एडब्ल्यूपी' में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।

6–7 दिसंबर, 2017 को गंगतोक, सिक्किम में टीएसजी/एमएचआरआरडी द्वारा एसएसए और यू–डाईस के तहत आयोजित 'वेस्टर्न रीजनल वर्कशॉप फॉर स्टेट/डिस्ट्रिक्ट लेवल एनआईएस कोऑर्डिनेटर्स ऑन फॉर्मुलेशन एण्ड एप्रेजल ऑफ एडब्ल्यूपी' में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया। ।

26–27 दिसंबर, 2017 को ओडिशा के भुवनेश्वर में टीएसजी/एमएचआरआरडी द्वारा एसएसए और यू–डाईस के तहत आयोजित 'इस्टर्न रीजनल वर्कशॉप फॉर स्टेट/डिस्ट्रिक्ट लेवल एनआईएस कोऑर्डिनेटर्स ऑन फॉर्मुलेशन एण्ड एप्रेजल ऑफ एडब्ल्यूपी' में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।

4–5 जनवरी, 2018 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में टीएसजी/एमएचआरआरडी द्वारा एसएसए और यू–डाईस के तहत आयोजित ' रीजनल वर्कशॉप फॉर स्टेट/डिस्ट्रिक्ट लेवल एनआईएस कोऑर्डिनेटर्स ऑन फॉर्मुलेशन एण्ड एप्रेजल ऑफ एडब्ल्यूपी' में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।

विकसित और संचालित प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम

एम.फिल/पीएचडी कार्यक्रम, 2017–18 केलिए (प्रो. एस.एम.आई.ए. जैदी और डॉ. एन.के. मोहंती के साथ) अनिवार्य पाठ्यक्रम संख्या सीसी–6 (शिक्षा में उन्नत योजना तकनीक) संचालित किया।

सितंबर, 2017 में पीजीडेपा पाठ्यक्रम संख्या 903 एजुकेशनल प्लानिंग : कॉन्सेप्ट' टाइप्स एण्ड एपरोचिज संचालन के लिए एसोसिएट संकाय।

पाठ्यक्रम संयोजक के रूप में, जुलाई, 2017 में पीजीडीईपीए ऑनलाइन एडवांस्ड कोर्स नंबर 907: एजूकेशनल प्लानिंग आयोजित किया।

शैक्षिक योजना के साथ काम करने वाले नीपा के कई अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के संचालन के साथ जुड़े।

एम.फिल/पीएचडी, डेपा और आईडेपा शोध प्रबंधों का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन

नैनी राव, जाकिर हुसैन सेंटर फॉर एज्यूकेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जेएनयू, नई दिल्ली –110067 द्वारा इंसैंटिव्स इन हायर एड्यूकेशन रूस्टडी ऑफ मोटिवेशन अमंगस्ट रिसर्च स्कोलर्स इन जेएनयू' नामक एम फिल शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया।

श्री चंडी प्रसाद रतूड़ी, उ.प्र. सचिव सचिव, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एज्यूकेशन, रामनगर, नैनीताल द्वारा 'देहरादून जिले के लिए विशेष संदर्भ मेंउत्तराखण्ड में माध्यमिक चरण में विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) योजना की कार्यान्वयन स्थिति का अध्ययन' नामक पीजीडीपीए शोध प्रबंध कार्य का पर्यवेक्षण किया।

मि. दुक्कू अल सईद संतो सकाजो, स्कूल इंस्पेक्टर, साउथ सूडान द्वारा, 'ट्रैण्ड्स एंड कॉजिज ऑफ ड्रॉपआउट्स इन प्राइमरी एड्यूकेशन': अ स्टडी ऑफ सिलैक्ट गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स इनमुनुकी पयम (डिस्ट्रिक्ट) सेंट्रल इक्वेटोरिया स्टेट ऑफ जुबा रिपब्लिक ऑफ सूडान' नामक आईडेपा शोध प्रबंध का पर्यवेक्षण किया।

सुश्री निधी रावत द्वारा 'भारत में प्राथमिक शिक्षा में जीआईएस आधारित स्कूल मैपिंग का एकअध्ययन', शीर्षक से पीएचडी कार्य का पर्यवेक्षण किया।

श्री दीपेंद्र कुमार पाठक द्वारा 'पश्चिम बंगाल में स्कूल आधारित प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी: बर्दवान और पुरुलिया जिलों में चुनिंदा माध्यमिक विद्यालयों का एक अध्ययन' शीर्षक से पीएचडी कार्य का पर्यवेक्षण किया।

एमएचआरडी, यूजीसी, राज्य सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राष्ट्रीय संस्थानों को प्रदान की गई महत्वपूर्ण परामर्श और सलाहकार सेवाएं

यूजीसी द्वारा 6 अप्रैल 2017 को अपने कार्यालय, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–02 में 'विश्वविद्यालय स्वायत्तता पर बैठक' में भाग लिया।

यू–डाइस डीसीएफ 2016/17 में वेरिएबल्स की समीक्षा करने के लिए एमएचआरडी समिति के सदस्य।

6 अप्रैल 2017, 12 अप्रैल 2017, 29 मई 2017 और 24 जुलाई 2017 को एमएचआरडी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में आयोजित यू–डाइस डीसीएफ 2016/17 में वेरियेबल्स की समीक्षा के लिए समिति की विभिन्न बैठकों में भाग लिया,और यू–डाईस डीसीएफ 2017/18 का मसौदा तैयार कियाऔर समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर 2017/18 के लिए डीसीएफ को अंतिम रूप दिया।

19 अप्रैल 2017 को एमएचआरडी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में अस्मिता (सभी स्कूलों की निगरानी, सूचना ट्रैकिंग और विश्लेषण) पर बैठक में भाग लिया।

27 अप्रैल 2017 को एमएचआरडी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में एसएसए संयुक्त समीक्षा मिशन समापन बैठक में भाग लिया।

एनसीईआरटी, नई दिल्ली में 28 अप्रैल 2017 को आयोजित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण पर बैठक में भाग लिया।

यूजीसी विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में, विश्वविद्यालय के कामकाज की समीक्षा करने के लिए 22–23 मई, 2017 तक श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), कटवारिया सराय, नई दिल्ली का दौरा किया।

26 मई 2017 को ओडिशा के भुवनेश्वर में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ओडिशा में एचईआई के आईडीपी के मूल्यांकन के तौर–तरीकों परएक–दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया। इसके बाद, उच्च शिक्षा विभाग, ओडिशा सरकार ओडिशा के चुनिंदा कॉलेजों के संस्थागत विकास योजनाओं (आईडीपी) कामूल्यांकन कर प्रस्तुत किया , जो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना में शामिल है।

यूनाइटेड स्टेट्स–इंडिया एज्यूकेशनल फाउंडेशन (यूएसआईईएफ), 12 हैली रोड, नई दिल्ली में 15 जून 2017 को आयोजित फुलब्राइट–नेहरू फैलोशिप के लिए आवेदन के मूल्यांकन पर एक दिवसीय बैठक में भाग लिया और इसके बाद फुलब्राइट नेहरू फैलोशिप। के लिए 100 से अधिक आवेदनों का मूल्यांकन किया।

एनआईटी, राउरकेला द्वारा 23 जून 2017 को होटल मारियन, जनपथ, भुवनेश्वर में ओडिशा राज्य मानव विकास रिपोर्ट (ओएसएचडीआर) पर एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया, ओडिशा एसएचडीआर का मसौदा तैयार करने के लिए सामग्री, अध्याय योजना और कार्यनीति योजना पर चर्चा की।

एनआईटी, राउरकेला द्वारा 1 अगस्त 2017 को होटल मैरियन, जनपथ, भुवनेश्वर में आयोजित ओडिशा राज्य मानव विकास रिपोर्ट (ओएसएचडीआर) पर एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया और ओडिशा एसएचडीआर में शामिल करने के लिए शिक्षा पर अध्याय की मसौदा रूपरेखा को अंतिम रूप दिया।

एमएचआरडी, भारत सरकार की परामर्श निगरानी समिति (एसएसए) के सदस्य के रूप में, एसएसए कार्यक्रम के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में योगदान दिया।

यूजीसी विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में, 11–13 सितंबर, 2017 तक अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस), देवनार, मुंबई का दौरा किया, ताकि विश्वविद्यालय के रूप में संस्थान की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जा सके।

एमएचआरडी, भारत सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्य के रूप में, प्रोफेसर एस.एम.आई.ए. जैदी की अध्यक्षता में. एसएसए और आरएमएसए के विलय पर कॉन्सेप्ट नोट तैयार करने ने कॉन्सेप्ट नोट के मसौदे को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

26 सितंबर 2017 को सचिव (एसई एंड एल), एमएचआरडी, नई दिल्ली की अध्यक्षता में शास्त्री भवन में आयोजित बैठक में एसएसए और आरएमएसए (एमएचआरडी द्वारा गठित समिति) के विलय पर कॉन्सैप्ट नोट प्रस्तुत किया।

एसएसए की थर्ड पार्टी मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए 21 नवंबर 2017 को एमएचआरडी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में आयोजित परामर्श निगरानी समिति (एसएसए) की बैठक में भाग लिया।

एनसीईआरटी, नई दिल्ली के शैक्षिक सर्वेक्षण प्रभाग के प्रभागीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में, 12 दिसंबर 2017 को जाकिर हुसैन ब्लॉक, एनसीईआरटी, नई दिल्ली में वार्षिक कार्य योजना और बजट की समीक्षा के लिएसर्वेक्षण प्रभाग कीप्रभागीय सलाहकार बोर्ड की आयोजित बैठक में भाग लिया।

यूजीसी विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में, विश्वविद्यालय के कामकाज की समीक्षा करने के लिए 14–16 दिसंबर, 2017 तक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), होसुर रोड, बैंगलोर का दौरा किया।

यूजीसी विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12–बी के तहत विश्वविद्यालय को शामिल करने के लिए बुनियादी सुविधाओं और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए 21–23 दिसंबर, 2017 तक इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, रिवाडी, हरियाणा का दौरा किया।

चार राज्यों में माध्यमिक शिक्षा विकास कार्यक्रम पर, 7 फरवरी 2018 को वर्ल्ड बैंक और एमएचआरडी, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से होटल क्लेरल्स, नई दिल्ली मेंआयोजित बैठकमें भाग लिया।

अध्यक्ष के रूप में, एनसीटीई और सीआईईटी, एनईटीईआरटी, नई दिल्ली में, 2017/18 के दौरान आयोजित दीक्षाकी तकनीकी उप–समिति की विभिन्न बैठकों में शामिल हुए।

यूजीसी विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में, विश्वविद्यालय के कामकाज की समीक्षा करने के लिए 15–17 फरवरी, 2018 से श्री चंद्रशेखरेंद्रा सरावती विश्व महाविद्यालय, एनातुर, कांचीपुरम, तमिलनाडु का दौरा किया।

यूजीसी विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में, विश्वविद्यालय के कामकाज की समीक्षा करने के लिए 23–24 फरवरी, 2018 को भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान का दौरा किया।

राज्य और जिला स्कूल शिक्षा विकास योजनाओं (परिप्रेक्ष्य और एडब्ल्यूपी एंड बी) की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य–क्षेत्रों को और स्कूल शिक्षा में प्रगति की निगरानी के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग करने में तकनीकी सहायता प्रदान की।

एक सदस्य के रूप में, स्कूली शिक्षा पर वित्तीय डाटा पर प्रो. जे.बी.जी. तिलक,नीपाकी अध्यक्षता में एमएचआरडी, भारत सरकार द्वारा गठित, विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के प्रारूपण और अंतिम रूप देने में योगदान दिया।

सदस्य के रूप में, एमएचआरडी, भारत सरकारकी विभिन्न शाला कोष संचालन समिति की बैठकों में भाग लिया।

एक सदस्य के रूप में, एमएचआरडी, भारत सरकार की दीक्षा संचालन समिति की विभिन्न बैठकों में भाग लिया।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, एमएचआरडी, भारत सरकार द्वारा गठित समग्र शिक्षा (स्कूल शिक्षा पर एकीकृत योजना) के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा के गठन के लिए समिति के सदस्य। समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए मसौदा रूपरेखा तैयार करने में योगदान दिया।

आरएमएसए, एमएचआरडी, भारत सरकार के परिणाम फ्रेमवर्क और मॉनिटरिंग दस्तावेज को (डा. एन.के. मोहंती के साथ) तैयार और अंतिम रूप दिया। एसईएमआईएस 2009/10 और यू–डीआईएसईआई 2016–17 डाटा के विश्लेषण के आधार पर आरएफडी में सभी मात्रात्मक संकेतकों के लिए 2016–17 डाटा प्रदान किया। इसके अलावा, जून 2017 में आरएमएसए की संयुक्त समीक्षा मिशन की बैठक में आरएमएसए आरएफडी 2017/18 प्रस्तुत किया।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

प्रभारी, नीपा में 4 जनवरी 2017 से यू–डाईस परियोजना.

अध्यक्ष, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, नीपा।

अध्यक्ष के रूप में, पीएमयू ने निगरानी और समीक्षा के लिए 2017/18 के विभिन्न तिमाहियों के लिए 'नीपा

में अनुसंधान अध्ययन/परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट' तैयार की।

यूनिसेफ इंडिया कंट्री ऑफिस, नई दिल्ली से वित्त पोषण सहायता के लिए 2017/18 और 2018/19 के लिए यू-डाईस परियोजना प्रस्ताव तैयार किया।

यूनिसेफ इंडिया कंट्री ऑफिस टीम,के सहयोग में यू-डाईस के डैशबोर्ड/डाटा विजुअलाइजेशन ऐप (http://udise-schooleduinfo.in.) को लॉन्च करने के लिए प्रमुख संकेतकों को अंतिम रूप दिया।

प्रभारी के रूप में, यू-डाईस परियोजना, नीपा (http://sdms.udise.in/) के स्कूल निर्देशिका प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस) पोर्टल (डेस्कटॉप और मोबाइल एंड्रॉइड ऐप दोनों) को डिजाइन और अंतिम रूप देने में योगदान दिया, जिसे अगस्त 2017 में राष्ट्रीय और साथ ही उप-राष्ट्रीय स्तरों पर स्कूल निर्देशिकाओं को तैयार करने और अद्यतन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

प्रभारी, यू-डाईस परियोजना, वर्ष 2017/18 के लिए स्कूल की प्रगति और प्रतिफलों पर छात्रवार डाटा अभिग्रहण के लिए छात्र ट्रैकिंग प्रणाली के रूप में नीपा (https://student.udise.in/) के छात्र डाटाबेस प्रबंधन सूचना प्रणाली (एसडीएमआईएस) सॉफ्टवेयर को डिजाइन और अद्यतन करने की दिशा में योगदान दिया-।

यू-डाईस डीसीएफ 2017/18 को अंतिम रूप दिया और यू-डाईस डीसीएफ 2016/17 में एमएचआरडी समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2017/18 के लिए डाईस डाटा संग्रह के लिए यू-डाईस के डाटा कैप्चर एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया। ।

अगस्त 2017 को नीपा में सचिव (एसई एंड एल), एमएचआरडी द्वारा यू-डाईस गतिविधियों की समीक्षा पर बैठक का आयोजन किया।

सदस्य, नीपा के अध्ययन बोर्ड।

सदस्य, नीपा की अकादमिक परिषद।

नीपा शोध रिपोर्ट प्रकाशन श्रृंखला 2015 को शुरू करने के लिए कार्यकारी समूह के संयोजक।

सदस्य, नीपा की ग्रैंड-इन-एड समिति।

नीपा की निर्माण समीक्षा और सलाहकार समिति के सदस्य।

नीपा की प्रकाशन सलाहकार समिति के सदस्य।

सदस्य, नीपा और एमएचआरडी, भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन तैयार करने के लिए नीपा समिति।

सदस्य, समिति नीपा के एम.फिल/पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा का डिजाइन

एम.फिल/पीएचडी कार्यक्रम 2015/16 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने में सहायता की।

शोध अध्यन

तमिलनाडु और ओडिशा में आरएमएसए के तहत जिला माध्यमिक शिक्षा योजना के विकास पर कार्रवाई अनुसंधान परियोजना (एस.एम.आई.ए. जैदी और एन.के. मोहंती के साथ) यह परियोजना तमिलनाडु के चार जिलों (थेनी और सलेम जिलों) और ओडिशा (गंजम और किंजर जिलों) में कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के पहले चरण में, रिसर्च टीम ने राज्य और जिला योजना टीमों के साथ कई दौर की बातचीत की। दो कार्यशालाएं और दो परामर्श बैठकें आयोजित की गईं; नमूना राज्यों और संबंधित साहित्य के योजना दस्तावेजों की समीक्षा की गई; और प्राथमिक और द्वितीयक डाटा एकत्र किए गए थे। नमूना राज्यों और जिलों से एकत्र किए गए डेटा और सूचना और फील्ड नोट्स के आधार पर, पहले चरण की मसौदा रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें स्कूली शिक्षा और उनके सामाजिक-आर्थिक और संस्थागत संदर्भ में नियोजन प्रथाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित किया।

कार्रवाई अनुसंधान के चरण 1 में नमूना जिलों के नियोजन टीमों की क्षमता निर्माण की जरूरतों की पहचान करने के बाद, अध्ययन प्रथाओं में सुधार करने और तमिलनाडु और ओडिशा में मॉडल जिला माध्यमिक शिक्षा योजनाओं को विकसित करने के लिए हस्तक्षेप अध्ययन के दूसरे चरण में किए। दूसरे चरण में, तमिलनाडु और ओडिशा

में नमूना जिलों की एक्शन रिसर्च टीमें मॉडल जिला माध्यमिक शिक्षा योजनाओं को विकसित करने में लगी हुई थीं। नीतिगत अस्थिरता (यानी आरएमएसए और एसपीओ के एसपीडी के लगातार स्थानांतरण और जिला स्तरीय कार्रवाई अनुसंधान/योजना टीमों के सदस्यों) के कारण नमूना जिलों में मॉडल माध्यमिक शिक्षा योजनाओं को विकसित करने में अपेक्षित समय से अधिक समय लगा। 2016/17 में, मॉडल डीएसईपी को चेन्नई और भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय कार्यशालाओं में साझा किया गया था, और बाद में, जिला कार्रवाई अनुसंधान टीमों को राज्य स्तरीय कार्यशालाओं में प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों के मद्देनजर योजनाओं को संशोधित करने का अनुरोध किया। 31 मार्च 2018 को, तमिलनाडु और ओडिशा के सभी 4 नमूना जिला अनुसंधान दल अपने मॉडल जिला माध्यमिक शिक्षा योजनाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में थे।

शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विभाग

बी.के. पांडा

कार्यक्रम आयोजन

डिप्लोमा कार्यक्रम

2016–17 में शैक्षिक योजना और प्रशासन मेंतीसरा स्नातकोत्तर डिप्लोमा आयोजित किया। कार्यक्रम टीम के सदस्यों के साथ, हैंडबुक, ब्रोशर, पठन सामग्री और कार्यक्रम की रिपोर्ट तैयार की।

2017–18 में शैक्षिक योजना और प्रशासन में चौथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा आयोजित किया। कार्यक्रम टीम के सदस्यों के साथ, हैंडबुक, ब्रोशर, पाठ्य सामग्री और कार्यक्रम की रिपोर्ट तैयार की।

2016–17 में शैक्षिक योजना और प्रशासन (आईडेपा) में 33वें अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा का आयोजन किया।कार्यक्रम टीम के सदस्यों के साथ–साथ हैंडबुक, ब्रोशर, पठन सामग्री और कार्यक्रम की रिपोर्ट तैयार की।

2017–18 में शैक्षिक योजना और प्रशासन (आईडेपा) में 34वें अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा का आयोजन किया। कार्यक्रम टीम के सदस्यों के साथ, हैंडबुक, ब्रोशर, पठन सामग्री और कार्यक्रम की रिपोर्ट तैयार की

17 जुलाई से 12 अगस्त, 2017 में शैक्षिक योजना और प्रशासन (आईपीईए) में दूसरा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया।

महाराष्ट्र के आश्रम स्कूलों के प्रमुखों के लिए प्रशिक्षण (13–17 नवंबर, 2017)।

महाराष्ट्र के आश्रम स्कूलों के प्रमुखों के लिए प्रशिक्षण (14–18 फरवरी, 2018)।

आंध्र प्रदेश के आश्रम स्कूलों के प्रमुखों के लिए प्रशिक्षण (9–13 जनवरी, 2018)।

नीपा में एम.फिल./पीएचडी को मार्गदर्शन प्रदान किया

रेबेका द्वारा 'सशस्त्र संघर्ष के दौरान स्कूली शिक्षा का संरक्षण और पुनर्निर्माण : मणिपुर का एक वैयक्तिक अध्ययन' (अवार्ड)।

ज्योत्सना सोनल द्वारा 'उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा' का अध्ययन (जारी)।

पूनम चौधरी द्वारा 'दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का प्रबंधन' का अध्ययन (जारी)।

एनसीईआरटी के लिए विकसित मॉड्यूल

– प्रभावी स्कूली शिक्षा के लिए मानचित्रण संसाधन। बीके पांडा

– संस्थागत योजना की अवधारणा और प्रक्रिया। बीके पांडा

कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों का विकास

शैक्षिक योजना और प्रशासन (पीजीडेपा और आईडेपा) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु 'विकास के लिए सामर्थ्य विकास' पर एक उन्नत पाठ्यक्रम विकसित किया।

'शैक्षिक अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन (आईपीईए) में अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम' नामक चार सप्ताह की छोटी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम को विकसित और डिजाइन कियाऔर मौजूदा आईडेपा कार्यक्रम की तरह नीपामें नियमित आधार पर कार्यक्रम के संचालन हेतु विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से मंजूरी प्राप्त की।

अनुसंधान परियोजनाएँ

अनुसूचित जाति के बच्चों के बीच शिक्षा – राजस्थान के दो गाँवों का गहन अध्ययन (जारी)।

वर्तमान में प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से वर्तमान और भविष्य की भूमिका पर शैक्षिक प्रशासकों के कार्य का गहन अध्ययन (जारी)।

सविता कौशल

प्रकाशन

जरनल्स / पत्रिकाओं / पुस्तकों में लेख

कुमार, के और सिंह, एस. द्वारा संपादित 'भारत में शिक्षा की चुनौतियां' शीर्षक वाली पुस्तक में दो अध्याय (अध्याय 9: स्कूलों को तैयार करने की चुनौतियों का सामना करना, पीपी 106–117 और अध्याय 11: 'बीइंग' और 'बीकमिंग' एक ईसीसीई प्रोफेशनलः ईसीईसी कार्मिक के व्यावसायिक विकास पर विचार' प्रकाशित, पृष्ठ 121–136 में पॉलिटिकल इंडिया पब्लिकेशंस, पटना, आईएसबीएनः 978–81–926723–2–8।

नीपा द्वारा प्रकाशित शैक्षिक योजना न्यूजलैटर, अंक 23, संख्या 1, जनवरी–जून 2017 में एशियन नेटवर्क ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में 'भारत में स्कूल स्तर पर शिक्षण–अधिगम में आईसीटी आधारित पहल' शीर्षक से प्रकाशित लेख।

'खुली एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भारत में बुनियादी शिक्षा' नामक पुस्तक आईएसबीएन (978–620–2–05132–3) लैप लैम्पर्ट अक्टूबर 2017 द्वारा प्रकाशित।

शोध पत्र 'प्रौद्योगिकी–आधारित सामर्थ्य विकास हस्तक्षेपों के प्रति जिला शिक्षा अधिकारियों की धारणाएँः यू–डीआईएसई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अध्ययन, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा का जर्नल' ISSN–0019–5006, खंड 78, संख्या 4, अक्टूबर–दिसंबर 2017, पृ. 88–103, प्रकाशित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली, भारत।

बालारामुलु, डी मूर्ति, आरके और श्रीनिवास दासु पी, कैनेडियन द्वारा संपादित पुस्तक 'आर्टिकल स्टडीज फ्रॉम फ्री प्रोग्रेस स्कूल' आईएसबीएन 978–1–926488–52–3 में 'टीचर एजुकेशनः इश्यूज एंड चौलेंजेस',नामक शोध पत्र प्रकाशित, एकेडमिक पब्लिशिंग, 2017 पृ. 124–126।

नीपाद्वारा प्रकाशित शैक्षिक योजना न्यूजलैटर, अंक 23, संख्या 1, जनवरी–जून 2017 में एशियन नेटवर्क ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में 'भारत में स्कूल स्तर पर शिक्षण–अधिगम में आईसीटी आधारित पहल' शीर्षक आलेख।

कार्यक्रम / पाठ्यक्रम विकास

2017–18 में शैक्षिक योजना और प्रशासन स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के समन्वयक। कार्यक्रम निदेशक और वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक के साथ बैकग्राउंड प्रपत्र, हैंडबुक, ब्रोशर, पठन सामग्री, कार्यक्रम की रिपोर्ट और चयनित पाठ्य सामग्री का निर्माण (पाठ्यक्रम कोडः

901)। पाठ्यक्रम कोड 905 और कोड 909 के लिए पाठ्यक्रम सामग्री के संदर्भ में पाठ्यक्रम संशोधन, पाठ्य सामग्री की पहचान, संचालनरणनीति और मूल्यांकन।

पीजीडेपा (2016–17) के दौरान पूरी की गई परियोजना रिपोर्ट पर आधारित समन्वित कार्यशाला, 10–14 अप्रैल, 2017।

पीजीडेपा (2016–17) के दौरानउन्नत पाठ्यक्रम कार्य पर आधारित समन्वित कार्यशाला,17–21 अप्रैल, 2017। कार्यक्रम में पाठ्यक्रम कोड 909 के दस सत्रों का संचालन।

डीईपीएऔर पीजीडेपा (2016–17) के मूल्यांकन, प्रस्तुति और प्रस्तुतीकरण पर पीजीडेपा के लिए समन्वित उन्नत पाठ्यक्रम कार्यशाला, 27 जून – 01 जुलाई, 2017।

आईपीईएकार्यक्रम, 17 जुलाई से 10 अगस्त, 2017 के लिए विभाग और संकाय सदस्यों के साथ शैक्षिक योजना और प्रशासन (आईपीईए) पर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की परिकल्पना, तैयारी और वितरण में सहयोग।

शैक्षणिक अधिकारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यक्रम संयोजक', 17 जुलाई – 11 अगस्त, 2017।

ब्रिटिश काउंसिल के साथ नीपाद्वारा 'समन्वित शिक्षक शिक्षा नियोजन कार्यशाला – एक सहयोगात्मक कार्यशाला' का आयोजन, 8 नवंबर, 2017।

15–19 जनवरी, 2018 को अल्पसंख्यक प्रबंधित संस्थानों के प्रमुखों के लिए संस्थागत विकास में अभिविन्यास कार्यक्रम के कार्यक्रम समन्वयक। कार्यक्रम में पांच सत्रों का संचालन।

नीपा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में योगदान

पीजीडेपा के लिए पाठ्यक्रम कोड 901 (बेसिक्स इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन) के एसोसिएट फैकल्टी एवं संसाधन व्यक्ति और पीजीडेपा के पाठ्यक्रम कोड 901 (बेसिक्स इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन) के लिए सात सत्रों का आयोजन।

पीजीडेपा के लिए पाठ्यक्रम कोड 905 (प्रोजेक्ट वर्क एंड राइटिंग) के पाठ्यक्रम संयोजक एवं सोर्स पर्सन और पीजीडीपीए के पाठ्यक्रम कोड 905 (प्रोजेक्ट वर्क एंड राइटिंग) के लिए बीस सत्र आयोजित किए।

पीजीडेपा के लिए पाठ्यक्रम कोड 902 (भारतीय शिक्षाः एक परिप्रेक्ष्य) के चार सत्र लिए।

शैक्षिक कार्यक्रम (आईपीईए), 17 जुलाई –11 अगस्त, 2017 के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में चार सत्र लिए।

15–19 जनवरी, 2017 को उच्च शिक्षा के अल्पसंख्यक संचालित संस्थानों के प्रमुखों के लिए संस्थागत विकास में अभिविन्यास कार्यक्रम में तीन सत्र लिए।

34वें डेपा पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम कोड 211 के पाठ्यक्रम प्रभारी। फरवरी 2017 में, आईडेपा के शोध पद्धति पाठ्यक्रम कोड 211 के ग्यारह सत्र लिए।

34वें डीईपीएपाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम कोड 213 (प्रोजेक्ट वर्क) का समन्वयक। 1 फरवरी, 2017 को शुरू होने वाले कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण किया और पाठ्यक्रम के लिए चार सत्र लिए।

उत्तर प्रदेश और दिल्ली में दो संस्थानों को मान्यता देने पर नीपा के इनोवेशन अवार्ड्स प्रोग्राम का आयोजन किया।

संगोष्ठी/सम्मेलन (राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय) में भागीदारी

29 मई– 2 जून, 2017 को आइईपी, पेरिस द्वारा आयोजित ई–संगोष्ठी में भाग लिया। संगोष्ठी का शीर्षक था "ट्रांसफोर्मिंग टीचर एजुकेशन टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम"।

20–22 जुलाई, 2017 को चेन्नई में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, तमिलनाडु द्वारा आयोजित 'द न्यू संगोष्ठी ऑन डेवलपिंग न्यू करिकुलम–2017' में सहभागिता की एवं प्रपत्र प्रस्तुत किया।

उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद द्वारा 29–30 अगस्त, 2017 को उस्मानिया विश्वविद्यालय में आयोजित 'मीडिया, राजनीति और उच्च शिक्षा' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'भारत में शरणार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए रास्तेः UNHCR% DAFI छात्रवृत्तिः एक विश्लेषण' नामक एक प्रपत्र प्रस्तुत किया।

हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा हैदराबाद में 27–29 मार्च, 2018 को आयोजित 'भारत में मैनुअल स्कैवेंजर्स के सामाजिक और व्यावसायिक गतिशीलताः सामाजिक बहिष्कार के दृष्टिकोण से नीति विश्लेषण' नामक राष्ट्रीय में "मैनुअल स्कैवेंजर्स के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में चुनौतियां और रणनीतियाँः एक सुलभ स्कूल, दिल्ली का वैयक्तिक अध्ययन' नामक प्रपत्र प्रस्तुत किया।

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहयोग

वी.वी. गिरी लेबर इंस्टीट्यूट, 4–22 सितंबर, 2017 द्वारा आयोजित 'कौशल विकास और रोजगार सृजन' पर अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 11 सितंबर, 2017 को 'ओपन स्कूलिंग/दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा' नामक दो सत्रों को लिया।

8 नवंबर, 2017 को चेन्नई में क्रिसलिस द्वारा आयोजित कार्यक्रम 'इंस्पिरर्स ऑफ ड्रीम्स' के लिए संसाधन व्यक्ति।

21–22 नवंबर, 2017 को एनसीईआरटी में 'बचपन के संदर्भ में स्थिरता' पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक में भाग लिया।

लोक प्रशासन और नीति अनुसंधान के ग्रीनर जर्नल, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के ग्रीनर जर्नल और अशैक्षणिक अनुसंधान के ग्रीनर जर्नल के संपादकीय बोर्ड के सदस्य आईएसएसएनः 2354–225X, http-gjournal.org।

विश्वविद्यालय अनुदान स्वीकृत जर्नल 'एजुकेशनल साइंस रिव्यू (ए रेफरेड एंड पीयर रिव्यू हाफ ईयर रिसर्च जर्नल ऑफ एजुकेशन) संख्या 64133, ISSN: 0974–5947 के संपादकीय सदस्य।

एआरएनईसीके सदस्य (बचपन के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्रीय नेटवर्क)।

एम.फिल. और पीएचडी कार्यक्रम

सुश्री निदा खान,नीपाके एम. फिल. अनुसंधान कार्य 'अल्पसंख्यक स्कूलों का कार्य और प्रबंधनः दिल्ली में चयनित स्कूलों का एक अध्ययन' का मार्गदर्शन।

एम. फिल कार्यक्रम के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम छह का संसोधन।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी

पीजीडेपा, आईडेपा, स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट पार्टिसिपेंट्स में डिप्लोमा और एम. फिल. शोधार्थियों को मार्गदर्शन

'स्कूलों में बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि पर 'ई.सी.सी.डी.' कार्यक्रम का प्रभाव' शीर्षक के शोध अध्ययन पर आईडेपाप्रतिभागी चेन्चो टीशरिंग (भूटान) को शोध मार्गदर्शन।

"भूटान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डे स्कूल और बोर्डिंग स्कूल के बीच शैक्षणिक उपलब्धि" शीर्षक के शोध अध्ययन पर आईडेपाप्रतिभागी संगय वांग्दी (भूटान) को शोध मार्गदर्शन।

"उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुना रिवर वैली में मिड–डे मील योजना के कार्यान्वयन का एक अध्ययन" शीर्षक से शोध अध्ययन पर उत्तराखंड से पीजीडीपीए के प्रतिभागी अमित चौहान को शोध मार्गदर्शन।

'जोरहाट जिले, असम के टिटबर ब्लॉक में प्री–प्राइमरी एजुकेशन का प्रबंधन' शीर्षक से शोध अध्ययन पर असम से पीजीडेपा के प्रतिभागी कृष्ण दत्त डेका को शोध मार्गदर्शन।

मोना सेदवाल

प्रकाशन

पुस्तकें

'इंडिया एजुकेशन रिपोर्टः प्रोगेस ऑफ बेसिक एजुकेशन', आर गोविंदा द्वारा संपादित, ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2017, प्रपत्र बैक, 288 पेज, आईएसबीएन 9780199474714।

पुस्तक में अध्याय

इंट्रोडक्सन : बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल इन इंडिया– ट्रैकिंग प्रोगेस शीर्षक सेआर. गोविंदा और मोना सेडवाल द्वारा संपादित पुस्तक 'भारत एजुकेशन रिपोर्टः प्रोग्रेस ऑफ बेसिक एजुकेशन' में एक अध्याय लिखा, ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2017 पृ. 1–29 आईएसबीएन 9780199474714।

संगोष्ठी / सम्मेलन / कार्यशालाओं में भागीदारी

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा), नई दिल्ली में 'उच्च शिक्षा का भविष्यः आर्थिक और सामाजिक संदर्भ', 7–8 सितंबर, 2017 को राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'स्वतंत्रता से पहले भारत में भारतीय विश्वविद्यालयों के उभार एवं विस्तार' नामक एक प्रपत्र प्रस्तुत किया। संगोष्ठी का आयोजन उच्च और व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा किया गया था, जो कि भारतीय आर्थिक संघ के सहयोग से अपने शताब्दी वर्ष में आयोजित करने के लिए उच्च शिक्षा में उभरते मुद्दों पर एक प्री–कॉन्फ्रेंस संगोष्ठी थी।

जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू में 16–18 नवंबर, 2017 को भारत के तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी (सीईएसआइ) वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2017, शीर्षक 'समकालीन शैक्षिक विमर्शों में आलोचना, सहानुभूति और कल्याण'' में 'औद्योगिक तकनीकी संस्थानों के लिए कौशल विकास – एक समीक्षा' नामक एक पत्र प्रस्तुत किया।

लखनऊ विश्वविद्यालय के ओएनजीसी भवन में 9–12 नवंबर, 2017 को "नव–उदारवाद, उपभोग और संस्कृति पर चालीसवें अखिल भारतीय समाजशास्त्रीय सम्मेलन' में एक सत्र की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग द्वारा किया गया। शिक्षा और समाज पर अनुसंधान समिति के आरसी सत्र–3 (आरसी–05) में 11 नवंबर, 2017 को दस प्रस्तुतियां दी गईं। सत्र के सह–अध्यक्ष डॉ. ब्रजेश कुमार, बीबीएयू, लखनऊ थे।

जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू में 17 नवंबर, 2017 को भारत के तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी (CESI) के 'समकालीन शैक्षणिक विमर्शों में समालोचना, सहानुभूति और कल्याण' नामक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 16–18 नवंबर, 2017 में 'शिक्षक शिक्षा में शैक्षणिक मुद्दों' पर 20वें तकनीकी सत्र की अध्यक्षता।

केंद्रीय विद्यालय संस्थान (सीआइई), शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में 8–9 मार्च, 2018 को 'स्कूल में समावेशः परिप्रेक्ष्य और संभावनाएँ' पर दो दिवसीय संगोष्ठी में एक सत्र की अध्यक्षता की। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन (आइएएसई), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मानव संसाधन विकास मंत्रालय), भारत सरकार, 8 मार्च, 2018 के तत्वावधान में शिक्षा विभाग द्वारा इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (मुख्य), मैक्स मुल्लर मार्ग, नई दिल्ली में 5 सितंबर, 2017 को प्रो. आर. गोविंदा और डॉ. मोना सेडवाल द्वारा संपादित पुस्तक 'इंडिया एजुकेशन रिपोर्टः प्रोग्रेस ऑफ बेसिक एजुकेशन' के विमोचन कार्यक्रम में धन्यवाद प्रस्ताव दिया। पुस्तक का विमोचन प्रो. श्याम मेनन द्वारा किया गया और कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली स्थित सामाजिक विकास परिषद (सीएसडी) द्वारा किया गया।

फिक्की फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली में 15 सितंबर, 2017 को 'न्यू एज स्किल्स फॉर टुडे एंड टुमोरो' पर दसवें फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ग्लोबल स्किल समिट के लिए विशेष आमंत्रित। शिखर सम्मेलन मुख्यतः वैश्विक कार्यस्थल में स्वचालन क्षमता एवं रोजगार और उत्पादकता पर इसके प्रभाव पर केंद्रित था।

कार्यशालाओं/सम्मेलनों/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा), नई दिल्ली में1 फरवरी –30 अप्रैल, 2017 को शैक्षिक योजना और प्रशासन (आईडेपा) में तैंतीसवें अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम के समन्वयक। नई दिल्ली में इस डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए उन्नीस देश के छब्बीस प्रतिभागियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा), नई दिल्ली में 17 जुलाई –11 अगस्त, 2017 को शैक्षिक प्रशासकों (आईपीईए) के लिए दूसरे अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के समन्वयक। नई दिल्लीमें इस कार्यक्रम के लिए दस देशों के सोलह प्रतिभागियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा), नई दिल्ली में शिक्षक–प्रशिक्षक नियोजन कार्यशाला, 13 नवंबर, 2017 के कार्यक्रम समन्वयक। यह राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन तथा ब्रिटिश काउंसिल, भारत संयुक्त कार्यशाला थी।

आंध्र प्रदेश के एलुरु में 'आश्रम स्कूलों के प्रमुखों के लिए स्कूल विकास योजना' 18–22 दिसंबर, 2017 को प्रशिक्षण कार्यशाला के कार्यक्रम समन्वयक। प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान स्कूल विकास योजना पर केन्द्रित करते हुए प्रतिभागियों के लिए समूह कार्य और उसकी प्रस्तुतियाँ आयोजित की गईं।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा), नई दिल्ली, 1 फरवरी–30 अप्रैल, 2018 को शैक्षिक योजना और प्रशासन (आईडेपा) में चौथा अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम के समन्वयक। नई दिल्ली में इस डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए बारह देशों के सत्ताईस प्रतिभागियों ने भाग लिया।

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहयोग

स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, मार्च 2018 के तृतीय वर्ष के प्रपत्र बी.एल.ई.डी. के ड्राफ्ट पर प्रतिक्रिया प्रदान की।।

अन्य शैक्षणिक/व्यावसायिक योगदान

रारूटलेज के लिए शिक्षा पर दो ड्राफ्ट प्रतियों का मूल्यांकन, टेलर एंड फ्रांसिस बुक्स की एक छाप, अप्रैल और नवंबर 2017।

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट (IJEED), मई 2018 के लिए एक आलेख की समीक्षा की। इंटरसाइंस पब्लिशर्स, संपादकीय कार्यालय, पोस्ट बॉक्स 735, ओल्नी, बक्स एमके 46 5 डब्ल्यूबी, यूके।

प्रख्यात निकायों की सदस्यता

तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी (CESI), लाइफ सेक्रेटरी ऑफ जाकिर हुसैन सेंटर फॉर एजुकेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई महरौली रोड, नई दिल्ली। सदस्यता संख्याः CESI,LM,39।

ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च (AIAER), भुवनेश्वर, ओडिशा के आजीवन सदस्य, सदस्यता संख्याः 3129

भारतीय समाजशास्त्रीय सोसायटी (आईएसएस), नई दिल्ली के सदस्य, सदस्यता संख्याः एलएमआई–3791।

राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र

रश्मि दीवान

सभी राज्यों में विद्यालय नेतृत्व विकास गतिविधियों, सामर्थ्य विकास कार्यक्रमों का नेतृत्व करना

एनसीईआरटी, नई दिल्ली के सहयोग से स्कूल परिवर्तन के लिए रोडमैप पर चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं सहित राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर फेस–टू–फेस कार्यक्रम।

ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभः स्कूल नेतृत्व में विकासशील परिप्रेक्ष्य वाले मॉड्यूल पर योगदान।

सामग्री विकास

विद्यालय प्रमुखः अद्यतन करना, हैंडबुक को संशोधित करना

विद्यालय प्रशासकः स्कूल प्रशासकों के लिए अवधारणा और पाठ्यक्रम तैयार करना

विद्यालय सुधार के लिए रोडमैप तैयार करना

विद्यालय नेतृत्व विकास पर नीति दिशानिर्देशों का मसौदा

नेटवर्किंग और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग

विद्यालय शिक्षा के राज्य विभाग

राज्य नेतृत्व की अकादमियाँ

नीपा की गतिविधियों में भागीदारी

शिक्षण/प्रशिक्षण सत्र

शैक्षिक प्रशासन पर एम.फिल.मुख्य पाठ्यक्रम

शैक्षिक प्रबंधन पर आईडेपा पाठ्यक्रम

शैक्षिक प्रबंधन पर डीईपीए पाठ्यक्रम

संस्थान के अन्य विभागों द्वारा आयोजित अधिकांश कार्यक्रमों में शिक्षण

शोध–निर्देशन

मीनू शर्मा – पीएचडी शोधार्थी – राजस्थान के अजमेर जिले में नव–साहित्यकारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रौढ़ शिक्षा की भूमिका (अवार्ड)

पारुल चौधरी – एम.फिल. शोधार्थी – 'दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में महिला प्रधानाचार्यों की कार्यशैली पर एक अध्ययन' (अवार्ड)

रशीम वाधवा – पीएचडी शोधार्थी – 'भारत में उच्च शिक्षा में प्रवेश के निर्धारक'

गीता बहल – पीएचडी शोधार्थी – नेतृत्व विकास और स्कूल में सुधारः राजस्थान के सरकारी और निजी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का तुलनात्मक अध्ययन'

शिवानी बख्शी – पीएचडी शोधार्थी – विद्यालय सुधार के नेतृत्व मार्गः केरल के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्यों पर एक अध्ययन'

शैक्षिक योजना और प्रशासन में डिप्लोमा (डेपा)

विलायत अलीः जम्मू और कश्मीर के दूरस्थ क्षेत्र में क्म्प्ज कारगिल के कार्यः चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ – एक नृजातीय अध्ययन

शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा)

सतीश कामरूपः मॉरीशस में शिक्षण स्टाफ को प्रेरित करने में स्कूलों के प्रमुखों की भूमिका का अध्ययन

एम.फिल.–पीएचडी कार्यक्रम

शैक्षिक प्रशासन पर एम. फिल. पाठ्यक्रम का संशोधन – सीसी 07

स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर एम. फिल. वैकल्पिक पाठ्यक्रम 15 का संशोधन

सदस्य, निर्देशक आवंटनसमिति

सदस्य, संचालन समिति

लिखित परीक्षा के संचालन पर्यवेक्षक

एम.फिल.–पीएचडी कार्यक्रम के शार्ट लिस्टेड उम्मीदवारों के लिए समिति

नीपा की अन्य गतिविधियाँ

विशेष आमंत्रित, नीपा शैक्षणिक परिषद

विशेष आमंत्रित, नीपा अध्ययन बोर्ड

नीपा में चयन समितियों के विशेषज्ञ

सदस्य, पुस्तक चयन समिति

उच्च शिक्षा में शैक्षणिक नेतृत्व पर कार्यक्रम के लिए आमंत्रित

22 सितंबर, 2017 को एनसीएसएल, नीपा में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना के तौर–तरीकों पर बैठक में सदस्य के रूप में आमंत्रित

''एक्सेस, इक्विटी और विविधता'' नामक थीम पर टीम को विवरण देने के लिए नीपा की परिप्रेक्ष्य योजना सलाहकार समितिः

– स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा विभाग और शाला सिद्धि

– प्रशिक्षण और सामर्थ्य विकास विभाग

नीपा के बाहर की गतिविधियाँ

तृतीय पक्ष के मूल्यांकन के लिए रमसा मूल्यांकन समिति के विशेषज्ञ।

केंद्रीय शिक्षक शिक्षा संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कई बैठकों के लिए आमंत्रित किया गया, जिसे अब राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा संस्थान के नाम से जाना जाता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ कई बैठकों के मनोनीत सदस्य। जिनमें प्रधानमंत्री कार्यक्रम, एचआरएम द्वारा आयोजित बैठकें, केब की 65वीं बैठक, संसद की परामर्शी बैठक आदि शामिल हैं।

संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आरएमएसए की समीक्षा/मूल्यांकन जांच हेतु परामर्श मॉनिटरिंग कमेटी (सीएमसी) में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित

स्कूल शिक्षा में नवाचारों पर नव–सम्मेलन (नवमेश), 18–20 अप्रैल, 2017, सीआइईटी, एनसीईआरटी

17 जुलाई, 2017 को आइएचसी में अप्रशिक्षित इन–सर्विस शिक्षकों, डाइट और स्कूल नेतृत्व के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य योजना पर चर्चा के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालयकी बैठक का आयोजन।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूल नेतृत्व विकास–संबंधित राज्यों में माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करने पर विश्व बैंक के संयुक्त कार्यक्रम पर भागीदारी और प्रस्तुति।

सुनीता चुघ

प्रकाशन

प्रवास–विच्छेदित शहरी वंचितः दो शहरों की मलिन बस्तियों में बच्चों की शैक्षणिक स्थिति, भारतीय शैक्षिक अनुसंधान पत्रिका, खंड–6, मार्च 2017

शोध अध्ययन

जारी

'भारत में शहरी मलिन बस्तियों में शिक्षा में बच्चों की भागीदारी का समीक्षात्मक मूल्यांकन'। यह परियोजना देश भर के दस शहरों (हैदराबाद, भुवनेश्वर, रायपुर, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, भोपाल, कानपुर, लुधियाना और दिल्ली) में चल रही है। आवासीय आंकड़े संग्रहण का कार्य 8 शहरों में पूरा हो चुका है और शेष दो शहरों (मुंबई और रायपुर) में बहुत उन्नत अवस्था में है। लखनऊ, कानपुर, भोपाल और लुधियाना में स्कूल सर्वेक्षण शुरू किया गया है। हैदराबाद के स्कूलों से आंकड़ा संग्रहण पूरा हो गया है। घरों से एकत्र किए गए डेटा की प्रविष्टि आठ शहरों के लिए समाप्त हो गई है। लखनऊ, भोपाल, कानपुर, लुधियाना और दिल्ली शहरों के घरेलू आंकड़ों का विश्लेषण करके संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार की गई है। नौ शहरों का प्रोफाइल माध्यमिक डेटा (जनगणना और शहर की रिपोर्ट) के आधार पर तैयार किया गया है।

कार्यशाला/परामर्श आयोजन

17–28 अप्रैल, 2017 को दिल्ली में, लक्षद्वीप के स्कूल नेतृत्व विकास हेतु राज्य संसाधन समूह की सामर्थ्य विकास कार्यशाला।

समन्वयकः मेघालय के डीएसईओ, डीएमसी और बीएमसी के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन पर राज्य स्तरीय सम्मेलन, 25–26 अक्टूबर, 2017।

स्कूल रूपान्तरण हेतु रोडमैपः स्कूल नेतृत्व विकास और शिक्षक विकास पर क्षेत्रीय कार्यशाला – उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली में सीआइईटी में, 3–5 दिसंबर, 2017।

मानव संसाधन विकास मंत्रालयद्वारा 17–18 जुलाई, 2017 को आयोजित ट्रांसफॉर्मिंग स्कूल शिक्षा के लिए रोडमैपः पंजाब द्वारा चंडीगढ़ के मेंटरिंग की कार्यशाला में भाग लिया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालयद्वारा 27–28 जुलाई, 2017 को आयोजित ट्रांसफॉर्मिंग स्कूल शिक्षा के लिए रोडमैपः गुजरात के दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की कार्यशाला में भाग लिया।

27 नवंबर, 2017, नीपा, नई दिल्ली में 'भारत में शहरी मलिन बस्तियों के बच्चों की शैक्षिक भागीदारी का समीक्षात्मक मूल्यांकन' पर एक शोध परियोजना के लिए दस शहर अनुसंधान समन्वयकों की एक कार्यशाला आयोजित की।

शैक्षिक प्रशासन में अभिनव अभ्यास की मान्यताः स्कूलों का दौरा किया और कबीरधाम जिले के अधिकारियों के साथ बातचीत की और छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट तैयार की।

18–20 मार्च, 2018 को गंगटोक में स्कूल नेतृत्व विकास के लिए प्रणालीगत प्रशासकों की सामर्थ्य विकास।

"स्कूल लीडरशिप एंड डेवलपमेंट फॉर एजुकेशन ऑफिसर्स ऑफ वेस्ट बंगाल", 21 मार्च, 2018, कोलकाता पर एक दिवसीय ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया।

संगोष्ठी/कार्यशालाओं में भागीदारी

भारत की तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी में 8 वां वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, 'क्रिटिकलि एमपथी एंड वेल्फेयर इन कोण्टेंपोरारी एजुकेशन डिस्कोर्स" पर 16–18 नवंबर, 2017 जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू में,'प्राइवेटाइजेशन एज एन इररेवेरसीबले फोर्सः करेंट ट्रेंड्स इन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया' पर एक शोधपत्र प्रस्तुत किया।

17–18 जून, 2017 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 'समावेशी गुणवत्ता शिक्षाः सतत विकास लक्ष्य 4 की ओर' नामक सम्मेलन में उत्तर प्रदेश में लखनऊ के मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के बीच प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिक भागीदारी के मुद्दे को तलाशने और संबोधित करने पर एक पत्र प्रस्तुत किया।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

स्कूल नेतृत्व विकास पर मसौदा रोडमैप और नीति दिशानिर्देशों के विकास से संबन्धित।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुलाई गई प्री–स्कूल और माध्यमिक शिक्षा के लिए आरटीई के विस्तार पर सीएबीई उप–समिति की बैठकों में भाग लिया।

17–18 जनवरी, 2018 को हैदराबाद के विद्यालयों का दौरा किया और बच्चों के साथ फोकस समूह चर्चा भी की।

17–19 अगस्त, 2017 को जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली में 'अकादमिक नेतृत्व कार्यक्रम और इकाई लेखन' पर एक कार्यशाला में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया, और 'उच्च शिक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए व्यावसायिक शिक्षा समुदाय' पर एक मॉड्यूल तैयार किया।

एम.फिल. के समन्वयक के पाठ्यक्रम ओसी–10– शिक्षा, साक्षरता और आजीवन सीखना।

पाठ्यक्रम 3 परः भारत में शिक्षा, ओसी–7: समानता और बहुसांस्कृतिक शिक्षा, ओसी–5: शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय प्रशासन, ओसी–8: शिक्षा, लोकतंत्र और मानवाधिकार, ओसी–15: स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन विषयों पर एम.फिल. के विचार–विमर्श में भाग लिया।

पीजीडेपा कार्यक्रम में प्रतिभागी संगोष्ठी में एक एसोसिएटेड फैकल्टी के रूप में सहाभागिता।

'स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट (2–27 जून)' पर एक महीने के ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम में अग्रणी भागीदारी पर विभिन्न सत्र।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुरोध पर 'कुष्ठ प्रभावित लोगों के बच्चों की शैक्षिक स्थिति' पर एक शोध प्रस्ताव तैयार किया।

घोरेचा रमेशकुमार द्वारा 'नगरपालिका स्कूल बोर्ड, वडोदरा के प्राथमिक विद्यालय प्रमुख शिक्षकों के नेतृत्व की भूमिका पर एक अध्ययन' शीर्षक से पीजीडेपा शोध प्रबंध का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन किया।

मृदुस्मिता सिंह द्वारा 'सामाजिक बहिष्कार और स्कूली शिक्षाः दिल्ली और जयपुर की मलिन बस्तियों का तुलनात्मक अध्ययन' विषयक पीएचडी के पर्यवेक्षक।

अन्य गतिविधियां

एम.फिल./पीएचडी की लिखित परीक्षा लिपियों के मूल्यांकन कार्यक्रम समिति के सदस्य।

परीक्षा समिति के सदस्य

छात्र कल्याण समिति के सदस्य

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य

आवास आवंटन समिति के सदस्य

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहयोग

2017–18 के लिए चुनिंदा राज्यों के लिए स्कूल नेतृत्व विकास के लिए पीएबी बैठकों में भाग लिया

कश्यपी अवस्थी

प्रकाशन

नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म : ए रिसोर्स फॉर और टीचेर्स, अवर हीरोजः ए स्ट्रेरेजी एंड अप्रोच, राष्ट्रीय एनसीटीई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मई 2017

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाओं में भागीदारी

राष्ट्रीय

सीआइई, नई दिल्ली, 10–11 मार्च, 2017 को शिक्षक शिक्षाः वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावना पर राष्ट्रीय सम्मेलन में ''लीडिंग स्कूलः मूविंग फ्रम इस्सुज एंड चौलेंजेस टू पोटेन्सियल सोल्युशन इन स्कूल एजुयकेशन" नामक प्रपत्र प्रस्तुत किया।

इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग,मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 9 मार्च, 2017 को आयोजित 'स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पोर्टल' पर कार्यशाला में भाग लिया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालयकी सभी क्षेत्रीय कार्यशालाओं,रायपुर (21–22 अप्रैल), पुणे (28–29 अप्रैल), बैंगलोर (12–13 मई), गुवाहाटी (5–6 अप्रैल) और चंडीगढ़ (1–2 जून) 2017 में 'रोडमैप टू स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट' पर भाग लिया और प्रपत्र प्रस्तुत किया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय कीचार क्षेत्रीय समीक्षा कार्यशालाओं,जयपुर (12–13 अक्टूबर), श्रीनगर (3–4 अक्टूबर), केरल (10–11 नवंबर) और रांची (17–18 नवंबर) 2017 में 'रोडमैप टू स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट' पर भाग लिया और प्रपत्र प्रस्तुत किया।

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में 26 मार्च–20 अप्रैल, 2018 को अकादमिक स्टाफ कॉलेज में आयोजित चार सप्ताह के 'शिक्षक प्रशिक्षकों पर रिफ्रेशर कोर्स' में भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय

राजगीर, बिहार में 11–13 जनवरी 2018 को 4 वें अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 'धर्म धम्म परंपराओं में राज्य और सामाजिक व्यवस्था' में 'इंटरनेशनलाइजिंग धर्मा धम्म : हरनेससिंग इनर एंड आउटर एनवायरनमेंट एंड प्रैक्टिशिंग सस्टेनेबल डेव्लपमेंट"पर एक शोधपत्र प्रस्तुत किया।

कार्यशालाओं/सम्मेलनों का आयोजन

4–5 सितंबर, 2017 को प्रणालीगत प्रशासकों के लिए मसौदा रूपरेखा और स्कूल नेतृत्व विकास के रोडमैप के लिए राष्ट्रीय संसाधन समूह कार्यशाला।

एसआईईएमएटी, गोनेर, जयपुर, राजस्थान में समीक्षा और प्रतिक्रिया कार्यशालाएँ, 27–28 अप्रैल 2017।

एसआईईएमएटी, गोनेर, जयपुर, राजस्थान में समीक्षा और प्रतिक्रिया कार्यशालाएँ, 10–11 मई, 2017।

एसआईईएमएटी, गोनेर, जयपुर में 50 स्कूल प्रधानाध्यापकों के लिए स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पर एक महीने का सर्टिफिकेट कोर्स, 22 मई–18 जून, 2017।

एसआईईएमएटी, उत्तराखंड में 50 स्कूल प्रधानाध्यापकों के लिए स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पर एक महीने का सर्टिफिकेट कोर्स, 1–30 जून, 2017।

राजस्थान राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास पर एसआरजी सदस्यों की सामर्थ्य विकास,12–21 जुलाई, 2017।

हिमाचल प्रदेश राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास पर एसआरजी सदस्यों की सामर्थ्य विकास, 12–22 अगस्त, 2017।

गुजरात राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास पर एसआरजी सदस्यों की सामर्थ्य विकास, 3–13 अक्टूबर, 2017।

सभी दक्षिणी राज्यों के साथ स्कूल नेतृत्व विकास के लिए रोडमैप हेतु क्षेत्रीय कार्यशाला, 23–25 नवंबर, 2017।

अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास पर एसआरजी सदस्यों की सामर्थ्य विकास, 15–25 जनवरी, 2018।

अरुणाचल प्रदेश राज्य में ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए अभिविन्यास, 26 जनवरी, 2018।

पोर्ट ब्लेयर,अंडमान एंड एन इकोबार द्वीप समूह पर समीक्षा और प्रतिक्रिया कार्यशाला, 7–8 फरवरी, 2018।

गंगटोक, सिक्किम में स्कूल नेतृत्व विकास के लिए प्रणालीगत प्रशासकों की सामर्थ्य विकास, 15–20 मार्च, 2018।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम निर्माण/संचालन

सभी स्तरों के अधिकारियों के लिए 'लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी' के लिए स्कूल शिक्षा पर एक पाठ्यक्रम डिजाइन विकसित किया।

संयुक्त रूप से 'डाइट के सुदृढ़ीकरण' पर एक संकल्पना नोट विकसित किया और राज्यों की प्रासंगिक

आवश्यकताओं के आधार पर कार्यात्मक मॉडल विकसित किए।

'स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन' पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम समन्वयक और स्कूल नेतृत्व में परिप्रेक्ष्य पर मॉड्यूल विकसित किए।

उत्तर प्रदेश राज्य और संघ शासित राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए कार्य योजना विकसित की।

स्कूल नेतृत्व विकास पर रोडमैप और नीति दिशानिर्देशों का विकास किया।

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहयोग

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग,मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान (सीयूटीई) की स्थापना पर एक संकल्पना नोट विकसित करने के लिए गठित समिति के संयोजक और सदस्य।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा श्री संजय अवस्थी की अध्यक्षता में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) तैयार करने और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा संस्थान (एनआईटीई) स्थापित करने के नियमों के तहत समिति के सदस्य।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संस्थान की स्थापना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) विकसित करने के लिए गठित समिति के संयोजक और सदस्य।

शिक्षक शिक्षा निदेशालय, एससीईआरटी, ओडिशा द्वारा मेम्बर, थिंकटैंक, शिक्षक शिक्षा के रूप में नामांकित।

डाईट की मजबूती के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालयद्वारा गठित समिति के सदस्य।

डाईट को मजबूत करने के लिए दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए समिति के सदस्य। 30 नवंबर, 2017 को आंध्र प्रदेश में डाईट और एससीईआरटी को परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किया।

स्कूल शिक्षा जीसीईआरटी, गांधीनगर में गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्य,

हिमगिरी एजुकेशन रिव्यू (एचईआर) के सलाहकार संपादकीय बोर्ड के सदस्य आइएसएसएन 2321–6336।

एडिशनल सेक्रेटरी सुश्री रीना रे स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक कार्य योजना विकसित करने के लिए गठित समिति के सदस्य।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के लिए स्कूल शिक्षा पर पाठ्यक्रम डिजाइन विकसित करने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालयके सचिव द्वारा गठित समिति के सदस्य।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित स्कूल नेतृत्व पर रोडमैप के विकास के लिए समिति के सदस्य।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

संकाय विकास और अनुसंधान केंद्र, बनस्थली विद्यापीठ, में अकादमिक नेतृत्व पर सत्र लेने के लिए आमंत्रित, 26 अप्रैल, 2018।

एजुकेशन टुडे सोसाइटी टुडे, एशिया पठार, पंचगनी में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित, 6 मई, 2018।

शिक्षकों के लिए 2 एनपीएससी निबंध लेखन प्रतियोगिता के लिए जूरी सदस्य।

उत्तराखंड अकादमी, नैनीताल, 9–11 जनवरी, 2017 को डीओपीटी, सरकार द्वारा प्रायोजित, "इनहानसिंग

एफेक्टिव एजुकेशनल लीडरशिप इन टीचर्स' पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किया गया।

माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान, श्री वासुदेव देवनानीय श्री सी. एस. राजन, उपप्रभारी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री की सलाहकार परिषद (सीएमएसी), श्री नरेशपाल गंगवार, सचिव, स्कूल शिक्षाय डॉ. उर्वशी साहनी, सदस्य, शिक्षा, सीएमएसी, श्रीमती गौरी ईश्वरन, सदस्य, शिक्षा, सीएमएसी, श्रीमती सीमा बंसल, निदेशक, सामाजिक प्रभाव, बीसीजी; और सुश्री यूफ्रेट्स, शिक्षा प्रमुख, यूनिसेफ के साथ"राजस्थान में शिक्षा परिदृश्यः संभावनाएँ; आज और कल" पर एक पैनल चर्चा में मॉडरेटर, 26 जुलाई, 2017।

इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में शिक्षक शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "शिक्षक शिक्षा पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एक सुझाव एवं परीक्षण" पर एक सत्र के रूप में आमंत्रित किया गया, 25 अगस्त, 2017।

राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्कूल नेतृत्व विकास के लिए पीएबी बैठकों में भाग लिया, 2017–18।

फैकल्टी डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में 19 जून, 2018 को 'स्कूलों में व्यावसायिकता का विकासः रणनीतियाँ और हस्तक्षेप' पर नव भर्ती स्कूल प्रधानाध्यापकों की सामर्थ्य विकास के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

15 फरवरी, 2017 को 'माता–पिता के रूप में शिक्षक' पर व्याख्यान देने के लिए मॉडर्न स्कूल, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली में आमंत्रित किया गया।

शिक्षक शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी, 18–19 सितंबर, 2017 में, "एजुकेशनल लीडरशिप एंड लीडरशिप स्ट्रैटेजी एंड रोडमैप फॉर ट्रांसफॉर्मिंग स्कूल्स" पर दो सत्रों के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश के स्कूलों के आयुक्त के अनुरोध पर 'अकादमिक पर्यवेक्षण और निगरानी' पर नए भर्ती किए गए मंडल शिक्षा अधिकारियों को शैक्षणिक सहयोग और परामर्श प्रदान किया।

11 अप्रैल, 2017 को 'शिक्षक प्रेरणा और शिक्षक विकास' के मुद्दों पर स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालयके सचिव की अध्यक्षता में बैठक के लिए आमंत्रित किया गया।

केंद्रीय विद्यालय, सेक्टर 8, आरके पुरम, नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2017 को "44वें जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान, बच्चों के लिए गणितीय और पर्यावरण प्रदर्शनी, 2017" के लिए जूरी सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया।

योजना और निगरानी विभाग (पीएमडी), एनसीईआरटी, 27–28 फरवरी, 2017 द्वारा एससीईआरटी, सिक्किम, गंगटोक में 'परियोजना नियोजन, निगरानी और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के डीआईईटी संकाय के लिए मूल्यांकन' पर एक कार्यक्रम के लिए 'संस्थागत योजना, और संस्थागत मूल्यांकन' पर सत्र लेने के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

अनुसंधान मार्गदर्शन

जयपुर, राजस्थान में स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम के संबंध में सरकारी स्कूल प्रमुखों की धारणाओं का अध्ययन – भारत जोशी

प्रमुख विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की भूमिका और जिम्मेदारियों का एक अध्ययनः मॉरीशस के पांच राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का विश्लेषण – युगेश दत्त पांडे

एन. मैथिली

प्रकाशन

''भारत में स्कूल नेतृत्व स्थितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व'', समसामयिक प्रपत्र 51, 2017, नई दिल्ली: नीपा।

"ड्ज स्कूल लीडरशिप मैटर फॉर स्टूडेंट लर्निंग इन इंडिया? ए केस स्टडी ऑफ सिक्किम", भारतीय शैक्षिक समीक्षा, खंड–56, संख्या–2, 2017।

''प्रीपेरींग स्कूल फॉर द फ्यूचरः मूविंग अवे फ्रॉम द कोन्वेंशनल अप्रोच (2014)' सुश्री अहमद, रुस्मिनी (2014) द्वारा, जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन 31 (4), अक्टूबर 2017 में प्रकाशित पुस्तक समीक्षा।

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाओं में भागीदारी

स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम पर राज्य संसाधन समूह, पुडुचेरी (22 मई –1 जून, 2017) और राज्य संसाधन समूह, मणिपुर, (16–27 नवंबर, 2017) की सामर्थ्य विकास पर कार्यशाला।

एससीईआरटी, सिक्किम (10–23 जुलाई, 2017) में स्कूल नेतृत्व अकादमी के लिए एसआरजी की सामर्थ्य विकास पर कार्यशाला।

एसएलए, सिक्किम में एक महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम (17 अगस्त –16 सितंबर, 2017)।

एसएलडीपी, पुडुचेरी (2 जून, 2017), सिक्किम (17 जुलाई, 2017) और मणिपुर (27 नवंबर, 2017) के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए एक दिवसीय अभिविन्यास।

कार्यशालाएँ/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन

भारत के 12 राज्यों (19–24 मार्च, 2018) के लिए स्कूल लीडरशिप अकादमी के संकाय के लिए अभिविन्यास सामर्थ्य विकास।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकास/संचालन

स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन कार्यक्रम पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए प्रमुख नवाचारों के प्रमुख क्षेत्र पर पूरे पाठ्यक्रम मॉड्यूल को तैयार किया।

व्याख्यात्मक नोटों के साथ विस्तृत प्रारूप तैयार किया और पीजी डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट (पीजीडीएसएलएम) के लिए पुस्तिकाएं लिखने के लिए एक प्रोटोटाइप। टीम के अन्य सदस्यों द्वारा लिखे जाने के लिए विभिन्न पुस्तिकाओं पर काम का समन्वय करना।

एनसीएसएल के न्यूजलैटर को प्रदर्शित करने हेतु प्रारूप तैयार किया।

सिस्टम लेवल प्रशासकों हेतु ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के मॉड्यूल लिखने का एक सामान्य प्रारूप तैयार किया।

शिक्षण

एसएलडीपी (27 जुलाई, 2017) पर अपने एक महीने के अभिविन्यास कार्यक्रम में केवीएस प्रधानाध्यापकों के साथ–साथ लक्षद्वीप (18 अप्रैल, 2017) के प्रतिभागियों के लिए एसएलडीपी की 10–दिवसीय कार्यशाला में आईडेपा प्रतिभागियों के लिए सैद्धान्तिक सत्र 'डीसीजन मेकिंग' पर (10 अप्रैल, 2017) 'लीडिंग इनोवेशंस' के बारे में बताया गया।उत्तरी और पश्चिमी राज्यों के शामिल प्रतिभागियों को स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट (18 जनवरी, 2018 और 19 मार्च, 2018) के एक महीने के सर्टिफिकेट प्रोग्राम में 'नोईन्ग मोर अबाउट इन्वोवेशन' के बारे में सिखाया गया।

सिक्किम (जुलाई 10–19, 2017) और मणिपुर (16–27 नवंबर, 2017) में स्कूल नेतृत्व अकादमी के लिए एसआरजी कार्यशाला में सभी प्रमुख क्षेत्रों पर सत्र आयोजित किए गए। अग्रणी नवाचारों, भागीदारी निर्माण और पुडुचेरी में एसआरजी कार्यशाला में प्रमुख क्षेत्रों के समेकन (22 मई –1 जून, 2017) को साकार किया गया।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

स्कूल नेतृत्व अकादमी की स्थापना की। 18 जुलाई, 2017 को सिक्किम में एसएलडीपी कार्यक्रमों की वृद्धि हेतु सलाहकार का चयन करने के लिए साक्षात्कार आयोजित किए।

मणिपुर में स्कूल भी लीडरशिप अकादमी की स्थापना मार्च 2017 में की गई।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (17 और 24 अप्रैल, 2017) द्वारा आयोजित जेआरएम मीटिंग और जेआरएम रैप अप मीटिंग में भाग लिया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (25 मई, 2017) द्वारा सीएसआर की पहल कार्यशाला में भाग लिया।

दिल्ली के स्कूल प्रिंसिपल के लिए धर्म अकादमी में 'पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप' पर एक व्याख्यान दिया (21 जून, 2017)।

एससीईआरटी, दिल्ली (18–19 अगस्त, 2017) में पीएसएलएम हेतु अध्येताओं के चयन के लिए साक्षात्कार पैनल के सदस्य के रूप में भाग लिया।

नीपा में 23 फरवरी, 2018 को दौरे पर आए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (जिसे पहले आइएएमआर के नाम से जाना जाता था) के अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों को 'स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम' पर एक वक्तव्य दिया।

सुभीथा जी.वी.

प्रकाशन

शोध पत्रः रिकोन्सेप्चुलैजिंग टीचर्स कोंटीनुअस डेवलपमेंट वीथिन ए न्यू पैराडाइम ऑफ चेंज इन द इंडियन कांटेक्स्टः एन एनालिसिस ऑफ लिटरेचर एंड पॉलिसी डॉकयुमेंट, शिक्षा में व्यावसायिक विकास, 44 (1) 2018।

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाओं में भागीदारी

एसएसए, गुवाहाटी, 13 अगस्त, 2017 को अनुवर्ती डिजाइन पर एक दिवसीय अभिविन्यास।

एससीईआरटी, गुवाहाटी में नवनियुक्त स्कूल प्रधानाध्यापकों (3–31 जुलाई, 2017) के लिए स्कूल नेतृत्व पर एक महीने का आवासीय प्रेरण कार्यक्रम।

एसएलएजी, एससीईआरटी, गुवाहाटी (30 जून –2 जुलाई, 2017) से एसआरजी की सामर्थ्य विकास।

स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, पुदुचेरी (22 मई –1 जून, 2017) पर राज्य संसाधन समूह की सामर्थ्य विकास पर कार्यशाला।

एससीईआरटी, गुवाहाटी में स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर दो दिवसीय समीक्षा कार्यक्रम (29–30 मार्च, 2018)।

कार्यशालाएँ/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन

केवीएस स्कूल के प्राचार्यों के लिए स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन में एक महीने का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम – एक इंडक्शन प्रोग्राम (9 जुलाई – 12 अगस्त, 2017)।

स्कूल नेतृत्व विकास और शिक्षक विकास पर क्षेत्रीय कार्यशाला – पूर्व और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सीआइईटी, एनसीईआरटी, नई दिल्ली (11–13 दिसंबर, 2017)।

ओडिशा में स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर ऑनलाइन कार्यक्रम (16 दिसंबर, 2017)।

तेलंगाना राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) की सामर्थ्य विकास (6–10 जनवरी, 2018)।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकास/संपादन

मुख्य पाठ्यक्रम 'स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए ट्रांसफरिंग टीचिंग–लर्निंग प्रोसेस' पर संपूर्ण पाठ्यक्रम मॉड्यूल तैयार किया।

केवीएस स्कूल के प्रधानाध्यापकों के लिए एक इंडक्शन प्रोग्राम– स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन में एक महीने के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में'ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग–लर्निंग प्रोसेस'पर सैद्धान्तिक सत्र पढ़ाया (9 जुलाई –12 अगस्त, 2017)।

एंथोनी जोसेफ

संगोष्ठी/सम्मेलनों में सहभागिता

17 अप्रैल, 2017 नीपा – दिल्लीः 'कोन्सेप्चुयल कोंटेस्टेशनः प्रोड्यूसिंग जेंडर नॉलेज इन एंड फॉर हायर एजुकेशन' पर एमिली एफ हैंडरसन, सेंटर फॉर एजुकेशनल स्टडीज, वारविक विश्वविद्यालय, इंग्लैंड द्वारा संगोष्ठी।

2017, 18 अप्रैलः नीपा – दिल्लीः 'इंडियाज एड एंड सॉफ्ट पावर इन अफ्रीकाः द केस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर प्रो. केनेथ किंग और प्रवीना किंग, यूके द्वारा संगोष्ठी।

2017, 05 जुलाईः नीपा – दिल्लीः 'द रोल ऑफ टीचर्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडटेक इमर्जिंग इश्यूज एंड क्वेश्चन' पर डॉ. पेट्रीसिया बर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्स कैलिफोर्निया, यूएसए द्वारा संगोष्ठी।

2017, 22 अगस्तः नीपा – दिल्लीः 'वाट ड्ज माइ आईआईटीयन टैग एक्चुअल्ली मीन? रिलेशन्स बिट्वीन एजुकेशनल टाइटल्स एंड पोस्ट्सः द केस ऑफ आईआईटी स्टूडेंट्स' द्वारा प्रो ओडिले हेनरी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस 8, फ्रांस द्वारा संगोष्ठी।

2017, 31 अगस्तः नीपा – दिल्लीः 'गवर्नमेंट एंड एजुकेशान इन यूएस'पर डॉ. क्रेग एल डिकर, काउंसलर, सांस्कृतिक और शैक्षिक मामले, अमेरिकी दूतावास, नई दिल्लीद्वारा संगोष्ठी।

2017, 13 सितंबरः नीपा – दिल्लीः 'डूइंग फील्डवर्क एंड इट्स चौलेंजेसः रिफ्लेशन बिट्वीन एजुकेशनल टाइट्ल्स एंड पोस्ट्सः द केस ऑफ आईआईटी स्टूडेंट्स' पर सैयदा जेनिफा जहान, भूगोल विभाग, शै, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर द्वारा संगोष्ठी।

2017, 21 सितंबरः नीपा – दिल्लीः 'ग्लोबल स्किल्स एंड ग्रेजुएट आउटकम' पर डॉ. सारा रिचर्डसन, रिसर्च डायरेक्टर, ऑस्ट्रेलियन काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च इन इंडियाद्वारा संगोष्ठी।

2017, 02 नवंबरः नीपा – दिल्लीः 'विल फेलिंग स्टूडेंट्स हेल्प दैम लर्न? द आरटीई 2009 एंड द रिवर्सल ऑफ दश्नो डिटेंशन पॉलिसी' पर प्रो. नलिनी जुनेजा, पूर्व प्रोफेसर, नीपा द्वारा संगोष्ठी।

13 नवंबर, 2017, नीपा – दिल्लीः समुदाय आधारित अनुसंधान और सामाजिक जिम्मेदारी, यूनेस्को द्वारा नीपा में आयोजित नॉलेज फॉर चेंज– 'समुदाय आधारित अनुसंधान' पर अंतरराष्ट्रीय संघ का शुभारंभ।

20 नवंबर, 2017, नीपा – दिल्लीः 'ड्रेन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन इंडिया। इज स्कूल कोंसोलीटेशन, द आन्सर? एविडेंसेज फ्रम कर्नाटक', पर डॉ. शिवा कुमार जोलाड, पूर्व प्रोफेसर, आईआईटी, गांधीनगर द्वारा संगोष्ठी।

25 जनवरी, 2018, नीपा – दिल्लीः 'इंडियन माइग्रेशन टू यूएस',पर डॉ. नील जी. :इज, एसोसिएट डायरेक्टर, ग्लोबल माइग्रेशन एंड डेमोग्राफी, प्यू रिसर्च सेंटर, वाशिंगटन, डीसी द्वारा संगोष्ठी।

संगोष्ठी में प्रस्तुत प्रपत्र

तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी ऑफ इंडिया (CESI) – 2017 – जम्मू विश्वविद्यालय, 16–18 नवंबर, 2017।

शिक्षा में प्रदर्शन मूल्यांकन पर राष्ट्रीय संगोष्ठीः गुणवत्ता और उत्कृष्टता की ओर, 06–07 मार्च, 2018।

शिक्षक शिक्षा में प्रदर्शन मूल्यांकन के आत्मसात्करण परिप्रेक्ष्य की खोज।

'शांति, मानव अधिकार और सहिष्णुता के लिए शिक्षा' पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, 13–14 मार्च, 2018।

कार्यशालाएँ/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन

राष्ट्रीय व्यावसायिक विकास संसाधन सुविधा – राज्य संसाधन समूहों के लिए स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एसएलडीपी) पर सामर्थ्य विकास कार्यशाला, निम्नलिखित हैं:

दिल्ली में 17–28 अप्रैल, 2017 को लक्षद्वीप के लिए स्कूल नेतृत्व विकास हेतु राज्य संसाधन समूह की सामर्थ्य विकास कार्यशाला।

तमिलनाडु– तमिलनाडु में राज्य नेतृत्व अकादमी में स्कूल नेतृत्व विकास हेतु राज्य संसाधन समूह की सामर्थ्य विकास कार्यशाला – मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाइकनाल, 16–25 जून, 2017।

तमिलनाडु – स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट – तमिलनाडु में स्टेट लीडरशिप अकादमी में एक महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम – मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाइकनाल, 30 अक्टूबर – 30 नवंबर, 2017।

दिल्ली– स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट – केंद्रीय विद्यालय के 84 प्रधानाचार्यों के लिए स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट

में एक महीने का सर्टिफिकेट कोर्स, 12 जुलाई – 09 अगस्त, 2017।

दिल्ली – स्कूल परिवर्तन का रोडमैपः स्कूल नेतृत्व विकास और शिक्षक विकास पर क्षेत्रीय कार्यशाला–पश्चिमी क्षेत्र, 18–20 दिसंबर, 2017।

तमिलनाडु –स्कूल नेतृत्व और विकास कार्यक्रम के लिए राज्य संसाधन समूह के रूप में 450 TN SS। स्कूल प्रमुखों की सामर्थ्य विकास के लिए समन्वयक। 8–12 जनवरी, 2018।

रिपोर्ट अवधि में प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम निर्माण/संचालन

1. एसएलडीपी – एनसीएसएल के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल – नीपा

टीमों का निर्माण एवं मार्गदर्शन– मुख्य क्षेत्र 04

2. एसएलडीपी – दीक्षापोर्टल के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल

खंड 1ः टीमों का निर्माण – सहयोग और सहकारिता के लिए प्रक्रियाओं का निर्माण

मॉड्यूल का नाम – टीम विकास और प्रशिक्षण

खंड 1ः स्वयं, स्कूल और समाज

खंड 2ः टीम विकास जीवन चक्र

खंड 3ः संवाद, प्रशिक्षण टीमें और प्रशिक्षण

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहयोग

शिक्षकों के लिए शिक्षक फोरम बैठक में सहायता

दिल्ली एमसीडी स्कूल

दस स्कूल, दस मीटिंग – 15–31 मार्च, 2018

शिक्षक प्रशिक्षणः जिम्मेदारियाँ और अपेक्षाएँ

पढ़ाने से सीखने की ओर बदलावों पर केन्द्रित

शिक्षक प्रशिक्षण के लिए विषयवस्तु चुनाव

नीपा से बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

भारत की तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी (सीईएसआइ)

ब्लॉग

रिफ्लेक्सिव पेडागॉजीः ए कैंडिड एंड मोर्डेंट गेज अपोन टीचिंग एंड टीचर आइडेंटिटी (08/05/18)

रिफ्लेक्सिव पेडागॉजीः रिसर्चिंग टीचर एजुकेशन (03/05/18)

क्षमता–आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण (सीबीईटी) – संवेदनशील, आकर्षक, सहज (03/16/18)

70 में जुबली हॉलः ए कॉल टू रिमेंबर, रेजोइस, रेन्यू (10/02/18)

रिफ्लेक्सिव पेडागॉजीः इंटरोगेटिव एससीमिलेटेड एजुकेशनल पर्सपेक्टिव फॉर आ रोबस्ट जुरिसप्रूडेंस ऑफ डिग्निटी (10/20/17)

ए दिल्ली मेट्रो राइडः हाउ डू वी लर्न? (05/08/17)

चारु स्मिता मलिक

प्रकाशन

शोध पत्र

"उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का विकास – चयनित संकेतक का एक समय–श्रृंखला विश्लेषण", मैनपावर जर्नल, अंक–51 1 और 2, जनवरी–जून 2017।

कार्यशालाएँ/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन

महाराष्ट्र राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए स्टेट रिसोर्स ग्रुप (एसआरजी) की सामर्थ्य विकास, 21–27 नवंबर, 2017।

स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन, 15–20 जनवरी, 2018 को एक महीने के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के संचालन के लिए संसाधन व्यक्तियों के लिए सामर्थ्य विकास।

उत्तर प्रदेश राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए स्टेट रिसोर्स ग्रुप (एसआरजी) की सामर्थ्य विकास, बैच–1 (25 अक्टूबर–03 नवंबर, 2017), बैच–2 (06–15 नवंबर, 2017) – स्कूल नेतृत्व अकादमी द्वारा संचालित।

उत्तर प्रदेश राज्य में स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर एक महीने का सर्टिफिकेट कोर्स, 1–30 जून, 2017 – स्कूल नेतृत्व अकादमी द्वारा संचालित।

रिपोर्ट अवधि में प्रशिक्षण सामग्री/पाठ्यक्रम निर्माण/संचालन

स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए दो पाठ्यक्रम विकसित किए, pslm.nuepa.org:–

1. स्व–विकास

2. अग्रणी स्कूल प्रशासन

मोनिका बजाज

प्रशिक्षण कार्यक्रम/सम्मेलन/कार्यशालाओं का आयोजन

समूहिक गतिविधियों में भाग लेने और उनका ब्यौरा तैयार करने के अलावा स्कूल नेतृत्व पर निम्नलिखित राष्ट्रीय एवं प्रदेशीय स्तर के कार्यक्रमों के आयोजन में अकादमिक, प्रशासनिक और रसद सहायता प्रदान की:

सिस्टम लेवल अधिकारियों के लिए स्कूल नेतृत्व विकास पर कार्यशाला, 4–5 सितंबर, 2017।

संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 17–28 अप्रैल, 2017 को प्रधानाध्यापकों/मुख्याध्यापकों/सहायक मुख्य अध्यापकों/शैक्षिक अधिकारियों के लिए स्कूल नेतृत्व विकास पर सामर्थ्य विकास कार्यक्रम।

केंद्रीय विद्यालय (केवीएस) में भर्ती किए गए 81 नए प्रधानाध्यापकों के लिए स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर एक महीने का सर्टिफिकेट कोर्स, 12 जुलाई–अगस्त 9, 2017।

स्कूल नेतृत्व, प्रबंधन तथा संचालन के लिए संसाधन व्यक्तियों हेतु एक महीने की सर्टिफिकेट कार्यशाला, 15–20 जनवरी, 2018।

स्कूल नेतृत्व, प्रबंधन तथा संचालन के लिए संसाधन व्यक्तियों हेतु एक महीने की सर्टिफिकेट कार्यशाला, 19–24 मार्च, 2018

एक दिवसीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति की बैठक, 7 मार्च, 2018।

स्कूल परिवर्तन के लिए रोडमैपः स्कूल नेतृत्व विकास और शिक्षक विकास (दक्षिणी क्षेत्र) पर क्षेत्रीय कार्यशाला, 23–25 नवंबर, 2017।

स्कूल परिवर्तन के लिए रोडमैपः स्कूल नेतृत्व विकास और शिक्षक विकास (उत्तर–पूर्वी क्षेत्र) पर क्षेत्रीय कार्यशाला, 11–13 दिसंबर, 2017।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम निर्माण/संचालन

दो पाठ्यक्रमों के लिए ई–सामग्री, स्व–अनुदेशात्मक सामग्री और वीडियो संसाधन विकसित करने में शैक्षणिक सहयोग प्रदान करनाः टीमों के निर्माण एवं मार्गदर्शन और स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन में ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए अग्रणी भागीदारी।

शिक्षण

केंद्रीय विद्यालय (केवीएस) में भर्ती किए गए 81 नए प्रधानाध्यापकों के लिए स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर एक महीने का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षण सत्र लिया, जुलाई 12–अगस्त 9, 2017।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

राष्ट्रीय सलाहकार समूह (एनएजी) की बैठक और इन–हाउस मीटिंग्स जैसी एनसीएसएल की विभिन्न बैठकों की रिपोर्ट तैयार की।

राज्य के अधिकारियों, राष्ट्रीय संसाधन समूह (एनआरजी), राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) और स्कूल प्रमुखों का ई–डेटाबेस तैयार किया।

स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के परिप्रेक्ष्य में योजना बनाने के लिए यूडाइस 2016–17 से स्कूल डाटा एकत्रित किए।

उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र

एन.वी. वर्गीज

प्रकाशन

पुस्तकें प्रकाशित

वर्गीज एन.वी., सभरवाल, एन.एस. और सी. एम. मलिश (सं.). (2018). भारत उच्चतर शिक्षा रिपोर्ट 2016: समता नई दिल्ली: सेज।

प्रकाशित शोध पत्र/आलेख

शोध पत्र/आलेख

वर्गीज एन.वी., मलिक जी. और गौतम डी.आर. (2017). भारत में उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती: राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के परिणाम का विश्लेषण। सीपीआरएचई अनुसंधान प्रपत्र श्रृखला 8. सीपीआरएचई/नीपा, नई दिल्ली।

वर्गीज, एन.वी. (2017), उच्च शिक्षा में अंतर्देशीय–गतिशीलता एवं वैश्वीकरण, डैश टी. आर. और बेहेरा, एम. (सं.). एजुकेशनल एक्सैस एंड एक्सिलेन्स, एलाइड प्रकाशक, नई दिल्ली, पृ. 9–24।

वर्गीज एन.वी. (2017). भारत में उच्च शिक्षा को पुनर्जीवित करना। आइआइईपी न्यूजलैटर, अंक 33, संख्या 1 जनवरी–जून 2017, पृ.11।

वर्गीज एन.वी. (2017).भारत में अध्ययन क्षेत्र के रूप में शिक्षा अनुसंधान और उच्च शिक्षा का उद्भव. एशिया में उच्च शिक्षा पर शोध: इतिहास, विकास और भविष्य, जोइसुन जंग और अन्य द्वारा संपादित. स्प्रिंगर.पृ. 299–313।

वर्गीज एन.वी. और सरकार एन (2017).समूह का प्रबंधन : भारत में निजी उच्च शिक्षा का विश्लेषण.सीपीआरएचई/नीपा, नई दिल्ली।

वर्गीज एन.वी., सभरवाल एन.एस. और मलिश सी.एम. (2017). भारत में उच्च शिक्षा में समानता और समावेश, सीपीआरएचई/नीपा, नई दिल्ली।

वर्गीज, एन.वी. और सभरवाल, एन.एस. और मलिश, सी. एम. (2018). 'उच्च शिक्षा और समानता: आईएचईआर 2016 का परिचय', वर्गीज, एन.वी., सभरवाल, एन एस और मलिश, सी.एम. (सं.). भारत उच्चतर शिक्षा रिपोर्ट 2016: समता, नई दिल्ली: सेज।

अनुसंधान रिपोर्ट

वर्गीज, एन.वी., पाणिग्रही, जे. और रोहतगी, ए. (2017). 'भारत के उच्च और तकनीकी संस्थानों का केन्द्रीकरण एवं कम वितरण', सीपीआरएचई/नीपाअनुसंधान रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मानव संसाधन विकास मंत्रालय), भारत सरकार, नई दिल्ली को सौंपी गई।

कार्यशालाएँ/ सम्मेलन/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

- 9वीं आरएमएसए, संयुक्त समीक्षा मिशन (जेआरएम), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 15 जून, 2017 की समापन बैठक।
- उच्च शिक्षा समिति की बैठक, फिक्की, नई दिल्ली, 19 जून, 2017।
- उच्च शिक्षा में विविधता और भेदभाव पर विशेषज्ञ समूह की बैठक (सीपीआरएचई/नीपा), नई दिल्ली, 26 जून, 2017।
- 28 जून, 2017 को भारतीय उच्चतर शिक्षा, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल विश्वविद्यालय में व्यापक भागीदारी की चुनौती पर व्याख्यान।
- यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय में विविधता और व्यापक भागीदारी पर व्याख्यान।

- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एमआईएस अधिकारियों के लिए यूडीआईएसई और एसडीएमआईएस की राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा कार्यशाला का उद्घाटन, 04 जुलाई, 2017।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (जुलाई 8–10, 2017) द्वारा आयोजित कुलपतियों के लिए उच्च शिक्षा हेतु डिजिटल पहल पर राष्ट्रीय सम्मेलन।
- विश्व बैंक, नई दिल्ली, (18 अगस्त, 2017) द्वारा आयोजित प्रमुख मुद्दों और उच्च शिक्षा के रुझानों में संतुलन–गुणवत्ता–प्रासंगिकता पर गोलमेज सम्मेलन।
- शैक्षिक परिणामों पर सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों और स्कूली शिक्षा के प्रभारी सचिवों का एचआरएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस, अप्रशिक्षित शिक्षकों और बी.एड./डी.एड कॉलेजों से संबंधित मुद्दे – एचआरएम, (16 अगस्त, 2017) में अध्यक्षता।
- 21 अगस्त, 2017 को शिक्षा नीति संबंधी समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर के. कस्तूरी रंगन के साथ बैठक।
- 28 अगस्त, 2017 को वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च, बैंगलोर द्वारा आयोजित "नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क: कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसीसेस पर एक इंटरेक्टिव सेशन, थीम के साथ बी–स्कूलों के डीनर्स/ डायरेक्टर्स के गोलमेज सम्मेलन में दिया गया मुख्य भाषण।
- ऑस्ट्रेलिया बिजनेस वीक भारत –2017 द्वारा आयोजित भारतीय उच्च शिक्षा नीति और उसके विकास पर पैनल चर्चा, ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग 29 अगस्त, 2017।
- यूनेस्को नई दिल्ली क्लस्टर कार्यालय के नए परिसर का उद्घाटन श्री प्रकाश जावड़ेकर, एचआरएम और सुश्री इरीना बोकोवा, यूनेस्को के महानिदेशक ने संयुक्त रूप से किया, तत्पश्चात यूनेस्को नई दिल्ली और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा रात्रि भोज, 30 अगस्त, 2017।
- 31 अगस्त, 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) की कार्यकारी समिति की बैठक।
- जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन पर राज्य स्तरीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण, 19 सितंबर, 2017।
- 25 सितंबर, 2017 को भारत की नई शिक्षा नीति पर जेएनयू (एएजे) की बैठक के पूर्व छात्र संघ में व्याख्यान।
- (1) इक्विटी और उच्च शिक्षा में समावेश, और (2) निजी उच्च शिक्षा, 03 अक्टूबर, 2017 को दो नीपा शोध पत्रों पर विमर्श हेतु प्रोफेसर मार्गिन्सन के साथ बैठक।
- आईआईसी, 06 अक्टूबर, 2017 द्वारा आयोजित "उच्च शिक्षा और कौशलः गुणवत्ता, शासन और नवाचार" पर उच्च शिक्षा कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण में प्रस्तुति।
- 10 अक्टूबर, 2017 को महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एमएनएलयू) में एमएनएलयू के तीसरे स्थापना दिवस पर व्याख्यान।
- 04 नवंबर, 2017 को उच्च शिक्षा, आईआईसी में विपणन और समूहकरण की चुनौतियों पर व्याख्यान।
- 16 नवंबर, 2017 को तुलनात्मक शिक्षा सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीईएसआई) द्वारा आयोजित समकालीन शैक्षिक विमर्श की जटिलताओं, परानुभूति एवं सुधार पर मुख्य उद्घाटन भाषण।
- 06 दिसंबर, 2017 को एनएएसी द्वारा आयोजित भारतीय विश्वविद्यालयों (ईक्यूयूएएम–बीआई) में गुणवत्ता आश्वासन प्रबंधन और बेंच मार्किंग रणनीतियों को बढ़ाने पर उद्घाटन बैठक।
- 20 दिसंबर, 2017 को पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी), की दसवीं पीएबी को 'शिक्षक और शिक्षण'पर बैठक,मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

मोना खरे

कृप्या शौक्षिक वित्त विभाग देखें

निधि एस. सभरवाल

प्रकाशन

प्रकाशित पुस्तकें

वर्गीज एन.वी., सभरवाल, एन.एस. और सी.एम. मलिश (सं.). 2018. भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2016 – इक्विटी। नई दिल्लीः सेज।

प्रकाशित शोध पत्र/आलेख

टियरनी डब्ल्यू.जी. और सभरवाल एन.एस. (2018). भारतीय उच्च शिक्षा पुनर्कल्पना : उच्च शिक्षा संस्थानों की एक सामाजिक पारिस्थितिकी. टीचर्स कॉलेज रिकॉर्ड. अंक 120, संख्या 5।

वर्गीज, एन.वी. और सभरवाल, एन.एस. और मलिश, सी. एम. (2018). 'उच्च शिक्षा और समानताः आईएचईआर 2016 का परिचय'. वर्गीज, एन.वी.., सभरवाल, एन.एस. और मलिश, सी.एम. (सं.). भारत उच्चतर शिक्षा रिपोर्ट 2016ः इक्विटी नई दिल्लीः सेज।

मधुसूदनन जे., सभरवाल, एन.एस. और सी.एम. मलिश (2018). ''समानता और उत्कृष्टताः नवोदय विद्यालय का एक अध्ययन''. वर्गीज, एन.वी., सभरवाल, एन.एस. और मलिश, सी.एम. (सं.). भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2016ः इक्विटी नई दिल्लीः सेज।

सभरवाल, एन.एस. और मलिश, सी.एम. (2018). 'विविधता और भेदभावः नागरिक शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा की भूमिका' वर्गीज, एन.वी., सभरवाल, एन.एस. और मलिश, सी.एम. (सं.). भारत उच्चतर शिक्षा रिपोर्ट 2016ः इक्विटी नई दिल्लीः सेज।

निधि एस सभरवाल (2018). माइंड द गैपः सम्मेलन के अवसरों के लिए प्रवेश में लिंग और जाति आधारित असमानताएँ. https://conferenceinference.wordpress.com/2018/02/12/guest-post-by-nidhi-s-sabharwal-mind-the-gap-gendered-and-caste-based-disparities-in-access-to-conference-opportunities.

सभरवाल, एन.एस. (2017). भारत में एक उच्चतर शिक्षा प्रणाली में समावेश की चुनौतियाँ और छात्र विविधता, अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा.संख्या 91. पृ.25–27।

टियरनी डब्ल्यू.जी. और सबरवाल एन.एस. (2017). शैक्षणिक भ्रष्टाचारः भारतीय उच्च शिक्षा में संस्कृति और विश्वास। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेव्लपमेंट. 55. पृ.30–40।

बुरूहा वी.के. और सभरवाल एन.एस. (2017). भारतीय शिक्षा के एक माध्यम के रूप में अंग्रेजीः शैक्षिक अवसरों तक पहुंच की असमानता, सीपीआरएचई शोध पत्र श्रृंखला।

टियरनी, डब्ल्यू. जी., सभरवाल, एन.एस. (आगामी). असमान संरचनाएंः भारतीय उच्च शिक्षा में वर्ग और जाति. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्वालिटेटिव स्टडीज इन एजुकेशन।

सीपीआरएचई नीति संक्षेप

सभरवाल, एन.एस. और सी.एम. मलिश (2017). भारत में उच्च शिक्षा के लिए समान पहुँच (2017). सीपीआरएचई पॉलिसी ब्रीफ 1. दिल्लीः उच्च शिक्षा में नीति अनुसंधान केंद्र/नीपा, नई दिल्ली।

सभरवाल, एन.एस. और सी.एम. मलिश (2017). भारत में उच्च शिक्षा में शैक्षणिक एकीकरण की प्राप्ति (2017). सीपीआरएचई पॉलिसी ब्रीफ्स 2. दिल्लीः उच्च शिक्षा में नीति अनुसंधान केंद्र/नीपा, नई दिल्ली।

सभरवाल एन.एस. और सी.एम. मलिश (2017). भारत में सामाजिक रूप से समावेशी उच्च शिक्षा परिसरों का विकास (2017). सीपीआरएचई पॉलिसी ब्रीफ्स 3. दिल्लीः उच्च शिक्षा में नीति अनुसंधान केंद्र/ नीपा, नई दिल्ली।

सीपीआरएचई रिपोर्ट/मिमियो

सभरवाल एन.एस. और सी.एम. मलिश (2017). 'छात्र विविधता और भारत में उच्च शिक्षा में भेदभाव' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी पर रिपोर्ट. सीपीआरएचई/नीपा, नई दिल्ली।

वर्गीज एन.वी., सभरवाल, एन.एस. और सी.एम. मलिश (2017). भारत में उच्च शिक्षा में समानता और समावेश। ब्रिटिश काउंसिल दिल्ली में प्रो. साइमन मार्गिन्सन के साथ बैठक के लिए तैयार किया गया ड्राफ्ट प्रपत्र। दिल्लीः उच्च शिक्षा में नीति अनुसंधान केंद्र, नीपा।

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाओं में भागीदारी

राष्ट्रीय

तुलनात्मक और ग्लोबल एजुकेशन (सीसीजीई) केंद्र, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग (आइआइएचईडी), ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जगदीशपुर, जिला सोनीपत, हरियाणा द्वारा आयोजित 'भारत में उच्च शिक्षा में छात्र विविधता और नागरिक शिक्षाः अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य, अंतरराष्ट्रीय रीसर्च सिम्पोजियम 2017', 'जानने एवं करने के अन्य तरीके': उच्च शिक्षा में सामाजिक विज्ञान के ज्ञान का वैश्विकरण, 11–12 दिसंबर, 2017।

19 फरवरी, 2018 को शिक्षा विभाग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'उच्च शिक्षा तक पहुंचः समकालीन मुद्दे'।

12–13 फरवरी, 2018 को नीपा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी,'भारत में शहरी हाशियापन, सामाजिक नीति और शिक्षा'में एक प्रपत्र 'हाशिए के भविष्य का पथ–प्रदर्शन : छात्र आकांक्षाएं और उच्च शिक्षा संस्थान' प्रस्तुत किया गया (सी.एम. मालिश के साथ संयुक्त रूप से)।

12 फरवरी, 2018 को इंडिया हैबिटट सेंटर, नई दिल्ली मेंमैसाचुसेट्स एमहर्स्ट और पुणे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित, 'समावेशी विश्वविद्यालयः 21 वीं सदी के लिए समानता, विविधता और उत्कृष्टता में संबद्धता' पर सिंपोजियम।

7–8 सितंबर, 2017 को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित "उच्च सिक्षा का भविष्यः 'सामाजिक–आर्थिक संदर्भ" पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।

12 अगस्त, 2017 को इंपीरियल होटल, नई दिल्ली में, विश्व बैंक समूह द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा पर गोलमेज सम्मेलन।

अंतरराष्ट्रीय

22–23 फरवरी, 2018 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में सीपीआरएचई द्वारा आयोजित 'उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता' विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी।

17–18 जून, 2017 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में, द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'इंटरनेशनल एंड क्वालिटी एजुकेशनः टूवार्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4' पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन।

कार्यशालाएँ/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

13 मार्च, 2018 को सीपीआरएचई कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन किया।

सीपीआरएचई/नीपा – उच्च शिक्षा में छात्र विविधता और सामाजिक समावेश पर मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय, एमहर्स्ट बैठकः नीपा, नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2018।

सीपीआरएचई/नीपा(सीएम मलिश के साथ संयुक्त रूप से) 'उच्च शिक्षा की सफलता और सामाजिक गतिशीलताः विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एससी/एसटी/ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग योजनाओं पर एक अध्ययन' प्रोजेक्ट की पहली शोध पद्धति कार्यशाला, 2–3 मई, 2017।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम निर्माण/संचालन

20 जुलाई, 2017 को नीपा में प्रोफेसर कुमार सुरेश द्वारा समन्वित 'अकादमिक लेखन कार्यशाला' के एक भाग के रूप में एम.फिल. और पीएचडी शोधार्थियों के लिए 'अकादमिक लेखन और शोध पत्र प्रकाशन' पर सत्र आयोजित किए गए।

10–17 जुलाई, 2017 को नीपा, नई दिल्ली में (सी. एम. मलिश के साथ संयुक्त रूप से) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विविधता और समानता के प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यशाला, में 'उच्च शिक्षा संस्थानों में सकारात्मक कार्रवाई और समावेशः नीतियां और व्यवहार' पर एक सत्र का संचालन।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

अनुसंधान पद्धति पर मुख्य पाठ्यक्रम के लिए एम. फिल. पाठ्यक्रम की समीक्षा समिति के सदस्य (सीसी 3–I)।

शिक्षा नीति पर मुख्य पाठ्यक्रम के लिए एमफिल पाठ्यक्रम समीक्षा समिति के सदस्य (सीसी 4)।

अनुसंधान पद्धति पर मुख्य पाठ्यक्रम के लिए एम. फिल. पाठ्यक्रम की समीक्षा समिति के सदस्य (सीसी 5–II)।

निष्पक्षता और बहु–सांस्कृतिक शिक्षा (ओसी 7) के वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए एम. फिल पाठ्यक्रम समीक्षा समिति के सदस्य।

विकलांगों की शिक्षा समावेश (ओसी–13) पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए एम.फिल. पाठ्यक्रम समीक्षा समिति के सदस्य।

नीपा के परिप्रेक्ष्य योजना के लिए 'अभिगम, समता और विविधता पर प्रोफेसर रश्मि दीवान, नीपा द्वारा आहूत अनुसंधान एजेंडा विकसित करने हेतु गठित समूह के सदस्य।

नीपा में 2017 के लिए एम.फिल./पीएचडी उम्मीदवार के आवेदनों की स्क्रीनिंग।

शिक्षण कार्यभार/मूल्यांकन

21 अगस्त, 2017 को राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के अनिवार्य पाठ्यक्रम 1 के लिए 'वंचितों की शिक्षा, शिक्षा पर परिप्रेक्ष्य' विषय पर एम. फिल. कक्षा में शिक्षण कार्य।

24–25 अप्रैल, 2017 को 'वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा में भेदभाव और बहिष्कार, 7 शीर्षक समता और बहुसांस्कृतिक शिक्षा' विषय पर एम. फिल. कक्षा में शिक्षण कार्य।

14–19 अप्रैल, 2017 को 'सीमांत श्रेणी का समावेशः नीतियां और वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए चुनौतियां' विषय पर एम.फिल. कक्षा में शिक्षण कार्य।

20 जुलाई, 2017 को नीपा द्वारा आयोजित 'लेखन एवं प्रपत्र प्रकाशन पर लेखन कला कार्यशाला में एक सत्र पढ़ा।

पीएचडी निर्देशन एवं संपादकीय सदस्यता

पीएचडी कार्य पर कोर समूह के सदस्य – उच्च शिक्षा के लिए लैंगिक मार्ग, वारविक विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम।

बोर्ड ऑफ जेंडर एंड एजुकेशन के संपादकीय सदस्य।

यूकेआरआई इंटरनेशनल डेवलपमेंट पीयर रिव्यू कॉलेज के सदस्य।

शोध अध्ययन

पूर्ण अनुसंधान परियोजना

नागरिक शिक्षा और लोकतांत्रिक अनुबंध हेतु उच्च शिक्षाः उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और भेदभाव का अध्ययन

भूमिकाः प्रधान अन्वेषक

उच्च शिक्षा प्रणाली और शिक्षार्थियों की संख्या में विविधता को ध्यान में रखते हुए, इस शोध परियोजना का उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षा परिसरों में विविधता और भेदभाव का पता लगाना है। उच्च शिक्षा के विस्तार और वर्ग तथा जाति की सीमाओं से बाहर निकलने वाले परिवारों के आकांक्षात्मक स्तरों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आज गैर–पारंपरिक सामाजिक समूहों की एक बड़ी संख्या कॉलेज परिसरों में प्रवेश करती है, और अब यह परिसर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, लिंग, भाषाई विविधता, क्षेत्रीय और शारीरिक क्षमता वाले पृष्ठभूमि के छात्रों से भरे हुए हैं। यद्यपि यह उच्च शिक्षा में समता प्राप्ति की दिशा में एक सकारात्मक कदम प्रतीत होता है, फिर भी मौजूदा शोध उन मुद्दों को अध्ययन का विषय बनाता है जो उच्च शिक्षा परिसरों में सामाजिक विभाजन और इससे जुड़े अभ्यास, पूर्वाग्रह और मूल्यों से पुनः उत्पन्न हो रहे हैं।

इस परियोजना ने इन परिसरों की संरचना और तंत्र की प्रकृति और विविधता के रूपों को समझने का प्रयास किया जो विविधता और भेदभाव से निपटने के लिए मौजूद हैं। परियोजना ने यह भी अध्ययन किया कि विविधता द्वारा प्रदान किए गए अवसर को नागरिक और लोकतांत्रिक शिक्षा विकसित करने तथा समकालीन समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए

मान्यता प्राप्त संस्थानों को बेहतर करने की दिशा में सकारात्मक लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सूचना के संग्रह और विश्लेषण के लिए अध्ययन में मात्रात्मक और गुणात्मक पद्धति के मिले–जुले रूप को शामिल किया गया। इस अध्ययन में 3200 छात्रों के बीच एक विस्तृत प्रश्नावली आधारित सर्वेक्षण कराया गया साथ हीसंकाय और प्रशासकों के साथ 200 साक्षात्कार और छात्रों के साथ लगभग 70 फोकस समूह चर्चाओं का आयोजन किया गया। इस अध्ययन को छह राज्यों, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में स्थित संस्थानों में लागू किया गया था। छह राज्यों की अनुसंधान रिपोर्ट और विश्लेषण पूरा हो गया है एवं रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए अक्टूबर 2016 में अनुसंधान सलाहकार समिति को प्रस्तुत किया गया था। अनुसंधान रिपोर्टों को आरएसी में प्रस्तुत करने से पहले, रिपोर्टों में अध्यायों की गहन समीक्षा की गई थी और तीसरी शोध पद्धति कार्यशाला में रिपोर्ट की सहकर्मी समीक्षा की तैयारी में समन्वयकों द्वारा विस्तृत प्रतिक्रिया दी गई थी। तीसरी शोध पद्धति कार्यशाला 7–8 जून, 2016 को आयोजित की गई थी।

शोध परियोजना के लिए तीसरी कार्यप्रणाली कार्यशाला का उद्देश्य ड्राफ्ट अनुसंधान रिपोर्टों पर चर्चा और समीक्षा करने और विश्लेषण रिपोर्ट पर चर्चा करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। केंद्र में तैयार विश्लेषण रिपोर्ट में छात्र सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़े और विश्लेषण तथा साक्षात्कार फोकस समूह चर्चा के विषयगत विश्लेषण शामिल थे। तीसरी अनुसंधान पद्धति कार्यशाला की बैठक में ऊपर सूचीबद्ध 12 उच्च शिक्षा संस्थानों के अनुसंधान दलों के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यशाला का आयोजन एक पियर रिव्यू बैठक के रूप में किया गया था। एक अन्य शोध टीम के सदस्यों में से एक ड्राफ्ट अनुसंधान रिपोर्ट के लिए चर्चा करने वाला था, जिसके बाद कार्यशाला में उपस्थित अनुसंधान टीमों के सभी सदस्यों ने चर्चा की।

सीपीआरएचई में शोध टीम के मार्गदर्शन और अनुसंधान दल के सहयोग से अग्रिम रूप से ड्राफ्ट शोध रिपोर्टों का प्रारूप तैयार किया गया था। कार्यशाला का आयोजन इस तरह से किया गया था कि शोध टीमों को पूर्ण प्रस्तुति करने के लिए पर्याप्त समय मिल सका और इसके उपरांत चर्चा भी हुई। ड्राफ्ट पर टिप्पणी करते समय सामान्य दिशानिर्देशों का पालन किया गयाः टिप्पणियां केवल मसौदा रिपोर्टों की समीक्षा पर आधारित थीं; विश्लेषण और लेखन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गएय लेखन और तर्कों में आंतरिक स्थिरता पर ध्यान दिया गया था; प्रत्येक खंड/उप–खंड और उसी के लिए उपयोग किए गए डेटा सेट पर विकसित तर्कों पर ध्यान केंद्रित किया गया था; डेटा त्रिकोणीयकरण पर जोर दिया गया था, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा का पर्याप्त संबंध हो; समीक्षकों ने उन पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया जहां पर ड्राफ्ट में परिणामों तक पहुँचने हेतु 'क्यों' की व्याख्या, परिणामों के विवरण (क्या) के साथ परिणामों की प्रक्रिया (कैसे) आदि के बारे में जिक्र था।

समूह से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, शोध रिपोर्टों को संशोधित किया गया और 18 अक्टूबर, 2016 को आयोजित तीसरी सलाहकार अनुसंधान समिति में प्रस्तुत किया गया। केंद्र ने 27–28 फरवरी, 2017 को इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें अकादमिक, शिक्षाविदों को एक साथ लाया गया और देश भर के नीति निर्माताओं ने भारत में उच्च शिक्षा में छात्र विविधता, और समता शामिल करने के लिए गहराई से जानकारी दी। केंद्र की योजना है कि शैक्षिक प्रशासकों को संवेदनशील बनाने के लिए नीतिगत संक्षेप और मॉड्यूल को सामने लाया जाए। यह परियोजना ICSSR द्वारा वित्त पोषित है।

प्रमुख निष्कर्ष

इस अध्ययन ने भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र विविधता को वर्गीकृत करने की एक विधि विकसित की। जिससे छात्र विविधता के तीन चरणों की पहचान की जाती हैः प्रथम चरण, सामाजिक विविधता है जो मात्रात्मक हैय राष्ट्र की जनसंख्या में मापने सकने योग्य एवं दृशयात्मक पहलू। द्वितीय चरण, शैक्षणिक विविधता है जिसमें शैक्षणिक परिणामों में समता हासिल करने के लिए शैक्षणिक अंतर को प्रदर्शित किया जाता है। तृतीय चरण, विविधता सामाजिक समावेशन की एक शर्त है, जिसमें उच्च शिक्षा में शामिल विभिन्न प्रकार विद्यार्थियों के अनुभवों को आकार देने वाले भेदभाव के रूपों को प्रदर्शित किया जाता है।

अध्ययन पाया गया कि शैक्षिक विषय क्षेत्रों के चुनाव में असमानता बनी हुई है। सुविधा प्राप्त समूहों (जैसे गैर–एससी/एसटी/ओबीसी सामाजिक समूह के छात्र) के छात्र तेजी से विज्ञान और इंजीनियरिंग अध्ययन कार्यक्रम चुनते हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि यह पूर्व–कॉलेज के शैक्षणिक अनुभवों में भिन्नता के कारण हो सकता है। सुविधा प्राप्त सामाजिक समूहों के छात्रों ने ज्यादातर सामाजिक–बहिष्कृत समूहों (जैसे एससी, एसटी और ओबीसी) के छात्रों, जिनका शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा है और वह सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, के विपरीत अंग्रेजी माध्यम वाले निजी स्कूलों में दाखिला लिया है। अध्ययन के विषयों के चुनाव में सामाजिक समूह की असमानता जाति और जातीयता के आधार पर विषयों के स्तरीकरण की ओर ले जाती है। शिक्षा में इस तरह के अनुशासनात्मक स्तरीकरण मौजूदा असमानताओं और अध्ययन के बाद रोजगार की संभावनाओं और प्रकृति से संबन्धित है।

इसके अलावा, वंचित सामाजिक–आर्थिक समूह के छात्र भी उच्च शिक्षा स्तरों पर सीखने में सहायता और समर्थन प्रदान करने वाली सीमित सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी के साथ पहली पीढ़ी के विद्यार्थी होने की अधिक संभावना रखते हैं। प्रवेश बिंदु पर पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी होने के नाते छात्र विविधता के प्रति संकाय सदस्यों के नकारात्मक दृष्टिकोण और अकादमिक असमानताओं के सीमित संस्थागत पहल से कक्षाओं में शैक्षणिक कमजोरियों के रूप में कई नुकसान उठाने पड़ते हैं। जो सामाजिक रूप से छात्रों के शैक्षणिक एकीकरण और उनकी शैक्षणिक सफलता की संभावना को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। इस प्रकार, जबकि समग्र सामाजिक विविधता में सुधार हुआ है फिर भी शैक्षणिक सफलता के अवसरों में सामाजिक समूह की असमानता अब भी मौजूद है।

अध्ययन के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि अब भी उच्च शिक्षा परिसरों में भेदभाव जारी है। यह पाया गया कि छात्र विविधता को बढ़ाने के लिए प्रमुख संकाय सदस्यों और संस्थागत नेतृत्व का रवैया ज्यादातर नकारात्मक है। समानता को संस्थागत बनाने और छात्रों को भेदभाव से बचाने के लिए उच्च शिक्षा अधिकारियों से उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर सेल, महिला सेल, एंटी–रैगिंग सेल जैसे सेल बनाने के स्पष्ट निर्देश हैं। अनुभवजन्य निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि यद्यपि सभी प्रकार की संस्थागत व्यवस्थाएं (प्रकोष्ठ के रूप में) मौजूद हैं, बावजूद इसके यह प्रकोष्ठ प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहे हैं, प्रकोष्ठों के बारे में छात्रों में जागःकता की कमी थीय कई लोग नहीं जानते थे कि किससे संपर्क करें और शिकायत कैसे करें। ऐसा लगता है कि प्रकोष्ठों की कार्यक्रम योजना, निगरानी और समन्वय में संस्थागत रुचि सीमित है, जो उन्हें उन छात्रों के लिए प्रभावी और सहायक बनाने के लिए है जिनकी उन्हें अत्यधिक जरूरत है।

अध्ययन से यह भी पता चलता है कि हमने परिसरों में विविधता हासिल करने के मामले में कुछ प्रगति तो अवश्य ही की है। प्रवेश के समय सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों ने स्तर विविधता को प्राप्त करने में योगदान दिया है। हालांकि, परिसरों में विविधता के मुद्दों को प्रदर्शित करने हेतु विस्तृत परीक्षण एवं प्रगतिशील कार्रवाई की आवश्यकता है। लेकिन, संस्थागत नेतृत्व में विविधता और असंवेदनशीलता के प्रति दृष्टिकोण की कमी उच्च शिक्षा में विविधता और समता पर विमर्श में शून्यता की स्थिति पैदा कर सकती है। जबकि विविधता के परिप्रेक्ष्य को विकसित करना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें छात्र विविधता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है।

इससे स्पष्ट है कि स्तर–II और स्तर–III की विविधता तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा की आवश्यकता है। हालांकि स्तर–II और स्तर–III की विविधता प्राप्त करने के लिए बाहरी कारक भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, स्तर–II और स्तर–III की विविधता को प्राप्त करना संस्थान का आंतरिक मामला है। यह अध्ययन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हम परिसर में विविधता को प्रदर्शित करने के प्रथम चरण में पहुंच गए हैं, जहां संस्थानों के भीतर इस पहल को ध्यान देने की आवश्यकता है। यह वह है जिसे हम छात्र विविधता की बदलती प्रकृति को प्रदर्शित करने में 'संस्थागत मोड़' के रूप में कह सकते हैं। 'संस्थागत मोड़' उन तरीकों में भारी बदलाव का अनुमान लगाता है जिसमें संस्थान काम कर रहे हैं, और संस्थागत हितधारकों जैसे कि संकाय सदस्यों और शैक्षणिाक प्रशासकों के दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में परिवर्तन होते हैं।

संस्थागत स्तर पर पहली और सबसे महत्वपूर्ण विविधता पहल छात्र विविधता को अधिक सकारात्मक और निधि के रूप में समझने हेतु प्रमुख नेतृत्व और संकाय सदस्यों को संवेदनशील बनाना है। संस्थाएँ भी सीखने को बढ़ावा देने में विविध भूमिका निभाती हैं और उन मतभेदों के बारे में संवाद करती हैं जो परिसर के पर्यावरण पर प्रभाव डालती हैं। 'दूसरों' के बारे में जागरूकता सहित शैक्षणिक हस्तक्षेप और विभिन्न स्तरों पर बातचीत सकारात्मक परिसर पर्यावरण और अंतर–समूह संबंधों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल है। इस प्रकार, संविधान के आदर्शों को महसूस करने और समाज के लोकतंत्रीकरण में योगदान देने हेतु, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को विविधता, नागरिक शिक्षा और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान, मूल्यों और कौशल हासिल करने में छात्रों की मदद करने की आवश्यकता है।

6 राज्य टीम रिपोर्ट और एक संश्लेषण रिपोर्ट इस परियोजना के एक भाग के रूप में तैयार की गई है।

उच्च शिक्षा में विविधता और भेदभावः डॉ. निधि एस. सबरवाल और डॉ. सी. एम. मलिश, नई दिल्ली, सीपीआरएचई/नीपा, 2016 द्वारा भारत के चयनित राज्यों में संस्थानों का एक अध्ययन।

उच्च शिक्षा में विविधता और भेदभावः प्रोफेसर आशा सिंह, डॉ. फजल अहमद और डॉ. बरना गांगुली, नई दिल्ली, सीपीआरएचई/नीपा, 2016 द्वारा बिहार में चयनित संस्थानों का अध्ययन।

उच्च शिक्षा में विविधता और भेदभावः प्रोफेसर निधि, डॉ, श्रवण कुमार और डॉ. रोमा स्मार्ट जोसेफ, नई दिल्ली, सीपीआरएचई/नीपा, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश में चयनित संस्थानों का एक अध्ययन।

उच्च शिक्षा में विविधता और भेदभावः कर्नाटक में डॉ. श्रीजित अलथुर, प्रोफेसर ए.एच. सेकेरा और डॉ. बी. वी. गोपालकृष्ण, नई दिल्ली, सीपीआरएचई/नीपा, 2016 द्वारा चयनित संस्थानों का एक अध्ययन।

उच्च शिक्षा में विविधता और भेदभावः डॉ. एच.ए. हुड्डा, डॉ. ए.वी. तलमले और डॉ. ए.सी. बैंकर, नई दिल्ली, सीपीआरएचई/नीपा, 2016 द्वारा महाराष्ट्र में चयनित संस्थानों का अध्ययन।

उच्च शिक्षा में विविधता और भेदभावः प्रोफेसर के एक्स जोसेफ, डॉ. टी.डी. साइमन, डॉ. के. राजेश, नई दिल्ली, सीपीआरएचई/नीपा, 2016 द्वारा केरल में चयनित संस्थानों का एक अध्ययन।

उच्च शिक्षा में विविधता और भेदभावः डॉ. सी.वी. बाबू और डॉ. सत्येंद्र ठाकुर, सीपीआरएचई/नीपा, 2016 द्वारा दिल्ली में चयनित संस्थानों का एक अध्ययन।

अनुसंधान परियोजना (जारी)

उच्च शिक्षा की सफलता और सामाजिक गतिशीलताः एससी/एसटी/ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए यूजीसी कोचिंग योजनाओं पर एक अध्ययन।

भूमिकाः सह–प्रधान अन्वेषक

उच्च शिक्षा की सफलता और सामाजिक गतिशीलताः एससी/एसटी/ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए यूजीसी कोचिंग योजनाओं पर एक अध्ययन के लिए रिसर्च स्टडी प्रोजेक्ट का उद्देश्य यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (यूजीसी) द्वारा शुरू की गई योजनाओं के प्रभावों की जाँच करना है। शिक्षा की सफलता, कैरियर और वंचितों की व्यावसायिक गतिशीलता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सीपीआरएचई/नीपा से यूजीसी द्वारा प्रायोजित कोचिंग योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक अध्ययन करने का अनुरोध किया। यूजीसी ने 11वीं योजना अवधि के बाद से उच्च शिक्षा में वंचित समूहों के लिए कोचिंग योजनाएं शुरू कीं। यह पिछले एक दशक में अस्तित्व में रहा है। योजना के प्रमुख उद्देश्य शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और कैरियर की गतिशीलता के उनके सफल समापन की सुविधा के लिए वंचित समूहों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाओं के रूप में अतिरिक्त शिक्षण इनपुट प्रदान करना है। वे कोचिंग योजनाएँ निम्नलिखित हैंः 1. एससी/एसटी/ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए उपचारात्मक कोचिंग, 2. एससी/एसटी/ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए

नेट/सेट की कोचिंग, और 3. एससी/एसटी/ओबीसी और अल्पसंख्यक के लिए नौकरी प्राप्ति हेतु कोचिंग क्लास।

यह अध्ययन निम्नलिखित व्यापक शोध प्रश्नों द्वारा निर्देशित है:

1) यूजीसी कोचिंग योजनाओं के लाभार्थी कौन हैं जो सामाजिक समूहों द्वारा अलग हैं?

2) कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में यूजीसी की कोचिंग योजनाएँ कैसे लागू की जा रही हैं?

3) छात्र की सफलता पर कोचिंग योजनाओं का क्या प्रभाव है?

4) योजनाओं को लागू करने में क्या अड़चनें हैं?

अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

क) यूजीसी कोचिंग योजनाओं के लाभार्थियों के सामाजिक समूह की संरचना का विश्लेषण करना;

ख) संस्थागत और यूजीसी स्तर पर यूजीसी कोचिंग योजनाओं की कार्यान्वयन प्रक्रिया को समझना;

ग) कोचिंग योजनाओं को लागू करते समय प्रत्येक हितधारकों (जैसेः संकाय सदस्यों, समन्वयकों, संस्थागत नेतृत्व और यूजीसी प्रशासकों) द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और बाधाओं को समझना;

घ) कोचिंग कक्षाओं में सीखने, प्रतिक्रिया प्रणालियों और सहकर्मी समूह बातचीत के संदर्भ में छात्र अनुभवों का पता लगाना;

च) रोजगार के लिए नेट/सेट और प्रतियोगी परीक्षाओं में अकादमिक प्रगति और सफलता पर कोचिंग योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करना; तथा

छ) कोचिंग नीतियों के कार्यान्वयन को मजबूत करने वाली नई नीतियों और प्रथाओं को विकसित करना।

इस अनुसंधान परियोजना के तहत पूरी की जाने वाली गतिविधियाँ हैं:

1) अध्ययन के लिए एक विस्तृत अनुसंधान प्रस्ताव विकसित किया गया था और यूजीसी की स्वीकृति के लिए यूजीसी के पास भेजा गया था।

2) अनुमोदन के बाद, केंद्र ने संस्थानों को केस स्टडीज के लिए पहचाना। संस्थानों की पहचान की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल थे: पहले कदम के रूप में, इन योजनाओं का लाभ उठाने वाले संस्थानों की सूची यूजीसी मुख्यालय और यूजीसी क्षेत्रीय कार्यालयों से ली गई; यूजीसी क्षेत्रीय कार्यालयों से सूची और सुझावों के आधार पर, केस स्टडी के लिए संस्थानों की एक अस्थायी सूची तैयार की गई। केस स्टडी संस्थानों के चयन के लिए निम्न विंदुओं पर विचार किए गए: 1. क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व; 2. संस्थानों के प्रकार का प्रतिनिधित्व; 3. तीनों योजनाओं को लागू करने वाले संस्थान; 4. तुलनात्मक रूप से उच्च बजट आवंटन; 5. एससी–एसटी बहुल क्षेत्र से संस्थान; 6. अल्पसंख्यकों की सेवा करने वाले संस्थान; और 7. महिलाओं की सेवा करने वाली संस्थाएँ।

3) केंद्र ने शिक्षाविदों, यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ एक अनुसंधान सलाहकार समिति का गठन किया। जिसकी पहली बैठक 4 अक्टूबर, 2016 को आयोजित की गई, जिसमें अध्ययन के प्रस्ताव, कार्यप्रणाली और अध्ययन के लिए चयनित संस्थानों पर चर्चा की गई। समिति की सिफारिश के आधार पर, 12 संस्थानों को केस स्टडी करने के लिए अंतिम रूप दिया गया है।

4) मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान उपकरण विकसित किए गए। अनुसंधान उपकरण में संस्थागत स्तर पर उपलब्ध द्वितीयक आँकड़े एकत्र करने वाले प्रारूप भी शामिल हैं, वर्तमान में कोचिंग कक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के बीच सर्वेक्षण प्रश्नावली, उत्तीर्णछात्रों के साथ समूह चर्चा तथाकोचिंग कक्षाओं के संस्थागत नेतृत्व, संकाय समन्वयकों, संकाय सदस्यों/प्रशिक्षकों के के साथ साक्षात्कार किए गए।

दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वंचित समूहों के शैक्षणिक सशक्तीकरण से जुड़े यूजीसी कोचिंग योजनाओं और संकाय सदस्यों के समन्वयक के परामर्श

से अध्ययन के लिए शोध उपकरणों का विश्लेषण किया गया। साधन विकास कार्यशाला का आयोजन 22 दिसंबर, 2016 को किया गया था। इन चर्चाओं ने उन तरीकों की जमीनी तस्वीर प्रदान की, जिन तरीकों से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में इस योजना को लागू किया गया है। इसके बाद, प्रत्येक उपकरण पर विस्तार से चर्चा की गई।

5) सदस्यों से मिली जानकारी के आधार पर, अनुसंधान उपकरणों को संशोधित और अंतिम रूप दिया गया।

अध्ययित किए जाने वाले सभी संस्थानों में अनुसंधान दल के चुनाव के सभी औपचारिकताएँ पूरी हो चुकी हैं। अध्ययित संस्थानों में अनुसंधान दल बनाने की प्रक्रिया में उन संस्थानों के समन्वयकों के चुनाव के लिए भी संस्थानों के प्रमुखों के साथ परामर्श किए गए। अनुसंधान सहयोग को औपचारिक बनाने के लिए समन्वयकों से पत्र व्यवहार किया गया था।

6) अध्ययित संस्थानों के अनुसंधान समन्वयकों के साथ पहली शोध पद्धति कार्यशाला का आयोजन किया जा चुका है।

7) परियोजना शुरू की जा चुकी है।

यह अध्ययन भारत में 12 राज्यों में स्थित 12 उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू किया जा रहा है, अर्थात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, दिल्ली, केरल, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और मेघालय।

अनुपम पचौरी

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाओं में भागीदारी

राष्ट्रीय

उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा विभाग की ओर से 7–8 सितंबर, 2017 को नीपा, नई दिल्लीः आइईएऔर नीपा में भारतीय आर्थिक संघ के शताब्दी वर्ष में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी 'उच्च शिक्षा का भविष्यः आर्थिक और सामाजिक संदर्भ' में 'भारत में उच्च शिक्षा में शिक्षण सुधारः संतुलन अनुभव एवं पहुँच' पर एक पत्र प्रस्तुत किया।

अंतरराष्ट्रीय

मुंबईः ईक्यूयूआईपीपीपीएस, जेएनयू और टिस में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से 26–27 फरवरी, 2018 को टीआईएसएस मुंबई, सार्वजनिक–निजी भागीदारी में अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक नेटवर्क कार्यशाला में 'पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप' के संदर्भ में 'पब्लिक गुड' को पुनर्परिभाषित करने के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी पर पैनल में एक प्रपत्र 'शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी के 'प्रचार' का प्रश्न' प्रस्तुत किया। सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी का आयोजन किया गया।

इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 22–23 फरवरी, 2018 को सेंटर फॉर पॉलिसी इन रिसर्च इन हायर एजुकेशन (सीपीआरएचई), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (नीपा) और ब्रिटिश काउंसिल की ओर से आयोजित 'इंटरनेशनल संगोष्ठी ऑन क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन' विषय पर डॉ. सयंतन मंडल के साथ 'भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों पर बाह्य और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन का प्रभावः राष्ट्रीय अध्ययन के निष्कर्ष' पर प्रपत्र प्रस्तुत किया।

कार्यशालाएँ/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 22–23 फरवरी, 2018 को सेंटर फॉर पॉलिसी इन रिसर्च इन हायर एजुकेशन (सीपीआरएचई), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (नीपा) और ब्रिटिश काउंसिल की ओर से आयोजित 'इंटरनेशनल संगोष्ठी ऑन क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन' विषय प्रोफेसर एनवी वर्गीस के साथ सह–संयोजक।

नई दिल्ली में 6–7 सितंबर, 2017 कोसेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन हायर एजुकेशन, नीपा की राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजना ''भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ताः संस्थागत स्तर पर आंतरिक और बाह्य गुणवत्ता आश्वासन का एक अध्ययन'' शीर्षक से संगठित अनुसंधान रिपोर्ट की समीक्षा (तीसरी शोध पद्धति कार्यशाला) आयोजित की।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम निर्माण/संचालन

'उच्च शिक्षा स्नातक में रोजगार' अनुसंधान परियोजना के लिए चयनित भारतीय राज्यों के विश्वविद्यालयों के शोध दल के संकाय सदस्यों हेतु 19 जनवरी, 2018 को द्वितीय अनुसंधान पद्धति कार्यशाला में 'उच्च शिक्षा स्नातक के नियोजन के आँकड़ों का गुणात्मक डेटा विश्लेषण' पर प्रोफेसर मोना खरे, नई दिल्लीः सीपीआरएचई–नीपा द्वारा समन्वित रूप से एक सत्र आयोजित किया, 18–19 जनवरी, 2018।

नीपामें एम.फिल और पीएचडी शोधार्थियों हेतु अकादमिक लेखन कार्यशाला' के एक भाग के रूप में 18 जुलाई, 2017 को 'अकादमिक लेखन में साहित्य समीक्षा' पर प्रोफेसर कुमार सुरेश द्वारा समन्वित रूप से सत्र आयोजित किया।

डॉ. नरेश कुमार, शैक्षिक नीति विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित 'शिक्षा में अनुसंधान विधियों पर कार्यशाला' में 25 अक्टूबर, 2016 को वार्ता की सहमतिः सहमति और शोधकर्ता के निर्माण के मुद्दे' पर अध्यापन।

शोध पद्धति के लिए दस संस्थानों (चार राज्य विश्वविद्यालयों और एक संबद्ध कॉलेज और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कॉलेज में से एक) से अनुसंधान टीमों के लिए अनुसंधान पद्धति कार्यशाला सामग्री विकसित की गई है – 'भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता : संस्थागत स्तर पर आंतरिक और बाह्य गुणवत्ता आश्वासन का अध्ययन। 'शोध सामग्री में 1) संस्थागत प्रोफाइल विकसित करने के लिए; 2) प्रारूप; संकाय के लिए सर्वेक्षण प्रश्नावली; 3) छात्रों के साक्षात्कार के लिए सर्वेक्षण प्रश्नावली; 4) संस्थागत नेतृत्व के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम – i) कुलपति, ii) रजिस्ट्रार, iii) वित्त अधिकारी, iv) विश्वविद्यालय स्तर पर विभाग के प्रमुख, v) कॉलेज स्तर पर विभाग के प्रमुख, vi) कॉलेज प्रिंसिपल vii) कॉलेज लेखाकार; और 5) संकाय के साथ फोकस समूह चर्चा के लिए विषयगत प्रारूप, और बाहरी गुणवत्ता आश्वासन और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन के कारण छात्रों को संस्थानों में होने वाले परिवर्तनों को समझना शामिल हैं, नई दिल्लीः सीपीआरएचई–नीपा।

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहयोग

सीपीआरएचई/नीपा में एन.वी. वर्गीस और अनुपम पचौरी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय मूल्यांकन परियोजना 'पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन पर शिक्षक और शिक्षण (पीएमएमएमएनएमटीटी)' के मूल्यांकन परियोजना। समन्वयक/प्रधान अन्वेषकः प्रोफेसर एन. वी. वर्गीस, डॉ. अनुपम पचौरी और डॉ. सयतन मंडल।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

अनुसंधान परियोजना (जारीः अनुसंधान परियोजना समन्वयक/सीपीआरएचई/नीपा प्रमुख अनुसंधान परियोजना, यूजीसी द्वारा प्रायोजित) भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ताः संस्थागत स्तर पर बाह्य और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन का एक अध्ययन।।

आइएचईआर 2017 के समन्वयक/सह–संपादकः विषय पर भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2017: उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और शिक्षण–प्रशिक्षण' को प्रोफेसर एन.वी. वर्गीस और डॉ. सयतन मंडल के साथ सह–संपादित किया जा रहा है। आइएचईआर 2017 के सह–संयोजकों के सहयोग से एक अवधारणा नोट विकसित किया गया। मसौदा अध्यायों की समीक्षा की गई और अध्यायों पर विस्तृत प्रतिक्रिया दी गई है। लेखकों द्वारा प्रस्तुत अंतिम अध्यायों की पांडुलिपियों को अंतिम रूप देने के लिए संसाधित किया जा रहा है।

अन्य संस्थागत गतिविधियों में योगदान

एम.फिल. पाठ्यक्रम विकासः शिक्षा और कौशल विकास पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम समिति के सदस्य (ओसी 02), डॉ. विनीता सिरोही, शैक्षिक प्रशासन विभाग, नीपा द्वारा समन्वित।

एम.फिल. पाठ्यक्रम विकासः अंतरराष्ट्रीय और तुलनात्मक शिक्षा पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम समिति के सदस्य (ओसी 03) डॉ मोना सेडवाल, शिक्षा विभाग, नीपा में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण विभाग द्वारा समन्वित।

एम.फिल. पाठ्यक्रम विकासः वैश्वीकरण और शिक्षा पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम समिति के सदस्य (ओसी 12), प्रोफेसर मोना खरे, शैक्षिक वित्त विभाग, नीपा द्वारा समन्वित।

एम.फिल. पाठ्यक्रम विकासः व्यावसायिक विकास और शिक्षकों के प्रबंधन पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम समिति के सदस्य (ओसी 15), प्रोफेसर प्रणति पांडा, स्कूल मानक और मूल्यांकन इकाई, नीपा द्वारा समन्वित।

नीपा के प्रोफेसर कुमार सुरेश द्वारा बुलाई गई नीपाके परिप्रेक्ष्य योजना के लिए 'शासन, प्रबंधन और जवाबदेही' पर शोध एजेंडा विकसित करने के लिए समूह के सदस्य।

समन्वयक/सह–संपादकः विषय पर भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2017: उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और शिक्षण– प्रोफेसर एन वी वर्गीज और डॉ. सांयतन मंडल। आइएचईआर 2017 के सह–संयोजकों के सहयोग से एक अवधारणा नोट विकसित किया गया। मसौदा अध्यायों की समीक्षा की गई और अध्यायों पर विस्तृत प्रतिक्रिया दी गई। लेखकों द्वारा प्रस्तुत अंतिम अध्यायों की पांडुलिपियों को अंतिम रूप देने के लिए संसाधित किया गया। अंतिम पांडुलिपि सितंबर 2017 में प्रकाशकों को सौंपी गई थी जिसे सेज द्वारा वर्ष 2018–19 में प्रकाशन के लिए स्वीकार कर लिया गया है।

एम.फिल. नीपा 2017 के उम्मीदवारों के आवेदनों की स्क्रीनिंग।

नीपा से बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

सदस्यः अंतरराष्ट्रीय और तुलनात्मक शिक्षा के लिए ब्रिटिश एसोसिएशन (बीएआइसीई)

आजीवन सदस्यः भारत की तुलनात्मक शिक्षा समिति (सीईएसआइ)

गरिमा मलिक

प्रकाशन

शोध पत्र/आलेख प्रकाशित

भारत में उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्तीः राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के परिणाम का विश्लेषण' सीपीआरएचई/ नीपा रिसर्च प्रपत्र सीरीज 8, नई दिल्ली (संयुक्त रूप से एन.वी. वर्गीस और डी.आर. गौतम के साथ), अक्टूबर 2017।

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाओं में भागीदारी

राष्ट्रीय

कार्यशालाओं में सहभागिता

30 जनवरी, 2018 को कनोरिया पीजी महिला महाविद्यालय, जयपुर में 'उच्च शिक्षा में गुणवत्ता वृद्धि हेतु शिक्षाशास्त्र के दृष्टिकोण का पुनरसंगठन' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'उच्च शिक्षा के विकास में हितधारकों और संस्थानों की भूमिका' पर पैनालिस्ट।

7–8 दिसंबर, 2017 को नीपा, प्राइड प्लाजा, एयरोसिटी द्वारा आयोजित कुलपति नेतृत्व कार्यशाला का संचालन।

26–28 मार्च, 2018 को नीपा, प्राइड प्लाजा, एयरोसिटीद्व ारा आयोजित विश्वविद्यालय प्रशासकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यशाला संचालन।

अंतरराष्ट्रीय

''भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तताः वैश्वीकरण के युग की जरूरत''। विश्व–भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन, 23–25 फरवरी, 2018 को अर्थशास्त्र और राजनीति विभाग द्वारा आयोजित 'वैश्वीकरण और विकास' पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रपत्र प्रस्तुत किया गया।

कार्यशालाएँ/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

11–12 सितंबर, 2017 को सीपीआरएचई/नीपा, नई दिल्ली द्वारा राज्य रिपोर्ट और राष्ट्रीय संश्लेषण रिपोर्ट के मसौदे पर चर्चा करने के लिए तीसरी अनुसंधान पद्ध ति कार्यशाला का आयोजन किया।

15–16 फरवरी, 2018 को नीपा, नई दिल्ली में उच्च शिक्षा बैठक का आयोजन किया।

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहयोग

'राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर वृत्ति योजना का मूल्यांकन' (प्रोफेसर एन.वी. वर्गीज के साथ) के लिए तैयार रिपोर्ट की। अगस्त 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

सीपीआरएचई वार्षिक रिपोर्ट (2016–17) तैयार की गई (डॉ. सायंतन मंडल के साथ)।

सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में यूजीसी–मानव संसाधन विकास केंद्र के लिए संसाधन व्यक्ति। 18 जनवरी, 2018 को अनुसंधान पद्धति पर अल्पकालिक कार्यक्रम में 'नीति संक्षेप तैयार करना' पर व्याख्यान दिया।

वैश्वीकरण और शिक्षा पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए एम. फिल पाठ्यक्रम की समीक्षा समिति के सदस्य (ओसी–12)।

अंतरराष्ट्रीय और तुलनात्मक शिक्षा (ओसी–3) पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए एम.फिल. पाठ्यक्रम समीक्षा समिति के सदस्य।

नीपा से बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

सदस्य – इंडिया हैबिटेट सेंटर

सदस्य – अंतरराष्ट्रीय केंद्र, गोवा

जिनुशा पाणिग्रही

प्रकाशन

जर्नल आलेख

''उच्च शिक्षा के अभिनव वित्तपोषण: बदलते विकल्प और निहितार्थ'' शीर्षक वाला प्रपत्र जर्नल 'हायर एजुकेशन फॉर द फ्यूचर', केरल स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल (KSHEC), केरल सरकार, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली, खंड संख्या 5, सं. 1, पृ. 61–74, जनवरी 2018।

अनुसंधान अध्ययन/संगोष्ठी रिपोर्ट

जून 2017 में एन.वी. वर्गीज और ए. रोहतगी के साथ 'भारत में उच्च और तकनीकी संस्थानों की संकेन्द्रण एवं वितरण' पर अनुसंधान परियोजना की रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मानव संसाधन विकास मंत्रालय), भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया।

''उच्च शिक्षा के वित्तपोषण में नवाचार'' नामक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी पर संयुक्त रूप से एन.वी. वर्गीज, दिसंबर 2017, नई दिल्ली पर रिपोर्ट प्रस्तुत की।

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाओं में भागीदारी

राष्ट्रीय

उच्च शिक्षा संस्थानों के वित्तपोषण के स्त्रोतों का बदलाव: समेकन का आकलन, ''उच्च शिक्षा का भविष्य: आर्थिक और सामाजिक संदर्भ'' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत, उच्चतर एंव व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपा, नई दिल्ली 07–08 सितंबर, 2017

12 अगस्त, 2017 को विश्व बैंक द्वारा सम्मेलन कक्ष में आयोजित 'उच्च शिक्षा में प्रमुख मुद्दे और रुझान: एमिली ईडन एंड होजेस, द इंपीरियल होटल, नई दिल्ली, राउंड टेबल में भाग लिया।

17–18 जून 2017 को भारत के अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में यूनिसेफ और केरल सरकार के सहयोग से सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित 'केरल मॉडल से सतत विकास लक्ष्य 4 के लिए समावेशी गुणवत्ता शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन' में भाग लिया।

व्याख्यान आमंत्रण

प्रो–वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, प्राचार्य और वित्त अधिकारी , नीपा के उच्च शिक्षा विभाग के लिए आयोजित 'विशेष रूप से उच्च शिक्षा में वित्त पोषण पर विशेष पाठ्यक्रम'

पर उच्च शिक्षा के वित्तपोषण के विभिन्न तरीकों पर दिए गए व्याख्यान; नई दिल्ली मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर, 30 अक्टूबर–03 नवंबर, 2017।

03 अप्रैल, 2017 को नीपा, नई दिल्ली में शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा में 'शिक्षा के लिए संसाधनों की व्यवस्था' विषय पर व्याख्यान दिया।

05 अप्रैल, 2017 को नीपा, नई दिल्ली में शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा में 'शिक्षा में संसाधनों का उपयोग' विषय पर व्याख्यान दिया।

संगोष्ठी/कार्यशालाओं में सहयोग

26–28 फरवरी, 2018 को एरोसिटी, नई दिल्ली में शैक्षिक वित्त विभाग, नीपा द्वारा आयोजित, 'रजिस्ट्रारों के लिए उच्च शिक्षा में नेतृत्व विकास' पर कार्यशाला में एक सत्र आयोजित किया।

22–23 फरवरी, 2018 को एयरो सिटी, नई दिल्ली में इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन में सेंटर फॉर हायर एजुकेशन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में 'क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन' विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में 'बाह्य गुणवत्ता आश्वासन' (पूर्ण सत्र) पर एक सत्र आयोजित किया।

7–8 दिसंबर, 2017 को ऐरो सिटी, नई दिल्ली में उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपाद्वारा आयोजित 'उप–कुलपतियों के लिए उच्च शिक्षा में नेतृत्व विकास' पर कार्यशाला में 'लीडरशिप डेवलपमेंट फॉर इंप्रूव्ड इंस्टीट्यूशनल परफॉरमेंस (प्लेनरी सेशन) के लिए एक सत्र' आयोजित किया गया।

17–18 जून, 2017 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा यूनिसेफ और केरल सरकार के सहयोग से आयोजित 'सतत विकास लक्ष्य के लिए समावेशी गुणवत्ता शिक्षा और केरल मॉडल से सीख' पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 'द केरल मॉडल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंटः लेसन इन गवर्नेंस, क्रॉस–सेक्टोरल लिंकेज एंड पार्टनरशिप' पर एक सत्र आयोजित किया।

अंतरराष्ट्रीय

19 मार्च–06 अप्रैल, 2018 को वाशिंगटन (डीसी), संयुक्त राज्य अमेरिका में तीन सप्ताह के लिए 'उच्च शिक्षा में यूएस–भारत संबंध विकास' अंतरराष्ट्रीय आगंतुक नेतृत्व कार्यक्रम (IVLP) के लिए अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा भारत से एक अंतरराष्ट्रीय आगंतुक के रूप में नामांकित।

कार्यशालाएँ/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

16 जनवरी, 2018 को राष्ट्रीय नीपा, नई दिल्ली में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के छात्रों और संकायों के साथ नीपाका एक परिचयात्मक सत्र आयोजित किया।

25–26 सितंबर, 2017 को नीपा, नई दिल्ली में 'भारत में सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों के वित्त पोषणः उनके अध्ययन का प्रवाह और उनके उपयोग का वित्त पोषण' विषय पर आयोजित अनुसंधान पद्धति कार्यशाला/पियर रिव्यू बैठक।

14 सितंबर, 2017 को नीपा, नई दिल्ली में एन.वी.वर्गीज के साथ 'उच्च शिक्षा के वित्तपोषण' पर भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2018 की दूसरी सहकर्मी समीक्षा बैठक का आयोजन किया।

30 मई, 2017 को नीपा, नई दिल्ली में एन.वी.,वर्गीज के साथ 'उच्च शिक्षा के वित्तपोषण' पर भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2018 की पहली सहकर्मी समीक्षा बैठक का आयोजन किया।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

पाठ्यक्रम विकास और उत्तर आलेख मूल्यांकन

डायरेक्ट पीएचडी, अंशकालिक पीएचडी और एम. फिल. कार्यक्रम का उत्तर स्क्रिप्ट मूल्यांकन 2017–18, नीपा, नई दिल्ली।

वैश्वीकरण और शिक्षा पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम (ओसी 12) के लिए एम. फिल पाठ्यक्रम की समीक्षा टीम के सदस्य तथा नीपा, नई दिल्ली में 15 जनवरी, 2018 को आयोजित बैठक में भाग लिया।

वैश्वीकरण और शिक्षा पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम (ओसी 12) के लिए एम. फिल पाठ्यक्रम की समीक्षा टीम के सदस्य तथा 09 जनवरी, 2018 को, नीपा, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लिया।

लिंग, शिक्षा और विकास पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम (ओसी 9) के लिए एम. फिल पाठ्यक्रम की समीक्षा टीम के सदस्य तथा 28 नवंबर, 2017 को नीपा, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय और तुलनात्मक शिक्षा पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम (ओसी 3) के लिए एम. फिल पाठ्यक्रम की समीक्षा टीम के सदस्य तथा 27 नवंबर, 2017 को नई दिल्ली में नीप ापर आयोजित बैठक में भाग लिया।

अनुसंधान परियोजना (जारी)

'भारत में सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों का वित्तपोषणः धन का प्रवाह और उनके उपयोग का एक अध्ययन' में रिसर्च प्रोजेक्ट समन्वयक/प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, सीपीआरएचई/नीपा प्रमुख रिसर्च प्रोजेक्ट (यूजीसी द्वारा प्रायोजित)।

सीपीआरएचई/नीपा पर एन.वी., वर्गीज के साथ "भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की केन्द्रीकरण और अति आपूर्ति" पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय परामर्श परियोजना का समन्वय।

नीपा में शिक्षण गतिविधियाँ

पढ़ाए गए पाठ्यक्रम

03 अप्रैल, 2017 को नीपा, नई दिल्ली में शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा) में 'शिक्षा के लिए संसाधन एकत्रण' विषय पर व्याख्यान दिया।

नीपा, नई दिल्ली, 05 अप्रैल, 2017 को शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा) में 'शिक्षा में संसाधनों का उपयोग' विषय पर व्याख्यान दिया।

सम्मेलनों/संगोष्ठियों में भागीदारी

नीपा में अन्य आंतरिक गतिविधियां

कार्यशालाओं/बैठकों में अध्यक्षता सत्र

14–16 दिसंबर, 2017 को स्कूल और गैर–औपचारिक शिक्षा विभाग, नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'भारत में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की भागीदारी में सुधार' पर कार्यशाला में एक सत्र की अध्यक्षता की।

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

तुलनात्मक और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी, संयुक्त राज्य अमेरिका के सह अध्यक्ष (चुनाव)।

भारत के तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी (सेसी) के सदस्य।

मलिश सी.एम.

प्रकाशन

प्रकाशित पुस्तकें

भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2016ः इक्विटीः (2018)। सेजः नई दिल्ली (संयुक्त रूप से एन.वी. वर्गीस और निधि एस. सभरवाल के साथ)।

प्रकाशित शोध पत्र/आलेख

उच्च शिक्षा अनुसंधान क्षेत्र, भारत (2018). सी. शिन, पी. तेइसीइरा (सं.), इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंटरनेशनल हायर एजुकेशन सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस. स्प्रिंगर।

भारत में उच्च शिक्षा में छात्र विविधता और समावेश की विधियाँ (2017), अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा, 91, पृ. 25–27 (निधि एस सभरवाल के साथ संयुक्त रूप से)।

पुस्तकों में अध्याय

शिक्षा और समानताः आइएचईआर 2016 (2018) का परिचय, वर्गीज,एन. वी., निधि एस. सबरवाल और सी.एम. मलिश (सं.), भारत उच्चतर शिक्षा रिपोर्ट 2016: इक्विटी सेजः नई दिल्ली, पृ. 1–15 (संयुक्त रूप से एन.वी. वर्गीस और निधि एस. सभरवाल के साथ)।

समानता और उत्कृष्टताः जवाहर नवोदय विद्यालय (2018) का एक अध्ययन, वर्गीज, एन.वी., निधि एस. सबरवाल और सी.एम. मलिश (सं.)। भारत उच्चतर शिक्षा रिपोर्ट 2016: इक्विटी सेजः नई दिल्ली, पृ. 273–300 (मधुसूदनन, जे. और निधि एस. सभरवाल के साथ संयुक्त रूप से)।

विविधता और भेदभावः नागरिक शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा की भूमिका (2018), वर्गीज, एन.वी., निधि एस. सबरवाल और सी. एम. मलिश (सं.)। भारत उच्चतर शिक्षा रिपोर्ट 2016: इक्विटी सेजः नई दिल्ली, पृ. 393–414 (संयुक्त रूप से निधि एस. सभरवाल के साथ)।

सीपीआरएचई नीति संक्षेप

भारत में उच्च शिक्षा की समान उपलब्धता (2017), सीपीआरएचई नीति संक्षेप 1. दिल्लीः सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन हायर एजुकेशन (संयुक्त रूप से निधि एस. सबरवाल के साथ)।

भारत में उच्च शिक्षा में शैक्षणिक एकीकरण की प्राप्ति (2017), सीपीआरएचई पॉलिसी ब्रीफ्स 2. सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन हायर एजुकेशन, नई दिल्ली (संयुक्त रूप से निधि एस. सभरवाल के साथ)।

भारत में सामाजिक रूप से समावेशी उच्च शिक्षा परिसरों का विकास (2017)। पॉलिसी ब्रीफ 3. दिल्लीः सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन हायर एजुकेशन (संयुक्त रूप से निधि एस सभरवाल के साथ)।

सीपीआरएचई रिपोर्ट/मिमियो

''भारत में उच्च शिक्षा में छात्र विविधता और भेदभाव'' (2017) पर राष्ट्रीय संगोष्ठी रिपोर्ट, दिल्लीः सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन हायर एजुकेशन (संयुक्त रूप से निधि एस. सभरवाल के साथ)।

भारत में उच्च शिक्षा में समानता और समावेश (2017) ब्रिटिश काउंसिल दिल्ली में प्रो साइमन मार्गिन्सन के साथ चर्चा बैठक के लिए तैयार किया गया ड्राफ्ट प्रपत्र, दिल्लीः सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन हायर एजुकेशन (संयुक्त रूप से एन.वी. वर्गीस और निधि एस. सभरवाल के साथ)।

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाओं में भागीदारी

राष्ट्रीय

12–13 फरवरी, 2018 को नीपा, नई दिल्ली में 'सीमांत समाज का भविष्य निर्माणः छात्र आकांक्षाएं और उच्च शिक्षा संस्थान,' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 'अर्बन मार्जिनलिटी, सोशल पॉलिसी एंड एजुकेशन इन इंडिया' मेंएक पत्र प्रस्तुत किया (संयुक्त रूप से निधि एस। सभरवाल के साथ)।

12 फरवरी, 2018 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली, भारत में मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट और पुणे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 21वीं सदी के लिए 'समावेशी विश्वविद्यालयों: समानता, विविधता और उत्कृष्टता के एकीकरण' पर संगोष्ठी।

7–8 सितंबर, 2017 को नीपा, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपा नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'उच्च शिक्षा का भविष्य : आर्थिक और सामाजिक संदर्भ' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।

12 अगस्त 2017, इंपीरियल होटल नई दिल्ली में वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा आयोजित 'उच्च शिक्षा गोलमेज सम्मेलन'।

अंतरराष्ट्रीय

10–16 जून 2017 को उच्च, हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंटपेटर्सबर्ग, रूस में शिक्षा और सामाजिक असमानता पर पांचवें इंटरनेशनल समर स्कूल में 'भारत में उच्च शिक्षा में विविधता और भेदभाव' पर एक प्रपत्र प्रस्तुत किया।

22–23 फरवरी, 2018 को भारत हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली, भारत में सीपीआरएचई द्वारा आयोजित "उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता" विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी।

10–16 जून 2017 10–16 जून 2017 को उच्च, हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंटपेटर्सबर्ग, में शिक्षा और सामाजिक असमानता पर पांचवें इंटरनेशनल समर स्कूल में भाग लिया।

17–18 जून, 2017 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षाः सतत विकास लक्ष्य 4' पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन।

कार्यशाला/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

2–3 मई, 2017 को सीपीआरएचई–नीपा में आयोजित परियोजना की पहली अनुसंधान पद्धति कार्यशाला, 'उच्च शिक्षा की सफलता और सामाजिक गतिशीलताः विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एससी/एसटी/ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग योजनाओं पर एक अध्ययन' (संयुक्त रूप से सीएम हरीश के साथ)।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकास/संचालन

18–29 दिसंबर, 2017 को नीपा में 'शिक्षा में गुणात्मक अनुसंधान विधियाँ', पाठ्यक्रम में 'गुणात्मक अनुसंधान प्रविधियों पर केन्द्रीय समूह चर्चा' के एक सत्र का आयोजन एवं संचालन।

10–17 जुलाई, 2017 को नीपा, नई दिल्ली में 'विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विविधता और समानता के प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यशाला'(संयुक्त रूप से निधि एस सभरवाल के साथ) में 'उच्च शिक्षा के संस्थानों में सकारात्मक कार्रवाई और समावेश' पर एक सत्र का आयोजन एवं संचालन।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

सीपीआरएचई रिसर्च प्रपत्र सीरीज के सह–संपादक।

उच्च शिक्षा के समीक्षकः उच्च शिक्षा अनुसंधान के अंतरराष्ट्रीय जर्नल।

नीपा संकाय के लिए गुणात्मक डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर्स (एट्लस्ती और एनविवो) का संगठित प्रदर्शन।

अनुसंधान पद्धति (कोर 5) पर मुख्य पाठ्यक्रम के लिए एम.फिल. पाठ्यक्रम की समीक्षा समिति के सदस्य।

समता और बहु–सांस्कृतिक शिक्षा (ओसी 7) पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए एम. फिल पाठ्यक्रम की समीक्षा समिति के सदस्य।

विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा के समावेश (ईसी 13) हेतु वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए एम. फिल पाठ्यक्रम की समीक्षा समिति के सदस्य।

अनुसंधान अध्ययन

अनुसंधान परियोजना (जारी)

उच्च शिक्षा की सफलता और सामाजिक गतिशीलताः एससी/एसटी/ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए यूजीसी कोचिंग योजनाओं पर एक अध्ययन

भूमिकाः प्रधान अन्वेषक

उच्च शिक्षा की सफलता और सामाजिक गतिशीलता के लिए अनुसंधान अध्ययन परियोजनाः विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एससी/एसटी/ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए यूजीसी कोचिंग योजनाओं पर एक अध्ययन द्वारावंचितों की सफलता, कैरियर तथा व्यावसायिक गतिशीलता और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा शुरू की गई योजनाओं के प्रभावों की जांच का अध्ययन करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सीपीआरएचई/नीपा से यूजीसी द्वारा प्रायोजित कोचिंग योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक अध्ययन करने का अनुरोध किया। यूजीसी ने 11 वीं योजना अवधि के बाद से उच्च शिक्षा में वंचित समूहों के लिए कोचिंग योजनाएं शुरू कीं थीं। जो पिछले एक दशक से अस्तित्व में हैं। योजना के प्रमुख उद्देश्य वंचित समूहों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाओं के रूप में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे अकादमिक पाठ्यक्रमों के सफल समापन और कैरियर को उचित दिशा प्रदान कर सकें। वे कोचिंग योजनाएँ निम्नलिखित हैंः 1. एससी/एसटी/ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए उपचारात्मक कोचिंग, 2. एससी/एसटी/ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए नेट/सेट के लिए कोचिंग,

और 3. एससी/एसटी/ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए सिविल सर्विसेज में प्रवेश हेतु कोचिंग क्लास।

यह अध्ययन निम्नलिखित व्यापक शोध प्रश्नों द्वारा निर्देशित है:

1) यूजीसी कोचिंग योजनाओं के लाभार्थी कौन हैं जो सामाजिक समूहों द्वारा अलग हैं?
2) कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में यूजीसी की कोचिंग योजनाएँ कैसे लागू की जा रही हैं?
3) छात्रों की सफलता पर कोचिंग योजनाओं का क्या प्रभाव है?
4) योजनाओं को लागू करने में क्या अड़चनें हैं?

अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

क) यूजीसी कोचिंग योजनाओं के लाभार्थियों के सामाजिक समूह की संरचना का विश्लेषण करना;

ख) संस्थागत और यूजीसी कोचिंग योजनाओं की कार्यान्वयन प्रक्रिया को समझना।

यूजीसी स्तर;

ग) कोचिंग योजनाओं को लागू करते समय प्रत्येक हितधारक (जैसे: संकाय सदस्यों, समन्वयकों, संस्थागत नेतृत्व और यूजीसी में प्रशासकों) द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और बाधाओं को समझने के लिए;

घ) कोचिंग कक्षाओं में सीखने, प्रतिक्रिया प्रणालियों और सहकर्मी समूह बातचीत के संदर्भ में छात्र अनुभवों का पता लगाने के लिए;

च) रोजगार के लिए नेट/सेट और प्रतियोगी परीक्षाओं में अकादमिक प्रगति और सफलता पर कोचिंग योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करना;

छ) कोचिंग योजनाओं के कार्यान्वयन को मजबूत करने वाली नई नीतियों और प्रथाओं को विकसित करना।

इस अनुसंधान परियोजनाओं के तहत पूरी की जाने वाली गतिविधियाँ निम्न हैं:

1) अध्ययन के लिए एक विस्तृत अनुसंधान प्रस्ताव तैयार किया गया तथा यूजीसी को स्वीकृति के लिए भेजा गया।

2) अनुमोदन के बाद, केंद्र ने केस स्टडीजके लिए संस्थानों की पहचान की। संस्थानों की पहचान की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल थे: पहले कदम के रूप में, इन योजनाओं का लाभ उठाने वाले संस्थानों की एक सूची यूजीसी मुख्यालय और यूजीसी क्षेत्रीय कार्यालयों से ली गई थी; यूजीसी क्षेत्रीय कार्यालयों से सूची और सुझावों के आधार पर, केस स्टडी के लिए संस्थानों की एक अस्थायी सूची तैयार की गई। केस स्टडी संस्थानों के चयन के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किए गए थे:–1. क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वय 2. संस्थानों के प्रकार का प्रतिनिधित्वय 3. तीनों योजनाओं को लागू करने वाले संस्थानय 4. तुलनात्मक रूप से उच्च बजट आवंटनय 5. एससी–एसटी बहुल क्षेत्र के संस्थानय 6. अल्पसंख्यक लोगों हेतु संस्थानय और 7. महिलाओं हेतु संस्थाएँ।

3) केंद्र ने शिक्षाविदों और यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ एक अनुसंधान सलाहकार समिति का गठन किया। 4 अक्टूबर, 2016 को अनुसंधान सलाहकार समिति की पहली बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रस्ताव के अध्ययन, कार्यप्रणाली और संस्थानों के अध्ययन के लिए चयनित संस्थानों पर चर्चा की गई। समिति की सिफारिश के आधार पर, 12 संस्थानों को केस स्टडी के लिए अंतिम निर्णय हुआ।

4) मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान उपकरण विकसित किए गए। अनुसंधान उपकरण में संस्थागत स्तर पर उपलब्ध माध्यमिक डेटा एकत्र करने के लिए प्रारूप शामिल हैं, वर्तमान में कोचिंग कक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के बीच सर्वेक्षण प्रश्नावली और पास आउट, छात्रों के साथ समूह चर्चा तथा संकाय समन्वयकों, संकाय सदस्यों/प्रशिक्षकों, कोचिंग कक्षाओं के प्रशिक्षकों और संस्थागत नेतृत्व के साथ साक्षात्कार।

5) अध्ययन के लिए अनुसंधान उपकरणों को यूजीसी कोचिंग योजनाओं के समन्वयकों और दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वंचित समूहों के शैक्षणिक सशक्तिकरण से जुड़े संकाय सदस्यों के

परामर्श से तैयार किया गया है। साधन विकास कार्यशाला का आयोजन 22 दिसंबर, 2016 को किया गया। चर्चा ने उन तरीकों की जमीनी तस्वीर प्रदान की, जिस तरह से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में इस योजना को लागू किया गया है। तत्पश्चात, प्रत्येक उपकरण पर विस्तार से चर्चा की गई।

6) सदस्यों से मिले इनपुट के आधार पर, अनुसंधान उपकरणों को संशोधित और अंतिम रूप दिया गया।

7) अध्ययित किए जाने वाले संस्थानों में अनुसंधान टीम का औपचारिककरण पूरा हो चुका है। इन संस्थानों में अनुसंधान दल बनाने की प्रक्रिया में समन्वयकों की पहचान करने के लिए संस्थानों के प्रमुखों के साथ परामर्श भी किए गए। अनुसंधान सहयोग को औपचारिक बनाने के लिए समन्वयक द्वारा पत्र द्वारा संपर्क किया गया।

8) अध्ययित संस्थानों के अनुसंधान समन्वयकों के साथ पहली अनुसंधान पद्धति कार्यशाला का आयोजन किया जा चुका है।

9) परियोजना शुरू की जा चुकी है।

यह परियोजनात्मक अध्ययन, देश के 12 राज्यों में स्थित 12 उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू किया जा रहा है, अर्थात् पंजाब, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, दिल्ली, केरल, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और मेघालय।

अनुसंधान परियोजना (पूर्ण)

नागरिक शिक्षा और लोकतांत्रिक अनुबंध हेतु उच्च शिक्षाः उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और भेदभाव का अध्ययन

भूमिकाः सह–प्रधान अन्वेषक

उच्च शिक्षा प्रणाली और शिक्षार्थियों की संख्या में विविधता को ध्यान में रखते हुए, इस शोध परियोजना का उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षा परिसरों में विविधता और भेदभाव का पता लगाना है। उच्च शिक्षा के विस्तार और वर्ग तथा जाति की सीमाओं से बाहर निकलने वाले परिवारों के आकांक्षात्मक स्तरों में वृद्धि के परिण ाामस्वरूप आज गैर–पारंपरिक सामाजिक समूहों की एक बड़ी संख्या कॉलेज परिसरों में प्रवेश करती है, और अब यह परिसर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, लिंग, भाषाई विविधता, क्षेत्रीय और शारीरिक क्षमता वाले पृष्ठभूमि के छात्रों से भरे हुए हैं। यद्यपि यह उच्च शिक्षा में समता प्राप्ति की दिशा में एक सकारात्मक कदम प्रतीत होता है, फिर भी मौजूदा शोध उन मुद्दों को अध्ययन का विषय बनाता है जो उच्च शिक्षा परिसरों में सामाजिक विभाजन और इससे जुड़े अभ्यास, पूर्वाग्रह और मूल्यों से पुनः उत्पन्न हो रहे हैं।

इस परियोजना ने इन परिसरों की संरचना और तंत्र की प्रकृति और विविधता के रूपों को समझने का प्रयास किया जो विविधता और भेदभाव से निपटने के लिए मौजूद हैं। परियोजना ने यह भी अध्ययन किया कि विविधता द्वारा प्रदान किए गए अवसर को नागरिक और लोकतांत्रिक शिक्षा विकसित करने तथा समकालीन समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों को बेहतर करने की दिशा में सकारात्मक लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सूचना के संग्रह और विश्लेषण के लिए अध्ययन में मात्रात्मक और गुणात्मक पद्धति के मिले–जुले रूप को शामिल किया गया। इस अध्ययन में 3200 छात्रों के बीच एक विस्तृत प्रश्नावली आधारित सर्वेक्षण कराया गया साथ हीसंकाय और प्रशासकों के साथ 200 साक्षात्कार और छात्रों के साथ लगभग 70 फोकस समूह चर्चाओं का आयोजन किया गया। इस अध्ययन को छह राज्यों, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में स्थित संस्थानों में लागू किया गया था। छह राज्यों की अनुसंधान रिपोर्ट और विश्लेषण पूरा हो गया है एवं रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए अक्टूबर 2016 में अनुसंधान सलाहकार समिति को प्रस्तुत किया गया था। अनुसंधान रिपोर्टों को आरएसी में प्रस्तुत करने से पहले, रिपोर्टों में अध्यायों की गहन समीक्षा की गई थी और तीसरी शोध पद्धति कार्यशाला में रिपोर्ट की सहकर्मी समीक्षा की तैयारी में समन्वयकों द्वारा विस्तृत प्रतिक्रिया दी गई थी। तीसरी शोध पद्धति कार्यशाला 7–8 जून, 2016 को आयोजित की गई थी।

शोध परियोजना के लिए तीसरी कार्यप्रणाली कार्यशाला का उद्देश्य ड्राफ्ट अनुसंधान रिपोर्टों पर चर्चा और समीक्षा

करने और विश्लेषण रिपोर्ट पर चर्चा करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। केंद्र में तैयार विश्लेषण रिपोर्ट में छात्र सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़े और विश्लेषण तथा साक्षात्कार फोकस समूह चर्चा के विषयगत विश्लेषण शामिल थे। तीसरी अनुसंधान पद्धति कार्यशाला की बैठक में ऊपर सूचीबद्ध 12 उच्च शिक्षा संस्थानों के अनुसंधान दलों के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यशाला का आयोजन एक पियर रिव्यू बैठक के रूप में किया गया था। एक अन्य शोध टीम के सदस्यों में से एक ड्राफ्ट अनुसंधान रिपोर्ट के लिए चर्चा करने वाला था, जिसके बाद कार्यशाला में उपस्थित अनुसंधान टीमों के सभी सदस्यों ने चर्चा की।

सीपीआरएचई में शोध टीम के मार्गदर्शन और अनुसंधान दल के सहयोग से अग्रिम रूप से ड्राफ्ट शोध रिपोर्टों का प्रारूप तैयार किया गया था। कार्यशाला का आयोजन इस तरह से किया गया था कि शोध टीमों को पूर्ण प्रस्तुति करने के लिए पर्याप्त समय मिल सका और इसके उपरांत चर्चा भी हुई। ड्राफ्ट पर टिप्पणी करते समय सामान्य दिशानिर्देशों का पालन किया गयाः टिप्पणियां केवल मसौदा रिपोर्टों की समीक्षा पर आधारित थीं; विश्लेषण और लेखन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गएय लेखन और तर्कों में आंतरिक स्थिरता पर ध्यान दिया गया थाय प्रत्येक खंड/उप–खंड और उसी के लिए उपयोग किए गए डेटा सेट पर विकसित तर्कों पर ध्यान केंद्रित किया गया था; डेटा त्रिकोणीयकरण पर जोर दिया गया था, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा का पर्याप्त संबंध होय समीक्षकों ने उन पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया जहां पर ड्राफ्ट में परिणामों तक पहुँचने हेतु 'क्यों' की व्याख्या, परिणामों के विवरण (क्या) के साथ परिणामों की प्रक्रिया (कैसे) आदि के बारे में जिक्र था।

समूह से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, शोध रिपोर्टों को संशोधित किया गया और 18 अक्टूबर, 2016 को आयोजित तीसरी सलाहकार अनुसंधान समिति में प्रस्तुत किया गया। केंद्र ने 27–28 फरवरी, 2017 को इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें अकादमिक, शिक्षाविदों को एक साथ लाया गया और देश भर के नीति निर्माताओं ने भारत में उच्च शिक्षा में छात्र विविधता, और समता शामिल करने के लिए गहराई से जानकारी दी। केंद्र की योजना है कि शैक्षिक प्रशासकों को संवेदनशील बनाने के लिए नीतिगत संक्षेप और मॉड्यूल को सामने लाया जाए। यह परियोजना आइसीएसएसआर द्वारा वित्तपोषित है।

प्रमुख निष्कर्ष

इस अध्ययन ने भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र विविधता को वर्गीकृत करने की एक विधि विकसित की। जिससे छात्र विविधता के तीन चरणों की पहचान की जाती हैः प्रथम चरण, सामाजिक विविधता है जो मात्रात्मक है; राष्ट्र की जनसंख्या में मापने सकने योग्य एवं दृशयात्मक पहलू। द्वितीय चरण, शैक्षणिक विविधता है जिसमें शैक्षणिक परिणामों में समता हासिल करने के लिए शैक्षणिक अंतर को प्रदर्शित किया जाता है। तृतीय चरण, विविधता सामाजिक समावेशन की एक शर्त है, जिसमें उच्च शिक्षा में शामिल विभिन्न प्रकार विद्यार्थियों के अनुभवों को आकार देने वाले भेदभाव के रूपों को प्रदर्शित किया जाता है।

अध्ययन में पाया गया कि शैक्षिक विषय क्षेत्रों के चुनाव में असमानता बनी हुई है। सुविधा प्राप्त समूहों (जैसे गैर–एससी/एसटी/ओबीसी सामाजिक समूह के छात्र) के छात्र तेजी से विज्ञान और इंजीनियरिंग अध्ययन कार्यक्रम चुनते हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि यह पूर्व–कॉलेज के शैक्षणिक अनुभवों में भिन्नता के कारण हो सकता है। सुविधा प्राप्त सामाजिक समूहों के छात्रों ने ज्यादातर सामाजिक–बहिष्कृत समूहों (जैसे एससी, एसटी और ओबीसी) के छात्रों, जिनका शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा है और वह सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, के विपरीत अंग्रेजी माध्यम वाले निजी स्कूलों में दाखिला लिया है। अध्ययन के विषयों के चुनाव में सामाजिक समूह की असमानता जाति और जातीयता के आधार पर विषयों के स्तरीकरण की ओर ले जाती है। शिक्षा में इस तरह के अनुशासनात्मक स्तरीकरण मौजूदा असमानताओं और अध्ययन के बाद रोजगार की संभावनाओं और प्रकृति से संबन्धित है।

इसके अलावा, वंचित सामाजिक–आर्थिक समूह के छात्र भी उच्च शिक्षा स्तरों पर सीखने में सहायता और समर्थन प्रदान करने वाली सीमित सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी के साथ पहली पीढ़ी के विद्यार्थी होने की अधिक संभावना रखते हैं। प्रवेश बिंदु पर पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी होने के नाते छात्र विविधता के प्रति संकाय सदस्यों के नकारात्मक दृष्टिकोण और अकादमिक असमानताओं के सीमित संस्थागत पहल से कक्षाओं में शैक्षणिक कमजोरियों के रूप में कई नुकसान उठाने पड़ते हैं। जो सामाजिक रूप से छात्रों के शैक्षणिक एकीकरण और उनकी शैक्षणिक सफलता की संभावना को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। इस प्रकार, जबकि समग्र सामाजिक विविधता में सुधार हुआ है फिर भी शैक्षणिक सफलता के अवसरों में सामाजिक समूह की असमानता अब भी मौजूद है।

अध्ययन के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि अब भी उच्च शिक्षा परिसरों में भेदभाव जारी है। यह पाया गया कि छात्र विविधता को बढ़ाने के लिए प्रमुख संकाय सदस्यों और संस्थागत नेतृत्व का रवैया ज्यादातर नकारात्मक है। समानता को संस्थागत बनाने और छात्रों को भेदभाव से बचाने के लिए उच्च शिक्षा अधिकारियों से उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर सेल, महिला सेल, एंटी–रैगिंग सेल जैसे सेल बनाने के स्पष्ट निर्देश हैं। अनुभवजन्य निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि यद्यपि सभी प्रकार की संस्थागत व्यवस्थाएं (प्रकोष्ठ के रूप में) मौजूद हैं, बावजूद इसके यह प्रकोष्ठ प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहे हैं, प्रकोष्ठों के बारे में छात्रों में जागरूकता की कमी थीय कई लोग नहीं जानते थे कि किससे संपर्क करें और शिकायत कैसे करें। ऐसा लगता है कि प्रकोष्ठों की कार्यक्रम योजना, निगरानी और समन्वय में संस्थागत रुचि सीमित है, जो उन्हें उन छात्रों के लिए प्रभावी और सहायक बनाने के लिए है जिनकी उन्हें अत्यधिक जरूरत है।

अध्ययन से यह भी पता चलता है कि हमने परिसरों में विविधता हासिल करने के मामले में कुछ प्रगति तो अवश्य ही की है। प्रवेश के समय सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों ने स्तर विविधता को प्राप्त करने में योगदान दिया है। हालांकि, परिसरों में विविधता के मुद्दों को प्रदर्शित करने हेतु विस्तृत परीक्षण एवं प्रगतिशील कार्रवाई की आवश्यकता है। लेकिन, संस्थागत नेतृत्व में विविधता और असंवेदनशीलता के प्रति दृष्टिकोण की कमी उच्च शिक्षा में विविधता और समता पर विमर्श में शून्यता की स्थिति पैदा कर सकती है। जबकि विविधता के परिप्रेक्ष्य को विकसित करना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें छात्र विविधता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है।

इससे स्पष्ट है कि स्तर II और स्तर III की विविधता तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा की आवश्यकता है। हालांकि स्तर II और स्तर III की विविधता प्राप्त करने के लिए बाहरी कारक भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, स्तर II और स्तर III की विविधता को प्राप्त करना संस्थान का आंतरिक मामला है। यह अध्ययन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हम परिसर में विविधता को प्रदर्शित करने के प्रथम चरण में पहुंच गए हैं, जहां संस्थानों के भीतर इस पहल को ध्यान देने की आवश्यकता है। यह वह है जिसे हम छात्र विविधता की बदलती प्रकृति को प्रदर्शित करने में 'संस्थागत मोड़' के रूप में कह सकते हैं। 'संस्थागत मोड़' उन तरीकों में भारी बदलाव का अनुमान लगाता है जिसमें संस्थान काम कर रहे हैं, और संस्थागत हितधारकों जैसे कि संकाय सदस्यों और शैक्षणिक प्रशासकों के दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में परिवर्तन होते हैं।

संस्थागत स्तर पर पहली और सबसे महत्वपूर्ण विविधता पहल छात्र विविधता को अधिक सकारात्मक और निधि के रूप में समझने हेतु प्रमुख नेतृत्व और संकाय सदस्यों को संवेदनशील बनाना है। संस्थाएँ भी सीखने को बढ़ावा देने में विविध भूमिका निभाती हैं और उन मतभेदों के बारे में संवाद करती हैं जो परिसर के पर्यावरण पर प्रभाव डालती हैं। 'दूसरों' के बारे में जागरूकता सहित शैक्षणिक हस्तक्षेप और विभिन्न स्तरों पर बातचीत सकारात्मक परिसर पर्यावरण और अंतर–समूह संबंधों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल है। इस प्रकार, संविधान के आदर्शों को महसूस करने और समाज के लोकतंत्रीकरण

में योगदान देने हेतु, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को विविधता, नागरिक शिक्षा और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान, मूल्यों और कौशल हासिल करने में छात्रों की मदद करने की आवश्यकता है।

इस परियोजना के एक भाग के रूप में 6 राज्यों की टीम रिपोर्ट और एक संश्लेषण रिपोर्ट तैयार हो चुकी है।

i) उच्च शिक्षा में विविधता और भेदभावः डॉ. निधि एस. सबरवाल और डॉ. सी. एम. मलिश, नई दिल्ली, सीपीआरएचई/नीपा, 2016 द्वारा भारत के चयनित राज्यों के संस्थानों का एक अध्ययन।

ii) उच्च शिक्षा में विविधता और भेदभावः प्रोफेसर आशा सिंह, डॉ.फजल अहमद और डॉ.बरना गांगुली, नई दिल्ली, सीपीआरएचई/नीपा, 2016 द्वारा बिहार में चयनित संस्थानों का अध्ययन।

iii) उच्च शिक्षा में विविधता और भेदभावः प्रोफेसर निधि, डॉ, श्रवण कुमार और डॉ. रोमा स्मार्ट जोसेफ, नई दिल्ली, सीपीआरएचई/नीपा, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश में चयनित संस्थानों का एक अध्ययन।

iv) उच्च शिक्षा में विविधता और भेदभावः कर्नाटक में डॉ. श्रीजित अलथुर, प्रोफेसर ए.एच. सेकेरा और डॉ. बी. वी. गोपालकृष्ण, नई दिल्ली, सीपीआरएचई/नीपा, 2016 द्वारा चयनित संस्थानों का एक अध्ययन।

v) उच्च शिक्षा में विविधता और भेदभावः डॉ. एच. ए, हुड्डा, डॉ. ए.वी. तलमले और डॉ. ए.सी. बैंकर, नई दिल्ली, सीपीआरएचई/नीपा, 2016 द्वारा महाराष्ट्र में चयनित संस्थानों का अध्ययन।

vi) उच्च शिक्षा में विविधता और भेदभावः प्रोफेसर के एक्स जोसेफ, डॉ. टी.डी. साइमन, डॉ. के. राजेश, नई दिल्ली, सीपीआरएचई/नीपा, 2016 द्वारा केरल में चयनित संस्थानों का एक अध्ययन।

vii) उच्च शिक्षा में विविधता और भेदभावः डॉ. सी. वी. बाबू और डॉ. सत्येंद्र ठाकुर, सीपीआरएचई/नीपा, 2016 द्वारा दिल्ली में चयनित संस्थानों का एक अध्ययन।

सायंतन मंडल

प्रकाशन

शोध पत्र/प्रकाशित आलेख

भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण–अधिगम के विश्लेषण में फ्रीरियन दृष्टिकोण – एक सैद्धांतिक व्याख्यान, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा जर्नल, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, खंड–78, संख्या–3, 2017।

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाओं में भागीदारी

राष्ट्रीय

11–12 दिसंबर, 2017 को अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगोष्ठी 2017, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जगदीशपुर, जिला सोनीपत, हरियाणा में शिक्षक सुधार से छात्रों में सुधारः भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण के बदलते दृष्टिकोण।

7–8 सितंबर, 2017 को उच्च शिक्षा के भविष्य पर राष्ट्रीय संगोष्ठीः आर्थिक और सामाजिक संदर्भ,नीपा, नई दिल्ली में पचौरी ए. के साथ भारत में उच्च शिक्षा के शिक्षण में सुधारः विशेषज्ञता और पहुँच का संतुलन।

17–18 जून को भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में समावेशी गुणवत्ता शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सहयोगः सतत विकास लक्ष्य 4 और केरल मॉडल से सीख पर प्रतिवेदन।

7–8 दिसंबर, 2017 को नीपा द्वारा प्राइड प्लाजा, एयरोसिटी में आयोजित, ,वाइस चांसलर लीडरशिप वर्कशॉप के लिए प्रतिवेदन।

21–22 फरवरी, 2018 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिवेदन।

26–28 मार्च 2018 को प्राइड प्लाजा, एयरोसिटी में नीपा द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय प्रशासकों की नेतृत्व विकास कार्यशाला के लिए प्रतिवेदन।

अंतरराष्ट्रीय

19–20 अक्टूबर, 2017 को 18वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन रिसर्च, सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी,

सियोल, कोरिया में प्रतिस्पर्धात्मक उच्च शिक्षा और पूर्वकालीन विश्वविद्यालयों में योग्यता।

18 अक्टूबर, 2017 को सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी, कोरिया में भारतीय की वयस्क और आजीवन शिक्षण प्रणाली

भागीदारीः विशेष सत्र

यूनिवर्सिटी ऑफ डेस्टो, बिलबाओ, स्पेन में विजिटिंग स्कॉलर, मास्टर्स ऑफ लाइफलॉन्ग लर्निंग (एमएएलएलएल) (कोहोर्ट 10) में अतिथि व्याख्याता। यूरोपीय आयोग द्वारा वित्त पोषित छात्रवृत्ति।

कार्यशालाएँ/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

29–30 अगस्त, 2017 को सीपीआरएचई/नीपा, नई दिल्ली में 'टीचिंग एंड लर्निंग इन इंडियन हायर एजुकेशन' नामक परियोजना के लिए मसौदा रिपोर्ट और राष्ट्रीय संश्लेषण रिपोर्ट पर चर्चा के लिए तीसरी अनुसंधान पद्धति कार्यशाला का आयोजन।

विकसित प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम/संचालन

एम.फिल./पीएचडी प्रवेश परीक्षा में पर्यवेक्षण

रिपोर्ट अवधि में सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहयोग

नीति समर्थन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मूल्यांकन परियोजना के तहत एन.वी. वर्गीज और अनुपम पचौरी के साथ सीपीआरएचई/नीपा में "शिक्षक और शिक्षण के आधार पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन का मूलयांकन (पीएमएमएमएनएमटीटी) '। परियोजना समन्वयक/प्रधान अन्वेषकः प्रोफेसर एन.वी. वर्गीस, डॉ. अनुपम पचौरी और डॉ. सायंतन मंडल।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

अनुसंधान परियोजना

i) 'भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम' अनुसंधान परियोजना समन्वयक/प्रधान अन्वेषक सीपीआरएचई/ प्रमुख अनुसंधान परियोजना नीपा (यूजीसी द्वारा प्रायोजित)।

शिक्षण–अधिगम को सभी शैक्षणिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जहां प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रों में शिक्षण–अधिगम में सुधार पर व्यापक शोध और विकास किये जा रहे हैं, वहीं भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण–अधिगम में सुधार के लिए साक्ष्य–आधारित नीति के लिए पर्याप्त और समकालीन शोध की कमी है। इस तरह उच्च शिक्षा के निरंतर बदलते परिदृश्य, बढ़ी हुई अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, छात्रों की विविधता और शैक्षिक सेवा प्रदाताओं के प्रकार, धन–मूल्य और दक्षता की बढ़ती मांग के कारण इस क्षेत्र में नई शिक्षण विधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अन्य सुधार अध्ययन यह भी अनुमान लगाते हैं कि उच्च शिक्षा सुधार (XI और XII योजना, योजना आयोग, भारत सरकार) के तहत उत्कृष्टता (समानता और विस्तार के साथ) की ओर राष्ट्रीय एजेंडा के रूप ध्यान केंद्रित करने के बावजूद उच्च शिक्षा में शिक्षण और युवाओं की स्थिति में सुधार के क्षेत्र में सम्यक रूप से सीमित सफलता प्राप्त हुई है। यही कारण है कि सीपीआरएचई/नीपा ने विभिन्न लाभप्रद बिंदुओं से शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध आयोजित करने की पहल की।

इसलिए प्रस्तावित अनुसंधान परियोजना का उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा में शिक्षण–अधिगम की प्रक्रिया और स्थिति का विश्लेषण व्यापक करना है ताकि मजबूत साक्ष्य–आधारित नीति–निर्माण की सुविधा के लिए ज्ञान का एक अनुभवजन्य निकाय विकसित किया जा सके और शोध को आगे बढ़ाया जा सके। यह अध्ययन ये तथ्य उपलब्ध करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि कैसे भारत अपनी उच्च शिक्षा में आने वाली फैकल्टी डेवलपमेंट सहित प्रभावी शिक्षण–अधिगम जैसी चुनौतियों का बेहतर जवाब कैसे दे सकता है। वर्तमान अध्ययन स्नातक और परास्नातक दोनों स्तरों पर शैक्षणिक विषयों की एक पूरी श्रृंखला में शिक्षण गुणवत्ता को देखकर, भारत में उच्च शिक्षा अनुसंधान में एक अंतर को

प्रदर्शित करेगा। वास्तव में यह भारत के परिपेक्ष्य में उच्च शिक्षा में एक बहुमुखी घटना के रूप में शिक्षण–अधिगम साहित्य में योगदान देने वाले शुरुआती अध्ययनों में से एक होगा।

शोध परियोजना वर्तमान में भारत में उच्च शिक्षा में शिक्षण–अधिगम की प्रक्रिया की जांच कर रही हैऔर ज्ञान का एक अनुभवजन्य निकाय विकसित कर रही है जो समकालीन और भविष्य की राष्ट्रीय नीतियों के बारे में सूचना प्रदान करेगा। वृहद परिपेक्ष्य में इस अनुसंधान परियोजना के मुख्य उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों (कॉलेजों और विश्वविद्यालयों) में शिक्षण–अधिगम की प्रक्रिया को समझना और संभावित विविधताओं और विभिन्न प्रथाओं की पहचान करनाय स्नातक 'और परास्नातक स्तर के कार्यक्रमों में कई विषयों पर शिक्षण की गतिशीलता को समझनाय उच्च शिक्षा में छात्रों के अधिगम में शिक्षण और शिक्षण पर्यावरण (संस्थागत) की प्रभावशीलता का विश्लेषण करनाय भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण–अधिगम, संकाय और शिक्षार्थी विकास के संदर्भ में नीतिगत प्राथमिकताओं और नीतिगत प्रतिक्रियाओं की एकसमान जमीनी और विश्लेषणात्मक रूप से मजबूत समझ प्रदान करना और अंत में उच्च शिक्षा में शिक्षण–अधिगम के क्षेत्र में विशिष्ट नीतिगत बदलावों का सुझाव देनाय है। अनुसंधान द्वारा उत्पन्न साक्ष्य। शोध परियोजना मुद्दों की जांच करने का एक बहु–राज्यीय, बहु–संस्थानिक अध्ययन है और नियोजित–मिश्रित पद्धति का दृष्टिकोण है। यह अध्ययन 2014–15 में कलकत्ता विश्वविद्याल;, पश्चिम बंगाल; गुरु घासीदास विश्वविद्याल;, छत्तीसगढ़; महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, गुजरात; और पेरियार विश्वविद्यालय, तमिलनाडु की अनुसंधान टीमों की एक शोध–पद्धति कार्यशाला के साथ शुरू किया गया था और 2015–16 के अंतिम शैक्षणिक वर्ष के दौरान अध्ययन में काफी प्रगति हुई है। दूसरी अनुसंधान पद्धति कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है और डेटा संग्रह चरण समाप्त हो गया है। इसमें समृद्ध गुणात्मक डेटा शामिल हैं, जैसे कक्षा अवलोकन और दूसरों के बीच समूह चर्चा तथा शिक्षकों, छात्रों और प्रशासकों से प्राप्त बड़ा मात्रात्मक डेटा। चार शोध टीमों द्वारा एकत्रित मात्रात्मक आँकड़े एसपीएसएस विश्लेषण के लिए तैयार किए गए थे। संस्थागत प्रशासकों, संकाय सदस्यों और संबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ समूह चर्चा से गुणात्मक एकत्र किए गए और उनका विश्लेषण किया गया। राज्य स्तर की रिपोर्टों का पहला मसौदा, जिसकी समीक्षा और संपादन चुनिंदा संस्थानों द्वारा किया जा रहा है,को टीमों के पास अंतिम रूप से जमा करने के पूर्व पुनरावलोकन हेतु भेज दिया गया है। संकलित रिपोर्ट तैयारी के अंतिम चरण में है। सीपीआरएचईने परियोजना की प्रगति और कार्यान्वयन पर बारीकी से नजर रखी और अनुसंधान रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने में राज्य की टीमों की मदद की। इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा की कोडिंग और विश्लेषण, राज्य–रिपोर्ट मसौदा लिखने, अबतक प्रस्तुत अध्यायों पर नियमित प्रतिक्रिया और टिप्पणियां प्रदान करने जैसी सहायता शामिल थी।

दोनों, राज्य और केंद्रीय टीमें अभी रिपोर्ट तैयार कर रही हैं, जिनके ऊपर चर्चा तीसरी विशेषज्ञ कमेटी और अगली अनुसंधान पद्धति कार्यशाला में की जाएगी।

ii) एन.वी. वर्गीज और अनुपम पचौरी के साथ सीपीआरएचई/नीपा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय मूलयांकन प्रोजेक्ट के तहत "शिक्षक और शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन का मूल्यांकन" का समन्वयन किया।

गरिमा मलिक और सीपीआरएचई/नीपा के साथ सीपीआरएचई की वार्षिक रिपोर्ट 2017 तैयार की।

सीपीआरएचई/नीपा वेबसाइट

समन्वित सीपीआरएचई वेबसाइट जो केंद्र, उसके मिशन और रोडमैप के बारे में जानकारी प्रदान करती है। वेबसाइट चल रही राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाओं और आगामी घटनाओं पर प्रकाश डालती है और संसाधनों को प्रसारित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती है, जैसे सीपीआरएचएच शोध पत्र श्रृंखला, सीपीआरएचई रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीयसंगोष्ठी और सम्मेलन रिपोर्ट। नीपाकी तकनीकी टीम के परामर्श से वेबसाइट का विकास हो रहा है।

पत्रिका सम्पादन

बंगाली पत्रिका के सह–संपादक – जनशिक्षा भवन (जन–शिक्षा और आजीवन सीखने पर), त्रैमासिक, कोलकाता।

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

इंडियन एडल्ट एजुकेशन एसोसिएशन (आईएईए), नई दिल्ली।

लाइफटाइम लर्निंग (ईएसएलईएम एलएलएल हब) के लिए एएसईएम एजुकेशन एंड रिसर्च हब, नेटवर्क 5 – कोर कॉम्पिटिशन।

सत्येन मैत्रा जनशिक्षा समिति (एसएमजेएस), कोलकाता।

भारतीय पाउलो फ्रेयर इंस्टीट्यूट (आईपीएफआई), कोलकाता।

स्कूल मानक एवं मुल्यांकन एकक

प्रणति पांडा

कृपया विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग देखें

वीरा गुप्ता

प्रकाशन

पुस्तकें/अध्याय

एसडीईपीए, राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखंड के लिए मॉड्यूल

व्यावसायिक नीति निर्माण पर अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए मॉड्यूलय नीपा, 21–25 नवंबर, 2016

शैक्षिक योजना और प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के चरण–5 (अग्रिम पाठ्यक्रम) के लिए व्यावसायिक नीति पर मॉड्यूल (पीजीडेपा 2015–16)

शोध पत्र/आलेख

आइएएफओआर जर्नल ऑफ द सोशल साइंसेसः खंड 2, अंक 2, शीतकालीन 2016 प्रकाशन, आइएसएसएन 2187–0640, 20 दिसंबर, 2016 में "शैक्षिक योजनाः भारत में सीडब्ल्युएसएन और एसएलडी बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर" शीर्षक पर प्रपत्र प्रकाशित।

उच्च शिक्षा समीक्षा पत्रिका में प्रकाशित लेखय 'पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया' पृ. 74, 12 दिसंबर, 2016।

रिपोर्ट अवधि में संगोष्ठी/सम्मेलनों में सहभागिता

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय

शैक्षिक प्रशासनों में नवाचारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता और एक सत्र में प्रस्तुतियों का मूल्यांकन, नीपा।

PGI, तीसरी वार्षिक सार्वजनिक स्वास्थ्य संगोष्ठी 'स्वास्थ्य संवर्धनः स्वास्थ्य जीवन और कल्याण सुनिश्चित करना' में "स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक" में सत्र के लिए अध्यक्ष, चंडीगढ़, 9–10 मार्च, 2017।

अल्पसंख्यक शिक्षा पर अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलनः चुनौतियाँ और संभावनाएँ. शिक्षा में नवाचार विषय पर सत्र, अखिल भारतीय शैक्षिक आंदोलन, दिल्ली, 5 मार्च, 2017।

स्कूल शिक्षा पर नीति गोलमेज सम्मेलन, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, नई दिल्ली, 22 मार्च, 2017।

'विश्वविद्यालय प्रशासनः मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, नीपा, 23–24 मार्च, 2017,

शाला सिद्धि का राष्ट्रीय सम्मेलन, नीपा, 6–7 फरवरी, 2017।

उच्च शिक्षा, सीपीआरएचई, नीपा, 16–17 फरवरी, 2017 के वित्त पोषण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी।

अनलर्न वर्कशॉप, एसएलडी पर नामांकन और नीतियों की चर्चा; यूनेस्को और महात्मा गांधी शांति संस्थान, 9–10 अप्रैल।

अंतरीप क्षेत्रीय कार्यशाला; 19–21 अप्रैल।

रिपोर्ट अवधि में सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहयोग

शिक्षाधिकारियों के लिए सीबीएसई प्रपत्र निर्माण, 18 अक्टूबर 2017।

संघ लोक सेवा आयोग, 15–23 जनवरी, 2017।

पीएसजी कॉलेज, बीओएम बैठक।

आई.पी. विश्वविद्यालय, अष्टवकर संस्थान का निरीक्षण, 2 जून, 2017।

शिक्षा निदेशालय दिल्ली, स्कूल प्रबंधन समिति की शक्तियों पर परामर्श, 3 जून, 2017।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शाला सिद्धि पर पीएबी की बैठक, 3 मई, 2017।

एनसीईआरटी, मुख्यधारा के स्कूलों में सीडब्ल्यूएसएन को शामिल करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम के लिए एनसीईआरटी में योजना की बैठकय 5 मई, 2016।

हरियाणा यूपीएससी, सामान्य ज्ञान प्रश्न–पत्र के लिए मूल्यांकनकर्ता 30 दिन।

स्कूल शिक्षा विभाग तेलंगाना, शाला सिद्धि पर एक दिवसीय संदर्भ कार्यशाला; 6 अप्रैल।

महाराजा सूरजमल संस्थान, बीएड कॉलेज की भर्ती के लिए चयन समिति के सदस्य; 28 अप्रैल।

प्रशिक्षण सामग्री विकास/निर्माण

14 मार्च–17 अप्रैल, 2017 को 209 पाठ्यक्रम,आईडेपा, नीपा का समन्वय।

नीपा से बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कोयंबटूर के शासी निकाय सदस्य; कर। डीओ नं. एफ.2–26 (7) 2004 (एसी)।

सिविल सेवा परीक्षक यूपीएससी, 15–23 जनवरी, 2017

दिए गए व्याख्यान

स्कूल शिक्षा पर व्याख्यानः 19 जनवरी –16 मार्च, 2017 को जनशक्ति सूचना प्रणाली पर अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में गुणवत्ता, परीक्षण और मूल्यांकन, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनईएलईआरडी)।

07–11 मार्च, 2017 को एससीईआरटी, दिल्ली तक गवर्नमेंट को–एड एसएसएस लाजपत नगर, नई दिल्ली में डीयूआरसीसी/सीआरसीसी के लिए आयोजित 5–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शाला सिद्धि, एससीईआरटी, दिल्ली पर एक सत्र में व्याख्यान।

'एजुकेशनल मैनेजमेंट' आईडेपा 209 पाठ्यक्रम पर व्याख्यान; नीपा, 14–16 मार्च, 2017।

'एथिक्स ऑफ टीचिंग' और 'प्लानिंग फॉर टीचिंग', पर व्याख्यान; एनआईटी, कुरुक्षेत्र, 17 मार्च, 2017।

शाला सिद्धि पर व्याख्यान, डाइट कड़कड़डूमा, दिल्ली, 30 मार्च, 2017।

एनयूईईआरडी (आइएएमआर) के आगंतुकों के साथ शाला सिद्धि पर सत्र, नीपा, 17 फरवरी, 2017।

शाला सिद्धि, एमसीडी और एनडीएमसी और एससीईआरटी पर दिल्ली के प्रधानाचार्यों की क्षमता निर्माण, 31 जनवरी, 2017।

नीति अनुसंधान लोकाचार पर व्याख्यान, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2017।

दिल्ली के सचिवालय में शाला सिद्धि प्रस्तुति, नीपा, 5 दिसंबर, 2016।

राज्य स्तरीय शैक्षिक प्रशासकों के लिए शैक्षिक प्रबंधन पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम में शाला सिद्धि पर सत्र, नीपा, 5–9 दिसंबर, 2016।

नीपाबीईओ वर्कशॉप में शाला सिद्धि पर प्रस्तुति, 16 दिसंबर, 2016।

अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए कार्यक्रम हेतु पैनल शिक्षा पर चर्चा, नीपा, 21 दिसंबर, 2016।

शाला सिद्धि, पीजीडेपा, नीपापर व्याख्यान, 9 नवंबर, 2016।

नीपा में 'प्राथमिक स्तर पर स्कूल प्रबंधन के विकेंद्रीकरण के अनुभव 'कार्यशाला में शाला सिद्धि पर व्याख्यान, 10 नवंबर को 7–11 नवंबर, 2016।

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शाला सिद्धि पर क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ, 14–17 नवंबर, 2016।

जम्मू में शाला सिद्धि पर क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ, 27–29, नवंबर, 2016।

नीपा, सीडब्ल्यूएसएन के शिक्षा प्रबंधन पर पीजीडेपा में व्याख्यान, 5 अक्टूबर, 2016।

छत्तीसगढ़ में शाला सिद्धि पर क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ, 4–6 अक्टूबर, 2016।

उत्तर प्रदेश में शाला सिद्धि पर क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ, 24–25 अक्टूबर, 2016।

मणिपुर में शाला सिद्धि पर क्षमता निर्माण कार्यशाला, 2–3 सितंबर, 2016।

गोवा में शाला सिद्धि पर क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ, 23–24 सितंबर, 2016।

फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में व्याख्यान, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, 6 अगस्त, 2016।

दिल्ली, एससीईआरटी में दिल्ली शाला सिद्धि के शुभारंभ में व्याख्यान, 5 अगस्त, 2016।

दमन और दीव में शाला सिद्धि पर क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ; 26–27 अगस्त, 2016।

21 जुलाई को नीति संकल्पना पर व्याख्यान; शैक्षिक प्रशासकों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, नीपा, 18 जुलाई से 12 अगस्त, 2016।

शाला सिद्धि पर व्याख्यान; बीईओ में, श्रीनगर में डीईओ सम्मेलन; 30 मई –1 जून, 2016।

शैक्षिक योजना और प्रशासन (पीजीडेपा) 2015–16 में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के चरण V (अग्रिम पाठ्यक्रम) के लिए व्यावसायिक नीति में 20 व्याख्यान; 8–14 अप्रैल, 2016।

अनुसंधान पर्यवेक्षक

छात्र, संगीता डे की पीएचडी "मिड–डे मील कार्यक्रम के नीति विश्लेषणः सरकारी दृष्टिकोण" का निर्देशन।

छात्र, दीपिंदर सेखों की पीएचडी सीडब्ल्यूएसएन संख्या. 11–8/2014–15/एए/सीएएस दिनांक 27 अगस्त, 2015 के लिए नीतियां और प्रथाएँ' का निर्देशन।

'कोहिमा जिले, नागालैंड के शैक्षिक ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयक की भूमिका और गतिविधियों का एक अध्ययन'; शैक्षिक योजना और प्रशासन 2016–17 में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए आवश्यकता की आंशिक पूर्ति में प्रस्तुत शोध प्रबंध; रुकोकोइनुओ मरीना।

डॉ। गिरीश कुमार के मार्गदर्शन में निधि त्रिपाठी के बाहरी परीक्षक के रूप में शोध प्रबंध का मूल्यांकन, "गिफ्टेड चिल्ड्रन, द अनटैप्ड नेशनल ह्यूमन रिसोर्सः लॉस्ट; 42 एडवांस प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन– 1 जुलाई, 2016–30 अप्रैल, 2017, आईआईपीए।

जांजीबार में स्कूल ड्रॉपआउट के पाठ्यक्रम पर जांचः उत्तर जिले का मेकवाटोनी शिक्षक केंद्र, खामिस सिलिमा कोम्बो (तंजानिया), आईडेपा, नीपा।

डॉ. के.आर. नारायणन सेंटर फॉर दलित एंड माइनॉरिटीज स्टडीज, जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रो अजरा जैजैक के मार्गदर्शन में तेमसुकला शोधार्थी द्वारा 'एजुकेशन

एंड आइडेंटिटी इन नगालैंडः एन इंटरप्रिटेशन ऑफ नगा सोसाइटी ऑफ द मॉडर्न टाइम्स में थीसिस का मूल्यांकन।

विभिन्न निकायों के सदस्य

जीआईएसी की 32वीं – 35वीं बैठक; नीपा

एम. फिल और पीएचडी के लिए संचालन समिति बैठक

विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य; 9 मई, 2016

अकादमिक परिषद की बैठक; 27 मई, 2016

रस्मिता दास स्वैन

प्रकाशन

गुप्ता, वी., और स्वैन, आर.डी. (2017) भारत में समावेश पर स्कूल के प्रदर्शन का आकलन, सीडब्ल्यूएचएन पर केंद्रण सहित समावेशी शिक्षा की नीति और योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन. (सं.) एक्सेल इंडिया पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाओं में भागीदारी

9 अक्टूबर, 2017 को ईसीईई, नीपा, नई दिल्ली में प्रचार–प्रसार और समन्वय पर राष्ट्रीय परामर्श।

3–5 अक्टूबर, 2017 को नीपा, नई दिल्ली में नीतिगत परिप्रेक्ष्य में गांधीवादी शैक्षिक विचारों पर राष्ट्रीय चर्चा की बैठकः प्रासंगिकता, चुनौतियां और संभावनाएं।

9–10 नवंबर, 2017 को नीपा, नई दिल्ली में भारत में समावेशी शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन।

प्रशिक्षण कार्यक्रम/सम्मेलन/कार्यशालाओं का आयोजन/सहभागिता

दिल्ली राज्य के लिए शाला सिद्धी का अभिविन्यास कार्यक्रम 31 जनवरी, 2017 त्यागराज स्टेडिय, नई दिल्ली।

शाला सिद्धी पर राष्ट्रीय सलाहकारी बैठक (स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक पर राष्ट्रीय कार्यक्रम) शाला सिद्धी, 06–07 फरवरी 2017 ।

उन्नत शाला सिद्धी वेब पोर्टल कार्यशाला (शाला सिद्धी) 11 फरवरी 2017।

उन्नत शाला सिद्धी वेब पोर्टल कार्यशाला (शाला सिद्धी) 13 फरवरी 2017।

स्व एवं बाह्य मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देशों पर निश्चयात्मकता और अनुवाद पर कार्यशालाएँ, 21–23 फरवरी, 2017।

उन्नत शाला सिद्धी वेब पोर्टल कार्यशाला (शाला सिद्धी) 27 फरवरी से 04 मार्च 2017।

उन्नत शाला सिद्धी वेब पोर्टल कार्यशाला (शाला सिद्धी) 06–11 मार्च 2017।

गुजरात के लिए राज्य विशिष्ट शाला सिद्धी पर क्षमता विकास कार्यक्रम 28–29 मार्च, 2017।

शाला सिद्धी दल के साथ शाला सिद्धी पर क्षमता विकास कार्यक्रम में भागीदारी (स्कूल स्वः मूल्यांकन) 525 अध्यापक शिक्षक, शिक्षा अधिकारी और स्कूल–प्रमुख, हरियाणा, 03–04 जून 2017।

शाला सिद्धी पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम, महाराष्ट्र, 21–24 जून 2017।

शाला सिद्धी दल के साथ स्कूल स्वं–मूल्यांकन क्षमता विकास कार्यक्रम में 55 अध्यापक शिक्षकों, शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रमुख के भागीदारी, राजस्थान 15 सितंबर 2017।

शाला सिद्धी के साथ, शाला सिद्धी पर क्षमता विकास कार्यक्रम में (स्कूल एवं मूल्यांकन) 250 अध्यापक शिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रमुख के साथ भागीदारी 19–20 सितंबर 2017।

शाला सिद्धी के साथ, शाला सिद्धी पर क्षमता विकास कार्यक्रम में (स्कूल एवं मूल्यांकन) 58 अध्यापक शिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रमुख के साथ भागीदारी 15 दिसंबर 2017, हिमाचल प्रदेश।

शाला सिद्धी के साथ, शाला सिद्धी पर क्षमता विकास कार्यक्रम में (स्कूल एवं मूल्यांकन) 45 अध्यापक शिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रमुख के साथ भागीदारी 28–29 दिसंबर 2017, जम्मू और कश्मीर।

बाह्य मूल्यांकन के लिए शाला सिद्धि पर कार्यशाला 10–13 जनवरी 2018।

स्व एवं बाह्य मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देशों पर निश्चयात्मकता और अनुवाद पर कार्यशालाएँ, 07–10 मार्च, 2017।

बाह्य मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देशों के विकास पर विशेषज्ञ समूह कार्यशाला, 15–17 जनवरी, 2018।

बाह्य मूल्यांकन (शाला सिद्धि) पर राष्ट्रीय परामर्शी बैठक, 23–24 जनवरी, 2018।

बाह्य मूल्यांकन दिशानिर्देश के लिए कार्यशाला, 22–23 मार्च 2018।

स्व एवं बाह्य मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देशों पर निश्चयात्मकता और अनुवाद पर कार्यशालाएँ, 07–10 मार्च, 2017।

बाह्य मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देशों के विकास हेतु विशेषज्ञ समूह कार्यशालाएँ, 15–17 जनवरी, 2018।

बाह्य मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय सलाहकारी बैठक 23–24 जनवरी, 2018।

शिक्षक शिक्षा में शासन, विनियमन और गुणवत्ता आश्वासन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, 15–16 मार्च, 2018।

शाला सिद्धि पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमः मुंबई, महाराष्ट्र, 21–24 जून, 2017।

शाला सिद्धि पर कोर ग्रुप की बैठक और क्षमता निर्माण कार्यक्रमः कुरुक्षेत्र, हरियाणा, 03–04 जून, 2017।

शाला सिद्धि पर कोर ग्रुप की बैठक और क्षमता निर्माण कार्यक्रमः जयपुर, राजस्थान, 15 सितंबर, 2017।

शाला सिद्धि पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमः पटना, बिहार, 19–20 सितंबर, 2017।

15 दिसंबर, 2017 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में शाला सिद्धि के कार्यान्वयन के लिए जिला टीमों के साथ कार्यशाला।

एससीईआरटी, दिल्ली के साथ कार्यशाला, 26 अप्रैल, 2018।

उच्च शिक्षा के वित्तपोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, नीपा भारतीय प्रवास केन्द्र, 16–17 फरवरी 2017।

घरेलू ज्ञान व्यवस्था और युवा सशक्तिकरणः नीतियां और व्यवहार, 02–03 मार्च 2017, नीपा

शैक्षिक प्रशासन में नवाचार पर राष्ट्रीय सम्मेलन जिला और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के लिए 04 मार्च, 2017, प्रवासी भारतीय केन्द्र, नीपा, नई दिल्ली।

सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के साथ संलग्रताः विचार और व्यवहार के रूप में स्वायतता, प्रो. मलाबिका सरकार द्वारा व्याख्यान, प्रेसिडेन्सी विश्वविद्यालय की स्थापना, कोलकाता, 09 मार्च 2017, नीपा।

विश्वविद्यालय–उद्योग अंतर पृष्ठांकनः उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए चुनौतियां और संभावनाएं, डॉ. राजीव दूबे द्वारा व्याख्यान, नीपा, 14 मार्च 2017

नीति परिप्रेक्ष्यः प्रसंगिकता, चुनौतियां और संभावनाएं पर गांधी शैक्षिक विचारों के लिए राष्ट्रीय चर्चा बैठक 03–05 अक्टूबर 2017, नीपा, नई दिल्ली।

ई.सी.सी.ई में परिवर्तन और समन्वयन के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय चर्चा नीपा, 09 अक्टूबा 2017, नई दिल्ली।

भारत में समावेशी शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन 09–10 नवंबर, 2017, नीपा, नई दिल्ली

एन.सी.एस.एल. राष्ट्रीय सलाहकारी बैठक में भागीदारी 2017–18, नीपा, नई दिल्ली 07 मार्च 2018

अध्यापक शिक्षा में अभिशासन, विनियामक और गुणवत्ता आश्वासन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, 15–16 मार्च, 2018

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम निर्माण/संचालन

स्कूल स्व–मूल्यांकन पर दिशानिर्देश (अंग्रेजी) 2017, स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक, नीपा, नई दिल्ली

स्कूल स्व–मूल्यांकन पर दिशानिर्देश (हिंदी) 2017, स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक, नीपा, नई दिल्ली

स्कूल बाह्य मूल्यांकन पर दिशानिर्देश (अंग्रेजी) 2017, स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक, नीपा, नई दिल्ली

स्कूल बाह्य मूल्यांकन पर दिशानिर्देश (हिंदी) 2017, स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक, नीपा, नई दिल्ली

उपयोगकर्ताओं के लिए वेब पोर्टल (अंग्रेजी) स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक, नीपा, नई दिल्ली

शाला–सिद्धी स्कूल स्वयं मूल्यांकन पर राष्ट्रीय आकलन रिपोर्ट, 2017 स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक, नीपा, नई दिल्ली (जुलाई 2017, अक्टूबर 2017, नवंबर 2017, दिसंबर 2017, जनवरी 2018

राज्य विशिष्ट स्कूल स्वयं मूल्यांकन ग्रेडिंग डैशबोर्ड, 2017 स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक, नीपा, नई दिल्ली (जुलाई 2017, अक्टूबर 2017, नवंबर 2017, दिसंबर 2017, जनवरी 2018

शाला–सिद्धीः रणनीतिक योजना और क्रियान्वयन, 2017 स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक, नीपा, नई दिल्ली

शाला–सिद्धी परिप्रेक्ष्य योजना 2017–2020 (2017) स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक, नीपा, नई दिल्ली

शाला–सिद्धी की प्रगृति और क्रियान्व्यन पर राष्ट्रीय रिपोर्ट (2017) स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक, नीपा, नई दिल्ली

शाला–सिद्धी : स्कूल स्व–मूल्यांकन विश्लेषण, महाराष्ट्र, 2017 स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक, नीपा, नई दिल्ली

वेबपोर्टल प्रबंधन और विकास का समनव्यन

यूनिट के सदस्यों के साथ विकसितः दिशानिर्देश, निगरानी तंत्र तथा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट

स्कूल स्वयं मूल्यांकन पर दिशानिर्देश (अंग्रेजी और हिंदी)

स्कूल बाह्य मूल्यांकन पर दिशानिर्देश (अंग्रेजी और हिंदी)

वेब पोर्टल के लिए उपयोगकर्ता निर्देश

शाला सिद्धि की प्रगति और कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय रिपोर्ट

शाला सिद्धिः स्कूल सेल्फ इवैल्यूएशन एनालिटिक्स

राष्ट्रीय ग्रेडिंग रिपोर्ट

राज्य विशिष्ट ग्रेडिंग रिपोर्ट (22 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश)

एम.फिल/पीएचडी पाठ्यक्रम संचालन

अनिवार्य पाठ्यक्रम, सीसी–1

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहयोग

वेब पोर्टल शाला सिद्धि के विकास में योगदान दिया

एम.फिल/पीएचडी के अनिवार्य पाठ्यक्रम सीसी–1 का विकास।

6 फरवरी, 2018 को नीपा में स्कूल स्वयं विकास पर डाईट स्टाफ के लिए ओरिएंटेशन

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

आईडेपा प्रोजेक्ट 'कौशल विकास के लिए नेतृत्वः एथियो टेलीकॉम एक्सीलेंस अकादमी, अदीस अबाबा, इथियोपिया का एक वैयक्तिक अध्ययन' का पर्यवेक्षण।

व्याख्यान हेतु आमंत्रण

विद्या भारती शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नेहरू नगर, नई दिल्ली में 3 नवंबर, 2017 को आमंत्रित व्याख्यान।

अधिकारिक और अन्य समिति के सदस्य

एमफिल/पीएचडी की प्रवेश परीक्षा समिति, सदस्य

अनुसंधान पद्धति I तथा II एवं शिक्षा का परिप्रेक्ष्य (सी.सी. –I) के एम.फिल परीक्षा मूल्यांकन के सदस्य।

एमफिल/पीएचडी कार्यक्रम का पुर्नगठन

संचालन समिति के सदस्य

अनुसंधान तथा नवाचार के लिए नॉक समिति के सदस्य

योजना अनुमोदन बोर्ड (पी.ए.बी.) शाला सिद्धी के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बैठक

शाला सिद्धी वेब पोर्टल का प्रबंधन

विभागाध्यक्षों के साथ शाला सिद्धी कार्यक्रम का प्रबंधन

राष्ट्रीय मनोविज्ञान अकादमी

इंडियन एसोसिएशन ऑफ एप्लाइड साइकोलॉजी

तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी, भारत (सीईएसआइ), नई दिल्ली

अखिल भारतीय शैक्षिक अनुसंधान संघ (एआइएईआर), भुवनेश्वर, ओडिशा

भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता

भारत स्कूल सकरात्मक मनोविज्ञान संघ, नई दिल्ली

संयुक्त संस्कृति मनोविज्ञान संघ, प्राची मेरठ

राष्ट्रीय एचआरडी नेटवर्क, हैदराबाद

प्रशिक्षण एवं विकास के लिए भारतीय समिति, नई दिल्ली

खेल मनोविज्ञान संघ, पटियाला

एमफिल/पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए योगदान (फरवरी 2018)

अन्य अकादमिक तथा व्यावसायिक गतिविधियां

परामर्शकारी गतिविधियों में योगदान

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

यूनिसेफ़

योजना अनुमोदन बोर्ड बैठक (पी.ए.बी.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

मनोविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज

जम्मू विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय प्रकाशकों की मनोविज्ञान पर पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा

विभिन्न विश्वविद्यालयों के दूरवर्ती अधिगम केंन्द्र

जम्मू और कश्मीर पुलिस अकादमी

प्रबंधन अध्ययन संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय

मनोविज्ञान परीक्षा तथा आकलन सेवा केंन्द्र

मानव संसाधन विकास केन्द्र (मनोविज्ञान तथा शिक्षा विभाग) के लिए अकादमिक संसाधन व्यक्ति।

आईसीटी अनुप्रयोग

के. श्रीनिवास

प्रकाशन

पुस्तकें/अध्याय

2017 में सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली से 'इमर्जिंग इंडिया में शिक्षा' शीर्षक वाली संपादित पुस्तक में 'भारत में खुले और दूरस्थ शिक्षा (व्क्स) पर एक वक्तव्य' पर एक अध्याय लिखा।

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाओं में भागीदारी

शिक्षण और सीखने में आईसीटी की भूमिकाः चुनौतियां और मुद्दे (मुख्य वक्ता) टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में आईसीटी पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, छोटू राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रोहतक, 18 नवंबर, 2017

फ्लिप्ड लर्निंग/क्लासरूम को सक्षम करने के लिए कदम (आमंत्रित अध्यक्ष) ई–लर्निंग और ई–टेक्नोलोजी पर राष्ट्रीय सम्मेलनः निर्देश और चुनौतियां, निर्देशात्मक मीडिया केंद्र, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद द्वारा आयोजित 20–21 फरवरी, 2018

रांची विश्वविद्यालय, रांची के लिए 8–9 अप्रैल, 2017 को "मूड एमओसी एंड ओईआर" पर दो दिवसीय संकाय विकास कार्यशाला के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।

तेलंगाना राज्य के सरकारी व्याख्याताओं के लिए दो चरणों (6 दिनों में प्रत्येक चरण) में एक फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप आयोजित की गई, "स्मार्ट क्लासरूम का प्रभावी उपयोग और ई–कंटेंट की तैयारी और संचालन", 9–14 मई, 2017।

यूजीसी–एचआरडीसी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा 15–16 मई, 2017 को आयोजित दो दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।

यूजीसी–एचआरडीसी, देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदौर द्वारा 22–23 मई, 2017 को आयोजित दो दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम कार्यशाला के लिए एक व्यक्ति के रूप में भाग लिया।

भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, हबीबगंज, 24–25 मई 2017 के संकाय सदस्यों के लिए यूजीसी–एचआरडीसी, देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदौर द्वारा आयोजित दो दिवसीय रिफ्रेशर कार्यक्रम के लिए एक संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।

तेलंगाना राज्य के सरकारी व्याख्याताओं के लिए दो चरणों में (6 दिन प्रत्येक चरण में) संकाय विकास कार्यशाला आयोजित की गई, 'स्मार्ट क्लासरूम का प्रभावी उपयोग और ई–कंटेंट की तैयारी और संचालन', 1–6 जून, 2017।

27 जुलाई, 2017 को मूडल एमओओसी और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज पर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ट्रस्ट (आईएसएसटी) के संकाय सदस्यों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का संचालन किया।

शिक्षा–सक्षम ऑनलाइन शिक्षण, शिक्षण और मूल्यांकन के लिए एमओओसी और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, 21–23 अगस्त, 2017 को शिक्षा विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के संकाय सदस्यों के लिए तीन–दिवसीय कार्यशाला आयोजित की।

दिल्ली पुलिस परियोजना, 30 अगस्त, 2017 के तहत इंदिरा गांधी महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (आइजीडीटीडब्ल्यू), दिल्ली के लिए ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के कार्यान्वयन पर एक दिन के विचार–मंथन सत्र में भाग लिया।

मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै द्वारा 4–5 सितंबर, 2017 को आयोजित दो दिवसीय फैकल्टी अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए एक संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।

15–16 सितंबर, 2017 को एमओओसी और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के फैकल्टी मेंबर्स के लिए टेक्नोलॉजी–सक्षम ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट के लिए दो दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई।

20–21 सितंबर, 2017 को चेन्नई में बीईओ, डीईओ के दो दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया।

सेंटर फॉर फैकल्टी ऑफ एडवांसमेंट ऑफ फैकल्टी ट्रेनिंग (सीएएफटी), कृषि विस्तार, आईसीएआर–आईएआरआई, नई दिल्ली द्वारा 16 अक्टूबर, 2017 को सेंटर फॉर एडवांसमेंट इन इंस्ट्रक्शंस इन एडवांसिंग इन टीचिंग–लर्निंग एंड ट्रेनिंग कम्पटीशन पर एक दिवसीय कौशल उन्मुख प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।

मंसूर एमओओसी और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, 23–25 अक्टूबर, 2017 के साथ मन्नार थिरुमलाई नाइकर कॉलेज के संकाय सदस्यों के लिए प्रौद्योगिकी–सक्षम ऑनलाइन शिक्षण, सीख और मूल्यांकन के लिए तीन दिवसीय लंबे कौशल–उन्मुख कार्यशाला का आयोजन किया।

पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन की योजना के तहत लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ (एलबीएसएसडब्ल्यू), नई दिल्ली के टीचिंग एंड लर्निंग सेंटर द्वारा आयोजित शैक्षिक प्रक्रियाओं में आईसीटी पर संकाय सदस्यों के लिए तीन–दिवसीय कौशल–उन्मुख कार्यशाला आयोजित की गई, शिक्षक और शिक्षण (पीएमएमएमटीटी), 27–30 अक्टूबर, 2017।

एनआइटी, वारंगल ई एंड आईसीटी अकादमी, 9–11 नवंबर, 2017 द्वारा आयोजित मूडल मूक, ओईआर, शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपकरणों पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के इंजीनियरिंग संकाय सदस्यों के लिए तीन–दिवसीय कौशल–उन्मुख कार्यशाला आयोजित की गई।

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ओडिशा (एनएलयूओ) के संकाय सदस्यों के लिए 20–22 नवंबर, 2017 को मूडल मूक, ओईआर, शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपकरण पर तीन–दिवसीय कौशल–उन्मुख कार्यशाला आयोजित की गई।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयूयू) के संकाय सदस्यों के लिए 27–29 नवंबर, 2017 को मूडल मूक, ओईआर, शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपकरण पर तीन–दिवसीय कौशल–उन्मुख कार्यशाला आयोजित की गई।

जामिया हमदर्द, नई दिल्ली, 30 नवंबर, 2017 द्वारा "इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज फॉर एनहांसिंग टीचिंग–लर्निंग एंड ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन" पर एक दिवसीय कौशल–उन्मुख प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।

शिक्षक और शिक्षण (पीएमएमएमटीटी), पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन की योजना के तहत 11–13 दिसंबर, 2017 को तेजपुर विश्वविद्यालय के टीचिंग एंड लर्निंग सेंटर द्वारा आयोजित मूडल मूक,ओईआर, पर संकाय सदस्यों के लिए तीन–दिवसीय कौशल–उन्मुख कार्यशाला का आयोजन किया।

बनस्थली विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा 31 दिसंबर, 2017 को आयोजित ऑनलाइन शिक्षण, शिक्षण और मूल्यांकन पर बनस्थली विश्वविद्यालय के संकाय के लिए एक दिवसीय कौशल उन्मुख प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया।

जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के संकाय सदस्यों के लिए 5–7 जनवरी, 2018 को मूडल मूक, ओईआर, शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपकरण तीन दिन की कौशल–उन्मुख कार्यशाला आयोजित की गई।

कर्नाटक विश्वविद्यालय गुलबर्गा के संकाय सदस्यों के लिए 22–24 जनवरी, 2018 को मूडल मूक,ओईआर, शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपकरण पर तीन दिवसीय कौशल–उन्मुख कार्यशाला का आयोजन किया।

पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति के संकाय सदस्यों के लिए 29–31 जनवरी, 2018 को मूडल एमओओसी, ओईआर, शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपकरण, तीन–दिवसीय कौशल–उन्मुख कार्यशाला का आयोजन किया।

बीआर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद के संकाय सदस्यों के लिए 8–10 फरवरी, 2018 मूडल मूक, ओईआर, शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपकरण पर तीन–दिवसीय कौशल–उन्मुख कार्यशाला का आयोजन किया गया।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में पीजी डिप्लोमा को संशोधित करने और स्कूल ऑफ एजुकेशन, इग्नू द्वारा आयोजित 7 अप्रैल, 2017 को विकसित करने के लिए बैठक में एक विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया।

भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस (एनसीएससी) के समग्र

संचालन और पर्यवेक्षण के लिए तीन साल के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक समिति (एनएसी) के सदस्य।

25 और 27 सितंबर, 2017 को मूक्स प्रस्तावों की पहचान और अनुमोदन के लिए एनसीईआरटी–मूक्स पर अकादमिक सलाहकार समिति (एएसी) के सदस्य।

शास्त्री भवन नई दिल्ली में 14 नवंबर, 2017 को पहली एसडब्ल्यूएवाईएएम बोर्ड की बैठक में नीपाका प्रतिनिधित्व किया।

मूक्स प्रस्ताव की पहचान और अनुमोदन के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान में यूजीसी–मूक्स पर शैक्षणिक सलाहकार समिति (विषय वस्तु विशेषज्ञ समूह) के सदस्य, 4 दिसंबर, 2017।

कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया (सीईएमसीए) द्वारा 29 सितंबर 2017 को आयोजित "ओआरई नीति कार्यान्वयन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में प्रभाव का असर" नामक अध्ययन के लिए मसौदा अनुसंधान उपकरण को अंतिम रूप देने के लिए एक दिन की कार्यशाला में भाग लिया।

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 15–16 जनवरी, 2018 को केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन (केब) की 65वीं बैठक में भाग लिया।

स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2018 को आयोजित बी.वोक (आईटी/आईटीईएस) के लिए कोर एरिया एक्सपर्ट कमेटी की पहली बैठक के सदस्य के रूप में भाग लिया।

एसडब्ल्यूएवाईएएम मूक सलाहकार समिति की सदस्यता

एनसीईआरटी के लिए अकादमिक सलाहकार समिति के सदस्य, स्कूल स्तर के लिए राष्ट्रीय समन्वयक एसडब्ल्यूएवाईएएम मूक पाठ्यक्रम।

यूजीसी (पीजी पाठ्यक्रम) के लिए अकादमिक सलाहकार समिति के सदस्य, स्वायम एमओसी पाठ्यक्रमों के परास्नातक पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय समन्वयक।

नीपा का प्रतिनिधित्व करने वाले पहली एसडब्ल्यूएवाईएएम बोर्ड की बैठक में भाग लिया।

एसडब्ल्यूएवाईएएम मूक – राष्ट्रीय संसाधन केंद्र (एनआरसी – अनुशासन विशिष्ट) शैक्षणिक सलाहकार समिति की सदस्यता

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), वारंगल, तेलंगाना के लिए अकादमिक सलाहकार समिति के सदस्य।

गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा के लिए अकादमिक सलाहकार समिति के सदस्य।

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश के लिए शैक्षणिक सलाहकार समिति के सदस्य

श्री लाल बहादुर संस्कृत संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के लिए अकादमिक सलाहकार समिति के सदस्य।

एसडब्ल्यूएवाईएएम मूक – राष्ट्रीय संसाधन केंद्र शिक्षा अकादमिक सलाहकार समिति की सदस्यता

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा), नई दिल्ली के लिए अकादमिक सलाहकार समिति के सदस्य।

राष्ट्रीय अध्येता

ए. मैथ्यू

प्रकाशन

''केरल में उच्च शिक्षा विकास पर नीतिगत विमर्श: समता और कम निजीकरण पर द्वंद्व'', द इंडियन जर्नल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अंक 39, संख्या 4, अक्टूबर–दिसंबर 2016, पृ. 53–78।

''कर्नाटक उच्च शिक्षा नीति में शामिल होने और निजीकरण के खतरे'', तकनीकी शिक्षा के भारतीय जर्नल; अंक 39, संख्या 3. जुलाई–सितंबर 2016, पृ. 71–92।

''आंध्र की शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाः आंध्रा प्रदेश और तेलंगाना में उच्च शिक्षा के उद्देश्य और अनपेक्षित प्रभाव'', कॉलेज पोस्ट, अप्रैल–जून 2017, पृ. 3–9; और पृ. 24–25।

''महाराष्ट्र उच्च शिक्षा में निजी हस्तक्षेप : जनकल्याण से व्यवसायीकरण और विरोध विनियमन'', कॉलेज पोस्ट, अप्रैल–जून 2018, पृ. 11–22।

''भारतीय संघवाद में दीर्घकालिक स्थायी तनावः शिक्षा में केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मामला'', कॉलेज पोस्टः अक्टूबर–दिसंबर 2016।

लिबिंगवांग और वेस्ली टेटर (एड) में सह–लेखक, सह–लेखक, उच्च शिक्षा में शिक्षकों की प्रोन्नति, भारत में अकादमिक पेशे में उन्नतिः अकादमिक में करियर की पुनरावृत्तिः एशिया–प्रशांत, यूनेस्को, बैंकॉक में व्यावसायिक उन्नति नीतियों और प्रथाओं 2017, पृ. 105–40।

पुस्तक समीक्षाः अय्यर, आर.वी. वैद्यनाथ (2016). द होली ग्रिलः इंडियाज क्वेस्ट फॉर यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, शैक्षिक योजना और प्रशासन के जर्नल, अंक 31, संख्या 2, अप्रैल 2017, पृ.169–73।

रिपोर्ट अवधि में संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाओं में सहभागिता

5–7 मार्च, 2017 को शैक्षिक प्रशासन विभाग, नीपा द्वारा आयोजित 'शैक्षिक प्रशासन में नवाचार' पर राष्ट्रीय सम्मेलन में संसाधन व्यक्ति।

16–17 मार्च, 2017 को 'सार्वजनिक क्षेत्र और शिक्षाः शैक्षिक नीति के लिए संभावनाएँ और चुनौतियाँ '', नीपा, राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण।

17–18 जून, 2017 को दिल्ली में सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित 'समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षाः टु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4' पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण।

7–8 सितंबर, 2017 को उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपा द्वारा आयोजित 'उच्च शिक्षा का भविष्यः आर्थिक और सामाजिक संदर्भ' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत प्रपत्र।

16–30 सितंबर, 2017 को इंटरनेशनल शरद ऋतु स्कूल 2017, वयस्क विभाग, सतत शिक्षा और विस्तार, दिल्ली विश्वविद्यालय में संसाधन व्यक्ति।

7–8 दिसंबर, 2017 को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक विकास विभाग, नीपा द्वारा आयोजित "कुलपतियों के लिए उच्च शिक्षा में नेतृत्व विकास" पर कार्यशाला में भाग लिया।

7–8 दिसंबर, 2017 को होटल प्राइड प्लाजा, नई दिल्ली में 'उच्च शिक्षा में नेतृत्व विकासः कुलपतियों के लिए कार्यशाला की रिपोर्ट' पर कार्यशाला में भाग लिया।

19 दिसंबर, 2017 को सीपीआरएचई, नीपा, द्वारा आयोजित 'उच्च शिक्षा के नवाचारों में नवाचार' पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

22–23 फरवरी, 2018 को इंडियन हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में सेंटर फॉर हायर एजुकेशन (सीपीआरएचई), नीपा द्वारा सेंटर फॉर हायर एजुकेशन (क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन) पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत प्रपत्र।

कार्यशालाएँ/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

डिजिटल अभिलेखागार शैक्षिक दस्तावेजः मुक्त पहुंच, डिजिटल अभिलेखागार में अब तक लगभग 12,000 दस्तावेज अपलोड किए गए हैं।

नीपा से बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

आजीवन सदस्यः भारत की तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी

आजीवन सदस्यः भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

परिशिष्ट

परिशिष्ट–I

नीपा परिषद के सदस्य

(31 मार्च, 2018 के अनुसार)

नीपा परिषद का संघटन

अध्यक्ष

1.	माननीय, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	प्रो. एन.वी. वर्गीज कुलपति नीपा, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष

पदेन सदस्य

3.	सचिव, भारत सरकार उच्चतर शिक्षा विभाग,	सदस्य
4.	सचिव, भारत सरकार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	सदस्य
5.	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली	सदस्य
6.	निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), नई दिल्ली	सदस्य
7.	वित्त सलाहकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य

तीन प्रख्यात शिक्षाविद्
अध्यक्ष, द्वारा नामित

8. प्रो. एच.सी. वर्मा
भौतिक विभाग
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
कानपुर–208 016

9. प्रो. विनय कुमार पाठक
कुलपति,
डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय
आईईटी कैम्पस, सीतापुर रोड,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226021

10. प्रो. मोहम्मद अख्तर सिद्दकी
प्रोफेसर
इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन
शिक्षा संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया,
नई दिल्ली–110025

अध्यक्ष द्वारा परिक्रमवार
राज्य प्रतिनिधि मनोनीत सदस्य
(पांच क्षेत्रों से एक–एक सदस्य)

11. अपर मुख्य सचिव, (उच्चतर शिक्षा)
कर्नाटक सरकार
कक्ष सं. 645, छठा तल, एम.एस. भवन,
बंगलुरू–560 001

12. अपर मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग
जन सम्पर्क विभाग
भोपाल–462 003

13. अपर मुख्य सचिव
हरियाणा सरकार,
स्कूल शिक्षा विभाग
चंडीगढ़

14. मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग
मेघालय सिविल सचिवालय
माइंतडू भवन, शिलांग–793 001

15. सचिव, (स्कूली शिक्षा)
झारखण्ड सरकार,
सचिवालय, रांची
झारखंड–834 001

संस्थान का एक संकाय सदस्य
(अध्यक्ष, नीपा परिषद द्वारा नामित)

16. प्रो. एन.वी. वर्गीज
निदेशक, सीपीआरएचई, नीपा
नई दिल्ली–110016

17. कुलसचिव (प्रभारी)
सचिव, नीपा, नई दिल्ली–110016

परिशिष्ट–II

प्रबंधन बोर्ड के सदस्य

(31 मार्च, 2018 के अनुसार)

1. नीपा के कुलपति, – अध्यक्ष–पदेन

2. अध्यक्ष, नीपा परिषद द्वारा नामित तीन सदस्य

3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक नामिती

4. नीपा के संकायाध्यक्ष; तथा

5. संकाय के दो सदस्य (संस्थान के प्रोफेसर, सह–प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर) परिक्रामी और योग्यता/उपयुक्तता–सह–वरिष्ठता के आधार पर नामित

कुलसचिव, नीपा प्रबंधन बोर्ड के सचिव होंगे

परिशिष्ट–III

वित्त समिति के सदस्य

(31 मार्च, 2018 के अनुसार)

1. प्रो. एन.वी. वर्गीज — *अध्यक्ष – पदेन*
   कुलपति,
   नीपा,
   नई दिल्ली–110 016

(अध्यक्ष, नीपा परिषद द्वारा नामित)

2. श्री इन्द्रपाल सिंह
   आई.ए. एंड ए.एस. (सेवानिवृत्त)
   भारत के उप नियंत्रक तथा महालेखा
   नियंत्रक, महालेखा कार्यालय, नई दिल्ली

3. **कुलपति द्वारा नामित एक सदस्य**

मा.सं.वि. मंत्रालय के प्रतिनिधि

4. श्रीमती किरण अरोड़ा
   अवर सचिव
   मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार
   (संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार के प्रतिनिधि)
   शास्त्री भवन,
   नई दिल्ली–110 001

अन्य सदस्य

5. श्री सुभाष सी. शर्मा — *सचिव*
   वित्त अधिकारी (प्रभारी)
   नीपा,
   नई दिल्ली–110 016

6. श्री बसवराज स्वामी — *आमंत्रिति*
   कुलसचिव
   नीपा,
   नई दिल्ली–110 016

परिशिष्ट–IV

अकादमिक परिषद के सदस्य

(31 मार्च, 2018 के अनुसार)

1.	प्रो. एन.वी. वर्गीज कुलपति, नीपा, नई दिल्ली	– *अध्यक्ष*	
2 से 4	तीन प्रख्यात शिक्षाविद् जो नीपा के कार्यकलापों से जुड़े हुए हों और संस्थान की सेवा में न हों)	– सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित
5.	डा. (श्रीमती) नज़मा अख्तर प्रोफेसर और अध्यक्ष शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विभाग नीपा, नई दिल्ली	– सदस्य	
6.	डा. सुधांशु भूषण प्रोफेसर और अध्यक्ष उच्चत्तर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपा, नई दिल्ली	– सदस्य	
7.	डॉ. अरुण. सी. मेहता प्रोफेसर और अध्यक्ष शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग, नीपा, नई दिल्ली	– सदस्य	
8.	डा. एस.एम.आई.ए. जैदी प्रोफेसर और अध्यक्ष शैक्षिक योजना विभाग, नीपा, नई दिल्ली	– सदस्य	
9.	डा. ए.के. सिंह प्रोफेसर और अध्यक्ष शैक्षिक नीति विभाग, नीपा, नई दिल्ली	– सदस्य	
10.	डा. प्रणति पांडा प्रोफेसर और अध्यक्ष विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग, स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक, नीपा, नई दिल्ली	– सदस्य	

11.	डा. मोना खरे प्रोफेसर और अध्यक्ष शैक्षिक वित्त विभाग, नीपा, नई दिल्ली	– सदस्य
12.	डा. कुमार सुरेश प्रोफेसर और अध्यक्ष शैक्षिक प्रशासन विभाग, नीपा, नई दिल्ली	– सदस्य
13.	डा. (श्रीमती) वीरा गुप्ता सह प्रोफेसर, स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक, नीपा, नई दिल्ली	– सदस्य
14.	डा. (श्रीमती) नीरू स्नेही सहायक प्रोफेसर, उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपा, नई दिल्ली	– सदस्य कुलपति द्वारा नामित
15.	प्रो. फुरकॉन कमर महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू हाउस, 16, कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, कोटला मार्ग, नई दिल्ली फोनः 23236105, ई–मेलः sgoffice@aiu.ac.in	– बाहय विशेषज्ञ
16.	प्रो. अतुल शर्मा अध्यक्ष, ओकेडीआईएससीडी, गुवाहाटी 264, रामा अपार्टमेंट, सैक्टर–11, पॉकेट–2, द्वारका, नई दिल्ली–110075 फोनः 09873097723, ई–मेलः sarmaatul@yahoo.com	– विशेष आमंत्रिति विशेषज्ञ के तौर पर आमंत्रित
17.	प्रो. सुदर्शन अय्यंगर प्लाट नं. 3, एआरसीएच कैम्पस नगरीया, ओजरापादा रोड, धरमपुर–396050, जिला वलसाद, गुजरात, भारत फोनः 9898636916, इे–मेलः sudarshan54@gmail.com	– विशेष आमंत्रिति
18.	प्रो. रश्मि दीवान अध्यक्ष, एन.सी.एस.एल. नीपा, नई दिल्ली	– *आमंत्रिति*
19.	प्रो. के. बिस्वाल प्रभारी, यू–डाईस नीपा, नई दिल्ली	– *आमंत्रिति*
20.	प्रो. के. श्रीनिवास अध्यक्ष, आई.टी. तथा पी.एम.यू. नीपा, नई दिल्ली	– *आमंत्रिति*
21.	डॉ. निधि सभरवाल सह–प्रोफेसर सी.पी.आर.एच.ई., नीपा, नई दिल्ली	– *आमंत्रिति*
22.	डॉ. सुमन नेगी सह–प्रोफेसर, नीपा, नई दिल्ली	– रिपोर्ताज
23.	प्रो. एस.एम.आई.ए. जैदी कुलसचिव (प्रभारी) नीपा, नई दिल्ली	– सचिव

परिशिष्ट–V

अध्ययन बोर्ड के सदस्य

(31 मार्च, 2018 के अनुसार)

1. प्रो. एन.वी. वर्गीज — *अध्यक्ष*
   कुलपति
   नीपा, नई दिल्ली

2. प्रो वीना आर. मिस्त्री — सदस्य
   बी–5, सीएस पटेल एन्क्लेव,
   3 प्रताप गंज, वढोदरा–390002

3. प्रो. एस. होम चौधरी — सदस्य
   ए–47/9 अपर रिपब्लिक
   आईज़ोल

4. प्रो. वसंत भट्ट — सदस्य
   डीन एवं प्रोफेसर
   क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर

5. डा. (श्रीमती) नजमा अख्तर — सदस्य
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विभाग
   नीपा, नई दिल्ली

6. डा. सुधांशु भूषण — सदस्य
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   उच्चत्तर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग
   नीपा, नई दिल्ली

7. डा. नलिनी जुनेजा — सदस्य
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग
   नीपा, नई दिल्ली

8. डा. एस.एम.आई.ए. जैदी — सदस्य
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   शैक्षिक योजना विभाग
   नीपा, नई दिल्ली

9. डॉ. अरूण सी. मेहता — सदस्य
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग
   नीपा, नई दिल्ली

10. डा. ए.के. सिंह — सदस्य
    प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
    शैक्षिक नीति विभाग
    नीपा, नई दिल्ली

11. डा. कुमार सुरेश — सदस्य
    प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
    शैक्षिक प्रशासन विभाग
    नीपा, नई दिल्ली

12. प्रो. रश्मि दिवान, अध्यक्ष — सदस्य
राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केन्द्र
नीपा, नई दिल्ली

13. प्रो. के. बिस्वाल, अध्यक्ष — सदस्य
परियोजना प्रबंधन एकक विभाग
नीपा, नई दिल्ली

14. प्रो. एन.वी. वर्गीज — सदस्य
निदेशक, सीपीआरएचई
नीपा, नई दिल्ली

15. डा. (श्रीमती) वीरा गुप्ता — सदस्य
सह प्रोफेसर (वरिष्ठतम)
नीपा, नई दिल्ली

16. नीरू स्नेही — सदस्य
सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठतम)
नीपा, नई दिल्ली

17. प्रो. प्रणती पांडा — आमंत्रिति
नीपा, नई दिल्ली

18. प्रो. मोना खरे — आमंत्रिति
नीपा, नई दिल्ली

19. प्रो. नीलम सूद — आमंत्रिति
नीपा, नई दिल्ली

20. प्रो. बी. के. पांडा — आमंत्रिति
नीपा, नई दिल्ली

21. प्रो. के. श्रीनिवास — आमंत्रिति
नीपा, नई दिल्ली

22. श्री बसवराज स्वामी — आमंत्रिति
नीपा, नई दिल्ली

परिशिष्ट–VI

संकाय और प्रशासनिक स्टाफ

(31 मार्च, 2018 के अनुसार)

कुलपति
प्रो. एन.वी. वर्गीज

शैक्षिक योजना विभाग

एस.एम.आई.ए. जैदी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
पी. गीता रानी, प्रोफेसर
एन.के. मोहंती, सहायक प्रोफेसर
सुमन नेगी, सहायक प्रोफेसर

शैक्षिक प्रशासन विभाग

कुमार सुरेश, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
विनीता सिरोही, प्रोफेसर
मंजू नरूला, सहायक प्रोफेसर
वी. सुचारिता, सहायक प्रोफेसर

शैक्षिक वित्त विभाग

मोना खरे, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
वेट्टुकुरी पी.एस. राजू, सहायक प्रोफेसर

शैक्षिक नीति विभाग

अविनाश के. सिंह, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
मनीषा प्रियम, सह–प्रोफेसर
एस.के. मलिक, सहायक प्रोफेसर
नरेश कुमार, सहायक प्रोफेसर

विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग

प्रणति पांडा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
रश्मि दिवान, प्रोफेसर
मधुमिता बंद्योपाध्याय, प्रोफेसर
सुनीता चुग, सह–प्रोफेसर
कश्यपी अवस्थी, सहायक प्रोफेसर

उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग

प्रो. सुधांशु भूषण, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
आरती श्रीवास्तव, सह–प्रोफेसर
नीरू स्नेही, सह–प्रोफेसर
संगीता अंगोम, सहायक प्रोफेसर

शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग

अरुण सी. मेहता, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
के. बिस्वाल, प्रोफेसर
ए.एन. रेड्डी, सहायक–प्रोफेसर

शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विभाग

प्रो. नज़मा अख्तर, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
बी.के. पांडा, प्रोफेसर
सविता कौशल, सहायक प्रोफेसर
मोना सेदवाल, सहायक प्रोफेसर

कंप्यूटर केंद्र

के. श्रीनिवास, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष

राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र

रश्मि दीवान, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
सुनीता चुग, सह–प्रोफेसर
एन. मैथिली, सहायक प्रोफेसर
सुभिथा जी.वी., सहायक प्रोफेसर

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र

एन.वी. वर्गीज, प्रोफेसर एवं निदेशक
मोना खरे, प्रोफेसर
निधि सदाना सभरवाल, सह–प्रोफेसर
अनुपम पचौरी, सहायक प्रोफेसर
गरिमा मलिक, सहायक प्रोफेसर
जिनुशा पाणिग्रही, सहायक प्रोफेसर
मलिश सी.एम., सहायक प्रोफेसर
सायंतन मंडल, सहायक प्रोफेसर

स्कूल मानक एवं मूल्याकन एकक

प्रो. प्रणति पंडा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
वीरा गुप्ता, प्रोफेसर
रश्मिता दास स्वैन, सह–प्रोफेसर

परियोजना प्रबंधन एकक

के. श्रीनिवास, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पीठ

सलाहकार (आई.ए.आई.ई.पी.ए. परियोजना)

प्रो. के. रामचन्द्रन, प्रोफेसर

प्रशासनिक और अकादमिक सहयोग

कुलसचिव

श्री बसवराज स्वामी, दिनांक 08.03.2018 तक (अपराह्न)
प्रो एसएमआईए जैदी (प्रभारी), दिनांक 08.03.2018 से (अपराह्न)

सामान्य और कार्मिक प्रशासन

जी. वीराबाहु, प्रशासनिक अधिकारी
जयप्रकाश धामी, अनुभाग अधिकारी
बी.आर. पहवा, अनुभाग अधिकारी (प्रभारी)

अकादमिक प्रशासन

पी.पी. सक्सेना, अनुभाग अधिकारी

वित्त और लेखा

डा. सुभाष सी. शर्मा, वित्त अधिकारी(प्रभारी)
चंद्रप्रकाश, अनुभाग अधिकारी

प्रशिक्षण कक्ष

जयप्रकाश धामी, अनुभाग अधिकारी (प्रभारी)

प्रकाशन एकक

प्रमोद रावत, उप प्रकाशन अधिकारी

हिंदी कक्ष

सुभाष सी. शर्मा, हिंदी संपादक और सहायक हॉस्टल वार्डन

पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र

पूजा सिंह, पुस्तकालयाध्यक्षा
डी.एस. ठाकुर, प्रलेखन अधिकारी

कंप्यूटर केंद्र

नवीन भाटिया, कंप्यूटर प्रोग्रामर

वार्षिक लेखा
2017-18

तुलन पत्र

31 मार्च 2018 तक

(राशि ₹ में)

निधि के स्रोत/देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	विगत वर्ष
कोष/पूंजीकृत निधि	1	-	-
मौजूदा देनदारियां और प्रावधान	2	56,76,70,015	58,39,38,955
योग		56,76,70,015	58,39,38,955
आस्तियों का आवेदन/परिसंपत्तियां	अनुसूची	**चालू वर्ष**	**विगत वर्ष**
स्थायी परिसंपत्तियां	3	19,11,31,842	19,74,26,332
चालू परिसंपत्तियां	4	18,22,05,495	20,57,18,655
ऋण, अग्रिम एवं जमा राशियां	5	5,87,19,877	4,74,51,931
पूंजी निधि	-	13,56,12,801	13,33,42,037
योग		56,76,70,015	58,39,38,955
लेखा की महत्वपूर्ण नीतियां	14		
आकस्मिक देयताएं और लेखा पर टिप्पणियां	15		

ह./–	ह./–	ह./–
(सुभाष चन्द शर्मा)	**(कुमार सुरेश)**	**(एन.वी. वर्गीज)**
वित्त अधिकारी (प्रभारी)	कुलसचिव (प्रभारी)	कुलपति

आय और व्यय लेखा

31 मार्च 2018 तक

(राशि ₹ में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	विगत वर्ष
अ. आय			
शैक्षणिक प्राप्तियां	6	4,56,501	4,48,958
अनुदान/सहायता अनुदान	7	29,20,92,402	26,74,81,987
अर्जित ब्याज	8	7,05,649	21,03,203
अन्य आय	9	28,61,576	62,84,363
योग (अ)		29,61,16,128	27,63,18,511
ब. व्यय			
कर्मचारियों के भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय)	10	19,00,00,285	17,85,99,027
शैक्षणिक व्यय	11	5,72,02,817	5,83,87,433
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	12	2,53,09,906	2,40,67,185
मरम्मत एवं रखरखाव	13	1,95,79,394	1,54,44,699
मूल्यह्रास	3	1,47,94,821	1,74,85,313
योग (ब)		**30,68,87,223**	**29,39,83,656**
पूंजी निधि में हो रहे अधिशेष/(घाटा)		**(1,07,71,095)**	**(1,76,65,145)**

ह./–
(सुभाष चन्द शर्मा)
वित्त अधिकारी (प्रभारी)

ह./–
(कुमार सुरेश)
कुलसचिव (प्रभारी)

ह./–
(एन.वी. वर्गीज)
कुलपति

अनुसूची 1–5

तुलन पत्र के भाग

31 मार्च 2018 तक

अनुसूची 1

कोष/पूंजी निधि

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष (2017–18)	विगत वर्ष (2016–17)
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(13,33,42,037)	(13,57,76,016)
जमाः कोष/पूंजी निधि में योगदान	84,91,956	2,00,95,929
जमाः उपहार/दान में प्राप्त आस्तियां	8,375	3,195
जमाः प्रयोजित परियोजना निधि से खरीदी गई आस्तियां	–	–
जमाः आय और व्यय लेखा से स्थानांतरित व्यय से अधिक आय	–	–
योग	**(12,48,41,706)**	**(11,56,76,892)**
घटायाः आय और व्यय खाते से स्थानांतरित घाटा	1,07,71,095	1,76,65,145
वर्ष के अंत में शेष	**(13,56,12,801)**	**(13,33,42,037)**

अनुसूची 2

मौजूदा देनदारियां और प्रावधान

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष (2017—18)	विगत वर्ष (2016—17)
अ. वर्तमान देनदारियां		
प्रतिभूति जमा	11,25,858	6,33,858
पत्रिकाओं की सदस्यता शुल्क (अग्रिम)	2,11,876	1,35,910
बकाया देयताएं	29,66,498	24,58,883
वेतन	80,51,567	85,46,217
मा.सं.वि.मं. को देय ब्याज	14,91,772	-
प्रायोजित परियोजना की प्राप्तियां (कुल व्यय)	13,07,68,949	12,92,35,573
अग्रिम में प्राप्त आय (वर्ष 2017—18 का अप्रयुक्त अनुदान)	1,53,52,376	5,46,41,734
योग (अ)	**15,99,68,896**	**19,56,52,175**
ब. प्रावधान		
पेंशन	35,21,53,075	33,53,83,881
उपदान	3,59,55,295	3,42,43,138
अवकाश नकदीकरण	1,95,92,749	1,86,59,761
योग (ब)	**40,77,01,119**	**38,82,86,780**
योग (अ+ब)	**56,76,70,015**	**58,39,38,955**

अनुसूची 2(अ)

प्रायोजित परियोजना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रारंभिक जमा		वर्ष के दौरान प्राप्तियां/वसूली	कुल	वर्ष के दौरान व्यय	जमा शेष	
		निकासी	जमा				निकासी	जमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा)	–	48,05,356	69,97,259	1,18,02,615	50,24,025	–	67,78,590
2	डाईस की स्थापना और संचालन (यूनीसेफ़) डा. के. बिस्वाल	–	12,57,890	20,81,912	33,39,802	22,74,031	–	10,65,771
3	सर्वशिक्षा अभियान पर परियोजना (मा.सं.वि. मंत्रालय)	–	1,13,194	–	1,13,194	5,900	–	1,07,294
4	14 राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में स्कूल प्रबंधन तथा पर्यवे. क्षण में ग्रा.शि.स./डी.टी.ए./एस.एम.डी.सी./नगरीय निकायों इत्यादि की भूमिका, एडसिल का अध्ययन, (प्रो. ए.के. सिंह)	–	5,63,371	–	5,63,371	–	–	5,63,371
5	माध्यमिक शिक्षा सूचना प्रणाली प्रबंधन (सेमिस) मा.सं.वि. मंत्रालय (प्रो. ए.सी. मेहता)	–	14,58,894	–	14,58,894	5,66,869	–	8,92,025
6	बुरूण्डी में भारत अफ्रीका शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (दक्षिण अफ्रीका)	–	23,51,152	–	23,51,152	–	–	23,51,152
7	प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक (एडसिल) डॉ. के. सुजाता	(13,63,560)	–	–	(13,63,560)	–	(13,63,560)	–
8.	महात्मा गाँधी शान्ति शिक्षा संस्थान (एम.जी. आई.ई.पी.)	–	21,00,000	-	21,00,000	-	-	21,00,000
9.	नेतृत्व कार्यक्रम (मा.सं.वि. मंत्रालय) डा. रश्मि दिवान	(8,70,595)	–	1,11,60,000	1,02,89,405	1,14,29,554	(11,40,149)	–

10	नीति अनुसंधान केन्द्र (यूजीसी) (प्रो. एन.वी. वर्गीज)	–	2,91,00,982	–	2,91,00,982	1,46,32,155	–	1,44,68,827
11.	राष्ट्रीय अध्येयता (आईसीएसएसआर) प्रो. एहसानुल हक	–	–	–	–	–	–	–
12.	प्रशासनिक उपरिव्यय प्रभार / बचत खाता पर ब्याज	–	1,76,43,026	38,34,447	2,14,77,473	18,097	–	2,14,59,376
13.	विविधता, भेदभाव और असमानता के साथ व्यवहार (डा. निधि सदाना – सीपीआरएचई)	–	17,55,196	6,40,000	23,95,196	11,35,990	–	12,59,206
14.	केन्द्रीय योजना कार्यक्रम विद्यालय मानक शिक्षा (प्रो. प्रणति पांडा)	–	1,78,18,643	–	1,78,18,643	55,93,005	–	1,22,25,638
15.	यूनेस्को क्षेत्रीय केन्द्र (के. सुजाता)	–	9,48,001	–	9,48,001	–	–	9,48,001
16.	श्रीलंका कार्यक्रम	–	13,29,194	–	13,29,194	5,49,960	–	7,79,234
17.	आरएमएसए के अन्तर्गत विद्यालय मानक	–	17,28,480	–	17,28,480	12,81,916	–	4,46,564
18.	वरिष्ठ अध्येता – डॉ. ए. मैथ्यू (आईसीएसएसआर)	–	37,333	3,44,000	3,81,333	3,20,000	–	61,333
19.	राज्य का राजनीतिक अध्ययन – डॉ. ए. मैथ्यू (आईसीएसएसआर)	–	6,65,012	10,00,000	16,65,012	9,13,973	–	7,51,039
20.	पंडित मदन मोहन मालवीय	–	4,16,38,322	-	4,16,38,322	75,30,364	–	3,41,07,958
21.	शिक्षण एवं अनुसंधान आस्ट्रेलिया (यूजीसी) डा. सुधांशु भूषण	(12,95,075)	–	14,89,914	1,94,839	1,94,839	–	–
22.	आईईपीए (विदेश मंत्रालय)	(9,62,079)	–	27,34,811	17,72,732	12,68,294	–	5,04,438
23.	आईआईईपी – यूनेस्को (के. सुजाता)	–	39,21,527	–	39,21,527	7,13,288	–	32,08,239
24.	अध्यापक शिक्षण – ब्रिटिश परिषद	–	–	45,000	45,000	45,000	–	–
25.	शिक्षा पर राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र (पीएमएमएमटी)	–	–	2,67,00,000	2,67,00,000	9,107	–	2,66,90,893
	योग	**(44,91,309)**	**12,92,35,573**	**5,70,27,343**	**15,50,26,607**	**5,35,06,367**	**(25,03,709)**	**13,07,68,949**

अनुसूची 2 (ख)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुप्रयुक्त अनुदान

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष (2017–18)	विगत वर्ष (2016–17)
अ. योजना अनुदान मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
शेष राशि अग्रानीत	5,46,41,734	5,95,21,650
जमाः वर्ष के दौरान प्राप्तियां (अनुदान)	26,12,95,000	10,10,87,000
योग (अ)	**31,59,36,734**	**16,06,08,650**
घटाकरः राजस्व व्यय के लिए उपयोग	29,20,92,402	8,58,70,987
घटाकरः पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग	84,91,956	2,00,95,929
योग (ब)	**30,05,84,358**	**10,59,66,916**
अनप्रयुक्त अग्रानीत (अ–ब)	**1,53,52,376**	**5,46,41,734**
ब. अनुदान योजनेतर मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
शेष राशि अग्रानीत	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्तियां (अनुदान)	-	18,16,11,000
योग (स)	-	**18,16,11,000**
घटाकरः राजस्व व्यय के लिए उपयोग	-	18,16,11,000
घटाकरः पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग	-	
योग (द)	-	**18,16,11,000**
अनप्रयुक्त अग्रानीत (स–द)	-	-
महायोग (अ+ब)	**1,53,52,376**	**5,46,41,734**

अनुसूची 3

अचल संपत्तियां

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	आस्तियां शीर्ष		सकल ब्लॉक				वर्ष के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास			निवल ब्लॉक
		मूल्यह्रास की दर	अथ शेष	परिवर्धन वृद्धि	कटौती	जमा शेष (4+5+6+7-8)	मूल्यह्रास अथ शेष	परिवर्धन पर वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	कटौती/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास (9+11-13)	31.03.18 (9-13)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
1	भूमि	0%	23,07,892	-	-	23,07,892	-	-	-	-	23,07,892
2	भवन	2%	12,19,75,038	21,26,487	-	12,41,01,525	24,39,501	42,530	-	24,89,287	12,16,12,238
3	कार्यालय उपकरण	7.50%	1,09,35,297	3,27,645	-	1,12,62,942	8,20,147	24,573	-	8,44,721	1,04,18,221
4	कम्प्यूटर और उपकरण	20%	43,11,175	19,36,300	-	62,47,475	8,62,235	3,87,260	-	12,49,495	49,97,980
5	फर्नीचर और फिक्सचर	7.50%	64,24,993	76,980	-	65,01,973	4,81,874	5,774	-	4,87,648	60,14,325
6	वाहन	10%	13,50,123	-	-	13,50,123	1,35,012	-	-	1,35,012	12,15,111
7	पुस्तकालय पुस्तकें	10%	82,24,196	7,51,576	-	89,75,772	8,22,420	75,158	-	8,97,577	80,78,195
8	जर्नल	10%	2,90,26,987	16,11,582	-	3,06,38,569	29,02,699	1,61,158	-	30,63,857	2,75,74,712
	योग (अ)		18,45,55,702	68,30,570	-	19,13,86,271	84,63,888	6,96,452	-	91,67,597	18,22,18,674
9	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	40%	23,42,422	-	-	23,42,422	9,36,969	-	-	9,36,969	14,05,453
10	ई–जर्नल	40%	98,21,232	16,69,761	-	1,14,90,993	39,28,493	6,67,904	-	45,96,397	68,94,596
	योग (ब)		1,21,63,653	16,69,761	-	1,38,33,415	48,65,462	6,67,904	-	55,33,366	83,00,049
11	कम्प्यूटर और उपकरण	20%	3,26,672	-	-	3,26,672	65,334	-	-	65,334	2,61,338
12	फर्नीचर, फिक्सचर और फिटिंग	7.50%	3,80,305	-	-	3,80,305	28,523	-	-	28,523	3,51,782
	योग (स)		7,06,977	-	-	7,06,977	93,857	-	-	93,857	6,13,120
	महायोग (अ+ब+स)		19,74,26,332	85,00,331	-	20,59,26,663	1,34,23,207	13,64,357	-	1,47,94,821	19,11,31,842

अनुसूची 4

चालू परिसम्पत्तियां

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (2017–18)	विगत वर्ष (2016–17)
	1. स्टॉक		
1.	प्रकाशन (हस्तगत)	3,57,313	3,71,853
2.	वस्तुसूची	11,15,241	4,37,289
	2. नकदी एवं बैंक बचत		
1.	भारतीय स्टेट बैंक (34778757702) (चालू खाता)	33,857	9,006
2.	बैंक बचत (बचत खाता)	18,06,57,811	20,48,78,248
3.	डाक टिकट (हस्तगत)	41,273	22,259
	योग	**18,22,05,495**	**20,57,18,655**

अनुसूची 5

ऋण, अग्रिम और जमा

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (2017–18)	विगत वर्ष (2016–17)
1.	**कर्मचारियों को अग्रिम (गैर–ब्याज)**		
1.	त्यौहार अग्रिम	89,100	64,800
2.	**कर्मचारियों को दीर्घावधि के लिए अग्रिम (ब्याज)**		
1.	मोटर कार	-	12,000
2.	कम्प्यूटर अग्रिम	-	5,700
3.	स्कूटर अग्रिम	21,000	-
3.	**अग्रिम और नकद मूल्य या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अन्य राशियां**		
1	पूंजी खाता पर	4,17,94,325	4,06,93,626
2	संकाय/स्टाफ के लिए विविध अग्रिम	27,30,337	12,00,090
3	चिकित्सा अग्रिम	6,21,368	2,48,439
4	एलटीसी अग्रिम	9,16,034	-
5	संकाय को यात्रा भत्ता अग्रिम	40,000	6,09,816
4.	**पूर्व भुगतान व्यय**		
1.	बीमा	26,774	**10,272**
2.	अन्य व्यय	98,48,526	-
5.	**जमा**		
1.	एल.पी. गैस	77,348	77,348
2.	जल मीटर	1,650	1,650
3.	विद्युत	17,500	17,500
4.	अन्य	1,800	1,800
6.	**प्रोद्भूत आय**		
1.	ऋण एवं अग्रिम	30,406	17,581
7.	**अन्य – यूजीसी/प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्य वर्तमान परिसंपत्तियां**		
1.	प्रायोजित परियोजनाएं में शेष ऋण	25,03,709	44,91,309
	योग	**5,87,19,877**	**4,74,51,931**

अनुसूची 6

शैक्षणिक प्राप्तियां

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (2017–18)	विगत वर्ष (2016–17)
	छात्रों से शुल्क		
	शैक्षणिक		
1.	छात्र शुल्क	2,77,800	1,75,500
	योग (अ)	2,77,800	1,75,500
	बिक्री		
1	प्रकाशन बिक्री	92,401	1,98,158
2	विवरणिका की बिक्री	86,300	75,300
योग (ब)		**1,78,701**	**2,73,458**
महायोग (अ+ब)		**4,56,501**	**4,48,958**

अनुसूची 7

अनुदान/सहायता अनुदान (प्राप्त अशोध्य अनुदान)

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष (2017-18) कुल	विगत वर्ष (2016-17) कुल
शेष अग्रानीत	5,46,41,734	5,95,21,650
जोड़करः वर्ष के दौरान प्राप्तियां	26,12,95,000	28,26,98,000
जोड़करः वर्ष के दौरान अन्य प्राप्तियां	-	-
योग	**31,59,36,734**	**34,22,19,650**
घटाकरः परिसंपत्तियों के प्रयोग पर व्यय (अ)	84,91,956	2,00,95,929
शेष	**30,74,44,778**	**32,21,23,721**
घटाकरः परिसंपत्तियों के प्रयोग पर राजस्व व्यय (ब)	29,20,92,402	26,74,81,987
शेष सी/एफ (स)	**1,53,52,376**	**5,46,41,734**

अनुसूची 8

अर्जित ब्याज

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (2017–18)	विगत वर्ष (2016–17)
1.	**अनूसूचित बैंकों के बचत खातों पर**		
	अ) योजनेतर	–	11,75,350
	ब) योजना	–	6,03,253
	द) अतिरिक्त प्रशासनिक निधि खाता	6,26,435	2,97,462
	य) छात्रावास खाता	13,608	13,913
2.	**ऋणों पर**		
	अ. कर्मचारी/स्टाफ (अग्रिमों पर ब्याज)	65,606	13,225
	योग	**7,05,649**	**21,03,203**

अनुसूची 9

अन्य आय

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (2017–18)	विगत वर्ष (2016–17)
अ. भूमि एवं भवनों से आय			
1	छात्रावास किराया	18,64,580	36,72,170
2	लाईसेंस शुल्क	2,11,613	2,85,428
3	जल प्रभार की वसूली	5,643	10,131
	योग (अ)	**20,81,836**	**39,67,729**
ब. अन्य			
1	रॉयल्टी से आय	10,696	26,665
2	विविध प्राप्तियां	86,630	61,844
3	स्टाफ कार प्रयोग	-	4,204
4	विभिन्न परियोजनाओं से प्राप्त संस्थागत प्रभार	-	13,80,696
5	अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री	16,189	-
6	निविदा फार्म की बिक्री	11,000	-
7	पेंशनरों के लिये चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रवेश शुल्क	3,01,200	4,61,400
8	चिकित्सा योजना के लिए योगदान	3,54,025	3,81,825
	योग (ब)	**7,79,740**	**23,16,634**
	महायोग (अ+ब)	**28,61,576**	**62,84,363**

अनुसूची 10

कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ (स्थापना व्यय)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (2017-18) योजनेतर	योजना	योग	विगत वर्ष (2016-17) योजनेतर	योजना	योग
1	वेतन और मजदूरी	1,58,16,009	2,33,84,637	3,92,00,646	3,90,16,330	18,147	3,90,34,477
2	बोनस और भत्ते तथा समयोपरि भत्ता	2,76,60,112	3,69,00,752	6,45,60,864	6,65,64,939	11,46,082	6,77,11,021
3	नई पेंशन योजना में योगदान	7,28,882	8,95,400	16,24,282	17,70,139	-	17,70,139
4	कर्मचारी कल्याण व्यय (वर्दी)	-	78,726	78,726	1,08,400	-	1,08,400
5	अवकाश यात्रा सुविधा	2,88,284	18,42,119	21,30,403	25,95,689	-	25,95,689
6	चिकित्सा भत्ता प्रतिपूर्ति	22,45,587	43,84,138	66,29,725	83,84,365	-	83,84,365
7	बाल शिक्षा भत्ता	-	5,86,797	5,86,797	9,82,096	-	9,82,096
8	यात्रा भत्ता	-	1,52,533	1,52,533	1,45,382	-	1,45,382
9	अन्य (सरकारी अंशदान–सीपीएफ)	-	23,04,664	23,04,664	67,864	-	67,864
10	सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ	-	-	-	-	-	-
अ)	पेंशन	-	5,14,08,677	5,14,08,677	4,70,04,572	-	4,70,04,572
ब)	ग्रेज्युटी	-	1,04,73,741	1,04,73,741	61,34,841	-	61,34,841
स)	अवकाश नकदीकरण	-	1,08,49,227	1,08,49,227	46,60,181	-	46,60,181
	योग	**4,67,38,874**	**14,32,61,411**	**19,00,00,285**	**17,74,34,798**	**11,64,229**	**17,85,99,027**

अनुसूची 10 अ

कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	पेंशन	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	योग
1.	01–04–2017 को अथ शेष राशि (अ)	33,53,83,881	3,42,43,138	1,86,59,761	38,82,86,780
2.	घटाकरः वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान (ब)	3,46,39,483	87,61,584	99,16,239	5,33,17,306
3.	31–03–2018 को उपलब्ध बचत राशि (स) (अ–ब)	30,07,44,398	2,54,81,554	87,43,522	33,49,69,474
4.	वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार 31–03–2018 को आवश्यक प्रावधान (द)	35,21,53,075	3,59,55,295	1,95,92,749	40,77,01,119
अ.	**चालू वर्ष में किये जाने वाले प्रावधान (द–स)**	**5,14,08,677**	**1,04,73,741**	**1,08,49,227**	**7,27,31,645**

अनुसूची 11

शैक्षणिक व्यय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (2017-18)			विगत वर्ष (2016-17)		
		योजनेतर	योजना	योग	योजनेतर	योजना	योग
1	क्षेत्र कार्य/सम्मेलन में भागीदारी (संकाय के लिए यात्रा भत्ता)	-	44,99,831	44,99,831	-	47,07,053	47,07,053
2	क्षेत्र कार्य/सम्मेलन में भागीदारी (भागीदार के लिए यात्रा भत्ता)	-	71,78,287	71,78,287	-	76,12,767	76,12,767
3	संगोष्ठी/कार्यशालाओं पर व्यय (शैक्षणिक कार्यक्रमों में व्यय)	-	63,18,680	63,18,680	-	48,52,343	48,52,343
4	आगन्तुक संकाय के लिए भुगतान (संसाधन/व्यक्ति को मानदेय)	-	6,86,732	6,86,732	-	5,13,592	5,13,592
5	संस्थान के अनुसंधान अध्ययन	-	1,20,06,191	1,20,06,191	-	2,00,35,471	2,00,35,471
6	छात्रों को छात्रवृत्ति (एम.फिल. और पी–एच.डी.)	-	95,57,090	95,57,090	-	1,06,52,992	1,06,52,992
7	छात्रवृत्ति/पुस्तकें व परियोजना अनुदान	-	5,71,251	5,71,251	-	2,72,422	2,72,422
8	प्रकाशन व्यय (मुद्रण से प्राप्त)	-	9,59,640		-	17,52,494	
	(1) जोड़करः पिछले वर्ष का भण्डार	-	3,71,853	9,74,180	-	3,47,993	17,28,634
	(2) घटाकरः वर्तमान पुस्तकों का भण्डार	-	(3,57,313)		-	(3,71,853)	
9	सदस्यता के लिए अंशदान	-	1,34,138	1,34,138	-	2,75,198	2,75,198
10	अन्य (फोटोकॉपी प्रभार)	-	5,72,589	5,72,589	-	4,15,255	4,15,255
11	गैर–सरकारी संगठन को अनुदान	-	1,07,37,980	1,07,37,980	-	57,91,537	57,91,537
12	एनईआर (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित)	-	39,65,868	39,65,868	-	15,30,170	15,30,170
	योग	**-**	**5,72,02,817**	**5,72,02,817**	**-**	**5,83,87,433**	**5,83,87,433**

अनुसूची 12

प्रशासनिक और सामान्य व्यय

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (2017-18)			विगत वर्ष (2016-17)		
		योजनेतर	योजना	योग	योजनेतर	योजना	योग
अ	**आधार संरचना**						
1	विद्युत प्रभार		85,65,129	85,65,129	84,93,297	4,96,350	89,89,647
2	जल प्रभार		14,47,886	14,47,886	23,84,580	12,06,754	35,91,334
3	किराया, दरें और कर (संपत्ति कर सहित)		4,02,786	4,02,786	3,96,977	-	3,96,977
4	सुरक्षा प्रभार		26,31,679	26,31,679	-	15,58,294	15,58,294
ब	**संचार**						
1	डाक तथा तार		4,79,278	4,79,278	-	5,25,043	5,25,043
2	टेलीफोन, फैक्स एवं इंटरनेट प्रभार		9,28,725	9,28,725	10,32,798	1,43,737	11,76,535
स	**अन्य**						
1	स्टेशनरी		7,36,072	7,36,072	-	16,89,002	16,89,002
2	पोषाहार व्यय		49,85,686	49,85,686	-	11,71,032	11,71,032
3	पेट्रोल/तेल/स्नेहक व्यय		2,45,383	2,45,383	3,26,445	-	3,26,445
4	बीमा		45,630	45,630	93,019	-	93,019
5	किराए पर टैक्सी		13,27,741	13,27,741	-	5,10,143	5,10,143
6	लेखा परीक्षा शुल्क		-	-	-	-	-
7	मजदूरी प्रभार		14,98,401	14,98,401	-	9,69,786	9,69,786
8	विज्ञापन प्रभार		13,39,755	13,39,755	-	23,19,410	23,19,410
9	अखबार प्रभार		1,04,587	1,04,587	1,57,979	9,357	1,67,336
10	अन्य (पाठ्यक्रम शुल्क/प्रशिक्षण)		-	-	-	5,750	5,750
11	विविध व्यय		5,69,364	5,69,364	75,095	5,01,705	5,76,800
12	प्रभार (अन्य खाते)	955	-	1,804	-	-	632
	योग	**955**	**2,53,08,102**	**2,53,09,906**	**1,29,60,190**	**1,11,06,363**	**2,40,67,185**

अनुसूची 13

मरम्मत एवं रखरखाव

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (2017-18)			विगत वर्ष (2016-17)		
		योजनेतर	योजना	योग	योजनेतर	योजना	योग
1	भवन का रख–रखाव		63,93,893		–	32,29,615	91,61,684
2	संपदा रखरखाव इलेक्ट्रिकल (एआरएमओ)			63,93,893	–	59,32,069	–
3	फर्नीचर तथा फिक्सचर का रख–रखाव		1,06,137	1,06,137	–	–	–
4	कार्यालय उपकरणों का रखरखाव		50,06,505	50,06,505	–	21,23,986	21,23,986
5	वाहनों के रख–रखाव (स्टाफ कार)		1,74,766	1,74,766	2,31,737	–	2,31,737
6	गृह व्यवस्था सेवाएं		78,80,093	78,80,093	–	38,98,642	38,98,642
7	बागवानी		18,000	18,000	–	28,650	28,650
	योग	**–**	**1,95,79,394**	**1,95,79,394**	**2,31,737**	**1,52,12,962**	**1,54,44,699**

अनुसूची 14

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखा निर्माण के आधार

1.1 जब तक कि विधि का उल्लेख न किया जाए और सामान्यतया आमतौर पर कहा गया है कि लेखे ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत लेखांकन के प्रोद्भूत विधि पर तैयार किए जाते हैं।

2. राजस्व मान्यता

2.1 विद्यार्थियों से शुल्क, निविदा प्रपत्रों की बिक्री, प्रवेश फार्म की बिक्री, रॉयल्टी नकद आधार पर लेखांकन किए जाते हैं।

2.2 छात्रावास किराये से आय नकदी आधार पर लेखांकित की जाती है।

2.3 हालांकि ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन की पूरी अदायगी के बाद शुरू होता है, गृह निर्माण पेशगी, वाहन और कंप्यूटर की खरीद के लिए कर्मचारियों को ब्याज सहित अग्रिम की वसूली प्रोद्भूत आधार पर की जाती है।

3. अचल परिसंपत्तियां और मूल्यह्रास

3.1 अचल संपत्ति भाड़ा, शुल्कों और करों और अधिग्रहण, स्थापना और परिचालन से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्च आवक सहित अधिग्रहण की लागत से निर्धारित किया जाता है।

3.2 उपहार के रूप में प्राप्त पुस्तकों पर मुद्रित बिक्री मूल्य को मूल्यवान माना जाता है। उपहार में प्राप्त जिन पुस्तकों मे मूल्य पुस्तक में मुद्रित नहीं होते, उनका मूल्यांकन के आधार पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। उन्हें पूंजी कोष में जमा करके संस्था की अचल संपत्ति के साथ विलय कर लिया जाता है। मूल्यह्रास संबंधित परिसंपत्तियों की लागू दरों पर निर्धारित किया जाता है।

3.3 अचल परिसंपत्ति का मूल्य मूल्यह्रास में घटाकर निकाला जाता है। अचल परिसंपत्तियों का अवमूल्यन निम्नलिखित दरों के अनुसार सीधे तौर पर किया जाता है।

1	भवन	2%
2	कार्यालय उपकरण	7.5%
3	कंप्यूटर और अन्य सहायक सामग्री	20%
4	फर्नीचर फिक्चर और फिटिंग्स	7.5%
5	वाहन	10%
6	पुस्तकालय में पुस्तकें	10%
7	जर्नल्स	10%
8	ई–जर्नल	40%
9	कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर	40%

3.4 समीक्षाधीन वर्ष के अन्तर्गत वर्ष के लिये जमा पर मूल्यह्रास स्वायत संगठनों के लिये पसंदीदा विद्धि है। इसके अतिरिक्त संपत्तियों का संग्रह पूरे वर्ष के लिए रहा, इससे मूल्यह्रास बराबर रहा।

3.5 जहां एक परिसंपत्ति जिसका पूर्णतः मूल्यह्रास हो चुका हो इसे तुलन पत्र में रु. 1 की एक अवशिष्ट मूल्य पर अंकन किया जाएगा और आगे उसका पुनः मूल्यह्रास नहीं किया जाएगा। इसके बाद, प्रत्येक वर्ष के परिवर्धन पर मूल्यह्रास के दर की गणना उस परिसंपत्ति शीर्ष के मूल्यह्रास की दर पर की जाएगी।

3.6 इलेक्ट्रानिक पत्रिकाओं (ई–जर्नल्स) पर व्यय की अधिकता को देखते हुए लाइब्रेरी में इसे पुस्तकों से अलग किया गया है। पुस्तकालय की पुस्तकों के संबंध में उपलब्ध कराए गए 10 प्रतिशत के अवमूल्यन के सापेक्ष 40 प्रतिशत की एक उच्च दर पर ई–जर्नल्स के संबंध में मूल्यह्रास प्रदान किया गया।

3.8 कंप्यूटर और सहायक सामग्री को अर्जित सॉफ्टवेयर के व्यय से अलग किया गया है

क्योंकि यह कोई ठोस वस्तु नहीं होती और इसकी लुप्तशीलता की दर अपेक्षाकृत उच्च होती है। उच्च स्तर के साफफ्टवेयर का अवमूल्यन दर 40 प्रतिशत है जबकि कंप्यूटर और सहायक सामग्री का अवमूल्यन दर 20 प्रतिशत है।

4. स्टॉक

5.1 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के आधार पर स्टॉक की मूल्य सूची के अनुसार स्टेशनरी, प्रकाशन और अन्य स्टॉक की खरीद को राजस्व व्यय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जबकि सामान्य प्रशासन अनुभाग से प्राप्त जानकारी से वस्तु सूची के अनुसार राजस्व व्यय को कम करके शेष स्टॉक का मूल्य अंकन किया जाता है।

5. सेवानिवृत्त लाभ

5.1 सेवानिवृत्त लाभ यानी, पेंशन, ग्रेच्युटी लाभ और अवकाश नकदीकरण पिछले वर्ष के लेखा (2016–17) के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है। इसलिए इस वर्ष वर्तमान प्रावधान की गणना पिछले वर्ष के मूल्यांकन का 5 प्रतिशत बढ़ाकर की गई।

5.2 विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी अन्य नियोक्ता संस्थानों से आये हैं और जिन्हें विश्वविद्यालय में समाहित कर लिया गया है, उनके नियोक्ता संस्थानों से प्राप्त पेंशन और ग्रेच्यूटी लाभ पूंजीकृत मूल्य के रूप में पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण का वास्तविक भुगतान संबंधित प्रावधानों के खातों में क्रेडिट किया जाता हैं। अन्य सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात् नई पेंशन योजना, सेवानिवृत्ति पर गृह नगर के लिए यात्रा बिल, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति, (वर्ष के अंत में वास्तविक भुगतान सह बकाया बिल) प्रोद्भूत रूप में लेखांकित किया गया है।

6. सरकारी और यू.जी.सी. अनुदान

6.1 सरकारी अनुदान और यू.जी.सी. अनुदान प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया गया है।

6.2 पूंजीगत व्यय की दिशा में प्रयुक्त सरकारी अनुदान पूंजीगत निधि में स्थानांतरित किया जाता है।

6.3 राजस्व व्यय (वास्तविक आधार पर) को पूरा करने के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान को प्रयुक्त मानकर उसे उस वर्ष की आय के रूप में लिया गया है जिसमें वह प्राप्त हुआ है।

6.4 अनप्रयुक्त अनुदान (इस तरह के अनुदान का भुगतान अग्रिमों सहित) को आगामी वर्ष में लिया गया है और उसे तुलनपत्र में देयताएं के रूप में प्रस्तुत किया गया।

7. पी–एच.डी. और एम.फिल. के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

7.1 पी–एच.डी. और एम.फिल. के छात्रों को छात्रवृत्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा प्रदान किए गए योजना अनुदान से भुगतान की जा रही हैं और इसे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक खर्च के रूप में लेखांकित किया जाता है।

8. चिकित्सा अंशदान

8.1 चिकित्सा अंशदान नीपा की चिकित्सा योजना के अनुसार योजनेतर खाते में जमा किया जाता है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति गैर–योजना खाते से भुगतान किया जाता है।

9. गैर सरकारी संगठनों को अनुदान

9.1 समान उद्देश्य वाले गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान वित्तीय सहायता अनुदान/योजना के खाते के अंतर्गत व्यय के रूप में लेखांकित की जा रही है।

10. बेकार वस्तुओं की बिक्री

10.1 सेवा में प्रयुक्त न होने वाली और पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय को ''अन्य आय'' में दर्शाया जाता है, क्योंकि बेकार वस्तुओं का मूल्य का पहले ही पूर्ण अवमूल्यन हो जाता है।

अनुसूची 15

आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियाँ

1. अचल संपत्तियां

1.1 अचल संपत्तियां केवल योजना अनुदान से खरीदी गई है। अनुसूची 3 में वर्ष के दौरान संबंधित अचल संपत्तियों में योजना निधि (₹85,00,331), और पुस्तकालय में किताबें और विश्वविद्यालय को तोहफे के मूल्य (₹8,375), की अन्य सपत्तियाँ शामिल की गई हैं। आस्तियां पूंजीगत निधि में जमा करके स्थापित की गई हैं।

1.2 31.03.2017 के तुलन–पत्र और पहले के वर्षों के तुलन–पत्र में साफ तौर पर अचल संपत्तियां योजना निधि से बनाई गईं। योजना और अन्य निधि से वर्ष 01.04.2017 से 31.03.2018 तक सवंर्धित और उन परिवर्धनों पर संबंधित अवमूल्यन को अलग रूप में प्रदर्शित किया गया है (अनुसूची–3)।

2. मौजूदा देनदारियां और प्रावधान

2.1 व्यय जो 31 मार्च, 2018 को देय थे जिनका भुगतान नहीं किया गया, उन्हें देयता और वेतन देय के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

2.2 आयकर अधिनियम 1961 के तहत कोई कर योग्य आय न होने की स्थिति में, आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

2.3 कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधानों के प्रति देयता। संचित अवकाश के नकदीकरण के एवज में एकमुश्त भुगतान के प्रति दायित्व और पिछले साल के अनुमान के आधार पर निर्धारित थे। इस साल, 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार वास्तविक मूल्यांकन किया गया था और पहले किए गए प्रावधानों में पिछले सालों को कवर करने के लिए, पूर्व की अवधि के व्यय का भुगतान किया गया था। वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 31.03.2018 को और 2017–18 में किए गए भुगतान और शुद्ध प्रावधानों को आगे 2017–18 के प्रावधानों के लिए आय और व्यय खाता द्वारा वर्ष 2018–19 के खातों में भुगतान किए गए थे।

3. मौजूदा परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम और जमा

3.1 विश्वविद्यालय की राय में मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋण, अग्रिम और जमाओं पर आमतौर पर कम से कम तुलन–पत्र में दिखायी गयी कुल राशि के बराबर मूल्य है।

4. भविष्य निधि खाता

4.1 सरकार से संबंधित निर्देश के अनुसार भविष्य निधि खाते के रूप में संस्थान द्वारा उन निधियों को सदस्यों के स्वामित्व में प्रस्तुत किया गया हैं, संस्थान के खाते से भविष्य निधि खाते को अलग किया जाता है। हालांकि प्राप्ति और भुगतान खाता, (उपचय के आधार पर) आय और व्यय खाता और भविष्य निधि खाते का तुलन–पत्र संस्थान के वार्षिक लेखा में संलग्न है।

5. नई पेंशन योजना खाता

5.1 नई पेंशन योजना के तहत सभी कर्मचारियों को पीआरए संख्या प्राप्त है। नियोक्ता और कर्मचारी अंशदान नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजटरी लि. (एनएसडीएल) में सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) द्वारा नियमित रूप से स्थानान्तरण कर रहे हैं। योगदान की स्थानांतरित होने की कोई राशि बकाया नहीं है।

6. सेवानिवृत्ति लाभ

6.1 सेवानिवृत्ति लाभ यानी पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है। विश्वविद्यालय कर्मचारियों की पिछले नियोक्ता से प्राप्त पेंशन और उपदान के पूंजीकृत मूल्य, संबंधित प्रावधान खातों में जमा किये गए है।

7. अनुदान

7.1 पिछले वर्षों में योजना अनुदान को आय के रूप में लिया गया, केवल वह छोड़कर जो पूंजीगत व्यय के लिये उपयोग किये जाते थे, बैंक शेष के योजना अनुदान खाते और अग्रिम द्वारा जिनका अनुदान कोष और बकाया समायोजन द्वारा भुगतान किया गया। इन्हें वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को तुलन पत्र की परिसंपत्तियों में दर्शाया गया। 31.3.2017 को अनुप्रयुक्त अनुदान को आगे बढ़ाया गया और तुलन पत्र मे देयताओं के रूप में दर्शाया गया।

8. बचत बैंक खातों में शेष के विवरण चालू परिसंपत्तियों की अनुसूची 'अ' में संलग्न हैं।

9. पिछले वर्ष के आंकड़े आवश्यकतानुसार फिर से वर्गीकृत किये गए हैं।

10. अंतिम खातों में आंकड़े निकटतम रुपए में अंकित किया गया हैं।

11. अनुसूची 1 से 13 को संलग्न किया गया है और यह 31 मार्च 2018 के तुलन–पत्र और इस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के आय और व्यय लेखा का अभिन्न भाग होता है।

प्राप्तियां और भुगतान लेखा

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

(राशि ₹ में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष (2017-18)	विगत वर्ष (2016-17)	भुगतान	चालू वर्ष (2017-18)	विगत वर्ष (2016-17)
प्रारंभिक जमा			**व्यय**		
1 बचत बैंक खाता	20,49,09,513	15,52,15,150	स्थापना व्यय	17,05,90,746	15,99,96,423
			शैक्षणिक व्यय	5,73,67,345	5,26,70,722
भारत सरकार (मा.सं.वि. मं.) से प्राप्त अनुदान			प्रशासनिक व्यय	1,62,86,367	1,73,56,659
(अ) योजनेतर	-	18,16,11,000	मरम्मत एवं रखरखाव	1,37,14,880	1,54,33,917
(ब) योजना	26,12,95,000	10,10,87,000			
शैक्षणिक प्राप्तियां	16,05,463	16,83,536	**अध्येयतावृत्ति के संबंद्ध में भुगतान**	95,57,090	1,06,52,992
प्रायोजित परियाजनाओं/ योजनाओं के संबद्ध में प्राप्तियां	5,92,42,798	11,62,06,646	**प्रायोजित परियोजनाओं/ योजनाओं के संबंद्ध में भुगतान**	5,57,21,821	7,83,19,479
प्राप्त ब्याज			**सीपीडब्ल्यूडी के लिए अचल सम्पत्ति और अग्रिम पर व्यय**		
1. बैंक वचत खाता			1. अचल संपत्तियां		
(क) योजना	14,91,772	6,03,253	(अ) योजना	1,62,13,995	2,00,95,929
(ख) गैर–योजना	-	11,75,350	(ब) गैर–योजना	-	-
(ग) केनरा बैंक	-	-	2. सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम	90,91,700	31,78,297
(घ) ओवरहेड प्रशासनिक निधि	3,55,470	2,97,462	**वैधानिक भुगतान सहित अन्य भुगतान**		
(ङ) छात्रावास खाता	13,608	13,913	प्रभार (अन्य खाते)	849	632
2. ब्याज अग्रिमों पर ब्याज	52,781	21,016	**जमा और अग्रिम**	24,33,694	6,44,928
अन्य आय	18,64,580	36,72,170	**प्रेषण**	4,03,33,118	4,06,94,278
जमा और अग्रिम	5,72,700	2,92,300			
प्रेषण	4,03,50,883	4,06,94,278	**शेष समापन**		
वैधानिक प्राप्तियों सहित विविध प्राप्तियां			**बैंक जमा**	18,04,20,704	20,48,87,254
1. ओवरहैड प्रशासनिक निधि खाता 1108	-	13,80,696	**हस्तगत डाक**	22,259	22,259
योग	**57,17,54,568**	**60,39,53,769**	**योग**	**57,17,54,568**	**60,39,53,769**

ह./–	ह./–	ह./–
(सुभाष चन्द शर्मा)	**(कुमार सुरेश)**	**(एन.वी. वर्गीज)**
वित्त अधिकारी (प्रभारी)	कुलसचिव (प्रभारी)	कुलपति

तुलन पत्र

भविष्य निधि–तुलन पत्र, 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

(राशि ₹ में)

देयताएं		चालू वर्ष (2017–18)	विगत वर्ष (2016–17)	परिसंपत्तियां	चालू वर्ष (2017–18)	विगत वर्ष (2016–17)
अथशेष	16,28,15,677		14,91,81,700	**निवेश**		
जीपीएफ				जीपीएफ/सीपीएफ निवेश	14,13,29,886	14,43,70,593
वर्ष में अंशदान	1,77,32,547			31 मार्च, 2017 को अर्जित ब्याज	30,76,090	16,50,504
ब्याज जमा	1,01,53,083					
घटायाः निकासी	–4,61,88,557	14,45,12,750	1,24,63,435			
सीपीएफ				**बैंक में नकदी**		
वर्ष के दौरान अंशदान	72,000			एसबीआई खाता नं. 10137881013	42,70,955	1,67,94,580
ब्याज जमा	55,282	1,27,282	1,19,620			
संस्थान अंशदान (सीपीएफ)						
ब्याज जमा		46,318	45,036			
मार्च 2017 के लिए अंशदान		69,736	67,864			
ब्याज जमा						
व्यय से अधिक आय की अधिकता		39,20,845	9,38,022			
		14,86,76,931	**16,28,15,677**		**14,86,76,931**	**16,28,15,677**

ह./–	ह./–	ह./–
(सुभाष चन्द शर्मा)	**(कुमार सुरेश)**	**(एन.वी. वर्गीज)**
वित्त अधिकारी (प्रभारी)	कुलसचिव (प्रभारी)	कुलपति

भविष्य निधि लेखा

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार आय और व्यय लेखा

(राशि ₹ में)

व्यय	(चालू वर्ष) 2017–18	(विगत वर्ष) 2016–17	आय		(चालू वर्ष) 2017–18	(विगत वर्ष) 2016–17
जीपीएफ खाते	1,01,53,083	1,06,10,165	निवेश / बचत खाते पर अर्जित ब्याज		1,27,49,942	1,23,99,051
सीपीएफ खाते	55,282	47,620	जोड़ें: मार्च 2017 को अर्जित ब्याज	81,16,923		66,91,337
			घटाया: मार्च 2016 के लिए उपार्जित ब्याज	(-66,91,337)	14,25,586.00	(-74,49,545)
संस्थान के अंशदान पर ब्याज (सीपीएफ)	46,318	45,036	प्राप्त संस्थान अंशदान (सीपीएफ)		69,736.00	67,864
संस्थान अंशदान (सीपीएफ)	69,736	67,864				
व्यय से अधिक आय की अधिकता	39,20,845	9,38,022				
	1,42,45,264	**1,17,08,707**			**1,42,45,264**	**1,17,08,707**

ह./–	ह./–	ह./–
(सुभाष चन्द शर्मा)	**(कुमार सुरेश)**	**(एन.वी. वर्गीज)**
वित्त अधिकारी (प्रभारी)	कुलसचिव (प्रभारी)	कुलपति

भविष्य निधि लेखा

जीपीएफ/सीपीएफ 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार प्राप्तियां और भुगतान लेखा

(राशि ₹ में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2017-18	विगत वर्ष 2016-17	भुगतान	चालू वर्ष 2017-18	विगत वर्ष 2016-17
प्रारंभिक जमा	1,67,94,580.01	58,67,704.00	जीपीएफ अग्रिम/आहरण	4,61,88,557.00	1,65,59,102.00
जीपीएफ अंशदान और प्राप्तियां	1,77,32,547.00	1,84,12,372.00	सीपीएफ अग्रिम/आहरण	–	–
सीपीएफ अंशदान और प्राप्तियां	72,000.00	72,000.00			
सावधि जमा नकदीकरण	5,18,32,093.00	4,44,81,020.00			
सीपीएफ अंशदान	69,736.00	67,864.00	वर्ष के दौरान निवेश	4,87,91,386.00	4,79,46,329.00
बैंक में सावधि जमाओं जीपीएफ/सीपीएफ खाते से प्राप्त ब्याज	1,27,49,942.42	1,23,99,051.00	जमा शेष	42,70,955.43	1,67,94,580.00
	9,92,50,898.43	**8,13,00,011.00**		**9,92,50,898.43**	**8,13,00,011.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(सुभाष चन्द शर्मा)	**(कुमार सुरेश)**	**(एन.वी. वर्गीज)**
वित्त अधिकारी (प्रभारी)	कुलसचिव (प्रभारी)	कुलपति

बैंक खातों में शेष राशि

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	बेंक खाते	चालू वर्ष (2017-18)	विगत वर्ष (2016-17)
1	भारतीय स्टेट बैंक (10137881320) योजनेत्तर	10,26,073	4,16,63,463
2	सिंडिकेट बैंक (91392010001112) योजना	2,54,07,637	1,31,51,503
3	सिंडिकेट बैंक (91392010001092) परियोजना	12,82,65,240	12,47,44,264
4	सिंडिकेट बैंक (91392010001108) ओवरहैड प्रशासनिक निधि	2,55,77,844	2,49,51,610
5	सिंडिकेट बैंक (91392015365) छात्रावास	3,70,185	3,56,577
6	केनरा बैंक खाता 25536	10,832	10,832
7	भारतीय स्टेट बैंक (34778757702) चालू खाता	33,857	9,006
	योग	**18,06,91,668**	**20,48,87,254**

गैर–सरकारी संगठन को अनुदान की सूची

वर्ष 2017-18 के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	गैर–सरकारी संगठनों के नाम	जारी राशि
1	प्रजयत्ना	4,47,000.00
2	अलीगढ हिस्टोरियन	5,17,000.00
3	इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस	7,05,000.00
4	समथा सोसायटी	2,80,000.00
5	मोनालीसा शिक्षा अवाम	1,50,000.00
6	सोसायटी फार एजुकेशन एंड डवलपमेंट	12,74,000.00
7	न्यू शिव शक्ति	2,47,930.00
8	सुमन शिक्षा येवन	1,50,000.00
9	सीमैट यूपी	2,50,000.00
10	दलित ग्रामीण विकास	6,00,000.00
11	आशीर्वाद रूरल डवलपमेंट	1,50,000.00
12	सोसायटी फॉर सोशियल ट्रांसफारमेशन	1,45,525.00
13	आनन्द मेमोरियल फाउण्डेशन	2,50,000.00
14	एसोसिएशन फॉर ग्लोबल रूरल	1,50,000.00
15	शास्त्रा यूनिवर्सिटी	16,59,150.00
16	नवनीत फाउण्डेशन	5,54,750.00
17	सोसायटी टू डिसेबिलिटी	7,89,649.00
18	सीईपीईसीएएमआई, एएमयू	2,93,846.00
19	विवेकानन्द कॉलेज, कोल्हापुर	14,240.00
20	अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी	3,00,000.00
21	इंडियन एकेडमी ऑफ सोशल साइन्स	2,50,000.00
22	साना एजुकेशनल डवलपमेंट सोसायटी	1,50,000.00
23	वाटर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी	1,50,000.00
24	मणिपुर एजुकेशनल डवलपमेंट एंड रिसर्च, इम्फाल	1,09,890.00
25	पीजी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन	5,50,000.00
26	माता कामेश्वरी फाउण्डेशन	4,50,000.00
27	उर्मिला फाउण्डेशन मधुबनी	1,50,000.00
	योग	**1,07,37,980.00**

अनुसूची–ग

निवेश का विवरण

01.04.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए निवेश का विवरण

क्र. सं.	बैंक का नाम	एफडी सं.	जारी करने की तिथि	परिपक्वता तिथि	कुल राशि	ब्याज की दर (%)
1	सिंडिकेट बैंक	970000/970075	20.05.2017	20.05.2018	76,14,235.73	6.60
2	केनरा बैंक	032137/037230/994560	12.06.2017	12.06.2018	70,00,000.00	6.90
3	केनरा बैंक	510179	29.1.2018	29.07.2018	59,63,740.00	6.35
4	सिंडिकेट बैंक	197811	07.09.2017	07.09.2018	40,00,000.00	6.50
5	सिंडिकेट बैंक	197821	17.09.2017	17.09.2018	50,00,000.00	6.50
6	सिंडिकेट बैंक	197828	25.09.2017	25.09.2018	70,00,000.00	6.50
7	सिंडिकेट बैंक	969781	04.10.2017	04.10.2018	35,00,000.00	6.50
8	सिंडिकेट बैंक	197860	30.10.2017	30.10.2018	90,00,000.00	5.50
9	सिंडिकेट बैंक	197861	30.10.2017	30.10.2018	90,00,000.00	5.50
10	सिंडिकेट बैंक	197862	30.10.2017	30.10.2018	90,00,000.00	5.50
11	केनरा बैंक	032400/037953/ 994980	30.11.2016	04.12.2018	70,00,000.00	6.50
12	केनरा बैंक	032401/037954/ 994981	30.11.2016	04.12.2018	70,00,000.00	6.50
13	सिंडिकेट बैंक	197895	05.01.2018	05.01.2019	65,00,000.00	6.60
14	सिंडिकेट बैंक	197964	05.02.2018	05.02.2019	20,00,000.00	6.75
15	पंजाब नेशनल बैंक	CBU022534/ 139900/23143/84157	12.01.2018	12.02.2019	95,00,000.00	6.50
16	पंजाब नेशनल बैंक	CBU022534/ 1543	16.02.2018	16.02.2019	1,46,97,437.00	6.50
17	सिंडिकेट बैंक	970252	26.02.2018	09.03.2019	75,00,000.00	6.75
18	पंजाब नेशनल बैंक	CBU022534/ 1066 pu54420/84166	12.01.2018	12.03.2019	95,00,000.00	6.50
19	पंजाब नेशनल बैंक	CBU022534/ 139900/23143/84175	12.01.2018	12.04.2019	91,30,209.00	6.50
20	एसबीआई एसपीएल जमा	812	27.06.1981	-	14,24,264.00	
				योग	**14,13,29,885.73**	

नकदीकरण 2017–18

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	एफडी सं.	जारी करने की तिथि	परिपक्वता तिथि	कुल राशि
1	सिंडिकेट बैंक	197812	07.09.2016	07.09.2017	30,00,000.00
2	सिंडिकेट बैंक	407156/969620	26.01.2017	26.01.2018	35,00,000.00
3	सिंडिकेट बैंक	969825	28.01.2017	28.01.2018	50,00,000.00
4	पंजाब नेशनल बैंक	CBU022534/ 139900/23143	26.11.2016	30.12.2017	1,63,91,447.00
5	पंजाब नेशनल बैंक	CBU022534/ 1066/pu54420	01.01.2017	31.12.2017	98,86,403.00
6	पंजाब नेशनल बैंक	CBU022534/1543	16.02.2017	16.02.2018	1,40,54,243.00
				योग	**5,18,32,093.00**

वर्ष 2017-18 के दौरान किये गये एफडी (सावधि जमा)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	एफडी सं.	जारी करने की तिथि	परिपक्वता तिथि	कुल राशि	ब्याज की दर (%)
1	केनरा बैंक	510179	29.01.2018	29.07.2018	59,63,740.00	6.35
2	पंजाब नेशनल बैंक	CBU022534/ 139900/23143/84157	12.01.2018	12.02.2019	95,00,000.00	6.50
3	पंजाब नेशनल बैंक	CBU022534/ 1066/ pu54420/84166	12.01.2018	12.03.2019	95,00,000.00	6.50
4	पंजाब नेशनल बैंक	CBU022534/ 139900/23143/84175	12.01.2018	12.04.2019	91,30,209.00	6.50
5	पंजाब नेशनल बैंक	CBU022534/ 1543	16.02.2017	16.02.2018	1,46,97,437.00	6.50
		योग			**4,87,91,386.00**	

वर्ष 2017-18 के निवेश विवरण

	(राशि ₹ में)
अथ शेष	14,43,70,593.00
वर्ष के दौरान किये गये निवेश	4,87,91,386.00
कुल निवेश	**19,31,61,979.00**
वर्ष के दौरान किये गये नकदीकरण	5,18,32,093.00
शुद्ध निवेश (अंत शेष)	**14,13,29,886.00**

शेष परीक्षण

1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक

(राशि ₹ में)

विवरण	अथशेष	हस्तान्तरण		अंतशेष
		निकासी	जमा	
पूंजीगत लेखा	**115676891.11 Dr**	**17665145.63**	**8500331.00**	**124841705.74 Dr**
पूंजीगत निधि	115676891.11 Dr	17665145.63	8500331.00	124841705.74 Dr
चालू देयताएं	**579447645.84 Cr**	**291329100.72**	**277047761.76**	**565166306.88 Cr**
राशि लेनदार	15973.00 Cr			15973.00 Cr
राशि लेनदार – सी.पी.एफ.	15973.00 Cr			15973.00 Cr
बिलों से कटौती		823241.00	823241.00	
ठेकेदार से आयकर – परियोजना		150237.00	150237.00	
ठेकेदार से आयकर – आवर्त्ती		671752.00	671752.00	
ठेकेदार से आयकर – योजनेतर		1252.00	1252.00	
वेतन से कटौती		39509877.00	39527642.00	17765.00 Cr
जी.पी.एफ. अंशदान (पुर्नप्राप्ति)		17696547.00	17696547.00	
सामूहिक बीमा योजना		81320.00	81160.00	160.00 Dr
आयकर (वेतन) – योजनेतर		6472600.00	6472600.00	
आयकर (वेतन) – परियोजना		1533100.00	1533100.00	
आयकर (वेतन) – योजना		8165048.00	8165048.00	
एल.आई.सी.		291396.00	291396.00	
नई पेंशन स्कीम से वसूली		1790229.00	1808154.00	17925.00 Cr
सोसायटी वसूली		3479637.00	3479637.00	
विशिष्ट परियोजना	124744263.84 Cr	65592551.72	69113528.35	128265240.47 Cr
प्रावधान	388286780.00 Cr		19414339.00	407701119.00 Cr
प्रावधान – ग्रेच्युटी	34243138.00 Cr		1712157.00	35955295.00 Cr
प्रावधान – अवकाश वेतन	18659761.00 Cr		932988.00	19592749.00 Cr
प्रावधान – पेंशन	335383881.00 Cr		16769194.00	352153075.00 Cr
मा.सं.वि.मं. को देय ब्याज			1491772.41	1491772.41 Cr
बकाया देनदारियाँ	2427946.00 Cr	2427946.00	2917796.00	2917796.00 Cr
भुगतान के बदले में	14964.00 Cr			14964.00 Cr
वेतन देय	8546217.00 Cr	8546217.00	8051567.00	8051567.00 Cr
सुरक्षा जमा समायोजित	633858.00 Cr	4000.00	496000.00	1125858.00 Cr
जर्नल की सदस्यता शुल्क (अग्रिम)	135910.00 Cr	135910.00	211876.00	211876.00 Cr
निधि हस्तांतरण – आवर्ती		25000000.00	25000000.00	

विवरण	अथशेष	हस्तान्तरण		अंतशेष
		निकासी	जमा	
निधि हस्तांतरण – गैर आवर्ती		40000000.00	40000000.00	
निधि हस्तांतरण – ओवरहैड एडमिन. खाता		35000000.00	35000000.00	
परियोजना खाते से हस्तांतरण		35000000.00	35000000.00	
अनुप्रयुक्त अनुदान – योजना	54641734.00 Cr	39289358.00		15352376.00 Cr
अचल संपत्तियां	197426332.15 Dr	21965663.00	28260152.00	191131843.15 Dr
कंप्यूटर तथा अन्य सामग्री	4311174.90 Dr	1936300.00	1249495.00	4997979.90 Dr
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2342422.00 Dr		936969.00	1405453.00 Dr
अचल परिसंपत्ति – प्रायोजित	706977.00 Dr		93857.00	613120.00 Dr
फर्नीचर और साजो–सामान	6424993.34 Dr	76980.00	487648.00	6014325.34 Dr
भूमि	2307892.03 Dr			2307892.03 Dr
पुस्तकालय की पुस्तकें	8224195.95 Dr	751576.00	897577.00	8078194.95 Dr
कार्यालय भवन	121975037.99 Dr	2126487.00	2489287.00	121612237.99 Dr
अन्य कार्यालय उपकरण	10935296.82 Dr	327645.00	844721.00	10418220.82 Dr
ई–जर्नल की खरीद	9821232.24 Dr	6685042.00	9611678.00	6894596.24 Dr
जर्नल की खरीद	25411680.95 Dr	10061633.00	7898602.00	27574711.95 Dr
जर्नल की खरीद	3615306.00 Dr		3615306.00	
स्टाफ कार की खरीद	1350122.93 Dr		135012.00	1215110.93 Dr
वर्तमान परिसंपत्तियां	248679276.95 Dr	632140387.55	642398001.20	238421663.30 Dr
स्टाफ को अग्रिम	2058345.00 Dr	21887362.00	19637968.00	4307739.00 Dr
एल.टी.सी. अग्रिम		2659675.00	1743641.00	916034.00 Dr
चिकित्सा अग्रिम	248439.00 Dr	2045425.00	1672496.00	621368.00 Dr
विविध अग्रिम	1200090.00 Dr	14220262.00	12690015.00	2730337.00 Dr
संकाय/स्टाफ का यात्रा भत्ता अग्रिम	609816.00 Dr	2962000.00	3531816.00	40000.00 Dr
अर्जित ब्याज	17581.00 Dr	12825.00		30406.00 Dr
ऋण तथा अग्रिम पर अर्जित ब्याज	17581.00 Dr	12825.00		30406.00 Dr
वस्तुसूची	437289.00 Dr	1115241.00	437289.00	1115241.00 Dr
वस्तुसूची– स्टेशनरी	437289.00 Dr	1115241.00	437289.00	1115241.00 Dr
पूर्व प्रदत्त व्यय	10272.00 Dr	9875300.00	10272.00	9875300.00 Dr
प्रीपेड – बीमा	10272.00 Dr	26774.00	10272.00	26774.00 Dr
प्रीपेड – अन्य जर्नल		9848526.00		9848526.00 Dr
स्टाफ से वसूली योग्य	82500.00 Dr	180300.00	152700.00	110100.00 Dr
कार अग्रिम	12000.00 Dr		12000.00	
कंप्यूटर अग्रिम	5700.00 Dr		5700.00	
त्योंहार अग्रिम	64800.00 Dr	150300.00	126000.00	89100.00 Dr
स्कूटर अग्रिम		30000.00	9000.00	21000.00 Dr
जमा (परिसंपत्तियां)	40693626.00 Dr	9091700.00	7991001.00	41794325.00 Dr
सी.पी.डब्ल्यू.डी. को जमा–सिविल/ इलैक्ट्रिकल	40693626.00 Dr	9091700.00	7991001.00	41794325.00 Dr

विवरण	अथशेष	हस्तान्तरण		अंतशेष
		निकासी	जमा	
विविध देनदार	98298.00 Dr			98298.00 Dr
रोकड़ हाथ में		1880155.00	1880155.00	
नकद रोकड़		5400.00	5400.00	
रोकड़ – परियोजना		1760615.00	1760615.00	
रोकड़ – योजनेतर		114140.00	114140.00	
बैंक खाते	204887253.95 Dr	587698918.55	611894504.20	180691668.30 Dr
3000 – सिंडीकेट बैंक – 91–1092 – परियोजना	124744263.84 Dr	99606722.35	96085745.72	128265240.47 Dr
4000 – चालू खाता – 34778757702	9006.00 Dr	25500.00	649.00	33857.00 Dr
6000 – हॉस्टल खाता	356577.03 Dr	13608.21		370185.24 Dr
8000 – केनरा बैंक	10832.10 Dr			10832.10 Dr
9000 – प्रशासन निधि खाता 1108	24951609.68 Dr	35626434.38	35000200.00	25577844.06 Dr
एस.बी.आई. – 10137881320 – योजनेतर	41663462.56 Dr	153575596.49	194212986.49	1026072.56 Dr
सिंडीकेट बैंक – 91–1112 – योजना	13151502.74 Dr	298851057.12	286594922.99	25407636.87 Dr
हस्तगत डाक टिकट	22259.00 Dr	41273.00	22259.00	41273.00 Dr
हस्तगत प्रकाशन	371853.00 Dr	357313.00	371853.00	357313.00 Dr
अप्रत्यक्ष आय		284222382.41	580338510.00	296116127.59 Cr
चालू खाता में जमा			25500.00	25500.00 Cr
4002 – छात्रों से फीस			25500.00	25500.00 Cr
प्राप्तियां – उपरी प्रशासनिक निधि खाता 1108			626434.38	626434.38 Cr
जमा पर ब्याज – उपरी प्रशासनिक निधि खाता 1108			626434.38	626434.38 Cr
प्राप्तियां – योजनेतर		1837271.00	5195454.00	3358183.00 Cr
पेंशन भोगी चिकित्सा दाखिला फीस		228600.00	529800.00	301200.00 Cr
स्वास्थ्य योजना अंशदान (सीजीएचएस)		153300.00	507325.00	354025.00 Cr
छात्रावास किराया		454000.00	2318580.00	1864580.00 Cr
ब्याज वाली पेशगियों पर ब्याज		15331.00	80937.00	65606.00 Cr
बचत खाता पर ब्याज		401661.00	401661.00	
विविध प्राप्तियां		11601.00	98231.00	86630.00 Cr
लाइसेंस शुल्क की वसूली		111718.00	323331.00	211613.00 Cr
जल प्रभार की वसूली		2533.00	8176.00	5643.00 Cr
रॉयल्टी		402.00	11098.00	10696.00 Cr
बेकार वस्तुओं की बिक्री		16189.00	32378.00	16189.00 Cr
विवरणिका की बिक्री		15000.00	101300.00	86300.00 Cr
प्रकाशन की बिक्री		262336.00	354737.00	92401.00 Cr
टेण्डर फॉर्म की बिक्री			11000.00	11000.00 Cr

विवरण	अथशेष	हस्तान्तरण निकासी	हस्तान्तरण जमा	अंतशेष
छात्र शुल्क		164600.00	416900.00	252300.00 Cr
प्राप्तियां–आवर्ती		262385111.41	554477513.41	292092402.00 Cr
मा.सं.वि. मंत्रालय से अनुदान – योजना		261295000.00	553387402.00	292092402.00 Cr
बचत खाता से ब्याज – योजना		1090111.41	1090111.41	
प्राप्तियां – योजनेतर		20000000.00	20000000.00	
मा.सं.वि. मंत्रालय से अनुदान – योजनेतर		20000000.00	20000000.00	
प्राप्तियां – हॉस्टल टेलीफोन बूथ			13608.21	13608.21 Cr
अप्रत्यक्ष व्यय		402418924.48	95531702.20	306887222.28 Dr
अवमूल्यन		14794820.00		14794820.00 Dr
अवमूल्यन – भवन		2489287.00		2489287.00 Dr
अवमूल्यन – कंप्यूटर		1249495.00		1249495.00 Dr
अवमूल्यन – कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		936969.00		936969.00 Dr
अवमूल्यन – ई–जर्नल		4596397.00		4596397.00 Dr
अवमूल्यन – फर्नीचर		487648.00		487648.00 Dr
अवमूल्यन – जर्नल		3063857.00		3063857.00 Dr
अवमूल्यन – पुस्तकालय पुस्तकें		897577.00		897577.00 Dr
अवमूल्यन – कार्यालय उपकरण		844721.00		844721.00 Dr
अवमूल्यन – अन्य (प्रायोजित)		93857.00		93857.00 Dr
अवमूल्यन – वाहन		135012.00		135012.00 Dr
व्यय – चालू खाता		649.00		649.00 Dr
4003 – विविध व्यय		649.00		649.00 Dr
प्रशा. निधि खाता 1108 में उपरिव्यय		200.00		200.00 Dr
9002–व्यय–उपरिव्यय प्रशा. निधि खाता 1108		200.00		200.00 Dr
गैर–आवर्ती व्यय		122294791.00	75554962.00	46739829.00 Dr
स्थापना व्यय – गैर–आवर्ती		122294791.00	75554962.00	46739829.00 Dr
1001 – अधिकारियों को वेतन		44412495.00	33232646.00	11179849.00 Dr
1002 – स्थापना के लिए भुगतान		4636160.00		4636160.00 Dr
1003 – वेतन – भत्ते		29982659.00	2339179.00	27643480.00 Dr
1004 – समयोपरि भत्ता		16632.00		16632.00 Dr
1005 – चिकित्सा प्रतिपूर्ति		4158406.00	1912819.00	2245587.00 Dr
1006 – अवकाश यात्रा रियायत		289616.00	1332.00	288284.00 Dr
1010 – नई पेंशन योजना (सरकारी अंश)		728882.00		728882.00 Dr
1011 – ग्रेच्यूटी		7761584.00	7761584.00	
1012 – पेंशन		29397652.00	29397652.00	
जीवन बीमा निगम – एन आर		223174.00	223174.00	

विवरण	अथशेष	हस्तान्तरण		अंतशेष
		निकासी	जमा	
विविध आकस्मिकता गैर आवर्ती		687531.00	686576.00	955.00 Dr
आवर्ती व्यय		265328464.48	19976740.20	245351724.28 Dr
1. स्थापना व्यय – आवर्ती		154398004.00	11136593.00	143261411.00 Dr
भत्ते और मानदेय		42330997.00	5450024.00	36880973.00 Dr
ग्रेच्युटी		10473741.00		10473741.00 Dr
अंशधारकों के पीएफ भुगतान पर ब्याज		2304664.00		2304664.00 Dr
अवकाश नकदीकरण		10849227.00		10849227.00 Dr
अवकाश यात्रा भत्ता		1844443.00	2324.00	1842119.00 Dr
वर्दी		78726.00		78726.00 Dr
पेंशनरों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति		1468947.00		1468947.00 Dr
स्टाफ के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति		2915191.00		2915191.00 Dr
नई पेंशन योजना		1063152.00	167752.00	895400.00 Dr
समयोपरि भत्ता		19779.00		19779.00 Dr
स्थापना का भुगतान		9808429.00	955311.00	8853118.00 Dr
अधिकारियों का वेतन		16770599.00	2239080.00	14531519.00 Dr
पेंशन		53730779.00	2322102.00	51408677.00 Dr
यात्रा भत्ता		152533.00		152533.00 Dr
ट्यूशन शुल्क		586797.00		586797.00 Dr
2. कार्यालय व्यय – आवर्ती		49817727.48	4930231.49	44887495.99 Dr
विज्ञापन		1339755.00		1339755.00 Dr
पोषाहार प्रभार		4985686.00		4985686.00 Dr
दैनिक मजदूरी प्रभार		1498401.00		1498401.00 Dr
विद्युत प्रभार		2492279.49	2492279.49	
विद्युत शुल्क आवर्ती		8569679.49	4550.00	8565129.49 Dr
बागवानी		18000.00		18000.00 Dr
हाऊस कीपिंग सेवाएं		7880093.00		7880093.00 Dr
बीमा		85555.00	39925.00	45630.00 Dr
स्थानीय यात्रा/टैक्सी प्रभार		1327741.00		1327741.00 Dr
भवन का रख–रखाव/हॉस्टल		6393893.00		6393893.00 Dr
उपकरणों का रख–रखाव		5016970.00	10465.00	5006505.00 Dr
फर्नीचर साजो–सामान का रख–रखाव		106137.00		106137.00 Dr
स्टाफ कार का रखरखाव		174766.00		174766.00 Dr
समाचार पत्र प्रभार		105683.00	1096.00	104587.00 Dr
अन्य विविध प्रशासनिक व्यय		699058.50	129695.00	569363.50 Dr
पेट्रोल तेल और स्नेहक प्रभार		245383.00		245383.00 Dr
डाक एवं टेलीग्राम प्रभार		520551.00	41273.00	479278.00 Dr

विवरण	अथशेष	हस्तान्तरण निकासी	हस्तान्तरण जमा	अंतशेष
दर/किराया और कर		402786.00	402786.00	
दर/किराया और कर		402786.00		402786.00 Dr
सुरक्षा व्यय		2631679.00		2631679.00 Dr
स्टेशनरी/वस्तुओं का भंडारण		2144668.00	1408596.00	736072.00 Dr
टेलीफोन प्रभार		937525.00	8800.00	928725.00 Dr
जल प्रभार		390766.00	390766.00	
जल प्रभार आवर्ती		1447886.00		1447886.00 Dr
3. शैक्षणिक व्यय – आवर्ती		23992017.00	3056328.71	20935688.29 Dr
शैक्षणिक कार्यक्रम (अ.जा./अ.ज.जा. सहित)		6685812.00	367132.00	6318680.00 Dr
संसाधन व्यक्तियों को मानदेय (अ.जा./ अ.ज.जा. सहित)		719832.00	33100.00	686732.00 Dr
सदस्यता और सदस्यता अंशदान शुल्क		135138.00	1000.00	134138.00 Dr
फोटोकॉपी प्रभार		572822.00	233.00	572589.00 Dr
मुद्रण प्रभार		1331493.00	357313.00	974180.00 Dr
छात्रवृत्ति, पुस्तकें तथा परियोजना (डेपा)		571251.00		571251.00 Dr
संकाय को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता		4640467.00	140635.71	4499831.29 Dr
भागीदारों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (अ.जा./ अ.ज.जा. सहित)		9335202.00	2156915.00	7178287.00 Dr
4. विश्वविद्यालय अध्ययन/एन.जी.ओ.		33154848.00	853587.00	32301261.00 Dr
तृतीय अखिल भारतीय सर्वेक्षण – राज्यों को अग्रिम (आर.एस. त्यागी)		157355.00		157355.00 Dr
तृतीय अखिल भारतीय सर्वेक्षण (आर.एस. त्यागी)		761873.00		761873.00 Dr
उन्नत स्कूल के लिए आधुनिक प्रशिक्षण		231000.00		231000.00 Dr
केन्द्रीय क्षेत्र योजना छात्रवृत्ति		581297.00		581297.00 Dr
केन्द्रीय अवधि मूल्यांकन क्षेत्र – वी.पी.एस. राजू		107000.00		107000.00 Dr
तुलनात्मक शैक्षिक लाभ – मोरा खरे		561733.00		561733.00 Dr
डीईओ और बीईओ के लिए क्षमता विकास सम्मेलन		1679581.00		1679581.00 Dr
बच्चों की शिक्षा का महत्वपूर्ण मूल्यांकन		2269483.00	270000.00	1999483.00 Dr
डेपा वेतन		498156.00		498156.00 Dr
शैक्षिक दस्तावेजों का डिज़िटल भंडारण (डा. मैथ्यू)		22484.00		22484.00 Dr
मदरसा में एसपीक्यूईएम योजना का मूल्यांकन		10714.00		10714.00 Dr
एम.फिल./पी.एच.डी. छात्रों को अध्येतावृत्ति		10074677.00	517587.00	9557090.00 Dr

विवरण	अथशेष	हस्तान्तरण निकासी	हस्तान्तरण जमा	अंतशेष
अध्ययन के लिए अनुदान सहायता		1780441.00		1780441.00 Dr
गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान		10737980.00		10737980.00 Dr
गहन अध्ययन के लिए गंभीर परीक्षा		190000.00	20000.00	170000.00 Dr
शिक्षकों की भागीदारी		382615.00	9464.00	373151.00 Dr
शिक्षा प्रशासन में राष्ट्रीय नवाचार		943726.00	20000.00	923726.00 Dr
राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति		231548.00		231548.00 Dr
लड़कियों के लिए राष्ट्रीय योजना (वीपीएस राजू)		47377.00		47377.00 Dr
बाल प्राथमिक स्तर सहभागी कारवाई		816516.00		816516.00 Dr
परियोजना प्रबंधन इकाई – डॉ. के.बिस्वाल		708535.00		708535.00 Dr
जीवनी पुस्तकों का प्रकाशन – आरती श्रीवास्तव		288424.00		288424.00 Dr
निजि–सार्वजनिक माध्यमिक शिक्षा एन.के. मोहंती		10321.00		10321.00 Dr
आरटीई के अधीन समता के समीक्षा की आवश्यकता – डा. नरेश कुमार		30000.00	15000.00	15000.00 Dr
विद्यालय प्रमुख की भूमिका – डा. रश्मि दीवान		17000.00		17000.00 Dr
आस्ट्रेलिया में शिक्षण और अनुसंधान – विनीता		15012.00	1536.00	13476.00 Dr
5. उत्तर–पूर्वी क्षेत्र		3965868.00		3965868.00 Dr
उत्तर–पूर्वी क्षेत्र		3965868.00		3965868.00 Dr
लाभ और हानि खाता	17665145.63 Dr		17665145.63	
महायोग		**1649741603.79**	**1649741603.79**	

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के लेखे पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, पूर्व में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखाओं, प्राप्ति और भुगतान लेखाओं की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार और सेवा शर्तों) के अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अधीन संलग्न तुलन–पत्र की लेखापरीक्षा कर ली है। हमें वर्ष 2020–21 तक की लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा गया है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी नीपा के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा के आधार पर अपने विचार व्यक्त करने की है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखाकरण के व्यवहार्य से एकरूपता, लेखाकरण के मानदंडों और पारदर्शिता के मानकों इत्यादि के संबंध में लेखाकरण व्यवहार पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां शामिल हैं। पृथक निरीक्षण रिपोर्टों/नि.म.ले. की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के द्वारा आवश्यकतानुसार विधि, नियमों और विनियमों (स्वामित्व और नियामक) के अनुपालन और वित्तीय संचालन और कार्य निष्पादन सहित कार्यदक्षता संबंधी पक्षों इत्यादि पर लेखा परीक्षा की टिप्पणियां प्रस्तुत की जाती है।

3. हमने आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा के मानदंडों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों के अधिक यथार्थ विवरणों से युक्त होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना तथा लेखा परीक्षा का निष्पादन करें। लेखा परीक्षा में, परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों की राशि तथा प्रकटीकरण के साक्ष्यों का लेखा परीक्षण होता है। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण के सिद्धांतों, महत्वपूर्ण आकलनों की समीक्षा के साथ–साथ प्रस्तुत किए गए संपूर्ण वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन शामिल है। हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षा हमारे विचारों को उचित आधार प्रदान करती है।

4. हम अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर प्रतिवेदन करते हैं कि–

(i) लेखापरीक्षा उद्देश्य के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमने समस्त सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

(ii) तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखे/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश सं. 29–4/2012 एफ.डी., दिनांक 17 अप्रैल 2015 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सही प्रकार से

तैयार किए गए हैं तथा लेखा बहियों के अनुसार हैं।

(iii) हमारी राय के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान ने समुचित रूप से लेखा पुस्तिकाओं और संबंधित दस्तावेजों का रखरखाव किया है जो कि ऐसी पुस्तिकाओं की जांच–पड़ताल से पता चलता है।

(iv) हम पुनः प्रतिवेदन करते हैं कि :

अ. भविष्य निधि तुलन पत्र

निम्नांकित तुलन–पत्र को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार नहीं दर्शाया गया हैः–

(i) तुलन पत्र के स.भ. निधि शीर्ष में रु. 14.45 करोड़ की राशि में ब्याज जमा का संचयी शेष तथा पिछले वर्षों के अं.भ. निधि की देयताएं सम्मिलित हैं। अं.भ. निधि में रु. 2.43 लाख की राशि चालू वर्ष के लिए अं.भ. निधि अंशदाताओं की देयताएं हैं।

(ii) तुलनपत्र के अंर्तगत दर्शाया गया रु. 39.21 लाख का ब्याज जमा चालू वर्ष के लिए है और पिछले वर्षों का संचयी शेष इसमें सम्मिलित नही है।

नीपा के पास उपलब्ध स.भ. निधि तथा अं.भ. निधि की वास्तविक देयताएं तथा ब्याज जमा का संचयी शेष लेखा में वर्णित नहीं है। इसे लेखा में वर्णित किया जाना चाहिए।

ब. आय तथा व्यय

ब.1. आय

ब.1.1. अनुदान/सहायता अनुदान (अनुसूची 7) – रु. 29.20 करोड़

(i) मा.सं.वि. मंत्रालय के द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार राजस्व व्यय के लिए उपयोग किए गए अनुदान (सेवानिवृति लाभ प्रावधान को छोड़कर तथा सेवानिवृति लाभ पर वास्तविक व्यय को सम्मिलित कर) को उपरोक्त अनुसूची में आय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इस प्रकार राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया अनुदान रू. 27.33 करोड़ (अनुलग्नक–II) होना चाहिए था परंतु इसे उपरोक्त अनुसूची में रु. 29.21 करोड़ दर्शाया गया है जिससे अनुदान/सहायता अनुदान की अतिरंजना हुई और परिणामस्वरूप पूंजीगत निधि की भी अतिरंजना हुई तथा वर्तमान देयताओं और प्रावधानों–अनुपयोगित सहायता अनुदान का रु. 1.88 करोड़ का अवमूल्यन हुआ।

(ii) उपरोक्त में रु. 5.46 करोड़ का सहायता अनुदान अथशेष था तथा 31 मार्च 2017 को सहायता अनुदात का अंतशेष रु. 6.41 करोड़ था जिससे वर्तमान देयताओ तथा प्रावधानों–अनुपयोगित सहायता अनुदात का अवमूल्यन हुआ तथा पूंजीगत निधि की रु. 0.95 करोड़ से अतिरंजना हुई।

स. सामान्य

रु. (–)13.56 करोड़ का कोष/पूंजीगत निधि को मा.स.वि. मंत्रालय के लेखा प्रारूप का उल्लंघन करते हुए देयताओं के बजाए परिसम्पतियों में दर्शया गया है।

द. सहायता अनुदान

नीपा ने रु. 26.13 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया, जिसमें से रु. 5.40 करोड़ मार्च 2018 में प्राप्त हुए तथा नीपा के पास अथशेष रु. 6.41 करोड़ था। नीपा ने कुल रु. 32.54 करोड़ में से रु. 28.18 करोड़ (अनुलग्नक ii) का उपयोग किया। 31 मार्च 2018 को रु. 4.36 करोड़ बचत शेष था।

नीपा ने वर्ष के दौरान मा.सं.वि. मंत्रालय से विशिष्ट परियोजनाओं के लिए रु. 3.79 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया और इन परियोजनाओं में रु. 6.40 करोड़ का अथशेष था। कुल राशि रु. 10.19 करोड़ में से रु. 2.64 करोड़ वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं पर व्यय किए गए और 31 मार्च, 2018 को रु. 7.54 करोड़ बचत शेष पाया गया।

य. प्रबंधन पत्र

लेखा से संबंधित जो कमियां लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई हैं, उनमें सुधार करने हेतु पृथक रूप से प्रबंधन पत्र के द्वारा कुलपति, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के संज्ञान में लाया गया है।

पिछले अनुच्छेदों में टिप्पणी के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि इस लेखा रिपोर्ट में तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा के विवरण लेखा पुस्तिका के अनुसार है।

(VI) हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कथित वित्तीय विवरण जो लेखाकरण की नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां के अधीन माने गये हैं, उपर्युक्त महत्वपूर्ण विवरणों तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अनुलग्नक भाग–I में प्रस्तुत अन्य दूसरी सामग्री के संदर्भ में आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुसार सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं:

(अ) जहाँ तक यह 31 मार्च 2018 को राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के तुलन पत्र की स्थिति से संबंधित हैं : तथा

(ब) जहाँ तक यह इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय तथा व्यय लेखे से संबंधित हैं।

भारत के नियंत्रक तथा महानिदेशक, लेखापरीक्षा की ओर से और कृते

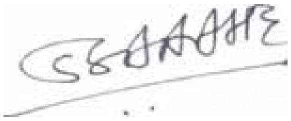

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 29.11.2019

महानिदेशक, लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय

नोट : "प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

अनुलग्नक–I

1. आंतरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था की पर्याप्तता

- संस्थान में अलग से कोई आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग नहीं है और न ही आंतरिक लेखा परीक्षण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

- संस्थान के पास कोई आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली नहीं है।

2. आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की पर्याप्तता

निम्नांकित क्षेत्र में नीपा को आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करना होगाः

- 31 मार्च 2018 तक 2000–01 से 2011–12 की अवधि के दौरान 33 बाह्य लेखा परीक्षा पैरा के उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

- कई मामलों में भुगतान से पहले वाउचर पर वित्त अधिकारी ने प्रतिहस्ताक्षर नहीं किए।

3. संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण

- 31.03.2012 तक अचल परिसंपत्तियों जैसे फर्नीचरों और फिक्सचर तथा कंप्यूटरों इत्यादि का भौतिक सत्यापन किया गया है।

- जुलाई 2012 तक पुस्तकों और प्रकाशनों का भौतिक निरीक्षण कर लिया गया था।

4. वस्तुसूची की भौतिक जांच

- स्टेशनरी, तथा उपभोग वस्तुओं का भौतिक सत्यापन 31 मार्च 2012 तक कर लिया गया है।

5. सांविधिक भुगतान में नियमितता

- लेखा के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2018 तक पिछले छः महीने से कोई भी सांविधिक देयता का भुगतान बाकी नहीं था।

अनुलग्नक–II

राजस्व व्यय का कार्यचालन

आय तथा व्यय लेखा शीर्ष	(राशि रू. में)
आय तथा व्यय लेखा के अनुसार स्थापना व्यय (अनुसूची 10)	19,00,00,285
अकादमिक व्यय (अनुसूची 11)	5,72,02,817
आय तथा व्यय लेखा के अनुसार प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (अनुसूची 12)	2,53,09,906
आय तथा व्यय लेखा के अनुसार रख–रखाव तथा मरम्मत (अनुसूची 13)	1,95,79,394
	29,20,92,402
उपरोक्त में सम्मिलित सेवानिवृत्त लाभ प्रावधान को घटाकर (अनुसूची 10 अ)	7,21,31,645
जमाः सेवानिवृत्त लाभ पर वास्तविक व्यय (अनुसूची 10 अ)	5,33,17,306
	27,32,78,063
कुल व्यय	
राजस्व व्यय	27,32,78,063
लेखा की अनुसूची 7 के अनुसार पूंजीगत व्यय	84,91,956
कुल व्यय	**28,17,70,019**

फा.सं. न्यूपा / प्रशासनिक / आरओ / परिपत्र / 030/20 17

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय

17-बी, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली -110016

नवंबर 30 , 2017

अधिसूचना

विषय : मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं द्वारा 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग - माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपर्युक्त विषय पर अपने दिनांक 10 नवंबर, 2017 और 29 नवंबर 2017 के पत्र सं.एफ 5-1 / 2017 (सीपीपी-आई/ डीयू) के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के आदेशों के अनुसार 'विश्वविद्यालय' का नाम परिवर्तित करने का निर्देश दिया है।

इस मामले पर दिनांक 30/11/2017 को कुलपति द्वारा बुलाई विभागाध्यक्षों और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की बैठक में और दिनांक 30/11/2017 को आयोजित वित्त समिति की बैठक में भी चर्चा की गई।

उपर्युक्त चर्चाओं के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से **राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा)** का नाम बदल कर **राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) (मानित विश्वविद्यालय) कर दिया जाये।**

इस संबंध में आवश्यक परिवर्तन पहले से ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट में कर दिया गया है और यथासमय अन्य रिकार्ड में भी कर दिया जायेगा ।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(बसवराज स्वामी)
कुलसचिव

1. संयुक्त सचिव (पी एंड आईसीसी), उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
2. सभी संकाय सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी और छात्र, न्यूपा ,नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान

(मानित विश्वविद्यालय)

17–बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली–110 016 (भारत)

दूरभाष : 91-011-26544800, 26565600

फैक्स : 91-011-26853041, 26865180

ई–मेल : niepa@niepa.ac.in

वेबसाइट : http://www.niepa.ac.in